

प्रतिथकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 0 32]

नर्द बिस्ली, गॉनिवार, अगस्त 8, 1987/आवण 17, 1909

No. 321

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8, 1987/SRAVANA 17, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संदया की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के क्य में रक्षा का मधी

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—कण्ड 3—उप-कण्ड (li)

PART II-Section 3-Sub-section (II)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरधार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defeace)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिकार्य विभाग)

नई विल्ली, 20 जुलाई, 1987

का.श्रा. 1962—स्मोटरीक नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी व्वारा यह सुधना दी जाती है कि श्री भो.पी. भरताज, एडबोकेंट ने उपन प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के श्रधीन एक श्राधेवन इस बात के लिए दिया है कि उसे दिल्ली ध्यवसाय करमे के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति को मोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का ग्राक्षेप इस सूचनाके प्रकाशन के चौदह दिन के भीसर लिखित रूप में मेरे पास भीजा आए ।

[सं. 5(41)/87-स्या.]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 20th July, 1987

SO 1962—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri O. P. Bhardwaj, Advocate for aparpointment as a Notary to practise in Jalandhar.

679 GI/87---1

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(41)/87-Judl.]

नई विल्ली, 22 जुलाई, 1987

का.धा. 1963.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के धनुसार में सक्तम प्राधिकारी वृजारा यह मूचना दो जाती हैं कि श्री एस.धार. खुराना, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी की उक्त नियम के नियम 4 के प्रधीन एक धावेदन इस बाल के लिए दिया है कि उसे जालंधर व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आसेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर शिखित कप में भेरे पास भेजा जाए।

> [सं 5(40)/87-म्याय.] जार. एन. पोख्वार, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 22nd July, 1987

S.O. 1963.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri S. R. Khurana, Advocate for appointment as a Notary to pratise in Jalandhar.

(2543)

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(40)/87-Judl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

गृह मंत्रालय

(धान्तरिक सुरक्षा विद्याग)

(पुनर्वास प्रमाग)

नई दिल्ली, 30 अपून, 1987

का. पा. 1964. — विस्थापित व्यक्ति (दावा) मनुपूरक अधिनियम 1954 (1954 की सं. 12) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा गृह मंद्रालय, मान्तरिक सुरला विश्वाग पूनर्वास प्रवाग के प्रधीन (बन्दोबस्त विग) में बन्दोबस्त घधिकारी श्री जे.वी. मृदगल को उक्त घिनियम के श्रधीन प्रयवा उसके द्वारा ऐसे घधिकारी को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए तत्काल प्रधाग से घितिएक्त बंबीबस्त धायुक्त नियुक्त करती है।

2. इसके द्वारा भूतपूर्व श्रम धीर पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की दिनांक 8-8-1984 की धिक्षसूचना संख्या-1(12)/विशेष सैल/8.3 एस.एस. II का धितकमण किया जाता है।

[संख्या 1(5)/विशेष सैल/86/एस.एस.1]]

एम. के. कंसल, बंदोबस्त भाय,क्त/पदेन भवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Internal Security)

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 30th June, 1987

- S.O. 1964.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Claims) Supplementary Act, 1954 (No. 12 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri J. R. Mudgal, Settlement Officer in the Settlement Wing of Rehabilitation Division, Department of Internal Security, Ministry of Home Affairs as Additional Settlement Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to such officer by or under the said Act with immediate effect.
- 2. This supersedes erstwhile Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Rehabilitation)'s Notification No. 1(12)/Spl. Cell/83-SS II dated 8th August, 1984.

[No. 1(5)/Spl. Cell/86-SS. III]

M. K. KANSAL, Settlement Commissioner/

Ex-officio Under Secy.

कार्मिक और लोक किकायत तथा पंजन मंत्रालय

(कार्मिक मीर प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1987

का.मा. 1965.— राष्ट्रपति, संविद्यान के अनुच्छेद 148 के खंब (5) के साथ पठित मनुच्छेद 309 के परन्त्क द्वारा प्रदास शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौर भारतीय लेखा परीक्षा मौर लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंशक मौर महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सिक्सि सेवा (म्राचरण) नियम,

1964 का भीर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; भर्मातु:--;

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (धाभरण) संशोधन नियम, 1987 है ।
 - (2) ये राजपक्ष में प्रकाशन की शारीख की प्रवस्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय सिविल सेवा (द्याचरण) नियम, 1964 के नियम 18 में स्पष्टीकरण 1 के चण्ड (1) में, उप खण्ड (ख) के स्थान पर निम्न-लिखित उप खण्ड रखा जाएगा, प्रयसि:---

"(ख) सभी उद्यार, चाहे वे प्रतिभूत हैं या नहीं, जो सरकारी सेवक द्वारा उद्यार दिए गए हैं या लिए गए हैं।"

[मं 11013/1/87-स्या. (ए)]

अ. जयरामन, निवेशक

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

P.G. & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 27th July, 1987.

- S.O. 1965:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to presons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Conduct) Amendment Rules, 1987.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In rule 18 of the Central Civil Services (Conduct) rule. 1964, in Explanation 1, in clause (1), for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely:—
 - "(b) all loans, whether secured or not, advanced or taken by the Government servant,"

[No. 11013/1/87-Ests(A)]

Dublished in the

A. JAYARAMAN, Director.

Note:—The following Amendments have been made to CCS (Conduct) Rules, 1964:—

Matification No.

Date

No.	Gazette of India		
	Part II Section	Section (ii)	3 Sub-
		S.O. No.	Date
1	2	3	 4
1. 25/23/68-Estt (A)	3-2-70	482	14-2-70
2. 25/11/72-Estt(A)	24-10-72	3643	4-11-72
3. 25/57/64-Estt (A)	5-1-73	83	13-1-73
4. 11013/12/75Estt (A)	13-2-76	846	28-2-76
5. 25/19/74-Estt(A)	30-6-76	2563	17-7-76
6. 11013/19/75-Estt(A)	6-7-7 <i>6</i>	2691	24-7-76
7. 11013/6/75-Estt(A)	24-11-76	4663	11-12-76
8. 11013/14/76-Estt(A)	24-8- 7 7	2859	17-9-77
9. 11013/3/78-Estt(A)	20-9-7 8	, 2859	30-9-78
10. 11013/12/78-Estt(A)	20-12-78	3	6-1-80

1 2	3	4	5
11. 110/13/3/80-Estt(A)	24-4-80	1270	10-5-80
12, 11013/21/85-Estt(A)	3-10-85	4812	19-10-85
13. 11013/o/85-Estt(A)	21-2-86	935	8-3-86
14. 11013/11/85-Estt(A)	7-3-86	1124	22-3-86
15. 11013/5/86-Estt(A)	4-9-86	3159	20-9-86
16. 11013/16/85-Estt(A)	10-9-86	3280	27-9-86
- ·			

का.आ. 1966—राष्ट्रपति, संविधान के धमुण्येद 309 के परल्तुक और धमुण्येद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदल्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीका और लेखा विभाग में सेवारय क्यियतियों के संबंध में नियंशक-महालेखा परीक्षक से परामर्थ करने के पण्चात् केन्द्रीय सिविध सेवा (पेंगन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नक्षितिया नियम बनाते हैं, धर्यात्ः—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल मेवा (पैंक्षन) दूसरा संशोधन नियम, 1987 है।
 - (2) ये राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
- 2. फेन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में, नियम 29 के स्थान पर निस्तिक्षित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--;

"29. जब किसी सरकारी सेवक को फालतू पौषित कर विया गया हो, तब धहुँक सेवा में परिवर्धन :ऐसा सरकारी सेवक, जो उस स्थापन में जिसमें वह सेवा कर रहा बा, फालतू भौषित किए जाने पर, कासिक, लोक शिकायत और पेंशम मंजालय के कासिक और प्रिक्रम मंजालय के कासिक और प्रिक्रम मंजालय के कासिक और प्रिक्रम विभाग में धवस्थित केन्द्रीय (फालतु कर्मवारिक्न्य) कोच्छ के माध्यम से या समृह "ध" कर्मवारी की बजा में, रोजगार और प्रिक्रमण महानिवेद्यालय के माध्यम से पुनः अभिनियोजित किए जाने की प्रसुविधा के लिए पान है और पुनः अभिनियोजित किए जाने की प्रसुविधा के लिए पान है और पुनः अभिनियोजित केहने के बजाय स्थेच्छ्या सेवानिकत्त होने का विकत्य कर्द्रता हैं, उसे यह हक हीगा कि वह धपने द्वारा की गई प्रहेंक सेवा में पांच वर्ष और औड़ परस्तु यह सब जब:

- (क) इन नियमों के नियम 13 के प्रथम परशुक्त में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे सरकारी सेवक द्वारा की गई प्रहेंक सेवा उस तारीख को, जिसको वह ऐसे विकल्प का प्रयोग करता है, पन्त्रह वर्ष से कम नहीं होगी और पूर्वोक्त परिवर्धन को सेखे में लेने के पश्चाल प्रहेंक सेवा की धविध उत्तरी सेवा से प्रक्रिक नहीं हो, जितनी सेवा उसने की होती जब वह धपनी धिवर्षता की तारीख को सेवा निवृत्त हो गया होता; प्रौर
- (ख) सेवानिवृत्त होने के जिक्त्य का प्रयोग कर दिया गया है और पेंसन मंजूर करने के लिए सक्तम प्राधिकारों को, उस तारीख से, जिससे संबंधित कर्में वारी फासतू चौषित किया गया है, वी मास की धवधि के धीतर संसूचना दे वी गई है।

[सं. 38/57/87-पी. प्रेंप्ड पी. डब्स्यू]

ए.के. पटनामक, छप सचित्र

पाद टिप्पण :

केन्द्रीय सिविम सेवा (पेंचन) नियम, 1972 का.घा. 934 ताशिख 1-4-1972 के रूप में प्रकासित किए गए वे नियमों का तीसरा संस्कारण (विसम्बर, 1981 तक संगोधित) 1982 में मुद्रित निया गया था । नियम तत्पंत्रवात् पेंगन और प्रशासनिक सुधार विद्याग (पेंसन भीर पेंगनभोगी कल्याण विभाग) की निम्नलिखित धिंधसूचनामी द्वारा संक्षोधित किए गए थे।

क.सं. प्रक्षिसूचना संख्या	सारीका
1. 新.城. 3477	10-9-83
2. का.भा. 4041	1-12-84
3. का.धा. 4218	8-12-84
4. %T. YT. 3324	20-7-85
5. का.भा. 5192	16-11-85
6. W1.W1. 5304	30-11-85
7. 新.斯. 762	1-3-86
8. W. W. 1246	29-3-86
9. का.चा. 2325	21-6-86
10 का जा. 1174	9-5-87

- S.O. 1966.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and, after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Second Amendment Rules, 1987.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, for rule 29, the following rule shall be substituted, namely:—
 - "29. Addition to qualifying service when a Government servant is declared surplus.—A Government servant who, on being declared surplus to the establishment in which he was serving, is eligible for the facility of being redeployed through the Central (Surplus Staff) Cell located in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions or in the case of a Group 'D' employee, through the Directorate General, Employment and Training and oots to retire voluntarily, instead of seeking redeployment, shall be entitled to have five years added to the qualifying service rendered by him:

Provided that-

- (a) not-withstanding anything contained in the first proviso to rule 13, the qualifying service rendered by such Government servant shall be not less than fifteen years on the date on which he exercises such option and the qualifying length of service after taking into account the aforesaid addition is not more than the service he could have rendered had he retired on the date of his superannuation; and
- (b) the option to retire is exercised and is communicated to the authority competent to sanction pension within a period of two months from the date from which the employee concerned has been declared surplus."

[No. 38/57/87-P&PW]

A. K. PATNAIK, Dy. Secy.

Foot Note:—The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 were published as S.O. 934 dated 1-4-1972. The Third Edition (corrected upto December 1981) of the rules was printed in 1982. The rules

were	subse	quently	amen	ded	vide	DP&AP	L
(DP8	(Wqs	Notifica	tions	σίv	en	below:	

S. Notification No. No.		Date
1.	S.O. 3477	10-9-1983
2.	S.O. 4041	1-12-1984
3.	S.O. 4218	8-12-1984
4.	S.O. 3324	20-7-1985
5.	S.O. 5192	16-11-1985
6.	S.O. 5304	30-11-1985
7.	S.O. 762	1-3-1986
8.	S.O. 1246	29-3-1986
9.	S.O. 2325	21-6-1986
10.	S.O. 1174	9-5-1987

द्यादेश

मई दिल्ली, 27 जुलाई, 1987

का. था. 1967.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन शिक्षित्रयम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदेशत कित्यों का प्रयोग करते हुए, चुरी कोयला खान साइटिंग, बिहार से कायले की चारों के बारे में व्याना खेलरी, जिला रांची (बिहार) में राजस्ट्रीकृत मामला प्रथम इतिला रिपोर्ट संक्षा 46/84 सारीख 11-6-84 की बाबत मारतीय वण्ड संहिता, (1860 का 45) की धारा 379 के अधीन वण्डतीय अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्त होने वाले बैसे ही संज्यवहार के अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्त होने वाले बैसे ही संज्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों, दुव्येरणों और एडयंतों के अध्येशण के लिए, बिहार सरकार की सहमार से, विल्ली विशेष पुलिस स्थापन के संबंध में मानिसयों और अधिकारिता का बिस्तारण सम्पूर्ण विहार राज्य पर करती है।

[संख्या 228/2/86~ए.ची.ची.H] मी.एन.के. का.चियानी, निवेशक

ORDER

New Delhi, the 27th July, 1987

S.O. 1967.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 5 read with section 6 of the Delh Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of Government of Bihar hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Bihar for the investigation of offences punish able under section 379 of the Indian Penal Code (45 or 1860) and attempts, abetments and conspivacies in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction in regard to case FIR No. 46/84 dated the 11th June, 1984 registered at Police Station Khelari, District Ranchi (Bihar) in regard to the theft of coal from Churi Colliery Siding, Bihar.

[No 228/2/86-AVD. II] K. N. K. KARTHIAYANI, Director (Vigilance)

विसा मिलासय

(राजस्व विभाग) -नई दिल्ली, 19 मई, 1987

(आयकर)

का. मा. 1968 मायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (V) हारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसदद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "वोहनावर फैनोशिय, तमिलनाडू", को कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1987-88 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 7298/का. सं. 197/167/85-धा. क. (नि.-1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th May, 1987

(INCOME-TAX)

S.O. 1968.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-Tax Act. 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Dohnavur Fellowship, Tamil Nadu" for the purpose of the said clause for the assessment years 1986-87 and 1987-88.

[No. 7298/F, No. 197/167/85-IT(A1)]

का.गा. 1969:— श्रायकर ग्रिधितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त ग्राक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनायं, "श्री हरीहर पुत्र भजन समाज (राजस्टर्ड), ग्रम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1987-88 के लिए ग्रिधमुचित करती है।

सिं. 7299/फा.सं. 197/105/86

S.O. 1969.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Hariharaputra Bhajan Samaj (Reg.), Bombay" for the purpose of the said clause for the assessment years 1986-87 and 1987-88.

[No. 7299/F. No. 197/105/86-IT(AI)]

का० ग्रा० 1970: —ग्रायकर ग्राधितियम, 1961 (1961 क्यू. 43) की घारा 10 की उपद्यारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार • एनद्द्रारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ "श्री कैलाण पाश्रम महासंस्थान, बंगलौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के लिए ग्राधिमुचित करती है।

[सं० 7294/फा०सं० 197/84/86-म्रा०का० (नि०-1)] वसीप सिंह, विशेष कार्य मधिकारी

S.O. 1970.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Kailash Ashram Mahasamsthana, Bangalore" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 7294/F. No. 197/84/86-IT(AI)] DALIP SINGH, Officer on Special Duty

(श्रायकर)

का। श्रा. 1971:—श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (196) का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रक्स शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भरकार एठव्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "बाला मन्दिर कामराज द्रस्ट, महास्य" की कर निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 के लिए श्रधिसुचित करती है।

[सं. 7292/का. सं. 197/204/86-मा..क. (नि.-1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1971.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Bala Mandir Kamraj Trust, Madras" for the purpose of the said clause for the assessment years 1984-85 to 1986-87.

[N. 7292/F. No. 197/204/80-11(A1)]

कां श्रा 1972: --- श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदक्त मिन्तियों का प्रयोग करते द्वुए, केन्द्रीय सर-कार ऐतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्य, "स्टूडेन्ट किस्चियन मूवमेंट ऑफ इण्डिया, बंगलीर" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के लिए श्रिधसुचित करती है।

[सं० 7291 /फा०सं० 197क/223/82-आ०क० (नि०-1)]

S.O. 1972.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Student Christian Movement of India, Bangalore" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 7291|F. No. 197A|223|82-IT(AI)]

का॰ मा॰ 1973: ---ग्रायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रवस्त मिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतव्हारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "(i)श्री मारदा मठ, कलकसा और (ii) रामाकृष्ण धारदा मिशन, कलकता" को कर निर्धारण वर्ष 1987-88 के लिए प्रधिस्चित करती है।

[सं॰ 7293/फा॰सं॰ 197/41/85-भा॰फ॰ (नि॰-1)]

S.O. 1973.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "(i) Sri Sarda Math, Calcutta and (ii) Ramakrishna Sarda Mission, Calcutta" for the purpose of the said clause for the assessment year 1987-88.

[No. 7293/F. No. 197/41/85-IT(AI))]

का॰ भा॰ 1974 — आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) उपरा रतत शानियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "गुरु गोबिन्स सिंह फाउण्डेशन, चण्डीगढ़" की कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के लिए अधियुचित क

[सं० 7296/का॰सं० 197/109/85-ग्रा॰क॰/नि०-1)]

S.O. 1974.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Guru Gobind Singh Foundation, Chandigarh" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 7296/F. No. 197/109/85-JT(AI)]

का० आ०1975:—- ग्रायकर भ्रतिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 10 की उपघारा (23-ग) के खण्ड (V) ज्ञारा प्रयत्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "मालंकार पर्यामा सीरियन चर्च ऑफ मालाबार" को कर निर्धारण वर्ष 1987-88 के लिए भ्रधिस्चित करती है।

[सं० 7295/फाटसं० 197/140/86-आं०क०(नि०1)]

S.O. 1975.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Malankara Marthoma Syrin Church of Malabar" for the purpose of the said clause for the assessment year 1987-88.

[No. 7295]F. No. 197]140[86-IT(AI)]

का० घा० 1976: — ग्रायकर प्रधितियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उन्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "दि बम्बई सोसायटी ग्राफ दि फ्लिस्कन सिस्टर्स अंफ मेरी" को कर निर्धारण वर्ष 1987-88 के लिए श्रिधसूचित करती है।

[सं॰ 7290 (फा॰मं॰ 197/196/86-মা॰ক॰(নি॰**-I**)]

S.O. 1976—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Bombay Society of the Franciscan Sisters of Mary" for the purpose of the said clause for the assessment year 1987-38.

[No. 7290/F. No. 197/196/86-IT(AI)]

का० गा० 1977.—श्वायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्य, "प्रकलिमगुं श्री श्रीनिवास पेदमल तिदकंद्वल", निवयारकोइल, जिला संजोर को ऐतिहासिक महत्य के लिए श्रधिमुचित करती है।

[ব্র্ত 7302/কাত্র্রত 176/84/86-সাত্র্কাত (বিত্র 1)]

S.O. 1977—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 80-G of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Arlmigu Sri Srinivasa Perumal Tirukoil", Nachiarkoil Tanjore District to be historic importance for the purpose of the said section.

[No. 7302]F. No. 176|84|86-IT(AI)]

(अयकर)

का॰ भा॰ 1978:—भायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदक्त मिनियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उपन उपधारा के प्रयोजनार्थ, "श्री महागणपति देम्पल, चशापुरम, पासवाट को सम्मस्त केरल राज्य के प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में श्रधिमृचित करती है।

[सं० 7303 फा०स० 176/3/87-आ०क० नि०-1]

SO. 1978—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 80 G of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Mahaganapathy Temple", Chathapuram, Palghat to be a place of public worship of renown throughout the State of Kerala for the purpose of the said sub-section

[No. 7303]F No. 176[3]87-IT(A1)]

(केन्द्रीय प्रयत्क्ष कर बोर्ड) नर्ड दिल्ली, 19 मई, 1987 (ग्रायकर)

का. आ. 1979:—ग्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 121 की उपधारा (1), द्वारा प्रदत्त गिक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष, कर बोर्ड एतद्द्वारा दिनाक 20-7-1974 की समय-रूमय पर प्रथासंशोधित मिस्सूचना सं. 679 [फा. सं. 187/2/74 ग्रा. क. (नि-1)] में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

2. ऋम सं. 14 तथा 14-क के सामने स्तम्भ सं०. 1, 2 तथा 3 के अर्न्तगत विद्यमान प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी:---

भायकर भायुक्त	प्रधान कार्यालय	क्षेद्राधिक। र
1	2	3
14. लखनऊ	लखन ऊ	1. सम्पद्या शुल्क एवं भायकर परिमण्डल लखनऊ 1
		2. लखनऊ परिमण्डल, लखनऊ
		3 _ू बेतन परिमण्डल, लखनऊ
		4. ग्रल्मोडा
		5. बॉराबेकी
		6 बरेली
		7. विजनौर
		8. बदायू
		′ 9. चन्दौसी
		10. हरवोई
		11. हल्द्वानी
		12. काशीपुर
		13. लखीमपुर-खंडी
		14 परिमण्डल-1,
		मुरावाबाँद
		15. परिमण्डल —П ,
		मुरावाबाद
		16. मैनीतॉल
		17. नजील [ा] बाद
		18. पीलीभीत
		19. पिथौरागढ
		20. रामपुर
		21. रायबरेली
		22. सम्भल
		23. शाहजहांपुर
		24. सीतापुर
		25. उन्ताब ०० जन्म क्रिय
		26. बहुराईच

1	2,	3
4-क इलाहबाद	इलाह्नाव	1. इलाहाबाद
		 सम्पदा भुल्क एलं ग्रायकर परिमण्डल,
		इलाहाबाद '
		सुरुतानपुर
		4. फैंआबाद
		5. फतेहपुर
		6. गोरखपुर
		7. बस्ती
		8. गोंड [ा]
		9. श्राजमगढ
		10. बलिया
		11. देवरिया
		12. वाराणसी
		13. मिर्जापुर
		14. जोन पुर
		15. गाजीपुर
		16. प्रतापगढ़
		17. माउनाय मंजन
	,	18. वधौली।

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

[संख्या 7305/फा. सं. 189/4/87 मा. क. (ति.-1)]

New Delhi, the 19th May, 1987

INCOME TAX

- S. O. 1979.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to its Notification No. 679 [F. No. 187/2/74-IT(A1)] dated 20-7-1974 as amended from time to time.
- 2. The existing entries under column No. 1, 2 and 3 against Serial No. 14 and 14A shall be substituted by the following entries:—

Commissioner of Income Tax	Head Quarters	Jurisdiction
1	2	3
14. Lucknow	Lucknow	 Estate Duty-Cum-Income-tax Circle, Lucknow. Lucknow Circle, Lucknow. Salary Circle, Lucknow. Almora Barabanki Bareilly Bijnor Badaun Chandausi Hardoi Haldwani Kashipur Lakhimpur-kheri Circle-I, Moradabad Circle-II, Moradabad

1 ,	2	3
	——————————————————————————————————————	16. Nainital
		17. Najibabad
		18. Pilibhit
		19. Pithoragarh
		20. Rampur
		21. Raebareli
		22. Sambhal
		23. Shahjahanpur
		24. Sitapur
		25. Unnao
		26. Bahraich
A. Allahabad	Allahabad	1. Allahabad
THE ALLEGANGE		2. ED-cum-IT. Circle, Allahabad,
		3. Sultanpur
		4. Faizabad
		5. Fatehpur
		6. Gorakhpur
		7. Basti
		8. Gonda
		9. Azamgarh
		10. Ballia
		11. Deoria
		12. Varanasi
		13. Mirzapur
		14. Jaunpur
		15. Ghazipur
		16. Paratapgarh
		17. Mau Nath Bhanjan
		18. Badheli

This notification shall take effect from 1-6-1987.

[No. 7305/F. No. 189/4/87-IT(A1)]

नई दिल्ली, 27 मॉर्च, 1987

का. भी . 1980—आयकर भिर्मित्यम, 1961 (1961 का 43), की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गिकितओं का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर वोर्ड एतद्द्वारा दिनांक 25 मई, 1978 की श्रिमिस्थना सं. 2309 [फा. सं. 187/ 11/78—आ. क. (-1)] में दी गई अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है।

क्रम सं. 11-ग कै सामने स्तम्भ (1), (2) तथा (3) के भ्रन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी:—

ग्रायकर		प्रधान	क्षेत्राधिकार
प्रा मुक्त		का र्यालय	
1		2	3
11-ग	कानपुर सेंट्रल	कानपुर	 केन्द्रीय परिमण्डल—I से VI का नपुर। केन्द्रीय परिमण्डल, इलाहाबाद
			2. कन्द्राय पारमण्डल, इलाहाबाद 3. केन्द्रीय परिमण्डल, गोरखपुर
			4. केन्द्रीय परिमण्डल-I, और II वाराणसी
			5. केन्द्रीय परिमण्डल $-\mathbf{I},\mathbf{II}$ और \mathbf{III} लखनऊ ।
			6. केन्द्रीय परिमण्डल, बरेली
			 तिरीक्षी सहायक भ्रायुक्त (कर-नि.) (केन्द्रीय) वाराणसी

यह ग्रधिसूचना दिनांक 15-1-1987 से लागू होगी।

[सं. 7206/फा. सं. 187/3/87 मा. क. (नि-1)] रोशन सञ्चाय, अवर गाविव, केन्द्रीय अध्यक्ष कर मोडे

New Delhi, the 27th March, 1987

S.O. 1980.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 2309 (F. No. 187/11/78-IT(A1) dated 25th May, 1978.

Existing entures under Columns (1), (2) & (3) against serial No. 11C shall be substituted by the following entries:—

Commissioner of Income-tax	Head Quarters	Jurisdiction
	2	3
HC. Kanpur Central	Kanpur	 Central Circles I to VI, Kanpur. Central Circle Allahabad. Central Circle Gorakhpur. Central Circles I & II, Varanasi. Central Circles I, II & III Lucknow. Central Circle Bareilly. I.A.C. (Assit) (Central), Varanasi.

The notification shall take effect from 15-1-1987.

[No. 7206 /F. No. 187/3/87-IT(A1)] ROSHAN SAHAY, Under Secy. Central Board of Direct Taxes

नई दिल्ली, 25 मई, 1987 (ब्रायकर)

का श्री. 1981 — श्रीयकर श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धाण 2 के खण्ड 44 क उप-खण्ड (iii) के श्रनुसरण में, केन्द्रीय मरकार एनद्द्वारा नीचे स्तम्भ 4 में उल्लिखित श्रिधसूचना (श्रिधसूचनाओ) का श्रिधलंबन करते हुए, नीचे स्तम्भ 3 में उल्लिखित कर वसूनी श्रिधकां निया के स्थान पर नीचे स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों की, जो केन्द्रीय सरकार के राजपंजित, अधिकारी है उक्त श्रिधिनियम के श्रन्यांत कर वसूनी श्रिधकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए श्राधिकृत करती है .—

क उन व्यक्तियों के नीम जिन्हें कर वसूली ग्रिधिकांरी उन कर वसूली ग्रिधिकारी (ग्रिधि- पुरीनी ग्रिधिसूचनाओं की संख्या स (ग्रिधिकारियों) की शक्तियों को प्रयोग करने हेतू कारियों) के नीम जिनके स्थान पर और तारीखं जिनका ग्रिधिल्यन प्राधिकृतं किया जाना है स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को किया जाना है।

	प्राधिकृताकया जाना हा	
2	3	4
]. सर्व श्री एंडी. सरविह	सर्वश्री एन .सी .सी रभजन	6050 दिनाक 23-11- 84 फा. सं. 398/39/84-क्रा. क. (बे)]
2. मर्वश्रीपी. सी. गुप्ती	सर्वश्री एस. पी. शर्मा	- नदैव
3. सर्वश्री ग्रार ए. वसल	सर्वश्री के. एल भाटियां-∐,	6168 दिनाक 8-3∼85 फि.ा. सं. 398/4/85—न्ना.क. (ज.)]
4 सर्वेश्री शार एत. शग्न ाल	सर्वेश्री एस, के, किरपोल	—-नदैव `
s. सर्वश्री एस एल. कुमार	सर्वश्री ए. के. मोगा	62:06 दिनांक 2:5-4-85 [फा. स. 3:98/4/85—फ्रा. क. (ब.)]
6. सर्वश्री बी. एत. खान भंदानी,	सर्दशीपी, के बिज्बोस	6226 दिनांक 18-5-85 [फा. मं 398/4/85श्रा. क) (ब.]

यह अधिमूचना तत्कील लागू होगी और जहां तक स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों की सम्बन्ध है कर बसूली प्रधिकारियों के स्था में उनके कार्यभार सम्भालने की तारीख (तारीखों) से लागू होगी।

[मं. 7312 का. सं. 398/17/87-आई टी (बी)]

New Delhi, the 25th May, 1987

(INCOME-TAX)

S.O. 1981: In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises the persons mentioned below in column 2, being the Gazetted officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officer (8) under the said Act in place of the Tax Recovery Officers mentioned below in column 3 in supersession of the Notification (8) mentioned below in column 4:

Sl. Name of the persons to be authorised No. to exercise powers of Tax-Recovery Officer(s)		Name of Tax Recovery Officer(s) Old Notification No. and date to in place of whom the persons mentioned in column 2 are to be authorised			
(1)		(2)		(3)	(4)
1. 8	S/Shri	A.D. Marwah	S/Shri	N.C. Sarbhajana	6050 dt. 23-11-84 [F. No. 398/39/84-1 T(B)]
2.	44	P.C Gupta	**	S.P. Sharma	-do-
3.	*1	R.A. Bansal	"	K.L. Bhatia-II	6168 dt. 8-3-85 [F. No 398/4/85/-1T(B)]
4.	**	R.N. Aggarwal	11	S.K. Kirpal	-do-
5.	**	S.L. Kumar	••	A.K. Monga	6206 dt. 25-4-85 [F. No. 398/4/85-1T(B)]
6,		V.N Khanchandani	44	P.K. Biswas	6226 dt. 18-5-85 [F. No. 398/4/85-T(B)]

2. This Notification shall come into force with immediate effect and in so far as persons mentioned in column 2 from the date(s) they take over charge(s) as Tax Recovery Officers.

[No. 7312 F. No. 398/17/87-IT(B)]

नई बिल्ली, 5 जून, 1987 (भायकर)

का. श्रा. 1982 — श्रायकर श्रधितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के श्रनुसरण कर वसूली श्रधिकारी के रूप में श्री के श्रार. उपाध्याय की नियुक्ति के संबंध में जारी की गई बित्त मंजालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 21-5-84 की श्रधिस्थाना सं. 5812 [फा. मं. 398/14/84 श्रा. क. (अ.)] को एनस्ट्रारा रह किया जाता है।

2. यह श्रिधसूचना श्री के. श्रार. उपाध्याय द्वारा कर बसूली श्रिधकारी का कार्यभार मौंपने की तारीख से लागु होगी ।

> [मं. 7335|फा. मं. 398|15|87|ग्रा. क. (व.)] बी. ई. ग्रालैक्जेंडर, ग्रवर मनिय

New Delhi, the 5th June, 1987

(INCOME-TAX)

- S.O. 1982.—The notification issued in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 5812 [F. No. 398/14/84-IT(B)] dated 21-5-84 in pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) appointing Shri K. R. Upadhyay as Tax Recovery Officer is hereby cancelled.
- 2 This notification shall come into force with effect from the date Shri K. R Upadhyay hands over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 7335/F. No. 398/15/87-IT(B)]
B F ALEYANDER, Under Secy

नई विल्ली, 15 स्रप्रेंस, 1987

का. आ. 1983— श्रीयकर श्रीधित्यम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121-क की उपधारा (1) द्वारों प्रवत्त णिक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारों निवेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिध्य भिक्तार क्षेत्र के धायकर धायक (अपील) स्तम्भ (2) की तत्सम्बन्धी प्रविद्धियों में विनिध्यक श्रीयकर धायक अतिकर या ध्यों ज कर से निर्धारित ऐसे ध्यक्तियों के बोरे से अपना कार्य निर्वेष्ठण करेंगे, जो श्रीयकर ध्रीधित्यम, 1961 की धारों 246 की उपधारों (2) के खण्ड (क) से (ज) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधित्यम, 1964 (1964 का 7) की धारा 11 की उपधारों (1) तथा ब्योज कर अधित्यम, 1974(1974 को 45) की धारों 15 की उपधारों (1) से उत्लिखित किसी भी ऐसे आदेश से व्यथित हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों यो व्यक्तियों की श्रीणयों की बोबत भी कार्य निर्वेष्ठण करेंगे, जिनके लिए बोर्ड ने अविनय अधिनियम 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपबंधा क अनुमीर निर्देण दिया है या भविष्य में निर्देश दें।

धनुसूची क्रम सं. श्रिष्ठिकार क्षेत्र तथा प्रधान कॉर्यालय परिमण्डल का नाम 3 1. बैतन परिमण्डल, हैंदरासाद। • 1 भायकर भायुक्त (भ्रमील)-1 हैदराबाद। 2 परिमण्डल-1, हैदराबाद । 3. विशेष जाच परिमण्डल-1, हैवराबाद। 4. फिल्म परिमण्डल, हैदराबाद। गर्बेक्षण परिमण्डल, हैदराबा र क रन्ल भारगल गण्ड्र तथा तिरूपति । 6. तिरूपति परिभण्डल तिरूपति, 7. चित्तुर परिमण्डल **४. धननपुर परिमण्ड**ल 9 अडोनी परिमण्डल 10. करनूल परिमण्डल 11. नि.स. श्रा. (क नि) रेज-1, हैंदराँबाँद। मम्पनी परिमण्डल हैदर्बिद। 2. ग्रायकर भाय्कत (अपील) --II है वराक्षाद। 2. स^मगरेष्टी परिमण्टल 3. निजामोबोद परिमण्डन 4. निरमल परिमण्डल S. नि. स आा. (क नि) रेज II हदशंबाद । 1. वारंगल परिमण्डल 3. द्यायकर भागुवत (अपील) III) हेदरांबाद । अस्माम परिमण्डल **३ हिन्दुपुर ग**िमण्डल 4 कुडडीपाह परिमण्डल ताण्ड्याल परिमण्डल 6 प्रोद्द[ा]तुर परिमण्डल / गण्डण परिमण्डल प्त. विशेष जाच परिमण्डल, गण्ट्र १. पीरमण्डल---।।। हैदराबाद 10 केन्द्रीय परिमण्डल, हैंदर्सनाद भेग्डीय परिमण्डल, काफीनां बा

3

- 12. केन्द्रीय परिमण्डल, विजयनाडा
- 13. नालगांडा परिमण्डल
- 14. महबूबनगर परिमण्डल
- 15. करीम नगर परिमण्डल
- 🗸 16. नि. स. ग्रा. (क. नि) रेंज---III हैदराबाद
- ् 17. परिमण्डल----] , हैदराँबाद
- 18 परिमण्डल—IV हैदराबाद।
- श्रायकर श्रायुक्त (श्रपील), विशासापसनम
- 1 श्री काकूलम परिमण्डल
- 2. विजय नगरम् परिमण्डल
- 3 विशाखापननम् परिमण्डल
- 4. विभेष जाच परिमण्डल, विशाखापत्तनम
- 5. बेतन परिमण्डल, विशाखापत्तनम
- म्रनाकापल्ली परिमण्डल
- 7. परिमण्डल-I, काकीनाडा
- 8 परिमण्डल-II, काकीनाडा
- 9 राजा सुन्दरी परिमण्डल
- 10. श्रमालपुरम परिमण्डल
- 11 रानाकांन परिमण्डल
- 12 तनम् परिमण्डल
- 13. भीयावरम् परिमण्डल
- 14. एसक परिमण्डल
- 15 परिमण्डल-री, बिजयबाहा
- 16 परिमण्डल- Π , विजयबाडा
- 17 विशेष जाच परिमण्डस, विजयभाहा
- 18. मछलीपसनम परिमण्डल
- 19 गुदीबाबा परिमण्डल
- 20 बापाटला परिमण्डल
- 21 तेनाली परिमण्डल
- 22. अंगोले परिमण्डल
- 23. नेस्सोर परिमण्डस
- 24 गण्टर परिमण्डल
- 25 विशेष जान परिमण्डल, गण्टूर

कहां कही कोई श्रायकर परिमण्डल, बार्ड श्रथवा जिला श्रथवा रेज श्रथवा उसवा कोई भाग इस श्रीधसूचना द्वारा एक श्रीधकार-क्षेत्र में किसी श्राय श्रीधकार क्षेत्र में श्रालिश्त कर दिया गया हो, वहां उस श्रीयकर परिमण्डल, वार्ड श्रथवा जिला प्रयवा रेंज श्रथवा उसके किसी भाग में किसे गये निर्धारणों से उत्पत्त होने वाली और इस श्रीधसूचना की नारीख से तत्काल पूर्व श्रिधकार-क्षेत्र के उस श्रीयकर श्रायकर परिमण्डल, वार्ड श्रथवा जिला श्रथवा रेज श्रथवा उसका कोई भाग श्रत्तरित किया गया हो, इस श्रीधसूचना के लाग होने की नारीख से श्रीधकार-क्षेत्र के उस श्रीयकर श्रीयकर श्रीयकर (श्रिपील) को श्रन्तरित की जायेंगी और उसके द्वारा निषटाई जायेगी, जिसके श्रीधकार-क्षेत्र में श्रमन परिमण्डल वार्ड श्रथवा जिला श्रथवा रेज श्रथवा रेज श्रथवा रेज श्रथवा रेमका कोई भाग श्रन्तरित किया गया है।

य**ह अधिमृष**ना दिनांक 15-4-1987 में लाग् होगी।

New Delhi, 15th April, 1987

S.O. 1983.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioners of Income-tax (Appeals) of the charges specified in column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of such persons assessed to Income-tax or Sur-tax or Interest tax in the Income-tax Wards, Circles and Districts specified in the corresponding entries in the column No. (2) thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in classes (a) to (h) of Sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961 in sub-section (1) of Section 11 of the Companies (Profits) Sur tax Act, 1964 (7 of 1964) and in sub-section (1) of 15 of Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or clauses of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (1) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

SCHEDULE			
S. No. Charges with Headquarters	Name of the Circle		
1 2	3		
1. Commissioner of Income-tax (Appeals)-J, Hyderabad.			
2. Commissioner of Income-tax (Appeals)-II, Hyderabad.	 Company Circle, Hyderab, d. Sangareddy Circle. Nizamabad Circle. Nirmal Circle. IAC (Assts) Range-II, Hyderabad. 		
3. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-III, Hyderabad.	 Warangal Circle. Khammam Circle. Hindupur Circle. Cuddapah Circle. Nandyal Circle. Proddatur Circle Guntur Circle. Spl. Inv. Circle, Guntur. Circle-III, Hydeabad. Central Circle, Hyderabad. Central Circle, Kakinada. Central Circle, Vijayawada. Nalgonda Circle. Mahaboobnagar Circle. Karinmagar Circle. IAC (Assts) Range-III, Hyderabad. Circle-II Hyderabad. Circle-IV, Hyderabad. 		

•

4. Commissioner of Income-tax, (Appeals), Visakhapdtnam.

3

- 1. Srikakulam Circle.
- 2 Vizianagaram Circle.
- 3. Visakhapatnam Circle.
- 4. Spl. Imv. Circle, Visakhapatnam.
- 5. Salary Circle, Vısakhapatnam.
- 6. Anakapalle Circle.
- 7. Circle-I, Kakinada.
- 8. Circle-II, Kakinada.
- 9. Rajahmundry Circle.
- 10. Amalapuram Circle.
- 11. Ralacole Circle.
- 12. Tanuku Circle.
- 13. Bhimavaram Circle,
- 14. Eluru Circle.
- 15. Circle-I, Vijayawada.
- 16. Circle-II, Vijayawada.
- 17. Spl. Inv. Circle, Vijayawada.
- 18. Machilipatnam Circle.
- 19. Gudivada Circle.
- 20. Bapatla Circle.
- 21. Tenali Circle.
- 22. Ongole Circle.
- 23. Nellore Circle
- 24. Guntur Circle.
- 25. Spl. Inv. Circle, Guntur.

Whereas the Income-tax Circle, Ward or district or Range or part thereof stands transferred by this Notification from one charge to another charge, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or Range or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Commissioner or Income-tax (Appeals) of the charge from when that Incometax Circle, Ward or District or Range or part thereof is

transferred shall from the date of this Notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Commissiones of Income-tax (Appeals) of the charge to whom the said Circle, Ward or District or Range or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 15-4-87.

[No. 7246/F. No. 261/8/87-IT/IT)]

नई विरुर्ली, 20 प्रप्राप्त, 1987

का, था. 1984. श्री यक्तर श्रीधित्यम, 1961 (1961 का 43) की श्रीर 121क की उपश्रारा (1) द्वारा प्रदेस लिसियों ना श्रमोग करते हुए और दिसाक 6-2-1986 की पूर्वेवर्ती श्रीसमूचना मं. 6585 (का. म. 261/2/86- आ. क व्या. में संशोधन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्रारा निदेश देता है कि नीचे दी गई श्रमुम्भी के रतम्भ (1) में विनिद्धित श्रीधकार-क्षेत्र के श्रीयकर श्रायुक्त (श्रपील) स्तम्भ (2) और स्तम्भ (3) की तत्मंबंधी प्रविद्यों में विनिद्धित श्रीयकर बार्डी, परिमण्डलों, जिलों और रेंजों में श्रीयकर श्रथना श्रीकर या ब्याजकर से निर्धारित ऐसे व्यक्तियों के बारे में श्रीपताकार्य निर्वेहण करेंगे, जो श्रीयकर श्रीधित्यम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में (ज), कंगनी (लॉभ) श्रीतकर श्रीधित्यम, 1964 (1964 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) तथा ब्याजकर श्रीधित्यम, 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उपधारा (1) में उल्लिखित किनी भी एसे श्रादेण में व्यक्तियम, 1961 की श्रीर विवेदण करेंगे जिनके लिए बोर्ड ने श्रीयकर श्रीधित्यम, 1961 की भारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपधारा (1) के उपवित्य से निर्देश दें।

प्रतयमी

त्रा. स. अधिकार-क्षेत्र	प्रांगमर बाँ ई/परिभाष्टल और जिने	
1	2	3
1. भ्रायुकर भ्रायुक्त (श्रपील). पृणे	श्रीयकर श्रीमुक्त, पुणे के क्षेत्राधिकार में श्रीने बाले सभी बार्ड और परिमण्डल।	पुणे रेज[, पुणे रेज]], पुणे रेज[]], पुणे [करनिर्धारण रेज[, पुणे । टाणे रेज[] टाणे । टाणे रेज[] टाणे । कर-निर्धारण रेज[], पुण ।
2. श्रीयकण् श्रीयुक्त (श्रपील), नासिक।	श्रायकर श्रायुक्त, नासिक के क्षेत्राधिकार में श्राने बाले सभी बॉर्ड और परिमण्डल ।	नामिक रेंज, नामिक कर-निर्धारण रेंज, मिक औरंगाबाद रेज, औरंगाबाद।
 अप्रिकर प्रायुक्त (अपील) कोल्हापुर। 	श्रीयकर श्रीयक्त, कोल्होंपुर के क्षेत्राधिकार में श्राने वाले सभी बाई और परिमण्डल	मोलापुर रेज, भोलापुर कोल्हापुर रेज, कोल्हापुर।

इस ब्रिधिसूचना के ख्राधार पर, ध्रायकर ब्रायुक्त (ब्रिपीच) नासिक वा द्यायकर ब्रायुक्त (ब्रिपीच), कोल्हापुर के क्षद्रा-ब्रिधिकार में ध्राने वाले किसी भी ब्रिपीच पर कोई क्षद्राधिकार नहीं रहेगा और श्रायकर ब्रायुक्त (श्रिपीच), पुणे, का ब्रायकर ब्रायुक्त (ब्रिपीच) नासिक के क्षद्राधिकार में ध्राने वाली किसी भी ब्रिपीच पर कोई क्षदाधिकार नहीं रहेगा।

जहां कोई श्रीयकर परिमण्डल, वार्ड श्रथवां जिला श्रथवां उसका कोई भाग इस श्रीयस्त्रना द्वारा एक श्रीयकार-भेत ने किसी श्रन्य श्रीधकार धोत में श्रन्तित कर दिया गया हों, वहां उस श्रीयकर परिमण्डल, बार्ड श्रथव लिजा श्रथवा उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस श्रीयमुँचना की गौरीख ने तत्काल पूर्व, श्रीयकार--श्रेत के उस श्रीयकर श्रायका के समक्ष विचाराधीन पड़ी श्रिपीलें, जिसके श्रीयकार--श्रत में श्रीयकर परिमण्डल यार्ड श्रथवा जिला श्रथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो इस अधिसूचना के लागू होने की बारीख में अधिकार-क्षेत्र के उस भावकर अधुक्त को अंतरित की जाएगी और उसक द्वारा निपटाई जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, बार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो

यह अधिमूचना दिनांक 1-4-1987 से लागू होगी।

[मं० 7249/फार्ल्स 281/14/87-आरकार्ल्यार्<u>क</u>]

New Delhi, 20th April, 1987

S.O. 1984.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in modification of the previous notification No. 6585 (F. No. 251/2/86-ITJ) dt. 6-2-86, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the Charges specified in Column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of such persons, assessed to Income-tax or Sur-tax or Interest-tax in the Income-tax Wards. Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in column (2) Column (3) thereof as are aggreized by any of the orders mentioned in Clauses (a) to (h) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961 in sub-section (1) of Section 11 of Companies (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964) and in sub-section (1) of Section 15 of the Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or classes of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (1) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

S. No.	Charges with	Income Tax Wards/ Circles and Districts	Range of IACs of Income-tax
1	2	. 3	4
	uissioner of Income-tax, als), Pune.	All Wards & Circles within the jurisdiction of Commissioner of Income-tax, Pune,	Pune Range-I, Pune. Pune Range-II, Pune. Pune Range-III, Pune. Asstt. Range-I. Punc. Thane Range-I. Thane. Thane Range-II, Thane. Asstt. Range-II, Pune.
(Appea	issioner of Income-tax, als), Nasik.	All Wards and Circles within the jurisdiction of Commissioner of Income-tax, Nasik.	Nasik Range, Nasik. Asstt. Range, Nasik. Aurangabad Range, Aurangabad
	dissioner of Income-tax, als), Kolhapur.	All Wards & Circles within the jurisdiction of Commissioner of Income-tax, Kolhapur.	Solapur Range, Solapur. Kolhapur Range, Kolhapur.

By virtue of this notification, the Commissioner of Income-tax (Appeals), Nosik shall exact to have any jutisdiction over any of the appeals falling in the jurisdiction of the Commissioner of Income-tax (Appeals), Kolhapur and the Commissioner of Income-tax (Appeals). Pune shall cease to have any jurisdiction over any of the appeals falling in the jurisdiction of the Commissioner of Income-tax, (Appeals), Nasik.

Whereas Income-tax Circle, Ward or District or Part thereof stands transferred by this notification from one charge to another charge, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or Part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Commissioner of Income-tax of the charge from whom the Income-tax Circle, Ward, or District or Part thereof is transferred shall from the date of this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Commissioner of Income-tax of the charge to whom the said Circle, Ward or District or Part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1-4-1987.

[No. 7249/F, No. 261/14/87-ITJ]

नर्ट दिल्ली, ६ मर्ट, 1987

का. श्रा. 1985—श्रायकर श्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 121क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करने हुए और उस संबंध में पूर्ववर्ती सभी श्रिधिसूचनाओं का श्रिधिलंधन करने हुए. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्रारा निर्देश देता है कि नीच दी गई श्रमुमूची के स्तम्भ (1) विनिधिष्ट श्रिधिकार-क्षेत्र के यायकर ग्रायुक्त (श्रिपील), क्तम्भ (2) और (3) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिधिष्ट श्रीयकर वार्डी, परिमण्डलों, जिलों और रेजों में श्रीयकर श्रथवा श्रीतकर श्रथवा ब्याजकर से निर्धारित ऐसे व्यक्तियों के बार में श्रपना कार्य निर्वहण करेग, जो श्रीयकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ज), कंपनी (लाभ) श्रीतकर श्रिधिनियम, 1964(1964 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) तथा ब्याजकर श्रिधिनियम 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी ऐसे श्रीदेण में व्यथित हुए है और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रीणियों की बाबत भी कार्य निवंहण करेंगे, जिनके लिंगे वोर्ड ने श्रीयकर श्रिधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपबन्धों के श्रनमार निदेश दिया है ये अविष्य में निदेश दें।

ग्रन्मची

गयकर ब्रायुक्त (ग्रधील) के मधिकार-क्षेत्र तथा प्रधान कार्यालय	श्रायकर वार्ड/परिमण्डल/जिले	नि म . ग्रायुक्त (कर-निर्धारण) के रेंज	
1	2	3 -	
1. आयकर प्रायुक्त (श्रापील) ा, थम्माई	ा. कंपनी परिमण्डल-।	ा. नि.स.श्चार, कर-निर्धा रेंज-ाए २ नि.स.श्चा., कर-निर्धा, रेंज-ाबी ३. ,, ,, ,, ,, रेज-ामी	
2. স্থাৰণ্ডৰ স্থাস্থৰ (গ্ৰেণীল)-2, মুম্বৰ্ছ	1 फिल्म परि . 2. कंपनी परि -3 (सौपे गये) 3 बी .एस . डी . (एस .) (सौपे गये)	•	
3. श्रायकर श्रायुक्त (श्रपील)-3, बम्बर्ड	 ग्रायकर ग्रिधकारी, कंपनी परिमण्डल-6 (7) मे (11) कर-निर्धा, परि -2 कर-निर्धा, परि,-2ण ग-4 वार्ड डी-2 वार्ड 		
4 आयकर बायुक्त (झपील) 4. बम्बर्ड	 कंपनी परि-2 विदेशी श्रनुभाग विदेशी कंपनी रेंज बिदेशी कपनी परि2 	 नि.स.म्रा., कर-निर्धा. रेंज-2ए नि.स.म्रा., कर-निर्धा. रेज-2वी नि.स.म्रा., कर-निर्धा. रेज-2सी 	

1	2	3
″ ग्राय कर ग्रायुक्त (भ्रपील)-5, बम्ब ई-	 श्रायकर ग्रधिकारी, कंपनी परि4 (1) से (5) 	 नि.स.मा., कर-निर्धाः रेंज-4ए ,, ,, ,, रेंज-4वी ,, ,, ,, ,, ,, रेंज-4वी
6. श्रायकर श्रायक्त (ग्रपील)-6, बम्बई	 ग्रा.क.ग्रिकि. कपनी परि. 5(1) में (θ) कर-निर्धा. परि-5 विदेशी कंपनी परिमण्डल-1 विदेशी कंपनी रेंज-1 	 नि.स.ग्रा., कर-निर्धा. रेंज-5ए ,, ,, ,, रेंज-5बी ,, ,, ,, रेंज-5सी
र्7. श्रायकत् श्रायुक्त (श्रपील)-8, बम्बई	 ग्रायकर ग्रधिकारी कंपनी परिमण्डल-3 (1) से (8) 	
 आयकर भ्रायुक्त (म्नपील)-8, बम्बई 	 ग्रीयकर मधिकारी कंपनी परिमण्डल-6 (1) से (6) 	
9. म्रायकर मायुक्त (मपील)-9, बम्बई [≯]	 डी. 1 वर्डि कर-निर्धारण परि7 	1. नि.स.मा. कर-निर्धा, रेंज-8
10. भ्रायकर भ्रायुक्त (श्रपील)-10, बम्बई	 सी-1 वार्ड सी-2 वार्ड सी#3 वार्ड सी#5 वार्ड पृना (सींपे गये) 	1. नि.स.भा., कर्र्यनिर्घा. रेंज-8ए
11. घ्रायकर श्रायुक्त (श्रपील)-11, सम्बर्ध	 सर्वेक्षण परि1 सर्वेक्षण परि2 ई-नार्ड जी-वार्ड जी.एवार्ड कर-निर्धारण परि9 	1. नि.सं.श्रा . कर-निर्धा . रेंज=9 2. ,, ,, ,, रेंज-9 ए 3. ,, ,, ,, रेंज-11 4. ,, ,, ,, रेंज-11ए 5. ,, ,, ,, रेंज-12 6. ,, ,, ,, ,, रेंज-12ए .
12- म्रायकर म्रायुक्त (भ्रपील)-12, बम्बर्ड	1. बी-1 वार्ड 2. बी-3 वार्ड . 3. सी-4 वॉर्ड	
13. झायकर भ्रायुक्त (श्रपील)-13, वम्बर्ड	 न्यास परिमण्डल मार्कीट वार्ड 10-वार्ड एस.झॉर. फ्रॉर सी. ए',वी. वार्ड एस.बी1 एस.बी2 	
1.4. श्रायकर श्राय्क्त (श्रपील) -14, बम्बई	 कंपनी परिमण्यल-4 कंपनी परिमण्यल-5 बी.एस.डी. (एस.) 	
15. स्रायकर श्रायुक्त (द्यपील)≁15, बम्बई	 बी. एस.डी. (ई) बी.एस.डी. (डब्स्यू.) बी.एस.डी. (यब्स्यू.) बी-2 वार्ड टी.डी.एस. 	

1	3	3 ,
16. भ्रायकर भ्रायुक्त (भ्रपील)-16, बम्बई	 ग्रायकर भिधकारी, कम्पनी परि3 (.9) से (15) केन्द्रीय परि24 भ्रायकर श्रीधकारी, कर-निर्धा. परि. (श्रव समाप्त किए गर्ये) 	 नि.स.धां., कर-निर्धाः रेंज-10ए नि.स.धां., कर-निर्धाः-रेंज-12 (ए) से (एफ)
17. म्रायक र भ्रायृक्त (श्रपील)-17, बम्बई	1. ए-1 वार्ड 2. ए-2 वार्ड 3. ए-3 वार्ड 4. ब्यवसायिक परि	ं1. नि .स .घा . , कर-निर्धा . रेंज-6 (ए) मे (ई)
18. श्रायकर श्रायुक्त (श्रपील) - 18, बम्बई	1. सम्पदा भुल्क	

जहां कोई श्रायकर परिमण्डल, वार्ड, जिला श्रयवा उसका कोई भाग इस अधिम ना द्वारा एक श्रधिकार-क्षेत्र से किसी श्राय श्रधिकार-क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया हो वहां उस श्रायकर परिमण्डल, वार्ड, जिल अथवा उसके किसी भाग में किये गये जिलारिणों से उत्पन्न होने वाली और इस श्रधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व, अिक र-क्षेत्र के उस श्रायकर श्रायुक्त (श्रपील) के समक्ष पड़ी श्रपीलें जिलारे श्रधिकार-क्षेत्र में श्रायकर वार्ड, परिमण्डल और जिला अथवा अ श्रयवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो, इस श्रधिसूचना के लागू होने की तारीख से श्रधिकार-क्षेत्र के उस अ निर्माश्रयक्त (श्रपील) को अन्तरित की आयेंगी और उसके द्वारा निपटाई जायेंगी, जिसके श्रधिकार-क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड व्या जिला अथवा रेंज श्रयवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो।

यह प्रधिस्चना 1-5-1987 से लागू होग्नी।

[सं ७ ३ / ०/फा.सं. 261/13/87-मा.क.न्या.]

New Delhi, 6th May, 1987

S.O. 1985.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121A of the Incme-tax Act, 1961 (43 of 1961) and, in supersession of all previous Notifications in this regard, the Central B and of Direct Taxes hereby directs that the Commissioner of Income-tax, (Appeals) of the Charges specified in column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of such persons assessed to Income-tax or Sur-tax or Interest-tax in the Income-tax Wards, Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in columns (2) & (3) thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in clauses (a) to (h) of sub-section (1) of Section 11 of Companies (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964), and sub-section (1) of Section 15 of the Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or classes of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (1) of sub-section (2) of section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

CIT(A) Charges with Headquarters	Income-tax Wards/Circles/Districts	Range of IAC, (Asstt.)	
1	2	· 3	
1. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-I, Bombay.	1. Companies Cir. I	1. IAC, Asstt. Range-I A 2. IAC, Asstt. Range-I B 3. IAC, Asstt. Range-I C	
2. Commissioner of Incometax. (Appeals)-II, Bombay.	 Film Circle Companies Cir. III (assigned) B.S.D. (S) (assigned) 		
3. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-III, Bombay.	 ITO, Com. Cir. VI (7) to (11) Asstt. Cir. II. Asstt. Cir. II A A-IV Ward: D-II Ward. 		
4. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-IV, Bombay.	 Companies Cir. II Foreign Section. Foreign Co. Range. Foreign Com. Cir. II 	 IAC, Asstt. Range-II A IAC, Asstt. Range-II E IAC, Asstt. Range-II C 	

(1)	(2)	(3)
5. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-V, Bombay.	1. ITO, Com. Cir. IV (1) to (5)	 IAC, Asstt. Range-IV A IAC, Asstt. Range-IV B IAC, Asstt. Range-IV C
6. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-VI, Bombay.	 ITO, Com. Cir. V (1) to (6) Asstt. Circle-V Foreign Com. Cir. I. Foreign Com. Range-I. 	 IAC, Asstt. Range-V A IAC, Asstt. Range-V B IAC, Asstt. Range-V C
7. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-VIII, Bombay.	1. ITO, Company Cir. III (1) to (8)	
8. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-VIII, Bombay.	1. ITO, Com. Cir. VI (1) to (6).	
9. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-IX, Bombay.	 D-I Ward Asstt. Cir. VII 	1. IAC, Asstt. Range-VII
 Commissioner of Income-tax, (Appeals)-X, Bombay. 	 C-I, Ward C-II Ward C-III Ward C-V Ward Poona (assigned) 	1. IAC, Asstt. Range-VIII A
11. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-XI, Bombay.	 Survey Cir, I Survey Cir, II E-Ward G Ward GA-Ward Asst. Cir. IX. 	 IAC, Asst. Range-IX IAC, Asstt. Range-XI A IAC, Asst. Range-XI IAC, Asstt. Range-XI A IAC, Asstt. Range-XII IAC, Asstt. Range-XII A
12. Commissioner of Income-tax, (Appeals)XII, Bombay.	 B-I Ward B-III Ward C-IV Ward 	
13. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-XIII, Bombay.	 Trust Circle. Market Ward X-Ward N.R.R.C. A-V Ward S.B. I S.B. II 	
14. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-XIV, Bombay.	1. Com. Cir. IV 2. Com. Cir. V	
15. Commissioner of Income-tax (Appeals)-XV, Bombay.	3. B.S.D. (S) 1. B.S.D. (E) 2. B.S.D. (W) 3. B.S.D. (N) 4. B-II Ward 5. T.D.S.	
 Commissioner of Income-tax, (Appeals)-XVI, Bombay. 	 ITO, Com. Cir. III (9) to (15) Central Cir. XXIV ITOs, Asst. Circle (Now dissolved) 	1. IAC, Asstt. Range-X A 2. IAC, Asstt. Range-III (A) to (F).
17. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-XVII, Bombay.	 A-I Ward A-II Ward A-III Ward Prof. Circle. 	1. IAC, Asstt. Range-VI (A) to (E).
18. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-XVIII, Bombay.	1. Estate Duty.	

Whereas an Income-tax Circle, Ward, District or part thereof stands transferred by this Notification from one charge to another charge, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or

part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Commissioner of Income tax (Appeals) of the charge from whom the Income-tax Ward, Circle and District or Range or part thereof is transferred, shall from the date this Notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Commissioner, of-Income-tax (Appeals) of the charge to which the said Circle, Ward or District or Range or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-5-1987.

===: -===⁻ ==

[No. 7270/F. No. 261/13/87-1TJ]

का. आ. 1986 — ग्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त और इस संबंध में सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शन्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में पूर्ववर्ती सभी प्रधिसूननाओं का स्प्रधिलंधन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बार्ड एतद्द्वारर निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिधिप्ट रेंज के अपीलीय सहायक स्रायक रहायकर कायक र के लिए निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और भायको छोड़कर जिन पर क्षेत्राधिकार स्रायकर भायक ्(भपीलं) में निहित है, श्रनुसूची स्तम्भ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में बिनिर्दिष्ट ग्रायकर परिमण्डला, वाजी, और/श्रथवा जिलों में श्रायकर से निर्धारित सभी व्यवितयों और श्राय के संबंध में श्रपने कार्य करेंगे।

मन्स	पी
	•

43K1.		
क. मं. प्रधान कार्यालयों महित रेंज	ग्रायकर परिमण्डल, बोर्ड और जिल	
1 2	3	
1. भ्रमीलीय सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त, ए-रेंज बम्सई ।	 I-वार्ड एन. मार. ग्रॉर. सी. अ्यावसायिक परिमण्डल डी. ग्रार. सी. ए~III वार्ड कर-निर्धारित परिमण्डल—Itए विदेशी कपनी परिमण्डल—I कंपनी परिमण्डल—I कंपनी परिमण्डल—II कर-निर्धारित परिमण्डल—I 	
2. श्रपीलीय सहायक ग्रायकर अधिुनत, बी-रेंज, बस्बई ।	 न्यांस कक्ष कंपनी परिमण्डल- V बी-I वार्ड बी-II वार्ड फिल्म परिमण्डल कंपनी परिमण्डल-III 	
3. श्रवीलीय सहायक षायुक्तर धाँयुक्त. सी-रेज, बम्बई ।	 ए	
 भ्रमीलीय सहायक मायकर मायुक्त, डी—रेंग, बम्बई । 	1. डी I वार्ड	
5. श्रपीलीय सहायक भायकर भायुक्त, इ-रेंज, बम्बई ।	1. डी—I वार्ड 2. डी —II वार्ड 3. सी—IV वार्ड	

` 1	. 2	3
6. श्र ीली	य सहायक भ्रामकर भ्रायुक्त, एक-रेंज, ब म्बर्ड ।	. 1. जी. एसे. डी. (एन.) 2. एस. वी. I . 3. एस. वी.—II 4. बी. एस. डी. (ई) 5. टी. खी. एस.
7. श्रपी ली	य सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त, जी-रेज, बम्बई ।	ा भी. एसं. डी. (पश्चिमी) ं.2. बी. एल. डी. (दक्षिणी)
ं 8. श्रपीली	य सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त, एच-रेंज, बम्बई ।	1. सर्वेक्षण परिमण्डल—्यें (पुरानी) 2. ई——वार्ड
9. भ्रागीली	य सहायक ग्रायकर प्रायुक्त, भ्राई-रेंज, वस्बई्।	 सर्वेकण परिमण्डल—II
10. श्रपीर	नीय सहायक भ्रायकर भ्रायु क् स, जे–रेंज, बम्बई ।	 जी वार्ड जी . ए वार्ड कर-निर्धारण रेंज IX
11. भ्रपीर	तीय सहायक श्रायकर श्रायुक्त, के-रेंज, वस्वई ।	1. सी III वार्ध
12. घ्रपीर	नीय सहायक भ्रायकर श्रायु क् त, एल-रेंज, बम्ब ई ।	 सी:—II बाई सी:—V वाई सी:—I वाई

जहां कहीं कोई प्रायकर परिमंडल, वार्ड प्रथम जिला प्रयम उसका कोई भाग इस प्रक्षित्वना द्वारा एक प्रपीलीय सहायक प्रायकर के प्रमाण जिला प्रथम उसके किसी भाग में किए गए करनिर्धारणों से उत्पन्न होने वाली प्रपीलों इस प्रिध्यक्ता की तारीख से तत्काल पूर्व, उस प्रपीलीय महायक प्रायकत के समक्ष विचाराधीन पड़ी प्रपीलों, जिसके प्रधिकार-क्षेत्र से उक्त परिमण्डल/वार्ड/जिला प्रस्तिरत किया गया हो, इस प्रधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस प्रपीलीय सहायक प्रायक्त को प्रन्तरित की जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी, जिसके प्रधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड प्रयक्ष जिला प्रथम उसका कोई भाग प्रस्तरित किया गया हो।

यहू ब्रिक्षिसूचना दिनांक 1-5-1987 से लागू होगी।

[सं. 7271 /फा. सं. 261/13/87-म्ना. क. न्या.]

S.O. 1986.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it is that behalf and in supersession of all the previous notifications, in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby direct that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range specified in Column (1) of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax in the Income-tax Circles, Wards and/or Districts, specified in the corresponding entry in column (2) thereof excluding all persons and income assessed to income-tax over which jurise diction rests with Commissioners of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE

S. Ranges with Headquarters No.	Income-tax Circles, Wards and Districts
1 . 2	3
Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, A-Range, Bombay.	 X-Ward. N.R.R.C. Professional Circle. B.R.C. A-III Ward Asstt. Circle-II A. Foreign Com Circle-I Company Circle-I Company Circle-II Asstt. Circle-II.

2 1 2. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 1. Trust Cell. B-Range, Bombay. 2. Company Circle-IV. 3. B-I Ward. B-II Ward. 5. Film Circle. 6. Company Circle-III. 3. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 1. A-I Ward C-Range, Bombay. 2. A-II Ward 3. A-IV Ward 4. A-V Ward 5. B-III Ward 6. Market Ward 7. Company Circle-IB 8. Company Circle-VI 9. Foreign Section Asstt, Circle-VI. 4. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 1. D-I Ward. D-Range, Bombay. 5. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, D-1 Ward E-Range, Bombay. D-II Ward 3. C-IV Ward 6. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, B.S.D. (N) F-Range, Bombay. 2. S.B. I 3. S.B. 11 4. B.S.D. (E) 5. T.D.S. 7. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 1. B.S.D. (West) G-Range, Bombay. 2. **B.S.D.** (South) 8. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 1. Survey Circle-I (Old) H-Range, Bombay. 2. E-Ward. 9. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax. 1. Survey Circle-II I-Range, Bombay. 10. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 1. G-Ward. J-Range, Bombay. 2. GA-Ward 3. Assit, Range-IX 11. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 1. C-III Ward K-Range, Bombay.

Whereas the Income Tax Circle, Ward of District or part thereof stands transferred by this Notification from one Appellate Assistant Commissioner of Income-tax to another Appellate Assistant Commissioner of Income-tax appeals arising out of the assessments made in that Income Tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant

12. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax,

L-Range, Bombay.

Commissioner of Income-tax from whom the circle ward district is transferred, shall, from the date of this Notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1-5-1987.

[No. 7271|F. No. 261|13|87-1TJ]

नई दिल्ली, 7 मई, 1987

1. C-II Ward

C-V Ward
 C-I Ward.

का. मा. 1987:—मायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए और भायकर प्रायुक्त (अपील) पटियाला, प्रायकर प्रायुक्त (अपील) लुधियाना, ध्रायकर प्रायुक्त (अपील) जालंधर, प्रायकर प्रायुक्त (अपील) प्रमृतसर और प्रायकर प्रायुक्त (अपील) जम्मू के संबंध में पहले से जारी की गई बोर्ड की स्विध्यचनाओं का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतवृद्धारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ स. (2) में विनिर्दिष्ट प्रभारों के प्रायकर प्रायुक्त (अपील) स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शायकर बोर्डी, परिमण्डलों, जिलों और रेंजों में भायकर प्रयंग प्रतिकर प्रथवा प्रायक्तर से, निर्धारित ऐसे व्यक्तियों के संबंध में कार्य निर्वेष्टण करेंगे जो भायकर

श्रीधिनियम, 1961 की धारा 246 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) न (ज) कंपनी (लाभ) स्रतिकर अधिनियम, 1964 (1864 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) नथा क्याजकर श्रीधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी ऐसे आदेश से व्यथित हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रीणियों की बाबन भी कार्य निर्त्रहण करेंगे जिनके लिए बोर्ड ने आक्यर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उप-धारा (2) के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार निर्देश दिया है या भविष्य में निर्देश दें।

भ्रनुसूची

कम सं.		श्रायकर बोर्ड/जिला/परिमंडल	नि. म. श्रा. की रेज
1	2	3	4
	भायकर म्रायुक्त (मपील) पटियाला	, 1. ध्रायकर श्रायुक्त, पटियाला के क्षेत्राधिकार मे ग्राने वाले पटियाला और लुधियाना में स्थित संपदा शुल्क परिमण्डलों सहित लुधियाना/पटियाला खन्ना, बरनाला, संगरूर, और मलेर कोटला स्थित सभी वार्ड/परिमण्डल/जिले । 2. ध्रायकर ध्रायुक्त (केन्द्रीय), लुधियाना के क्षेत्रा- धिकार के केन्द्रीय परिमण्डल, पटियाला ।	ं2 नि. स. ग्रा. रेंज–I. ∐ और Ⅲ ा, 3. नि. स. श्रा. (कर-निर्धा.) और त. 4. नि. स. ग्रा. (कर-निर्धा.) लुधियाना । 5. नि. स. श्रा. (केन्द्रीय) रेंज-[श्रीर Ⅲ,
	द्यायकर धायुक्त (ग्रपीप) चण्डीगढ़	, 1 भाषकर आयुक्त, पटियाला के क्षेत्राधिकार में आने वाले चण्डीगढ़, शिमला, सोलन, पालमपर, मण्डी स्थित सभी वार्ड/परिमण्डल जिसमें चण्डीगढ़ का सम्पदा गुरूक परिमण्डल भी भामिल है। 2 आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) लुधियाना के अल्ला-धिकार में आने वाले चण्डीगढ़ और करनाल के केन्द्रीय परिमण्डल। 3 आयकर आयुक्त, हरियाणा, रोहतक और आय-कर आयुक्त, पटियाला के केन्द्रीधिकार में आने वाले जांच परिमण्डल, गुड़गाब, हिसार, रोहतक और यमुनानगर के सर्वेक्षण परिमण्डल। 4 आयकर आयुक्त, रोहतक (हरियाणा) के केन्द्रा-धिकार में आने वाले सम्पदा शुक्त परिमण्डलो. महितं सभी वार्ड/जिल/परिमण्डल।	 ति. म. ग्रा. (कर-निर्धा.), चण्डीगढ़ ति. म. ग्रा. (केन्द्रीय~] और []), ल्रियाना । श्रीयकर श्रायुक्त, हरियाणा रोहतक के क्षेत्रा-
	भ्रायकर श्रायुक्त (ग्रपील), क्षुध्रियाना ।	ग. श्रायकर श्रायुक्त, जालन्धर के क्षेत्राधिकार में श्राने वाले कपूरथला, होशियारपुर, मोगा, श्रवोहर, मंसा, फिरोजपुर, मुक्तमर, और भटिंडा के सभी वार्ड/परिमण्डल/जिले। श्रायकर श्रायुक्त (केन्द्रीय) के क्षेत्राधिकार में श्राने वाले लुधियाना क्षेत्र के सभी वार्ड/परि-मण्डल/जिले।	 श्रीयकर श्रीयुक्त, जालंधर श्रथित् स्तम्भ 3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार मे श्राते वाले सभी क्षेत्र। ति. स. श्रा. (केन्द्रीय) रेंग्र—[अौर]], लुधियाना ।
4. !	न्नायकर भ्रायुक्त (भ्रपील), ज्ञालन्धर ।	ां. श्रायकर श्रायक्त, जालन्धर के क्षेत्राधिकार में	. ति स. ग्रा. रेज[और II, जालन्धर। 2. ति स. ग्रा. (कर-निर्धार्), जालंधर रेज- [अौर II, जालंधर । 3. ति स. ग्रा. (केन्द्रीय), भ्रमृतसर।

1

- 5. मायकर मायुक्त (भंपील), 1. मायकर मायुक्त, म्रमृतसर के क्षेत्राधिकार मे भाने वाले सहित भ्रम्तसर, बटाला, ग्रदास-पुर और तरनतारन स्थित सभी वार्ड/परिमण्डल/ जिले जिनमें संपदा शहक परिमण्डल भी शामिल 2. नि. स. ग्रा. (कर-निर्धा.), ग्रम्तसर।
 - 1. स्तम्भ 3 के स्थानों के संबंध में श्रायकर श्रायुक्त, श्रमुतसर के क्षेत्राधिकार में श्राने वाले नि. स. ग्रायुक्तों की सभी रेंजें।
 - 2. ग्रायकर श्रायुक्त (केन्द्रीय), लुधियाना के क्षेत्रा-3 नि. स. म्रा धिकार में आने वाले अमृतसर क्षेत्र के सभी धार्ड/ परिमण्डल/जिले।
- 6 श्रायकरश्रायुक्त (ग्रवील), 1. भ्रायकर श्रीयुक्त, ग्रम्तमर के क्षेत्राधिकार मे म्राने वाले जम्म, उधमुपर, पठानकोट और जम्मू । श्रीनगर के सभी वार्ड/परिमण्डल/जिले ।
- 1 स्तम्भ 3 में उहिलखित स्थानों के संबंध मे ग्रायकर ग्रायुक्त के क्षेत्राधिकार में ग्राने वाले अप्रा. के रेंज।
- 2. आयकर भ्रायुक्त (केन्द्रीय) के क्षेत्राधिकार में 2 नि. स. भ्रा. (केन्द्रीय) भ्रमतसर । ग्राने वाले केन्द्रीय परिमण्डल, श्रीनगर।

जहां कोई श्रायकर परिमण्डल, वार्ड श्रयवा जिला श्रयवा उसका कोई भाग इस श्रधिसूचना द्वारा एक श्रधिकार क्षेत्र से किसी भ्रन्य अधिकार क्षेत्र में भ्रन्तरित कर दिया गया हो वहां उस **श्रा**यकर-परिमण्डल, वार्ड भ्र<mark>यवा</mark> जिला श्रथवा उसके किसी भागमे किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस प्रधिसूचनों की नॉरीख से पूर्व प्रधिकार क्षेत्र के उस प्रायकर ग्रायकत (प्रपील) के समक्ष विचाराधीन पड़ी ग्रापीलें जिसके ग्राधिकार क्षेत्र में ग्रायकर परिमुण्डल, वार्ड ग्रंथवा जिला उसका कोई भाग ग्रन्तरित किया गया हो, इस श्रधिमूचना के लागु होने की तारीख से श्रधिकार क्षेत्र के उस श्रायकर श्रायुक्त (श्रपीक) को श्रन्तरित की जाएगी और उसके द्वारा निपंटोई जाएंगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, बार्ड प्रथमा जिला प्रथमा उसका कोई भाग ध्रन्तरित किया गया हो।

यह श्रधिसूचना दिनाक, 15-4-1987 मे लागू होगी।

[सं. 7272 /फा सं. 261/11/87--ग्रा. क. न्या.]

New Delhi, the 7th May, 1987

S.O. 1987. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of Board's previous notifications issued earlier in respect of Commissioner of Income-tax (Appeals) Patiala, Commissioner of Income-tax, (Appeals), Chandigarh, Commissioner of Income-tax (Appeals), Ludhiana, Commissioner of Income-tax(Appeals), Jalandhar, Commissioner of Income-tax (Appeals), Amritsar and Commissioner of Income-tax-(Appeals), Jammu, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioners of Income-tax, (Appeals) of the charges specified in Col. No. (2) of the schedule below, shall perform their functions in respect of such persons assessed to Income-tax, or sur-tax or Interest-tax, in the Incometax Wards, Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in Col. (3) and Col (4) thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in clauses (a) to (h) sub-section 11 of Companies (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964) and in sub-section (1) of Section 15 of the Interest Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or classes of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (1) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

S. Charge with Hea No.	dquarters	Income-tax Wards/Distt./Circles.	Range of IAC
1 2		3	4
1 Commissioner of (Appeals), Patial		1. All Wards/Circles/Distt. located at Ludhiana, Patiala, Khanna, Barnala, Sangrur, Ropar, and Malerkotla including Estate-Duty Circles located at Patiala and Ludhiana within the jurisdiction of CIT, Patiala.	 1. 1AC, Range Patiala. 2. IACs, Range-I, II and III, Ludhiana. 3. IAC (Asstt.) Patiala and 4. IAC (Asstt.) Ludhiana.

1	2	• 3	4
	,	2. Central Circle, Patiala within the jurisdiction of CIT (Central), Ludhiana.	5. IAC (Central), Range-I & II Ludhiana.
2:	Commissioner of Income-tax, (Appeals), Chandigarh.	1. All Wards/Circles/Distt. located at Chandigarh, Simla, Solan, Palampur, Mandi within the jurisdiction of CIT, Patiala including Estate Duty Circle, at Chandigarh.	 IAC ,Chandigarh. IAC (Asstt.) Chandigarh.
		 Central Circles at Chandigarh and Karnal within the jurisdiction of CIT (Central) Ludhiana. Investigation Circles, Gurgaon, Karnal & Survey Circles at Chandigarh, Gurgaon, Hissar, Rohtak & Yamunanagar within the jurisdiction of CIT, Haryana, Rohtak & CIT, Patiala. 	1. IAC (Central-I & II), Ludhiana
		4. All Wards/Distt./Circles, including Estate Duty Circles within the jurisdiction of CIT, Rohtak (Haryana).	1. All Ranges within the juris- diction of CIT, Haryana, Rohtak.
3.	Commissioner of Income-tax, (Appeals), Ludhiana.	1. All Wards/Circles/Distt. located at Kapurthala, Hoshiarpur, Moga, Abohar, Mansa, Faridkot, Phagwara, Ferozepur, Muktsar and Bhatinda within the jurisdiction of CIT, Jalandhar.	diction of CIT, Jalandhar vis-a-vis stations mentioned in Col. 3.
		2. All Wards/Circles/Distt. located at Ludhiana within the jurisdiction of CIT, (Central), Ludhiana.	2. IAC (Central) Range-I & II, Ludhiana.
4.	Commissioner of Income-tax, (Appeals), Jalandhar.	 All Wards/Circles/Distt. located at Jalandhar, including Estate Duty circles within the jurisdiction of CIT, Jalandhar All Wards/Circles/Distt. located at Jalandhar within the jurisdiction of CIT (Centfal), Ludhiana. 	 IAC, Ranges-I & II, Jalandhar. IAC (Asstt), Jalandhar, Range-I & II, Jalandhar. IAC (Central), Amritsar.
5.	Commissioner of Income-tax, (Appeals), Amritsar.	1. All Wards/Circles/Distt. located at Amritsar, Batala, Gurdaspur and Taran- Taran, including Estate Duty Circles, within the jurisdiction of CIT, Amritsar.	 All IACs Ranges, within the jurisdiction of CIT, Amritsar with regard to the stations in Col. 3. IAC (Asstt.) Amritsar.
		 All Wards/Circles/Distt. located at Amritsar within the jurisdiction of CIT, (Central), Ludhiana. 	3. IAC (Central), Amritsar.
6.	Commissioner of Income-tax, (Appeals), Jammu.		1. IACs Ranges within the jurisdiction of CIT, Amritsar in respect of stations in Col. 3.
		2. Central Circle, Srinagar, within the jurisdiction of CIT (Central), Ludhiana.	2. IAC (Central), Amritsar.

Whereas the Income-tax Circles, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one charge to another charge, appeals, arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or Distt, or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Commissioner of Incometax (Appeals) of the Charges from whom that Income-tax Circles, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect be transferred to and dealt with by the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charge to whom the said circle, ward or district or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 15-4-1987.

नई विल्ली, 15 मई, 1987

का. मा. 1988---भायकर ग्रिविनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाली ग्रन्य सभी शक्तियों का प्रधीग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर वोद्यं एतद्द्वारा दिनोक 24-2-87 की प्रविस्थाना थं. 7144 (फा. सं. 261/4/87-भा.क. (न्या.) में और भागे निम्मलिखित संबोधन करता है।

क्रम सं. (1) स्तम्भ सं. 3 के सामने निम्नलिखित ओड़ा जाएगा:---

क्र. सं. रें ब तथा प्रधान कार्यालय	ग्रायकर परिमंडल, वार्ड या जिले
1. ग्रपीलीय सहायक	8. भ्रनिवासी/परिमण्डल, मद्रास
भायकर भाय ुक ,	9. फिल्म परि मण्डल, मद्र ास
'ए' रेंज, मद्राम	10. टी.डी.एस. परिमण्डल, मद्रास

ा. कम पं. (5), स्तम्भ सं. 3 के सामने निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :---

क. सं. रेंज तथा प्रधान कार्यालय		ग्रायकर परिमण्डल, वार्ड या जिले
5 श्रपीलीय सहायक श्राय्क्त, "ई"	4.	नगर परिमण्डल- 5, मद्राय
रैंज, मद्रास	5.	कुड्डासोर, /परिमण्डल
	6,	पाण्डिचेरी परिभण्डन

III. कम. सं. 7 और स्तम्भ (2) तथा (3) में इसके सामने की सभी प्रविष्टियों को हटा दिया जायगा।

IV. कम. सं. 8, 9, 10 तथा 11 की कमणः 7, 8, 9 तथा 10 में पुनः अंकिन किया जायगा। यह प्रधिसूचना विनांक 1-6-87 से लागू होगी।

[सं. 7275/फा. सं. 261/21/87-ध्या.क. न्या.]

New Delhi, the 15th May, 1987

S.O. 1988:— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxe 1 creby makes the following further amendments to the Notification No. 7144 (F. No. 261/4/87-ITJ) dated 24-2-1987.

I. Against Sl. No. (1) Column No. 3, the following shall be added:

Sl. No.	Range with Head Quarters	Income-tax Circles, Wards or Districts
1	2	3
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'A' Range, Madras.	 Non-Resident Circle, Madras. Film Circles, Madras. TDS Circles, Madras.
. — .—	11. Against Sl. No. (5), Column No. 3, the following	shall be added:
Sl. No.	Range with Head Quarters	Income-tax Circles, Wards or Districts.
1	2	3
	Appellate Assistant Commissioner 'E' Range, Madra	s 4. City Circle-V, Madras.

III. Sl. No. 7 and all entries in Column No. (2) and (3) against it shall be deleted.

IV. Sl. No. 8, 9, 10 and 11 shall be renumbered as 7, 8, 9 and 10 respectively.

This Notification shall take effect from 1-6-1987.

का. गा. 1989.--- श्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 122 की उपघारा (1) द्वारा प्रदल्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस न बंध में सभी पूर्ववर्ती प्रधिसूचनाओं का प्रधिसंघन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर कोई एतद्द्वारा निवेश देता है कि नीचे दी गई श्रनसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्विष्ट रेंजों के श्र्यीक्षी सहायक प्रायक्तर श्रायकर श्रायकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और ग्राय को छोड़कर, जो ग्रायकर श्रायक्त प्रपील के क्षेत्राधिकार में निहित है, उक्त श्रनसूची के स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रथिष्ट में विनिर्विष्ट श्रायकर परिमण्डलों, वार्डों और जिलों में, श्रायकर से निर्धारित मभी व्यक्तियों और ग्राय के संबंध में श्रयना कार्य करेंगे।

	अनुसूची
क.सं. रेंज	भायकर परिमण्डल/ वार्ड / जिले
 श्रपीलीय सहायक, श्रायकर श्राय्कत, 	 जालंधर में कार्य कर रहे सभी परिमण्डल/वार्ड/जिले जिनमें केन्द्रीय परिमण्डल, विशेष परिमण्डल, जांच परिमण्डल सथा
जालंधर रेंज, जालधर	सर्वेक्षण परिमण्डल भी शामिल है।
	2. होणियारपुर, फगवाड़ा, कपूरथला, मोगा, फरीदकोट, फिरोज- पुर, भटिण्डा, अबोहर, मुक्तसर तथा मानसा में कार्य कर रहे सभी परिमण्डल/वाडं/जिले जिनमें विशेष परिमण्डल तथा सर्वेक्षण परिमण्डल भी शामिल हैं।

जहां कही कोई झायकर परिमण्डल, वार्ड और जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा भटिण्डा रेंज से जालंधर में झन्तरित कर दिया गया हो, वहां उस आयकर परिमण्डल, थार्ड, जिला अथवा उसके किसी भाग में दिए गए कर-निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली अपीलें इस झिंधसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व भटिण्डा रेंज के अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें जिसके अधिकार क्षेत्र से उक्त भायकर परिमण्डल, वार्ड या जिला अयवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो, अपीलीय सहायक आयुक्त, आलंधर रेंज, जालंधर द्वारा निपटाई जाएंगी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड और जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो।

अहां किसी विशिष्ट स्थान के प्रधान कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले सभी वार्ड, परिमण्डलर तथा जिले एक अपीलीय सहायक भायुक्त को सौपे गए हैं, वहां वह हाल ही में समाप्त इन प्रधान कार्यालयों के∰परिमण्डलो, वार्डी तथा जिलों के संबंध में भी क्षेत्रा-धिकार का प्रयोग करेगे।

यह प्रधिसूचना 1-6-1987 से लागू होगी।

[सं. 7276/फा.सं. 261/79/87-आर.क. न्या.]

S.O. 1989:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all the previous Notification in this behalf, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range specified in Column (2) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and Incomes assessed to Income-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column (3) thereof excluding all persons and incomes assessed to Income-tax over which the jurisdiction vests in Commissioners of Income-tax (A):—

SCHEDULE

SI.	Range	Income-tax Circles/Wards/Districts
No	•	
1	2	3
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Jalandhar Range, Jalandhar.	 All Circles/Wards/Distt. Functioning at Jalandhar including Central Circles, Special Circles, Investigation Circles and Survey Circles. All Circles/Wards/Distt. functioning at Hoshiarpur, Phagwara, Kapurthala, Moga, Faridkot, Ferozepur, Bhatinda, Abohar, Muktsar and Mansa inincluding Special Circles and Survey Circles.

Whereas the Income-tax Circles, Wards and Districts or part thereof stands transferred by this Notification from Bhatinda Range to Jalandhar Range, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circles, Wards or District or part thereof pending immediately before the date of this Notification before the AAC, Bhatinda Range from which the Income-tax Circles. Ward or District or part thereof is transferred to and shall be dealt with by the A.A.C. Jalandhar Range, Jalandhar to whom the said Circles, Ward or District or part thereof is transferred.

Where all circles, wards or districts having headquarters, at a particular place have been assigned to an Appellate Asstt. Commissioner, he will have jurisdiction in respect of Circles, Wards and Districts at these headquarters since abolished also.

This notification shall take effect from 1-6-1987.

[No. 7276/F. No. 261/19/87---ITJ]

नई दिल्ली, 27 मई, 1987

का. श्रा. 1990—श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा. (1) द्वारा प्रदल शिक्षयों का प्रयोग करते हुए, और इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिखंचन करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद् द्वारा निदेश देना है कि दीचे दी गई श्रनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिद्धिट रेंजों के श्रपीलीय सहायक श्रायकर श्रायुक्त, श्रायकर में निर्धारित उन मभी व्यक्तियों और श्राय को छोड़कर, जो आयकर आयुक्त (श्रपील) के क्षेत्राधिकार में निहित हैं, उक्त श्रनुसूची के स्तम्भ 3 की तत्सबधी श्रविद्धि में विनिद्धिट श्रायकर परिमण्डलों, वाहीं और जिल्लों में श्रायकर में निर्धारित सभी व्यक्तियों और श्राय के संबंध में श्रवनं कार्य करेंगे।

अनुसुधी

क्र.सं.	<mark>श्रपीलीय सहायक श्राम्क्त की रे</mark> ंज	न्नायकर परिमण्डल, वार्ड तथा जिला
1	2	3
1	श्रपीलीय महायक श्रायकर श्रायुक्त "क" रेंज, हैदराबाद।	1 परिमण्डल-1, हैदराबाद
2.	श्रपीलीय महायक श्रायकर भ्रायुक्त,	 करीम नगर परिमण्डल
	"ख" रॅज, हैंदराबाद।	2 व्यम्माम परिमण्डल
		3 परिमण्डल-4, हैदराबा द
		4 फिल्म परिसण्डल, हैदराबाद
		केन्द्रीय परिमण्डल, हैदराबाद
		6 कपनी परिमण्डल, हैदराबाद
		7 वेतन परिमण्डल्, हॅद राबाद
3.	ग्रपीलीय सहायक त्रायकर श्रायुक्त, ''ग'' रेंज, हैदराबाद	1. परि मफ् ल III, हैद राबाद
4.	भ्रपीलीय सहायक आयकर भ्रायुक्त	 परिमण्डल-III हैवराबाद (परिमण्डल-II)
	"घ" रेंज, हैदराबाद ।	2. विशेष जाच परिमण्डल-[, हैदराबाद
		 विशेष परिमण्डल-I तथा I∏
		 4 ्सर्वेक्षण परिमण्डल, हैदराबाद
		 महसूब नगर परिमण्डल
		 निज्ञामाबाद परिमण्डल
		 वारंगल परिमण्डल
		8. निर्मल परिमण्डल
		 सांगरेङ्की परिमण्डल
		10. वि गेष जाभ परिमण्डल
		11 विशेष परिमण्डल, हैदराबाद
		1 2. नाल गोडा परिमण्डल ।

जहां कहीं कोई भायकर परिमण्डल, वार्ड या जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिमूचना द्वारा एक द्वेज से किसी भन्य रेंज में भन्नित्य कर दिया गया हो वहां उस आयकर परिमण्डल, वार्ड या जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर-निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली अपीलों इस अधिसूचना की तारीख में तत्काल पूर्व रेंज के उस अपीली महायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन बड़ी अपीले, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त अध्यक्तर परिमण्डल, वार्ड या जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तित्व किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख में रेंज के उस अपीलीय महायक आयुक्त को अन्तरित की जाएंगी और उसके हारा नियटाई जाएंगी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमृष्टल, वार्ड और जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो।

े यह भश्चिमूचना दिनांक 1-5-1987 से लागू होगी।

New Delhi, the 27th May, 1987

S.O. 1990:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all the previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column (2) of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to Income-tax in the Income-tax circles, wards and districts specified in the corresponding entry in column No. 3 thereof excluding all persons and incomes assessed to Income-tax over which the jurisdiction vest in the Commissioner of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE

S. No.	Appellate Assistant Commissioner's Range	Income-tax Circle, Ward and District
1	2	3
Con	nellate Assistant nmissioner of Income-tax, Range, Hyderabad.	1. Circle-I, Hyderabad.
2. App	pellate Assistant	1. Karimnagar Circle.
	missioner of Income-tax,	2. Khammam Circle.
'B'	Range, Hyderabad.	3. Circle-IV, Hyderabad.
		.4. Film Circle, Hyderabad.
		5: Central Circle, Hyderabad.
		6. Company Circle, Hyderabad.
a	11 4- A - 2-4 4	7. Salary Circle, Hyderabad.
Cor	pellate Assistant nmissioner of Income-tax, Range, Hyderabad.	1. Circle-III, Hyderabad.
4. App	pellate Assistant	1. Circle-II, Hyderabad (Circle-II).
Cor	nmissioner of Income-tax,	2. Spl. Inv. Circle-I, Hyderabad.
,D,	Range, Hyderabad.	3. Spl. Circle-I & III
		4. Survey Circle, Hyderabad.
		5. Mahaboobnagar Circle.
		6. Nizamabad Circle.
		7. Warangal Circle.
		8. Nirmal Circle.
		9. Sangareddy Circle.
		10. Spl. Inv. Circle.
		11. Spl. Circle, Hyderabad.
		12. Nalgonda Circle.

Whereas an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appellate arising out of assessments made in that circle, ward or district or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is

transferred shall from the date this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1-5-1987.

[No. 7314/F. No. 261/20/87-ITJ]

का० न्नां० 1991:— मायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 122 की उपधारा (1), धनकर मिधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 9, दानकर मिधिनियम, 1958 (1958 का 18) की घारा 8 द्वारा प्रदल शिक्तियों का प्रयोच करते हुए, और इस संबंध में सभी पूर्व वर्ती अधिसूचनाओं का मिलियन करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे थी गई मनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिद्दि रेंजों के अपीलीय सहायक आयकर आयकर आयकर/धनकर/दानकर से निवारित उन सभी व्यक्तियों और आय/धन/दान को छोड़कर जो आयकर आयुक्त (अपील) के क्षेत्राधिकार में निहित है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) को तत्सम्बन्धी प्रविधिट में विनिद्ध आयकर परिमण्डलों, वार्डों और जिलों में आयकर/धनकर/दानकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय/धन/दान के संबंध में अपने कार्य करेंगे।

धन <u>ु</u> सूची		
रेज तथा, प्रधान कार्यालय	*ग्रायकर परिमण्डल बार्ड तथा जिले	
1	2	
1 श्रपीलीय सहायक, भ्रायकर म्रायुक्त, रेज⊷ी, बगलौर	 परिमण्डल—1, बंगलीर विदेश प्रनुभाग, बंगलीर कम्पनी परिमण्डल—I में VII, बगलीर ट्रस्ट परिमण्डल, बगलीर फ़िल्म परिमण्डल, बगलीर बेलारी परिमण्डल, बेलारी हॉस्पेट परिमण्डल, हॉस्पेट 	
2. भ्रपीलीय सहायक, भ्रायकर भ्रायुक्त रेज-II, बगलौर।	 परिमण्डल-II, बगलौर परिमण्डल-IV, बंगलौर सर्वेझण परिमण्डल, बगलौर केन्द्रीय परिमण्डल, बगलौर जाच परिमण्डल, बगलौर मैसूर परिमण्डल, मैसूर माण्डया परिमण्डल, माण्डया हासन परिमण्डल, हासन दुमकुर परिमण्डल, दुमकुर 	
3 अपीलीय सहायक श्रामकर श्रायुक्त, रेजIII, बगलौर।	 परिमण्डल-III, बंगलौर बेतन परिमंडल, बगलौर कोलार परिमण्डल, कौलार किकमगलूर परिमण्डल, चिकमगलूर उद्यापी परिमण्डल, उद्यापी कूर्ग परिमण्डल, मेरकर मगलौर परिमण्डल, मगलौर संपदाशुस्क एव ग्रायकर परिमण्डल, बगलौर (ग्रायकर/धनकर/ वानकर के मामले) रायचूर परिमण्डल, रायचूर गुलवर्ग परिमण्डल, गुलवर्ग। 	
4 अपीलीय सहायक, भ्रायकर श्रायुक्त, धारवाड रंज, हुबली	1 हुबली परिमण्डल, हुबली 2 धारबाड़ परिमण्डल, धारबाड़ 3 गाड़ग परिमण्डल, गाडग 4 शिमोगा परिमण्डल, शिमोगा 5 चित्रदुर्ग परिमण्डल, चित्रदुर्ग 6 कारबांड परिमण्डल, कारबाड़ 7 वेब गिरि परिमण्डल, देवगिरि 8 बीजापुर परिमण्डल, बोजापुर 9. बगलकोट परिमण्डल, बगलकोट 10. पणजी परिमण्डल, पणजी 11 मारमाव परिमण्डल, मारगाव 12 बेलगाम परिमण्डल, वेलगाम	

^{2.} जहां कही कोई आयकर परिमण्डल, वार्ड या जिला ग्रथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेज में अन्तरित कर दिया गया हो, वहां उस आयकर परिमण्डल, वार्ड या जिला श्रथता उसके किसी भाग में किए गए कर निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली अपील इस श्रिधसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व गेंज के उस अपीलीय सहायक आयक्त के समक्ष

. बिचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके ग्रधिकार क्षेत्र से उक्त ग्रायकर परिमण्डल, वार्ड या जिला ग्रयवा उसका कोई भाग भन्तरित किया गया हो, इस ग्रीधिसूचना के लागू होने की नारीख में रेंज के उस ग्रपीलीय सहायक ग्रायुक्त को भन्तरित की जाएंगी, और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी, जिसके ग्रधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड और जिला ग्रथवा उसका कोई भाग ग्रन्तरित किया गया हो। यह ग्रिधिसूचना दिनांक 1−6−1987 से लागू होगी।

टिप्पणी:—सम्पदा शृस्क धिधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा 2-क के द्वारा प्रदक्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, किन्द्रीय सरकार प्रपीलीय सहायक धायकर ध्रायकत, रेंज-III, बंगलीर को, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ब, नई विस्ली, हारा जारी की गई विश्वक 28-12-1982 की अधिसूचना संठ 59/82/फा॰मं०/307 11/82-सं०शु० के ध्रनुसार विनांक 3-1-1983 से उन सम्पदा शृल्क ध्रपीलो के संबंध में संपदा शृल्क ध्रपीलीय नियंत्रक, बंगलीर के रूप में नियुक्त किया है जो संपदा शृल्क ध्रपीलीय नियंत्रक [आयकर आयुक्त (अपील)-III, बंगलीर] के क्षेत्राधिकार में नहीं आती हैं। इस प्रकार संपदा शृल्क की उन अपीलों को छोड़कर जो आयकर आयुक्त (अपील) के क्षेत्राधिकार में माती है, सम्पदा शृल्क नियंत्रक, बंगलीर के क्षेत्राधिकार में भाने वाले सभी महायक संपदा शृल्क नियंत्रक, बंगलीर (अपीलील सहायक आयुक्त रेंज-III, बंगलीर) के क्षेत्राधिकार में आपीली सहायक आयुक्त रेंज-III, बंगलीर) के क्षेत्राधिकार में आपीली स

[सं० 7315 /फा० सं० 261/23/87-भा०फ०न्या०]

S.O. 1991:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) Section 9 of Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Section 8 of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958) and in supersession of all previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all the persons and the Income/Health/gift assessed to income-tax/Wealth-tax/gift tax in the Income-tax Circle, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column (2) thereof excluding all persons and income/wealth/gift assessed to Income-tax/Wealth-tax/Gift-tax over which the jurisdiction vests with the Commissioner of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE

Income-tax, Circles, Wards & Districts Ranges with Head Quarters S. No. 2 1. Appellate Assistant 1. Circle-I, Bangalore. Commissioner of Income-tax, 2. Foreign Section, Bangalore. Range-1, Bangalore. 3. Company Circles-I to VII, Bangalore. 4. Trust Circle, Bangalore. 5. Film Circle, Bangalore. 6. Bellary Circle, Bellary. 7. Hospet Circle, Hospet. 2. Appellate Assistant 1. Circle-II, Bangalore. Commissioner of Income-tax, 2. Circle-IV, Bangalore. Range-II, Bangalore. 3. Survey Circles, Bangalore 4. Central Circles, Bangalore. 5 Investigation Circle, Bangalore. 6. Mysore Circle, Mysore. 7. Mandya Circle, Mandya. 8. Hassan Circle, Hassan. 9. Tumkur Circle, Tumkur. 3. Appellate Assistant 1. Circle-III, Bangalore. Commissioner of Income-tax, 2. Salary Circle, Bangalore. Range-III, Bangalore. 3. Kolar Circle, Kolar. 4. Chickmagalur Circle, Chickmagalur. Udapi Circle, Udapi. 6. Coorg Circle, Mercar. 7. Mangalore Circle, Mangalore. E.D. Cum-Income-tax Circle Bangalore (Incometax/Wealth-tax/Gift-tax cases). 9. Raichur Circle, Raichur. Gulbarga Circle, Gulbarga.

1	2	3
4.	Appellate Assisstant	1. Hubli Circle, Hubli.
	Commissioner of Income-tax,	2. Dharwar Circle, Dharwar.
	Dharwar Range, Hubii.	3. Gadag Circle, Gadag.
	•	4. Shimoga Circle, Shimoga.
		5. Chitradurga Circle, Chitradurga.
		6. Karwar Circle, Karwar.
		7. Davangere Circle, Davangere.
		8. Bijapur Circle, Bijapur.
		9. Bagalkot Circle, Bagalkot.
		10. Panaji Circle, Panaji.
		11. Margao Circle, Margao.
		12. Belgaum Circle, Belgaum.

2. Whereas the Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands trnsferred by this Notification from one range to another range, as appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before Appellate Assistant Commissioner of the range from whom that lucome-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred, shall from the date this notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the range to whom the said circles, ward or district or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-6-1987.

Note: In exercise of the powers conferred by sub-section 2A of Section 4 of 1953 (34 of 1953), the Central Government has appointed the Appellate Assistant Commissioner of Income-Tax, Range-III, Bangalore as the Appellate Controller of Estate Duty, Bangalore in respect of Estate Duty appeals over which the jurisdiction do not vest with the Appellate Controller or Estate Duty (Commissioner of Income-tax (Appeals)-III, Bangalore with effect from 3-1-1983 as per Notification No. 59|82|F. No. 307|11|82-ED dated 28-12-1982 issued by the Central Board of Direct Taxes, New

Delhi. Hence the Appellate Controller of Estate Duty, Bangalore (AAC Range-III, Bangalore) will have jurisdiction over estate duty appeals against orders passed by all Assistant Controller of Estate Duty within the jurisdiction of the Controller of Estate Duty Banagalore other than the Estate Duty appeal in respect of which the jurisdiction vests with the Commissioner of Income-tax (Appeals).

[No. 7315]F. No. 261[23[87-FTJ]

नई दिल्ली, 3 जुन, 1987

का उसकारी

		अनुसूच।		
क्रम सं॰	 रेंज	आयकर परिमण्डल/बोर्ड/जिले		
1	2	3		
८ 1 ग्रापीसीय सा	हायक भ्रायकर, भ्रायुक्त नागपुर रेज, नागपुर	 श्रायकर श्रिधकारी, क-बार्ड, नागपुर न्तदैव, क-वार्ड, नागपुर श्रायकर श्रिधकारी, ख-वार्ड, नागपुर तदैव ग-वार्ड, नागपुर तदैव घ-वार्ड, मागपुर तदैव प-वार्ड, नागपुर तदैव प-वार्ड, नागपुर तदैव प-वार्ड, नागपुर तदैव फ-वार्ड, नागपुर तदैव फ-वार्ड, नागपुर श्रपर श्रायकर श्रिकारी, ज-वार्ड, नागपुर 		
		10. श्रेपरश्चायकर श्राधकारा, ज-वाड, नागपुर		

भारतका राजगैल भगस्य १ 1987/जानम 17 1909 2 3 आयकर अधिकारी, झ-बार्ड, नागपुर - म्रपर म्रायकर म्रधिकारी*,*ळ-वार्ड, नागपुर म्रायकर प्रधिकारी, ञा-बार्ड नागपूर ---तदैव---- ट-वार्ड, नागपूर 1.4 ---त**ाँ**व---ठ-वार्ड, भागपूर 1.5 —-सदैव--- ड-वार्ड, नागपूर ---सदै**व-**---त-वार्ड, नागपूर 17 ---तर्देव-- त-वार्क, नागपूर 19 श्रपर भ्रायकर घधिकारी, त-वार्ड, नागपूर 20 मायकर अधिकारी, नगर परिमंडल, नागपुर 21 - आयकर श्रधिकारी, क-बार्ड, गोडिया भायकर भ्रधिकारी, ख-वार्ड, गोडिया ---तदैव--- क-वार्ड, चन्द्रपुर 23 ---सदैध--- ख-धार्ड, चन्द्रपूर 25 प्रथम ग्रायकर ग्रिधकारी, ट्रस्ट परिमण्डल, नागपुर 26 द्विनीय ग्रायकर ग्रधिकारी, ट्रस्ट परिमङ्ख, नागपुर 27 ब्रायकर ब्रधिकारी, ट्रस्ट एवं सपदा शुल्क परिमडल, नागपूर सहायक सपदा शुल्क नियन्नक, नागपुर ग्रायकर ग्रधिकारी, परिमडल-1 (1), नागपूर ---तदैव--- परिमडल-1(2), नागपूर 30 ---तदैव--- 'परिमंडल-1(3), नागपुर 31 ---तदेव----परिमङल-1(४), नागपूर 33 परिमङ्ख-1(5) नागपूर ----तदैव--- परिमङ्ल-1(6), नागपूर ~--न**दैव---**-परिमंडल- $\mathbf{H}(1)$, नागपूर 35 ्परिमडल- $\Pi(z)$, नागपुर **---मदेव**----36 ---न**दै**व----परिमडल- $\Pi(3)$, नागपूर 37 ---- तदैव----परिसङ्गन- $\mathrm{III}(|1)$, नागपूर 38 परिमंडल-III(2), नागपुर --नदेव**--**-39 परिमंडल-Ш(3), नागपुर ~--तदैव---4.0 परिमंडल- $\mathbf{H}(4)$, नागपूर 41 परिमङ्ल- $\Pi I(5)$, नागपुर ---तदैव----13 ग्रायकर ग्रधिकारी, ट्रम्ट परिमंडल नागपुर प्रथम ग्रायकर ग्रक्षिकारी, वेतन परिमडल, नागपूर 45 द्वितीय ---तदैव-- मर्वेक्षण परिमङ्क, नागपुर ्रप्रथम श्रायकर श्रधिकारी सर्वेक्षण परिमङ्ल, नागपुर *द्वितीय---तदैव--- सर्वेक्षण परिमडल¦ नागपुर* 48 तृतीय --तदैव-- सर्वेक्षण परिमंडल, नागमूर ्रथम ब्रायकर श्रधिकारी, कर-निर्धारण, नागपुर ६० द्वितीय---तदैव---कर-निर्धारण नागपूर . तृतीय ----तदैव--- कर-निर्धारण नागपूर 52 प्रथम --- तदेव---गोंडिया 53 द्वितीय ——तदैव——, गोडिया

श्रायकर श्रधिकारी, विदेश श्रनभाग, नागपुर

59 अपर ब्रायकर अधिकारी, परिमद्दल-1(३०), नागपुर⊹

श्रायकर श्रधिकारी गोडिया

---नदैव--- भडार 57 प्रथम श्रायकर श्रिधकारी, चन्द्रपुर 58 वितीय आयकर अधिकारी, चन्द्रपूर . 1

3

1

2- भ्रपीलीय सहायक भायकर भायुक्त, भ्रकोला ।

```
1. भायकर अधिकारी, क-वार्ड, भकोला
```

- 2. भपर भायकर भ्रधिकारी क-वार्ड, श्रकीला
- आयकर सधिकारी, ख-नाई, महोवा
- 4. --तदैव-- ग-बोई, स्रकोसा
- 5. --तदैय-- घ-बीर्ड, प्रकीला
- 6. —तदैव-- ड-बोर्ड, प्रकोला
- 7. ---तदैव--- क-बोर्ड, ग्रमरावती।
- 8. --- तदैव-- ख-वार्ड, अमरावती
- 9 --तर्षेत्र-- ग-वार्ड, ग्रमरावती ।
- 10. ---तदैव--- घ-वार्षं, ग्रमरावती।
- 11. --तदैव-- क-वार्ड, वर्घा।
- 12. ---तदैव-- ख-वार्ड, वर्घा।
- 13 --- तदैव-- यदतमस
- 14. --सदैव-- ख-वार्ड, यदनमल।
- 15. सहायक सपदा शुल्क, नियंत्रक, प्रकोला।
- 16. प्रथम भायकर भ्रधिकारी, श्रकीला।
- 17. वितीय ---तदैव-- भकौला।
- 18. तृतीय ---तदैव--- श्रकोला।
- 19. चतुर्थ ग्रायकर ग्रधिकारी, श्रकीला।
- 20. प्रथम भ्रायकर अधिकारी, भ्रमरावती।
- 21 दितीय ---तदैव-- ग्रमरावती।
- 22 तृतीय --तदैव-- ग्रमरावती।
- 23. चतुर्थ तदैव-- श्रमरावती।
- 24. अपर चतुर्थ भायकर भ्रधिकारी, श्रमरावती।
- 25. प्रथम ग्रायकर ग्रधिकारी, वर्धा।
- 26. दितीय -- तदैव-- वर्धा।
- 27. प्रथम भायकर भ्रधिकारी, यवतुमल।
- 28 द्वितीय --तर्वैय-- यवतमल।
- 29. श्रायकर श्रधिकारी, प्खाम गाव।
- 30 ग्रायकर ग्रधिकारी, केन्द्रीय प्ररिमंडल-I, नागपूर
- 31 -- तदैव-- केन्द्रीय परिमञ्जल-II, नागपूर
- 32 --सर्वेय-- केन्द्रीय परिमंडल-III, नागपुर
- 33 ---तदैव-- केन्द्रीय परिमंडल-IV, नागपूर
- 34. ग्रायकर ग्रधिकारी, केन्द्रीय परिमंडल-क, नागपुर
- 35. ---तर्वेय--- केन्द्रीय परिमंडल-ख, नागपूर
- 36. --सर्वय-- केन्द्रीय परिमंडल-ग, नागपूर
- 37 ---तदैव-- केन्द्रीय (जांच), प्रकोसा
- 38 -- तदैव-- (जांच) वर्धा।
- 39 --- तदैव--- (जांच) यवत्मल।

जहां कहीं कोई आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग इस ग्रधिसूचना द्वारा एक रेज से किसी अन्य रेंज में अन्तरित कर विया गया हो, वहां उस श्रायकर परिमंडल, वार्ड या जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर-निर्धारणों में उत्पन्न होने वाली अपीले इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व रेज के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार क्षेत्र से उकत आयकर परिमंडल, वार्ड या जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त का अन्तरित की आएगी और उसके द्वारा निपटाई आएंगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमंडल, वार्ड और जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो।

यह प्रशिसुबना विनांक 28-4-1987 से लागू होगी।

New Delhi, the 3rd June, 1987

S.O. 1992 In exercise of the powers conferred in sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all previous notification in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellat Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax in the Income-tax Circles/Wards/Districts specified in the corresponding entry in column (2) thereof excluding al persons and income assessed to Income-tax over which the jurisdiction vests in Commissioners of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE				
SI. No.	Range	Income-tax Circles/Wards/Districts		
1	2	3		
	Appellate Assistant Commissioner of Incometax,	1. Income-tax Officer, A-Ward, Nagpur. 2do- A-Ward, Nagpur.		
	Nagpur Range, Nagpur.	3. Income-tax Officer, B-Ward, Nagpur.		
	Magput Mange, Magput,	4do- C-Ward, Nagpur.		
		5do- D-Ward, Nagpur.		
		6do- Ę-Ward, Nagpur.		
		7do- F-Ward, Nagpur.		
		8 do- G-Ward, Nagpur.		
		9. –do– H-Ward, Nagpur.		
		10. Addl. Income-tax Officer, H-Ward, Nagpur.		
		11. Income-tax Officer, I-Ward, Nagpur.		
		12. Addl. Income-tax Officer, I-Ward, Nagpur.		
		13. Income-tax Officer, J-Ward, Nagpur.		
		14. –do– K-Ward, Nagpur.		
		15do- L-Ward, Nagpur.		
		16. –do– M-Ward, Nagpur.		
		17. –do– N-Ward, Nagpur		
		18do- P-Ward, Nagpur.		
		19. Addl. Income-tax Officer, P-Ward, Nagpur.		
		20. Income-tax Officer, City Circle, Nagpur.		
		21. Income-tax Officer, A-Ward, Gondia.		
		22. Income-tax Officer, B-Ward, Gondia.		
		23do- B-Ward, Gondia.		
		23do- A-Ward, Chandrapur.		
		24do- B-Ward, Chandrapur. 25. Ist Income-tax Officer, Trust Circle, Nagpur.		
		26do- Trust Circle, Nagpur.		
		27. Income-tax Officer, Trust cum-Estate Duty Circle		
		Nagpur,		
		28. Asst. Controller of Estate Duty Nagpur.		
		29. Income-tax Officer, Circle-I(1), Nagpur.		
		30do- Circle-I(2), Nagpur.		
		31do- Circle-I(3), Nagpur.		
		32do- Circle-I(4), Nagpur.		
		33do- Circle-I(5), Nagpur.		
		34do- Circle-I(6), Nagpur.		
		35do Circle-II(1) Nagpur.		
		36. do- Circle-II(2), Nagpur.		
		37do- Circle-II(3) Nagpur.		
		38do- Circle-III (1), Nagpur.		
		39do- Circle-III(2), Nagpur.		
		40. do- Circle-III(3), Nagpur.		

THE GAZETTE OF INDIA - AUGUST 8, 1987/SRAVANA 17, 1909 3 2 1 Circle-III(4), Nagpur. 41. --do--Circle-III(5), Nagpur. 42. -- **x**0--Trust Circle, Nagpur. 43. -de-44. 1st Income-tax Officer, Salary Circle, Nagpur. Salary Circle, Nagpur. -2nd 45. -do-46. 1st Income-tax Officer, Survey Circle, Nagpur. Survey Circle, Nagpur. 47. 2nd / -do-48. 3rd -do-Survey Circle, Nagpur. 49. 1st Income-tax Officer, Asstt. Nagpur. Asstt. Nagpur. 50. 2nd --do--51. 3rd -do-Asstt. Nagpur. -do-Gondia. 52, lst 53. 2nd ~do-Gondia. Income-tax Officer, Foreign Section, Nagpur. Income-tax Officer, Gondia. -do-Bhandar. 56. 57. Ist Income-tax Officer, Chandrapur. 58. 2nd Income-tax Officer, Chandrapur. 59. Addl. Income-tax Officer, Circle I(2), Nagpur. 1. Income-tax Officer, A. Ward, Akola. 2. Appellate Assistant Addl. Income-tax Officer, A-Ward, Akola. Commissioner of Income-tax, Income-tax Officer, B-Ward, Akola. 3. Akola. 4. -do-C-Ward, Akola. D-Ward, Akola. 5. -do--do-E-Ward, Akola. 6. 7. -do-A-Ward, Amravati. 8. -do-B-Ward, Amravati. 9. –do− C-Ward, Amravati. 10. -do-D-Ward, Amravati. -do A-Ward, Wardha. 11. B-Ward, Wardha. 12. --do--A-Ward, Yavatmal. 13. --do--14. -do-B-Ward, Yavatmal. Assistant Controller of Estate Duty, Akola, 1st Income-tax Officer, Akola. 2nd -do-17. Akola. 18. 3rd -do-Akola. 19. 4th -do-Akola. 1st Income-tax Officer, Amravati. 21. 2nd --do--Amravati. .22, 3rd ~do-Amravati. 23. 4th -do--Amravati.

Addl. 4th -do-

26. 2nd

31.

32.

33.

28. 2nd

1st Income-tax Officer Wardha.

~do-

-do-

--do--

. --do--

-do-

29. Income-tax Officer, Khamgaon.

27. 1st Income-tax Officer, Yavatmal.

Amravati.

Wardha.

Yavatmal.

Central Circle-II, Nagpur.

Central Circle-III, Nagpur.

Central Circle-IV, Nagpur.

30. Income-tax Officer, Central Circle-I, Nagpur.

==== ====				·	
I	2		3		
		34.	Income-tax	Officer.	Central Circle-A, Nagpur.
		35,	- d o-		Central Circle-B, Nagpur.
		36.	-do	-	Central Circle, C, Nagpur.
		37	-do-	٠.	(Investigation), Akola.
		38.	-do	•	(Investigation), Wardha.
		39.	- do-		(Investigation), Yavatmal.
			.'		

Whereas an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom the Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date of this Notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 28-4-1987.

[No. 7324/F. No. 261/25/87-1TJ]

नई दिस्ली, 4 जून, 1987 श्रुद्धिपक्ष

का. आ. 1993—विनाक 15 अप्रैल, 1987 की अधि-सूचता संख्या 7246(फा.सं. 261/8/87-आ.क.न्या.) देखें जिसमें भायकर आयुक्त (अपील), आध्र प्रदेश के क्षेत्रा-धिकार का उल्लेख किया गया है। ऋ.सं. 3 पर उल्लिखत श्रायकर आयुक्त (अपील)-III हैदराबाद के क्षेत्राधिकार में से निम्नलिखित को हटाया जायेगा तथा मद संख्या 9 से 18 को क्षमानुसार 7 से 16 में प्रम संख्यीकित किया जायेगा।

हटाया जायें} "7. गण्टूर परिमण्डल

बिशेष जांच परिमंडल, गुण्टूर'' :

यह शुद्धिपत्र दिनाभ 15 अप्रैल, 1987 से लागू होगा। [सं. 7325/फा.सं. 261/8/87-आ.क.न्या] के.पी. गांगुली,

> विशेश कार्य प्रधिकारी (न्या.) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

New Delhi, the 4th June, 1987 CORRIGENDUM

5.O. 1993.—Refer Notification No. 7246 (F. No. 261|8,87-JTJ) dated the 15 April, 1987 specifying jurisdiction of Commissioners of Income-tax (Appeals), Andhra Pradesh. In the jurisdiction of Commissioner of Income-tax (Appeals)-III, Hyderabad mentioned at S. No. 3 the following shall be deleted from the jurisdiction of C.I.T. (Appeals)-III, Hyderabad and items No. 9 to 18 shall be renumbered as 7 to 16 consecutively.

Delete "7 Guntur Circle

8 Spl. Inv. Circle, Guntur".

This comes into effect from 15th April, 1987.

[No. 7325/F. No. 261/8/87-ITJ]
K. P. GANGULI, O.S.D (1)
Central Board of Direct Taxes

(सीमासुल्क समाहर्ता कः कार्यालय) भंगलौर 6 मार्च, 1987 सीमासुल्क

(ग्रधिसूचना सं 1/87-सीमा)

का मा. 1894.—सीमाशुल्क मिधिनियम 1962 की धारा 8 द्वारा प्रयक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जे.पी. कीशिक, सीमाशुल्क समाहर्ता, कर्नाटक सीमाशुल्क समाहर्तालय, अंगलीर एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क समाहर्ता, वंगलीर के दिनांक 18-3-1976 की मिधिसूचना नं. 1/76 में निम्नप्रकार संशोधन करता हू जैसे : उक्त बतायी गयी मिधिसूचना की सारणी में क्रमांक 2 से सम्बन्धित प्रविद्यों को छोड़ दिया जाये।

[सी.न. VIII 8/48/106/86-सी2/सीमा] जे.पी. कौशिक, समाहर्ता

(Office of the Collector of Customs)
Bangahore, the 6th March, 1987
CUSTOMS

(Nonfication No. 1/87-Cus.)

SO 1994.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Customs Act, 1962, I J. P. Kaushik, Collector of Customs, Karnataka Customs Collectorate, Bangalore, hereby make the following amendment in Notification of the Collector of Customs and Central Excise, Bangalore No. 1/76 dated the 18th March, 1976, namely —

In the said Notifiction, in the Table, Sl. No. 2 and the entries relating thereto shall be omitted.

[C No VIII/48/106/86-C-2|Cus.]
J. P. KAUSHIK, Collector

(समाहर्तालय केन्दीय उत्पाद शुरुक : मध्य प्रवेश) इन्दौर, 17 जुलाई, 1987 .

ग्रधिसूचना संख्या 8/87

का. भा. 1995:— मध्यप्रवेश समाहर्तालय के श्री श्रार. के. थावानी, श्रीधक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुरुक समूह "ख" 28-5-87 के श्रपरान्ह मे शामकीय सैंशा से स्वरूष्टीक सैंशानिवृत्त हुए । [प०सँ० II(3)/3-गोप/87]

(Central Excise Collectorate, M.P.) Indore, the 17th July, 1987

(NOTIFICATION NO. 8|87)

S.O. 1995.—Shri R. K. Thawanl, Superintendent, Central Excise Group 'B' of Central Excise Collectorate, Indore has voluntarily retired from the Government service in the afternoon of 28-5-1987.

{C. No. II(3)/3-Con/87]

(अधिसूचना सख्या 11/87)

का आ. 1996:--समाहर्तालय केन्द्रीय उत्पाद सुल्क, इन्दौर के श्री मुस्ताफा खान, अधीक्षक समूह "ख" निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-6-87 के श्रपरान्ह में शासकीय सेवा से निवृत्त हो गए।

> [प. सं II (3)/3-गोप/87] ना० राजा, समाहर्ता

TIFICATION NO. 11/87)

S.O. 1996.—Shri Mustafa Khan, Superintendent, Central Excise Group 'B' of Indore Collectorate having attained the age of Superannuation retired from Government service on 30-6-87 in the afternoon.

[C No. II(3)/3-Con/89]N. RAJA, Collector

वाणिक्य मंत्रालय

नर्ध विस्ती, 8 प्रगस्त, 1987

का. घा 1997:---केखोय सरकार, निर्यात (क्यालिटी नियंत ण बीर निरीक्षण) प्रधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 की उपधारा (2) के साद (य) द्वारा प्रवत्त सिन्तियों का प्रयोग करने हुए, रंगलेप तथा संबंध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी निर्येतण भौर निरीक्षण) नियम, 1987* का धौर संशोधन करने के लिए निम्मलिखित नियम बनातों है, प्रथात---

- 1 (1) इन नियमो का मिल्लिम साम रगलेप तका संबद्ध उत्पाद के नियति (क्वासिटी नियसण और निरीक्षण) संगोधन नियम, 1987 है। हैं।
- (2) ये राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख को प्रकृत होंगे। [2 रालेप तथा संबद्ध उत्पाद निर्मात (क्वानिटी नियत्नण भीर निरीक्षण) नियम, 1987 के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखिन नियम रखा आएगा सर्वाल--
 - "6. निरीक्षण कीस.→-इन नियमों के मधीन निरीक्षण कीस के कव मे निर्यातकर्ता हारा मिशकरण की प्रत्येक परेखण के पात-पर्वक्त निःशुक्त मृत्य के प्रत्येक एक सौ क्ष्पण पर 50 पैसे की वर से कीस वी जाएगी।"

[फाइल सं 6(26)/86-ई धाई एंड ई पी] एन० एस० हरिहरन, निदेशक

*पाव टिप्पण --मूल नियम कार्व भाव 308 तारीच 7-2-1987 द्वारा प्रकाशित *
किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 8th August, 1987

- SO. 1997.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Paints and Allied Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1987* namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Export of Paints and Allied Products (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1987.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Export of Paints and Allied Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1987, for rule 6, the following rule shall be substituted namely:—
 - "6. Inspection fee—a fee at the rate of 50 paise for every one hundred rupees of FOB value of each consignment shall be paid by the exporter to the Agency as inspection fee under these rules."

[F. No. 6(26)/86-EI&EP] N S HARIHARAN, Director

Foot note—The principal rules were published vide · S O. 308 dt 7-2-1987.

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1987

का थ्रा 1998:—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार श्रीधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्रारा इस अधिसूचना के श्रनुसम्बक में उल्लिखित उपक्रमों के पंजीकरण के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है। उक्त उपक्रम ऐसे उपक्रम है, जिन्हें उक्त अधिनियम के भाग-क के अध्याय-III के उपबन्ध अब लागू नहीं होते हैं।

[स. 16/12/86-एम.-3]

मधिसूचना स. 16/12/86-एम - III का मनुलग्नन

क्रम सं उपक्रमीं के नाम

र्पजीकत पत

वंजीकरण संख्या

 मैसर्स का नपुरः टैक्सटाइल्स 85/20, कपूरगण, का नपुर लिमिटेड। 161/70

2. मसर्स एग्री प्रसीसन्स इता भेन्टस निकट आई. टी. प्रीई. भी. ओ. कुबेर नगर/ 2246/85 निपटिंड. सरवीर नगर, अहमदीबाद-382340

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs) New Delhi, the 23rd July, 1987

S.O. 1998.—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969

(54 of 1969), the Cantral Government hereby notifies the cancellation of the registration of the undertakings mentioned in the Annexure to this notification, the said undertakings being undertakings to which the provisions of Part A Chapter III of the said Act no longer apply.

[No. 16/12/86-M-III]

ANNEXURE TO THE NOTIFICATION NO. 16/12/86.M-III

Sl. Name of the Undertakings No.	Registered Address	Registra- tion No.
1. M/s Cawapore Textiles Limited.	85/20, Cooperganj Kanpur.	161/70
2. M/s. Agro Precisions Implements Ltd.	Near ITI P.O. Kubernagar/ Sardarnagar,	· 2 246 /85
	Ahmedabad-382340.	

नर्ड दिल्ली, 27 जुलाई, 1987

का. भा. 1999.—एकाधिकार तथा भन्नरोधक व्यापारिक व्यापारिक

[सं. 16/12/86-एम-3] एल .सी∵ गोयल, ग्रवर सचिव

अधिस्चना स. 16/12/86-एम.- 3 का अनुसन्तक

कश्च सं.	उपक्रमों के नाम	पंजीकृत पता	पंजीकरण	- संख्या
1	2	3	4	_
. मैं . र	नामली प्राध्वेट लि.	नारंग हाजस, 34, छत्रपती शिवाजी महाराज बम्बई-400039		 2/80
: मै ्स ्षिः	ोर्मसा गुग^र व र्न्स	ुफाजलभाग विल्डिंग, 45/47 महात्मा गांधी रोड, 👯 सम्बर्ड-400023	1 23	3/75
	तोर्मया केमिकल ट्रीज सिमिटेड,	फाजलभाय बिल्डिंग, 4∜ 47, महात्मा गोधी रोड, बम्बई⊶ 400023	134	19/7-7
ृंफैक्ट्री (श्रम	करवाडी सुगर 'सिमिटेड, 'सकरवाडीट्रेडिंग ती सिमिटेड) हैं	यूसुफ बिल्डिंग, 43, महारमा गांधी रोड, फ़ीर्ट, बम्बई, 23	1 23	4 75
	क्षमी वाडी गु गर लिमिटेड	यथोगरि	1 23	5/75

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 7th July, 1987

S.O. 1999.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of the undertakings mentioned in the Annexure to this notification, the said undertakings being undertakings to which the provisions of Part A Chapter III of the said Act no longer apply.

[No. 16/12/86-M-III] L C. GOYAL, Under Secy.

ANNEXURE TO THE NOTIFICATION NO. 16/12/86-M. III.

S N	l. Name of the lo. Undertakings	Regd. Address	Registra
ļ	2	3	4
l	M/s. Mamii Private Limited.	Narang House, 34, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg	1482/80
2.	M/s. Somaiya Sugar Works Limited	Bombay-400 039. Fazalbhoy Bldg 45/47, Mahatama Gandhi Road,	1233/75
3.	M/s. Somaiya Chemical Industries Limited.	45/47, Mahatama Gandhi Road,	1349/77
4.	M/s. Sakarvadi Sugar Factory Limited (now Sakarvadi Trad- ing Company Limited).	Bombay-400 023. Yusuf Building, 43, Mahatama Gandhi Road, Fort Bombay-23.	1234/75
5	M/s. Lakshmiwadi Sugar Factory Limited.		1235/75

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिम्ली, 22 जुल[ा]ई 1987

का. श्रा. 2000--केन्द्रीय गरकोर को यह प्रतीत होता है कि इसमें उपाबंद अनुमूची में उत्किखित भूमि में कोयला अभिप्राप्य किए जाने की संभावनों हैं, श्रत: केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (ब्रर्जन और विकास) श्रिधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त प्रवित्यों का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के भ्रपने भ्रामय की मूचना देती है।

ं इस अधिसूचना के अधीन आने वाल क्षेत्र के रेखांक स. मी-1 (ई) III/जे जे आर / 388-387, तारीख 5 मार्च, 1987 की निरीक्षण वेस्टर्न कोलफील्डस लि. (राजस्व विभाग) कोल एस्टेट मिबिल लाईन्स नागपुर, 440001 या कलक्टर चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1, काउसिस हाउस स्ट्रीट, कलकरना के कार्यालय में किया जा सकता है।

इम प्रधिसूचनों के प्रधीन पाने वॉली भूमि में हितबब सभी व्यक्ति उक्त प्रधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्यों, जार्टी और प्रन्य दस्तावेंकों को, इस प्रधिसूचनों के प्रकाशन की तारीख से नब्ब दिन के भीतर राजस्व प्रधिकारी वैस्टनें कोलफीन्ड्स लि., कोल एस्टेट, सिधिल लाईन्स, नागपुर -440001 की भेजेंगे।

श्रनुसूची दियुलवाडा ब्लाक वणी क्षेत्र जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

. मंग्राम का नाम	पटवारी सर्किल स .	तहसील जिला	क्षेत्र हैंक्टरो टिप्पणिया म
1 2	3	4 5	6 7
1. माजरी	4	भद्रावती चन्द्रापुर	115.00 भाग .
४ दियूलव िष्टा	4.	भद्राबनी चन्द्रपुर	676.39 भाग
3. कृणाद	28	भद्रावती चन्द्रपुर	165.00 भाग
		योग	953.39 हैंक्टर (लगभग) या ् 2355.92 एकड (लगभग)

मीमा वर्णन

क—ाव—न सेखा बिस्दु ''क'' से श्रारम्भ होती है और ग्राम माजरी और दियलवाडा से होकर जाती है और बिन्टु ''ग'' से मिलती हैं।

ग⊸—घ रेखा, ग्राम विज्ञासन और दियूलवाड़ा की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु ''घ से मिलती है। घ ––इ रेखा ग्राम दियूलवाड़ा और चारगाव, कुणाद और चारगाव की समिम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु ''इ'' मे मिलती है।

🚤 रेखा, ग्राम मुणाद से होकर जाती है और बिन्दु च" से मिलती है।

च--क ृ रेखा, ग्रामा कृणार्द दिय्लवाड़ा, माजरी की बहुँरी सीमा के साथ साथ जाँनी है और श्राँरिभक बिन्दु ''क'' से मिलती है।

[म. 43015 /9 /87 सी.ए.]

MINISTRY OF ENERGY)

(Department of Coal)

New Delhi, the 22nd July, 1987

S.O. 2000 — Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the schedule hereto annexed,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan bearing No. C-1 (E) /III/JJR/388—387 dated the 5th March, 1987, of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440 001 or at the Office of the Collector Chandrapur (Maharashtra) or at the Office of the Coal Controller-1, Council House, Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section -13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440 001 within ninety days from the date of publication of this notification.

SCHE DULE DEULWA DA BLOCK WANI AREA

DISTRICT-CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

Serial Numbe	Name of village er	Patwari Circle Number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	2	3	- 4	5	6	7
1. MA 2. DE 3. KU	ULWADA	4 4 28	Bhadrayati Bhadrayati Bhadrayati	Chandrapur Chandrapur Chandrapur	115.00 673.39 165.00	Part Part Part

Total area 953.39 hectares (approximately), or 2355.92 acreas (Approximately)

Boundary description:

A-B-C... The line starts from point 'A' and passes through villages Majri and Deulwada and meets at Point 'C'.

C-D ... The line passes along the common boundary of villages Vijasan and Deulwada and meets at point 'D'.

D-E ... The line passes along the common boundary of Villages Deulwada and Chargaon, Kunad and Chargaon, and meets at Point 'E'.

E-F .. The line passes through village Kund and meets at point 'F'.

F-A .. The line passes along the outer boundary of villages Kunad, Deulwada, Majri and meets at the starting point 'A'.

[No. 43015/9/87-CA]

नई दिल्ली 24 जुलाई, 1987

पा. था. —2001 केन्द्रीय सरकार ने, कीयला धारक क्षेत्र (ग्रर्जन और विकास (श्रिधिनियम ,1957 (1958 का 20) ही धारा 4 की उपधारा (1) के श्रधीन भारत के राजपत्त, माग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 20 श्रप्रैल, 1985 में प्रकाशित गारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की श्रिधिसूचना सं. का. श्रा. 1674, तारीख 1 श्रप्रैल, 1985 द्वारा उस श्रधिसूचना से संलग्न श्रनुसूची में और इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में भी विनिर्विष्ट परिक्षेत्र में 25551.52 कि (लगभग) या 10340.561 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के श्रपने श्राणय की सूचना की ति। 679 GI/87—6

कौर उक्त भूमि की बाबत उक्त भौधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के भधीन कोई सूचना नहीं थी गई है;

अतं अब, केन्द्रीय सरकार,, उक्तं अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 अप्रैल 1987 से भारम्भ होने बाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिदिष्ट करती है, जिसके भीतर फेन्द्रीय सरकार उक्तं भूमि या ऐसी भूमि पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने आगाय की सूचना दे सवेगी।

भनुसूची यहेराबांध ब्लाक हासवेब क्षेत्र जिला महद्योल (मध्य प्रदेश)

क. सं. ग्राम	पटवा री	समझोता	तहसील	जिला	क्षेत्र हैंक्टर मे	टिप्पणिया	
	हलका सं.	मं. ,					
1 2	3	4	5		6	7	
1. बहराबांध	18	699	कोटमा शह	हडोल इंडोल	894.948	सम्पूर्ण	
2. कोरया	18	, 155	"	11	442.206	13	
3. भाटा हाइ	18	791	17	11	788.321	71	
4. इंगरिया खुर्द	18	397	1)	1)	485,349	2)	
5. भगता	18	769	11	11 -	361,346	भाग सम्पूर्ण	
6. जलस [ा] र	17	350	11	"	550.027		
7. केवटार	17	163	11	11	€00.538	,	
8. चब ईटोला	17	467	"	,	382 111	₹	
9. साजाटोल [ा]	17	973	11	n	666 052	11	
10. थानगांव	19	425	71	1)	1471.304	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
11. कुदरी	19	115	11	t	166.766	1,4	
12. ৰতীলী	19	723	11	17	796 873	<i>,,</i> •	
13. बैनीबहरा	19	751	11	19	461.143	11	
14. बेलगांव	19	755	"	D	553 333	***	
15. लोहमरा	21	929	11	11	80.232	भाग सम्पूर्ण	
16. कनापाग	21	84)1	"	206.110	सपूर्ण -	
17. सोभनाटोला	21	982	11	н	11.107	n	
18. ड्रंगरिया कला	21	398	37	n	625.937	1.9	
19⊷ मैन टोना	21	847	11	31	484 529		
20. मोहरी(उर्फ							
मोहरी [े] खुर्द	21	877	"	•)	312 320-	भाग	
			 कुल या	क्षेत्र	10340 561	हैक्टर (लगभग)	
					25551 52	एकड (लगभग)	

सीमा वर्णन

क- ख रेखा, बिन्दु ''क'' से धारम्भ होती है और केवई नदी के पूर्वी तट के साँध साथ जाता है और कोरया और कोठी ेग्रामो की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु ''ख'' पर मिलती है।

ख---ग रेडा, कोरया, केवटार और बहेरावांध की ग्रामो की उत्तर सीमा के साथ साथ जाती है, तब साजाटोला ग्राम की उत्तर पश्चिमी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्द "ग" पर मिलती है।

ग—घ	्रेखा घबई टोला ग्राम की पूर्वी सीमा और जलसार, बलगांव और बछोली ग्रामों की उत्तरी पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।
प~~ङ	रेखा बङोती ओर थानगांत्र की पूर्वी नीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु ''ङ' पर मिलती है।
हव	रेखा; थानगाव ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ साथ जाती है, तब मोहरी खुर्द और सिगुडी ग्रामो की सम्मिलित भीमा के गाथ साथ जाती है और "बिन्धु" "च" पर मिलती है।
च ন্ত	रिया, मोहरी खुर्द बिजुरी ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है और मौहरी खुर्द, लोहसरा और भगता ग्रामा से होकर जाती है, तब केंनागिरा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "छ" पर
छव	मिलती है । रेखा केनापारा, इंगरिया कला और मैनटोला ग्रामों की दक्षिणी सीमा के साथ साथ जाती है, ंश्रीर भारिंगक
	बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं. 43015 / 1 / 85 सी ए]

New Delhi, the 24th July, 1987

S.O. 2001:—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal) No. S.O. 1674 dated the 1st April, 1985 under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and published in part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 20th April, ,1985 the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in land measuring 25551.52 acres (approximately), or 10340.561 hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule appended thereto as also in the Schedule hereto annexed;

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) 7 of the said Act has been given;

Now therefore in excercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act the Central Government hereby specified a further period of one year commencing from the 20th April, 1987 as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said land or any rights in or over such lands.

SCHEDULE BAHERABANDH BLOCK HASDEÖ AREA

DISTRICT SHADHOL (MADHYA PRADESH)

	ial Village mber	Patwari . Halka Number	Settlement number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Baherabandh	18	699	Kotma	Shahdol	894.948	Full
2.	Koraya	18	155	Kotma	Shahdol	442.206	Full
3.	Bhatadand	18	<i>7</i> 91	Kotma	Shahdol	788.321	Fuil
4.	Dongaria Khurd	18	397	Kotma	Shahdol	485.349	Full
5.	Bhagta	18	769	Kotma	Shahdol	361.34 5	Part
6.	Jalsar	17	350	Kotma	Shahdol	5 50.02 7	Full
7.	Keotar	17	163	Kotma	Shahdol	500,538	Full
8.	Dhabaitola	17	467	Kotma	Shahdol	382.111	Full
9.	Sajatola	17	973	Kotma	Shahdol	666,062	Full
0.	Thangaon	19	425	Kotma	Shahdol	1471.304	Full
11.	Kudri	19	115	Kotma	Shahdol	166.766	Full
12.	Bachhauli	19	723	Kotma	Shahdol	7 96.873	Full
3,	Bonibahara	19	751	Kotma	Shahdo!	461,143	Full
4.	Bělgaon	19	755	Kotma	Shahdol	553.333	Full

1			2		3	
15. Lohsara	21	929	Kotma	Shahdol	80.232	Part
16. Kenapara	21	84	Kotma	Shahdol	206.110	Full
17. Sobhnatola	21	982	Kotma	Shahdol	111,107	Full
18. Dongaria-Kala	21	398	Kotma	Shahdol	625.937	Full
19. Maintola	21	847	Kotma	Shahdol	484.529	Full
20. Mahuwari Alies Mahauwari Khurd	20	87 7	Kotma	Shahdol	312,320	Part

Total areas: 10340.561 hectares (approximately), or 25551.52 acres (approximately).

BOUNDARY DESCRIPTION: ---

- A-B Line starts from point 'A' and passes along the eastern bank of river Kewai and meets on the common boundary of villages Koraya and Kothi at Point 'B'.
- B-C Line passes along the northern boundary of villages Korya, Keotar and Baherabandh, then proceeds along the north-western boundary of village Sajatola and meets at point 'C'.
- C-D Line passes along the eastern boundary of village Dhabaitola and north-eastern boundary of villages Jalsar, Belgaon and Bachhauli and meets at points 'D'.
- D-E Line passes along the eastern boundary of villages Bachhauli and Thangaon and meets at point 'E'.
- E—F Line passes along the southern boundary of village Thangaon, then proceeds along the common boundary of villages Mahuwari Khurd and Sigudi and meets at point 'F'.
- F-G Line passes along the common boundary of villages Mahuwari Khurd, Bijuri, proceeds through villages Mahuwar Khurd, Lohsara and Bhagra, then along the eastern boundary of village Kenapara and meets at point 'G'
- G-A Line passes along the southern boundary villages Kenapara, Dongaria Kala and Maintola and meets at the starting point 'A'.

[No. 43015/1/85-CA]

े का.भा. 2002 .--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है किं इससे उपावस धनुसची में उल्लिखित भिम में कीयला अभिप्राप्त किए काने की संभावना है.

धतः केन्द्रीय सरकार, कोयलाधारक कोछ (धर्जन और विकास) धिधनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुँग, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के ध्रपने धाशय की सूचना देती है;

इस प्रधिसूचना के प्रधीन भाने वाले क्षेत्र में रेखांक का निरीक्षण साउध ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (राजस्वधनुभाग) सीपत रोड, बिलासपुर-495001 के कार्यालय में या कलक्टर, सूबरगढ़ (उड़ीसा) के कार्यालय में प्रथवा कोयला नियंत्रक, 1-काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकरता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस प्रशिवसूचना के प्रधीन प्राने वाली मूमि में हिन्बक सभी व्यक्ति उक्त प्रधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्विष्ट सभी नक्णों, चाटों बीर प्रन्य वस्तावेजों का, इस अधिमूसूना के राजपत में प्रकाशन की तारीख़ से नक्वे दिन के भीतर, सहागक संपदा प्रवंधक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ब्स लि., सीपत रोड, विलासपुर, को भेजेंगे।

श्चनुमूची गोपालगुर एक्सटेन्शन ब्लाक झाई बी बैंकी कोलफील्ड जिला सुन्दराह, (उड़ीसा)

रेखांक सं.एस.ई.सी.एल./बीएसपी/ जी.एस. (परियोजना)/5 दिनांक 10 जनवरी, 1987 (पूर्वेक्षण के लिए प्रधिमुक्ति भूमि)

थ ि. स	ो. मीजा बन्ध ग्राम संख्	क्षेक्षएक क टिप्पणि में						
1	2		3	4	5	6	7	
1.	1. दिक्तिली पारा		हे मगिरी	सुन्ध रगढ़		1743.85	पूर्ण	
2.	सिया रमल	17	हेमगिरी	3	नुन्द रगढ़	862,34	·पूर्ण	
3.	गोपालपुर	19	हेमगिरी	₹	न्द <i>रग</i> ढ़	140.67	भाग	
	. त्र्भृतिया		हेमिगरी	3	पुस्य रग <i>क</i>	2381.32	पूर्ण	
	करलीकछर		हेमरिरो	;	मुन्द रगङ्	511.94	पूर्ण	

1	2	3	4	5 .	6	7
в.	 कुलकडा	77	हेमगिरी	मुन्दरंगह	542 82	पूर्ण
7.	ब कीयहल	78	हेमगिरो	सुन्द रगढ़	836.33	पूर्ण
8	बॉनगः ,	79	हेमशिरी	सुन्द रसक्	1234.64	पूर्ण
9.	गर्जनबहुष	89	हेमगिगी	सुन्द रहाद	798.35	पूर्ण
10.	व गरदेला	90	हेमगिरी	सुन्दरगढ्	1055 96	पूर्ण
11.	किरिशीसरा	91	हेमगिरी	सुन्द रगढ़	1681 11	पूर्ण
12.	जपती जंगल			-	420 00	

कुल क्षेत्र 12209 33 एकड़ (लगमग)

या

4941.05 हेक्ट्रेयर (लगभग)

सीमा वर्णन.

ट-ट1-ट-2-ट-3 रेखा "ट" जिन्दु के आरंभ रे होती है, जो जाम झुपुहरेगा, तुमुलिया, उपतीजंगल का एक जिसगम बिन्दु है, और शाम तुमुलिया की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जासी है और बिन्दु "ट-3" पर मिलती है।

ट-3-ट-4-ट-5 रेखा, ग्राम बगस्केला की दक्षिणी सीमा के माय-साथ जाती है और बिन्दु "ट-5" पर मिलती है।

ट-5,ट-6,ट-7- ृरेखा भागत ग्राम किरिपसिर। की पिष्यमी सीमा के ट-8, ट-9, ट-10 स.ब-म.च भागतः विक्षणी पुर्वी और उस्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ट-10" पर मिलती है।

ट-10-ट-11-ट-12 रेखा गर्जनबहुल और बालिगा ग्रामी की पूर्वी सीमा के साथ-माथ जाती है और बिन्दू "ट-12" पर मिलती है।

 ट 12 ट-13 रेखा बॉलगा, बलीबहल, टिकिलीपारा ग्रामों की उत्तरी

 ट-14, ट-15,
 सीमी के साथ-साथ गाती है और बिन्दु "ट-16" पर

 ट-16
 भिलती है ।

ट-16-ग-ख रेखा सरदेगा ग्राम की उस्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है ग्रीर बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख-क-द-य-त-ण रेखा सप्देगा ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है और नाले की उत्तरी सीमा के साथ-साथ गोपालपुरैं ग्राम के बीच में से गुजरती **है भौ**र बिन्दू ''ग'' पर मिलती है ।

ण-इ-ड रेखा गोपालपुर ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है भीर नालें की दक्षिणी सीमा के साथ उसी ग्राम से होंकर जाती है भीर बिल्दु "ड" पर मिलती

इन्ड-ट रेखा सियारमल, तुमुलिया ग्रामो की पश्चिमी सीमा के साथ आती है भीर "ट" के ध्वारधिक विकास पर मिलती है।

> [मं. 43015/10/87-सी.ए.] समय सिंह, प्रवर सचिव

SO 2002:—WHEREAS it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

NOW. THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Beating Areas (Acquisition and Development) Act. 1957 (20 of 1957), the Central Covernment hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the area covered by this notification can be inspected at the office of the South Fastern Coalfields Limited (Revenue Section). Seenst Road, Bilaspur-495001 or at the office of the Collector, Sundargarh (Orissa) or at the office of the Coal Controller. 1, Council House Street Calcutta, All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to insub-section (7) of section 13 of the sold Act to the Assistant Estate Manager. South Fistern Coalfields Limited. Seepat Road, Bilaspur within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Jazette.

THE SCHEDULE

GOPALPUR EXTENSION BLOCK IB VALLEY COALFIELD DISTRICT SUNDARGARH (ORISSA)

Pha No SECU/33P 3M (PROD)/5

Dated 10th January, 1987

(showing land notified for prospecting)

il. No.	Name of village	Sottlement Number	Tahsil'
1.	Tikilipaga	15	Hemgiri .
2	Siarma1	17	Hemgiri
3.	Gopalour	19	Hemgiri
4.	Tumulia	75	Hemgiri
5.	Karlikachhar	. 76	Hemgiri
б.	Kulada	77	Hemgiri
7.	Bankibabal	78	Hemgiri
8.	Baling a	79	Hemgiri
9.	Garjanbahal	89	Hemziri
0.	Bangurukela	90	Hemghi
1.	Kitipsira	91	Hemgici
Ž.	Japtijangal		

District	Area in acres	Remarks
Sundarg írh	1743 85	Full
Sun largarh	862.34	Full
Sundarg 17h	140 67	Part
Sundargarh	2381.32	Full
Sundargarh	511.94	Full
Sundargerh	542.82	Fall
Sundargarb	836.33	Full
Sundargarh	1234.64	Full
Sundargarlı	798.35	Full
Sundargarh	1055.96	Full
Sundargath	1681,11	Full
	420 00	

Total: 12209.33 acres (approximately), or 4941 05 hectares (approximately)

Boundary Description

K-K1-K2 Line starts from point 'K' which is a trijuncK3. tion point of Villages Jhupurunga,
Tumulia, Japtijangle and passes long
the Southern boundary of Village
Tumulia and meets at point "K3".

K3-K4-K5. Line passes along southern boundary of Village Bangurukela and meets at point "K5".

	•	स्वास्थ्य और परिवार क्रस्याण मंद्रालय
K5-K6-K7 K8-K9-K10.	Line passes partly along the western boundary, partly along south eastern and northern boundary of Village Kiripsira and meets at point "K10".	(स्वास्त्र्य विभाग) नई दिल्ली, 30 जून, 1987 का.श्रा. 2003 — देग्त चिकित्सक ग्रधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के उपखण्ड (क) के ग्रनुसरण
K10-K11-K12.	Line passes along the eastern boundary of Villages Gaijanbahal and Balinga and meets at point "K12".	में डा. के. गोबिन्दन नायर, मंगलया, करूमाना, स्निवेंद्रम, को केरल राज्य दन्तचिकिसकों के भाग "क" में रजिस्ट्रीकृत
K12-K13-K14- K15-K16.	Line passes along the northern boundary of Villages Balinga, Bankibahal, Tikilipara and meets at point "K16".	दन्त चिकित्सको द्वारा 25 फरवरी, 1987 से डा. बाला- कृष्णन नायर के स्थान पर भारतीय दन्त चिकित्सक परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया गया है;
K16-C-B	Line passes along the northern boundary of Village Sardega and meets at point "B".	श्रतः उक्त श्रिधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 के खण्ड (क) के श्रानुसरण में
B-A-R O-P-O.	Line passes along the western boundary of Village Sardega and proceeds through Village Gopalpur along the northern boundary of nallah and meets at point "O".	केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की श्रिधिमूचना मं. का.था. 430 तारीख · 24 जनवरी, 1984 में निम्नलिखित संगोधन करती है, श्रर्थातु:
O-N-M-	Line passes along the western boundary of Village Gopalput and proceeds through the same village along the southern boundary of nallah and meets at point "M".	उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के पपन्तुक के साथ पठित खण्ड (क) के झन्तर्गत निर्वाचित " शीर्ष के झधीन फम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान
M-L-K.	Line passes along the western boundary of Villages Slarmal, Tumulia and meets at the starting point "K".	पर निम्मलिखित रखा जायेगा, धर्थात्ः— "10. डा. के. गौविन्दन निर्वाचित केरल 25-2-82 नायर दन्तचिकित्सक परिषद्
	[No. 43015/10/87—CA] SAMAY SINGH, Under Seev.	[संख्या वी. 12013/1/87-पी.एस.] जी.जी.के. नायर, श्रवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health) New Delhi, 30th June, 1987

S.O. 2003 —Whereas in pursuance of clause (a) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), Dr. K. Govindan Nair, Mangalya, Karamana, Trivandrum has been elected to be a member of the Dental Council of India by the Dentists registered on Part 'A' of the Kerala State Dentists with effect from the 25th February, 1987, Vice Dr. K. Balakrishnan Nair;

Now, therefore, in pursuance of clause (a) of section 3 read with sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, No. S.O. 430 dated the 24th January, 1984 namely:—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (a) read with the proviso to section 3", for serial number 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"10. Dr. K. Govindan Nair Elected Kerala 25-2-1987".

Dental Council

> [No.V. 12013/1/87-PMS] G. G. K. NAIR, Under Secy.

शहरी विकास मंत्रालय नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1987

का.श्रा. 2004: केन्द्रीय सरकार शारा के राजपत्न, विनांक 13 मार्च, 1976 (का.मा. 1053) का श्रधसूचना का भागत. उपातर करते हुए और सरकारी स्थान (अप्राधि-कृत श्रिधभागियों की वेदंखली) श्रिधिनयम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 हारा प्रवस्त समितयों का प्रयोग करते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित श्रिधकारी को सरकार के राजपन्नित श्रिधकारियों की पंक्ति के समसुख्य श्रीधकारी होने के नाते, उक्त श्रीधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पद्मा श्रीधकारी नियुक्त करती है और यह भी निदेश देती है कि उक्त श्रीधकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिधिक्ट सरकारी स्थानों के संबंध में श्रपनी श्रीधकारिता की स्थानी सीमाओं के भीतर उक्ष श्रीधिनियम के द्वारा या उसके श्रीधित सम्पद्मा श्रीधकारी को प्रदत्त णिक्तमों को प्रयोग और श्रीधरोपित कर्तव्यों का पार्लन करेगा।

सा रणी

ग्रधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और प्रधिकारिताकी स्थानीय सीमाएं
1	2
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, (लेटर प्रंस यूनिट), मिन्टो रोड, नई दिल्ली	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली स्थित प्रबन्धक भारत सरबार मृद्रणालय (लेटर प्रैस यूनिट) मिन्टो रोड, नई दिल्ली, के प्राणासनिक नियंद्रणा- धीन सरकारी स्थान, जिनमें भूमि और भवन भी सम्मिलित है।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, 7th July, 1987

S.O. 2004:—In partial modification of notification dated the 28th February, 1976 (S.O. 1053) published in the Gazette of India, dated the 13th March, 1976 and in exercise of the powers coferred by section 3 of the Public Premises Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below being an officer equivalent to the rank of Gazetted Officers of the Government to be Estate Officer for the purposes of the said Act and further directs that the said officer shall exerise the powers confered and perform the duties imposed, on Estate Officers, by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said table.

THE TABLE

Designation of the officer	Categories of publicfpremises and local limits of jurisdiction		
1	2		
Manager, Government of India Press (Letter-Press Unit), Minto Road, New Delhi.	Public premises including Land and Buildings under the administrative control of the Manager Government of India Press (Letter Press Unit), Minto Road, New Delhi, situated in the Union Terroitory of Delhi.		
·—	[F. No. 70 (2)/86—A 5] NATTHU SINGH, Under Secy.		

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गीस मंत्रालय

नई दिल्ली 29 जलाई, 1987

का. मा. 2005 :—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का प्रजैन) प्रधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3, उपधारा (1) के प्रधीन बारत नरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मलालय की प्रधिसूचना का. मा. स. 582 तारीख 17-6-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस प्रधिसूचना से संलग्न प्रनुसूची में विनिर्दिय्ट भूमियों के उपयोग केन्द्राधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए धर्जित करने का धपना धामय घोषित कर विया था।

और यत: सक्षय प्राधिकारी ने उनत प्रियनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रधीन सपकार की रिपोर्ट दें दी है।

[फाइल सं. 70(2)/86-ए-5] नत्थु सिंह, भवर सचिव

और ग्रागे यत . केन्द्रीय सरकार ने उकन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस ग्रधिसूचना से संलग्न ग्रनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों मे उपयोग का ग्राधिकार ग्राजिस करने का विनिश्चय किया है।

भव ग्रात: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) ब्रारा प्रवक्त सिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतव्द्रारा धीषित करती है कि इस मधिसुबना में संख्तन श्रनुसूची त्रिनिविच्ट उक्त भूमियों में उपयोग का मधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एत४ द्वारा श्रीजत किया जाता है।

और भागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देशी है कि उक्स भूमियों से उपसेश का भाविकार केन्द्रीय यरकार में निष्टित हीने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रवाशन की इस तारीख को निष्टित होगा।

पूरकबाद सूची एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	चक न	पुराना न.	क्षत्रफल एक्क्ट्रम
1	2	3	4	5	6	7
इटाषा	औरेपा	औरेपा	खजुहा	146	1/3 मि. 29/1 मि. 29/2 मि.	1-35
				150	28 मि.	0-02
						

2590	THE GAZETTE OF INDIA: A	AUGÚST 8.	1987/SRAVANA 17, 1909	PART II-SEC. 3(ii)
٥٧٥	, the order is of more . I	rocor o,	1367/320171112 17, 1363	[TAKT IL-SEC. 5(N)]

1	2	3	4	. 5	6	7
				280	28 मि.	0-22
				222	27 मि.	0-59
					31 मि.	
					30 मि.	
				चकरोड	27 मि.	0-03
					39 मि.	
					32 मि.	0-03
				240	27 मि.	0-10
				307	27 मि,	0-37
				4.	39 मि,	٠
					39 मि.	
				अकरोब	39 मि.	0-03
				326	३ ७ मि .	0 - -03
				3 40	३ ७ मि. 38 मि.	0-50
				66	41/2 मि.	0.05
				0.0	41/2 मि. 42 मि.	0-75
					43 年.	
				बा ग	41/2 मि.	0-15
				80	43 मि.	0-03
					44 मि.	
				213	4.4 मि.	0-01
				रास्ता	280 मि.	0-12
				217	240 मि.	0-15
					230 मि.	
				42	230 मि.	0-12
					,	4- 63
	औरेपा	औरेपा	खजुहा	चकरोड	230 मि.	0-02
इटावा			•	28	230 मि.	10-00
				3	231 मि.	0-10
				चकरोड	230 मि.	0-02
					239 मि.	
				121	229 मि.	0-93
					228	
				286	223 मि.	1-05
					226/2 मि	
				पकरोड	225 मि.	0-02
				4.41.410	226/2 मि	0-02
				~- -	226/2 (म 225 मि.	A 8.2
				नासी		0-02
					217 मि.	
				83	225 मि.	0-01
				245	217 मि.	0-85
					226/2 मि	
				रास्ता	216 मि.	0-07
				9 5	213 मि.	0-90
					210 मि.	`
					211 मि.	
					212 मि.	
				चकरोध	178 मि.	0-03
				161	178 मि.	0-03
				283	178 मि.	
					177/2 मि	0:50

_ 7	6	5	4	3	2	1
1-27	177/1 मि.	179				
	177/2 मि					
	176/1 मि.					
0 <u>~</u> 22	176/2 मि.	115				
6-74						
0-18	173/3 मि.	रास्ता				
0-37	17 2 /2 मि.					
0-07	160	नोला .				
11-99	37					
)/84—अभी. पी. j	[#. O-14016/430					

MINISTRY OF PETROLEUM AND N.G.

New Delhi, the 29th July, 1987

S.O. 2005.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and N.G. S.O. 582 dated 17-6-87 under sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 6, of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE
H.B.J. GAS PIPE LINE PROJECT

District	Tahsil	Pargana	Village	Chak No.	Old No.	Area in Acre
1	2	3	4	5	6	7
Etawah	Auraiya	Auraiya	Khajuha	146	1/3M 29/1M 29/2 M	1–35
				150	28M	002
				280	28M	0-22
				222	27M	0–59
					31M	• •••
					30M	
				Chakrod	27.M	003
					39M	
					32M	003
				240	27M	010
				307	27M	0-37
				•	39M	
				Chakrod	39M	0-03
				326	39M	0-56
					38M	
				66	41/2M	0-75
					42M	
					43M	

2503	١
J. J. Y	,

1	2	3	4	5	6	7
	Bagh				41/2M	0-15
				80	43M	
					44M	
				213	44M	0-01
				Rasta	280M	0-12
				217	240M	0–15
				40	230 M	0.40
				42	230M	0-12
						4–63
Etawah	Auraiya	Auraiya	Khajuha	Chakrod	230M	30-00
	•			28	230M	00-00
				3	231M	0-10
				Chakrod	230M	002
					231 M	
				121	229M	093
					228M	
				286	223M	1-05
					226/2M	
				Chakrod	225M	0-02
					226M	
				Nali	225M	002
					217M	
				83	225M	0-01
				245	217M	0–55
					226M	0.05
				Rasta	216 M	007
				95	213M	0-09
					210M	
					211M	
				Chales d	212M	0.02
				Chakrod	178M	0-03
				161 283	178M	0-03
				203	178M	0-50
					177/2M 179M	0-50
				179	175M 171/1 M	1-27
				177	177/2M	1-21
					176/1M	
				- 115	176/2M	0-22
						6-74
Etawah	Auraiya	Auraiya	Khajuha	Rasta	173/2M	0-18
	,	,	y		172/2 M	0-37
				Nali	160	0-07
			· 		37	11-99

[No. O-14016/430/84 GP]

का. मा. सं. 2006:—ं-यतः रेट्रोलियन और खनिज पाइय लाइन (सूमि में उपयोग के मधिकार का मर्जन) मधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के भ्रधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक में मंजालय की भ्रधिसूचना का. मा. सं. 583 तारीख 17-6-87 द्वारा कंदीम सरकार ते उस मधिसूचना के संज्ञान प्रनुसूची में विनिदिस्ट भूमियों के उपयोग के मधिकार को पाइप लाइमों को विछाने के लिए मजिल करने का भ्रमना बाहाय घोषित ूँ कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधकारी ने उक्तं प्रधिनियम की घारा 6 की उपन्नारा (1) के प्रधीन सरकार को रिपोर्ट वे दी है।

और प्राप्ते यत: केश्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चाल इस मधिसचना से संस्थन मनसची में विनिर्दिश्ट मुनियों में उपयोग के मधिकार भजित करने का विनिध्यय किया है।

भ्रव ग्रत : उक्त अधिनियम की आरा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त वक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सुरकार एतव्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संस्थान अनुसूची में विनिधिष्ट उक्त मूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपसाइन विकान के प्रयोजन के लिए एतव्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और मार्ग उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश वेती है कि उक्त भूमियों में उपयोगका मिक्षिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के वजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रक्राशन की इस तारीख को निहित होगा।

पूरकवाव सूची एच. बी. के. गैस पाइप लाइन शोजेक्ट

मभपव	तहसील	परगना	भाग	पकर्न, ————————————————————————————————————	पुराना नं.	क्षेत्रफल एकड्
1	2	3	4	5	6	7
टावा	भीरेया	औरया	पीपरपुर	_	4	0-0
					5	0-1
					6	00
					3	0-2
				<u>*</u>	26/2	0—:
				नाली	29/1	0
				19	29/2	1-
					30	
					31/1	
					31/2	
					33 मि.	
				443	33 मि.	0
				चकरोड	33 मि.	0-
				नाली	34 मि.	0-
					1	0-
					35	0-
				217	34/1 मि.	0-
					34/2 मि,	
					34/3 fम	
				114	34/3 मि	0-
				83	34/3 मि.	0-
				रास्ता	34/3 मि.	Û,
				387	40 मि.	0-
					41 मि.	
				389	41 मि.	0-
				चकरोड	41 मि.	0-
				रास्ता	.42 मि.	o-
					24	0-
				295	51/2/1 मि.	0-
					51/1 मि.	
				284	51/1 मि.	0-
				332	50/2	0-
				नाली	93 मि.	0-
					94	0-
				290	93/1 मि.	1-
				381	93/1 मि.	0
					93/3 मि.	
					624/93	
				नासी	93/2 मि.	0
				22	84 मि.	0-
					624/93	
				71	84 मि.	0-
					624/3 मि.	
				नासी	84 मि.	0-
					83/1	0-

1	2	3	4	5	6	7
					83/2	0-20
					81	0-18
				-	85/1	0-20
					85/2	0-0 G
				रास्ता	73	0-10
				11	187 मि	0-60
				108	187 मि.	0-15
				43	187 मि	0-22
					186 मि	
				220	186 मि.	0-02
				चकरोड	187 मि.	0-10
					189/1 मि.	
					188 मि.	
				417	187 मि.	0~15
					188 मि.	
					189/1 मि.	
				चकरोड	189/1	0-02
				253	189/1 मि.	0-75
					189/2 मि.	0 70
					189/3 मि.	
					196/1 मि,	
					196/2 मि.	
					196/3 मि.	
				385	196/1 पि!	0-56
					196/2 मिं.	0-30
					196/3 मि.	
				यस्ता	197मि.	0-04
					198/1 मि.	0-09
				173	236 मि.	0-55
				नासी	236 मि	0-02
				127	236 मि.	0-05
				रास्ता	235 मि.	0-03
				278	235 मि	0-25
				231	235 सि.	0-10
				240	235 मि.	0-10
				पकरोड	235 मि.	0-15
				88	237 मि.	0-04
					235 मि.	0-04
				258	235 मि,	0-10
					237 मि.	0.10
				364	237 मि.	1-80
					235 मि.	1-60
					267	0-04
					266	0-12
				سيننه	268/1	0-12
					268/2	1-30
				=-	269	0-12
					271	0-12
					272	0-56 0-50
					157	
					13/	n_n 4
					10/	0-04

वोड.--स्तम्भ 5 में / ~1 विष्ह दर्शाये गणे है वह वकवाहर समझा आये।

S.O. 2006.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and N.G., S.O. 583 dated 17-6-87 under sub-section (1) of Section 3 of the retroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Villäge	Chak No.	Old No.	Area in acre
1	2	3	4	5	6	7
Etwah	Auraiya	Auraiya	Piparpur		4	0-08
	·	-			5	0-12
					6	006
					3	0-25
				_	28/2	0-58
				Nali	29/1	0-03
				19	29/2	1-10
					30	
					31/1	
					31/2	
					33 M	
				443	33 M	0-12
				Chakrod	33 M	0-02
				Nali	34 M	0-02
					1	0-30
					35	0-02
				217	34/1 M	0–27
					34/2 M	
					34/3 M	
				114	34/3 M	0-26
				83	34/3 M	001
				Rasta	34/3 M	0-03
				387	40 M	0-25
					41 M	
				389	41 M	0-28
				Chakrod	41 M	001
				Rasta	42 M	· 003
				_	24	0-02
				295	51/2/1 M	0-68
					51/1 M	
				284	51/1 M	0-12
				332	50/2 M	0-65
				Nali	93 M	0-03
					94	0-02
				290	93/1 M	108
				381	93/1 M	0-75
					93/3 M	
					624/93	
				Nali	93/2 M	0-02
				22	84 M	0-15
					624/93	•

[PART	II-SEC.	36	(ii)

Etwah	Auraiya	Auraiya	Piparpur (Contd.)	71 Nali — — Rasta 11 108 43	84 M 624/3 M 84 M 83/1 83/2 81 85/1 85/2 73 187 M 187 M 187 M 186 M	0-15 0-02 0-02 0-20 0-18 0-20 0-06 0-10 0-60 0-15 0-22
			(Contd.)	Rasta 11 108 43	84 M 83/1 83/2 81 85/1 85/2 73 187 M 187 M 187 M 186 M	0-02 0-20 0-18 0-20 0-06 0-10 0-60 0-15 0-22
				Rasta 11 108 43	83/1 83/2 81 85/1 85/2 73 187 M 187 M 187 M 186 M	0-02 0-20 0-18 0-20 0-06 0-10 0-60 0-15 0-22
				11 108 43 220	83/2 81 85/1 85/2 73 187 M 187 M 187 M 186 M	0-20 0-18 0-20 0-06 0-10 0-60 0-15 0-22
				11 108 43 220	81 85/1 85/2 73 187 M 187 M 187 M 186 M	0-18 0-20 0-06 0-10 0-60 0-15 0-22
				11 108 43 220	85/1 85/2 73 187 M 187 M 187 M 186 M	0-20 0-06 0-10 0-60 0-15 0-22
				11 108 43 220	85/2 73 187 M 187 M 187 M 186 M	0-06 0-10 0-60 0-15 0-22
				11 108 43 220	73 187 M 187 M 187 M 186 M	0-10 0-60 0-15 0-22
				11 108 43 220	187 M 187 M 187 M 186 M	0-60 0-15 0-22
				108 43 220	187 M 187 M 186 M	0-15 0-22
				43 220	187 M 186 M	0–22
				220	186 M	
					186 M	
						0-02
				Chakrod	187 M	0-10
					189/1 M	
					188 M	
				417	187 M	015
					188 M	
					189/1 M	
				Chakrod	189/1	0-02
				253	189/1 M	0-75
					18 9/2 M	
					189/3 M	
					196/1 M	
					196/2M	
					196/3 M	
				385	196/1 M	0-56
					196/2M	0 20
					196/3 M	
				Rasta	197 M	0-04
					198/1 M	000
				173	236 M	0~55
				Nali	236 M	0-02
				127	236 M	0-05
				Rasta	235 M	0-03
				278	235 M	0-25
				231	235 M	0-18
				240	235 M	0-10
				Chakrod	235 M	0–15
				88	237 M	0-04
					235 M	
				258	235 M	0-10
					237 M	
				364	237 M	1-80
					235 M	- 77
					267	0-04
					266	0–12
				-	268/1	0-06
					268/2	1-30
					269	0~12
					271	0~55
					272	0-50
					157	0-30 0- 04
				68		16–92

का. घर. 2007--- पतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के मधिकार का मर्जन) मिधिनियम, 1982 (1962 का 50) की धारा 3 की उपमारा (1) के भिद्यान भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मिधिनुजना का.मा.सं. 584 तारीख 17-6-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ते उस श्रीभूचना में संलग्न मनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों के उपयोग के श्रीभकार को पाइप लाइनों को विछाने के पीलए मिनित करने का मपना माशय चौषित कर दिया था।

'और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त भ्रमिनियम की भारा 6 की उपघारा (1) के भ्रमीन सरकार को रिपोर्ट वे दी है।

और भ्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस प्रधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार भ्रजित करने का विनिध्चय किया है।

सब सतः उक्त सिक्षितियम की धारा 6 की उपसारा (1) द्वारा प्रदेश शक्तिका प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतव्हारा भौकित करती है कि इस सिक्षित्वना में संलग्न सनुसूची विनिदिष्ट उक्त मूमियों में उपयोग का सिकार पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एतव्हारा सर्जित-किया जाता है।

और भागे उस बारा की उपबार। (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश वेती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का मिलकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाबाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख कौ निहित होगा।

वाद सूची एक, बी. जें. गैस पाइप लाइन प्रोजेश्ट

निपद	तहसील	परगना	प्राम	पक ग.	पाद सं.	क्षेत्रफल (एकड में
1	2	3	4 ,	5	6	7
टावा	भौरेया	ओरैया	लहोखर		15 मि.	0-40
					16 मि.	Q-95
				~~	60 年.	0-08
				चकरोड	16 मि ,	0-02
				127	16 मि.	0-10
				चकरोड़	59 मि .	0-02
				199	59 मि .	Q45
					5 5 मि .	
				. 292	55 मि .	.0-30
				20	55 मि .	0-40
					56 मि	
				पकरोड़	55 मि.	0-02
					56 मि .	
				49	55 मि . ,	0-02
					54 मि.	
				217	53 मि.	0~20
					54 मि .	
					56 मि .	
				181	53 मि.	0-35
					56 मि.	
					5 2/ 1	0-07
					52/2/1	0-43
				33	26 मि.	0 20
					5 2/2/2 मि .	
				352	4ु9ं/2 मि .	0-15
				चस्ता	40 मि	0-01
				नासी	39 मि.	0-25
				160	38/2 मि .	0- 22
				16	38/2 मि .	0-20
				106	30/2 मि.	0 – 53
					29 मि.	0-42
				यकरोड़	33 मि.	0-08
				,	30 मि .	0, 00
				54	33 मि.	0-03
				318	30 मि.	0-03 0-17
				नाली	243	0-03
				असर	179/2	0-03
				नामी	174 मि.	0-01 [′]

1	2	3 1	4	5	6	7
হাৰা	ओरैंगा	ओरैमा	ल होवा र	249	174/मि.	0- 50
					175 मि.	
				•	173 मि.	
				246	173 मि.	0-07
				ऊस र	193 मि .े	0-08
				कस र	194 मि.	0-10
					196 मि .	0-68
				नानी	199 जि.	0-02
				•8	199 मि .	0-40
				ऊसर	201 मि.	0-53
				सङ्क	295 मि.	0-12
				ऊसर	315/1/1	0-50
			-	315/1/2	0-03	
			369	316	0-01	
			नाली	317	0-03	
			वंजर	320/6/1/6	0-12	
				नाली	320/6/1	0-03
				~~	320/6/2	0-13
					320/1/1	0-30
				P	320/3/1	0-25
				384	320/4/1	0-27
					320/4/2	
				390	320/2	0-30
				नाली	320/6/5	0-03
				न ह र	312 मि.	0-12
				नाली	311/4/4	0-03
					311/4/1	0-05
					311/5/1	0-22
					311/6/1	0-33
					311/7/1	0-33
				-	311/8	0-33
					311/9	0-03
				60		18-84

नोट:-स्तम्म 5 मे दर्शाए गए "ऊसर ये। डेम"को चक बाहर समझा जाए।

[मं. O-14016/321/84-जी.पी.]

S.O. 2007.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and N.G. S.O. 584 dated 17-6-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Covernment hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	€hak No.	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6	7
Etawah	Auraiya	Auraiya	Lahokhar		15 M 16 M	0-40 0-95
					60 M	0-08
				Chakrod	16 M	0-02

1	2	3	4	5	6	7	
Etawah	Auraiya	Auraiya	Lahokhar	127	16 M	0-10	
				Chakrod	59 M	002	
				1 9 9	59 M	0-45	
					55 M		
				292	55 M	0-30	
				70	55 M	0-40	
				, •	56 M		
				Chakrod	55 M	0-02	
				CHARLOG	56 M	5 72	
				49	55 M	00-02	
				72	54 M	00-02	
				217		0-20	
				217	53 M	0-20	
					54 M		
					56 M		
				181	53 M	0-35	
					56 M		
				-	52/1	0-07	
					52/2/1	0-43	
				33	26 M	0-20	
					52/2/2		
				352	49/2	0-15	
				Rasta	40 M	0-01	
				Nah	39 M	0-25	
				160	38/2 M	0-22	
				16	38/2 M	0-20	
				106	38/2 M	0-53	
					29 M	0-42	
				Chakrod	33 M	008	
				344	30 M	J J J	
				54	33 M	0-03	
				318	30 M	0-17	
				Nali	243	0-03	
				Usher	179/2	0-03	
				Nalı	174	0-07 0-01	
				249	174 M	0-50	
				247		0-20	
					175 M 173 M		
				24		0.05	
				246	173 M	0- 07	
				Ushar	193 M	0-08	
				Ushar	194 M	0–10	
					196 M	0-68	
				Nali	199 M	0-02	
				8	199 M	0–40	
				Ushar	201 M	0-53	
				Road	295 M	0-12	
				Ushar	315/1/1	0-50	
					315/1/2	0-03	
				369	316	0-01	
				Nalı	317	0-03	
				Banjar	320/6/1/6	0-12	
				Nalı	320/6/1	0-03	
					320/6/2	0-03	
					320/1/1	0-30 ·	
					320/3/1	0-30	
					1734/17/4	U = 7)	

1	2	3	4	5	6	7
				384	320/4/1	0-27
					329/4/2	
				390	320/2	0-30
				Nali	320/6/5	0-03
				Nahar	212 M	0-12
				Nali	311/1/4	0-03
					311/4/1	0-05
					311/1/1	0-22
					311/5/1	0-33
				-	3.1/1/1	0-33
				~ —	311/8	0-33
				مبين	311/9	001
				60	به چه نیسیونی په په په په نیان نیان نیان نیان نیان نیان نیان نیا	18-84

Note: -It is understood that "Ushar and Dish" showm under Col. 5 out of Chak

[No. O-14016/32I/84-GP]

का. मा. 2008---यतः केन्द्रीय संरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह बावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच.बी.जे. तक पेट्रोलियम परिवहम के लिए पाइपसाइन बारतीय पैस प्राधिकरण सि. द्वारा विछाई जानी चाहिए।

और यत. प्रतीत होता है कि ऐसी साइनों को विकान का प्रयोजन के सिए एतुद्रपावत अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का प्रविकार प्रजित करना आवश्यक है।

म्रन. मन पेट्रोलियम और व्यतिष पाइपमाईन (भूमि में उपयोग मधिकार का मर्जन) मधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा श्रवल शाँक्तयों का प्रयोग करते क्षुप्र केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का स्रविकार मंजित करने का म्रपना मान्नय एतव्हारा घोषित किया है।

बसर्ते कि उक्त भूमि में हितबढ़ कोई व्यक्ति उस मूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि विकासवीप बिल्बिय, 22, स्टेलन रोड, लखनऊ-226019 यू.पी. को इस ग्राधिसूचना की तारीख ने 21 बिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह बाहता है कि उसकी भुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विचि व्यवसायी के मार्फत ।

धनुषूरक बाद धनुसूची एक.बी.जे. गैंस पाइप लाइन प्रोप्तेस्ट

विवरण	क्षेत्रफल	गाटा सं०	प्राम	परगमा	तहसील	वनपद
7	6	5 ,	4	3	2	1
	0-08	169	कैयाना	वि धूना	तिधूना	(टावा
	0-03	296				
	0-04	1130				
	0-07	1129				
	0-08	1051				
	0-10	298				
-						
	70-40	6				

सिं.O-14018/03/84-जी पी

S.O. 2008.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H. B. J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government

hereby declares its intention to acquire the right of use therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the layur of the pipeline ander the land to the Competen Authority, Gas Authority of India Ltd., H. B. J. Pipelin Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow 226019 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person by legal practioner.

Supplementry Case (Schedule) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Keaiwa	169	0-08
				296	003
				1130	0-04
				1129	0-07
				1051	0 08
				298	0-10
				6	0-40

INo. O-14016/03/84-GP7

का. ग्रा. 2009.---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सोकहित में यह भावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच.बी.जे. तक वेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा विछाई जानी चाहिए।

भीर यतः प्रतीत होता है कि ऐसी साइनों को विछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध मनुसूची में विणत भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना मावश्यक है।

. भतः भन पेट्रोलियम भौर सानिज पाटपलाईन (भूमि में उपयोग श्रविकार का भर्जन) भविनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का श्रविकार प्रक्रित करने का अपना प्राक्षय एतद्वारा पोषित किया है।

अपार्त कि उक्त भूमि में हिसबद कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सलम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकारण कि. बिकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ 226019 यू.पी. को इस बिधसुचना की सारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

धौर ऐसा भाखोप करने वाला हर व्यक्ति विविदिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो सर किसी ृविधि व्यवसागी की मार्फत ।

धनुषुरक बाद धनुषुषी एष. बी. जे. मैस पाइप लाइन प्रोजेन्ट

						Λ.
श्रु तपद	तहसील	परवना	प्राम	गाटा सं .	मेवफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	स्रीरैया	भौरैया	\$ परी	508	0-10	
			-	1098	0-03	
				2	013	

[ff. O-14016/647/84-3f] की]

S.O. 2009.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H.B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India I td.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government

hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Aethority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project. Vikas Deep Building. 22. Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4 .	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Kainjrı	508 1098	0-d0 0-03
				2	0-13
				127- 0	1401 C/C47/07 C D

[No. O. 14016/647/87-G.P.

का. आ 2010--- यतः केखीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह भाषश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एवं वी. जे तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. हारा विछाई जानी चाहिए।

भीर यत प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतपुनाबद्ध धनुसूची में विशेष भूमि में उपयोग का प्रक्रिकार मंजित करन। भागवस्यक है।

भत. यस पेट्रोसियम और सनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग भ्रधिकार का भर्जन) मर्शिनियम, 1962 (1962 का 50) की घारा 3 की उपघारा (1) द्वारा प्रदल समित्रयो का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का श्रीकार मजित करने का थपना भावय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बत्तरों कि उक्त भूमि मैं हितबंद कोई व्यक्ति उन भूमि के नीचे पाइप लाइन मिछाने के लिए झालेप नजन प्राधिकारी, भारतीय नैन प्राधिकरण नि विकासवीप बिल्डिंग, 22, स्टेकन रोड, लखनऊ 226018 यू.ची. को इस मिस्चिना की सारीच से 21 दिन के भीतर कर सकेना।

भीर ऐसा भाक्षेप करने वालां हर स्पन्ति विनिविस्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उनकी सुनवाई स्पक्तिगत रूप से हाँ या किसी विधि स्पनसायी के मार्फत ।

षशुपूरक बाध प्रमुखूषी एव.बी.से. गैस पाइप साइन प्रोजेन्ट

क्षनपव	तहसील	पराना	न्नाम	गाटा तं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3 .	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	विधुना	लखनो	870	0-23	

[सं O-14016/02/85--- जी पी]

S.O. 2010.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H. B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by aub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government

hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent As thority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Lakhno	870	0-23
				[NoC	D-14016/02/85-G.P.]

का. आ. 2011---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह झावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एक की जे. तक पेट्रोलियः के परिवहन के लिए वाइपलाइन भारतीय गैंस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

ग्रीर यसः प्रमीत होता है कि ऐसी लाइमीं को बिछाने का प्रमौजन के लिए एतद्यावश्च शनुसूची में बंगिस भवि में उपयोग का स्रविकार धर्मकत करन खादास्यक है। भत श्रव पंद्रोलियम ग्रीर विनिज पाष्ट्रपलाईन (भूमि में उपयोग ग्रीधकार का भजन) श्रीधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तिया या प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार न उस में उपयोग का ग्रीधकार श्रीनित करने का श्रयना श्रावय एनद्द्वारा घोषित किया है।

बरातें कि उक्त मूमि में हितबद कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप'लाइन विछाने के लिए ब्रासेप मक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि विकासदीप बिल्डिंग, 12.2, स्टेशन रोड, लक्षमऊ 22.6019 यूपी को इस अधिसुचना की लारीख में 2.1 दिन के भीतर कर मकेगा।

भीर ऐसा भाक्षेप करने वासा हर व्यक्ति विसिद्धिटन यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहुना है कि उसका सुनगर्ध व्यक्तिगन रूप से हा या किसी विधि व्यवसायी की मार्फन ।

भनुपूरक बाद भनुसूची एच बी जें गैस पाइप लाइन प्रोजश्ट

अ नपद	तहसील	परंगना	ग्राम	गाटा स	क्षेत्रफन	विवरण
1	2	3	4	3	6	7
इटाका	 मीरिया	श्रीरैया	<u>-</u> नौसी	50	0-20	

				1	0-20	•
						

[म O-14016/424/84~जी.पी]

SO 2011—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from IIB to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government

hereby declares its intention to acquire_the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd II. B. J Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U P

And every person making such an objection shall also tate specifically whether he wishes o to heard in person or by legal practitioner

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Naulı	50	0-20
				1	0-20

[No O. 14016/429/84-G.P.]

का भा 2012 ---यत केरबीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह भावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एवं की जे तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाडपुलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत प्रतीस होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने का प्रयोजन के लिए एसद्पाबद्ध ग्रेनुसूची में बर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रजित करना सावस्यक है।

मत भवं पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि मे उपयोग मिधकार का भ्रजीन) श्राधानयम 1962 (1962का 50) की घारा 3 की उपघारा (1) द्वारा प्रदेश नासियों का प्रयोग करने हुए केस्त्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार सर्जित करने का भ्रपना भागत एनदुवारा घोषित किया है।

बागर्ते कि उस्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस (भूमि के नार्च पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधियारा भारतीय गैंग प्राधियारण सि बिकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लावनऊ-226019 मू पी को इस प्रधिसूचना की तारीख से 21 विन के भीतर कर सकेगा।

भीर ऐसा स्राक्षेप करने वालः हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन क[ु]गा कि क्या वह चाहमा है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्प्टेतः

भन्पूरक वाद भनुसूची एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजक्ट

জিলা	तहसील	परगना	मीना	भ भाषा सं.	;	क्षेत्रफ ल
1	2	3	4	5	6	7
टाबा	औरया	न िरंगः	लखनापुर	140	्रिमि. । 6 मि.	0-29
				431	(1 年, 6 年, 1 年 2 年, 4 年,	0-36
				68	{2 म. 3 मि. 4 मि.	0-20
				89	ि3 सि. }4 मि. }12 मि.	0-44
				132	2 म. 3 मि. 4 मि. 7 3 मि. 12 मि. 13 मि. 13 मि. 14 मि. 15 मि.	e~ 2 2
				204	(14 मि 15 मि. 16 मि. 17 मि. 18 मि.	0~ 3 5
				105	े 18 मि. [*] ∫ 18 मि - े 19 मि.	0– 1 i
				-	1 97	

[d O-14016/322/84-31.41.]

S.O. 2012.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H.B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided that any person interested in the said land may, with n 21 day, from the date of this notification object to the laying of the pipeline unit; the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also stare specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	¥ 3	4	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Lakhnapur	140 (1 M (6 M	0-29
	·			431	0-36
				$ \begin{array}{c} 68 & \begin{cases} 2 \text{ M} \\ 3 \text{ M} \\ 4 \text{ M} \end{cases} $	0-20

बाग 11वा 3(11)]		मास्त्रका सम्बद्ध	- MAKE 8' TREVIAL			
1	2	3	. 4	5	6	7
				89	{3 M 4 M 12M 13 M	0-44
				122	12 M 13 M 14 M 15 M	022
				204	14 M 15 M 16 M 17 M 18 M	035
				105	{ 18 M 19 M	0-11
				7		1-97

[No. O-14016/322/84-G.P.]

का आ: 2013--यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह जावण्यक है कि उत्तर प्रदेश में एव.भी जे सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइस भारतीय गैस प्राधिकरण लिए हारा विखाई जानी काहिए।

और यतः प्रतीत होना है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एउदुपाँचयः अनुसूची में वर्षित सूमि में उपयोग का निवकार श्रीवित करना आवश्यक है।

अत. अस पेट्रोलियम और खानिज पाइपलाईन (मूमि में उपयोग अधिकार का अर्थन) मिलियम 1962 (1962 का 50) की बारा उकी अपद्यारा (1) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार भजिन करने का अपना मालय एतव्हारा योगित किया है।

बगतें कि उसते भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाडप लाइन विछाने के लिए झाओप सलम प्राधिकारी, भारतीय गैत प्राधिरकरण सि. विसामधीप बिहिडग, 32, स्टेशन रोड, लखनक-226019 यू.पी. को इस अधिसूचना की नारीय से 31 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा बाक्षेत्र करने जाला हर व्यक्ति जिलिबिक्कतः यह भी कवन करेगा कि क्या वह काहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिमल कर के हो भा किसी विक्रि व्यवसाधी के मार्फतः

क्षमध्यक बाव समृद्यी एक . बी. के. गैस पाडप लाईन गोजैनट

- जनपद	तहसील	परगता	श्राम	पाटा से.	क्षेत्रफल	विवरण
इटाबा	विद्युना	विष्मा	नगवस्तपु र	182	0-03	
			·- 	- 		

[सं. मो-14016/392/84-जी,पी]

S.O. 2013.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H.B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the

Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the bying of the pipeline unfer the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 UP.

And every person making such an objection shall also tate specifically whether he wishes to be heard in person to by legal practite, ter

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE) H.B.J. GAS PIPE LINE PROJECT

District	Tahsıl ·	Pargana	Village	Plot No.	Area in acr	es
1	2	3	4	5	6	7
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Bhagwantpur	182	0-03	

[No. O-14016/392/84/G.P.]

का मा. 2014 → प्यक्ष केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित से यह भावश्यक है कि उत्तर प्रवेश में एव की जे. तक पैट्रोलियम के परि-वहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि द्वारा विखाई जानी चाहिए।

भीर मन प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने का प्रयोजन के लिए एनदुपाबद प्रनुस्थी में वर्णित भूमि में उपयोग का प्रधिकार सर्जित करना प्रावश्यक है।

श्रत सब पेट्रोलियम और खिनिज पोडपलाईन (मृमि मे उपयोग मिक्तार का सर्जन) अधिनियम, 1962 (1962का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवस बक्तियों को प्रयो्ग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस मे उपयोग का ग्रिधकार प्रजित करने का अपना आवाय एतद्द्वारा योथिन किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप आइन बिछाने के लिए घाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय पैस प्राधिकरण लि विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनज-226019 मृं पी को इस घिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिधिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मृतवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि अपवसायी के मार्फत।

श्रनपूरक बाद सनुसूची एव की जी गैस पाइपसाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगंशा	र् ग्राम	ेगाटी म	क्षेत्रफल	विव रण
1	2	3	4	5	6	7
	→	विद्यूमा	· नवादा वाद्	53	0-23	
चंदावा	1.12.11	, , , , , ,		49/4	0-29	
				44/1	005	
				44/2	0-02	
				44/3	0-02	
				41/1	0-10	
				41/2	0-08	
				81/1	0-05	
				39	0-34	
				83	0-14	
				426/2	0-13	
				462/3	007	
				186	0-17	
				47	0-04	
				42	0-06	
				54	0-05	
				187	0-07	
				188	0-03	
				423	0-02	
				511/2	6- 07	
				511/3	0-05	
				8 5 / 1	0 ⊶0 5	
				504/2	0-17	
				23	2-31	

. 679 GI/87-9

SO 70%—-Whereas appears to the Const Comments of a senecessary in the other interess Ω the the transport of Petrolium form FLB to I in Uting Place a state Pipeture should be laid , the Gr. Authory of India Ltd.

And v hereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the.

and Act, 1962 (30 of 1962), the Control Government and y declared the ment to act me the right of user that an

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land by the Competent Authority, Gas Authority of India I td. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building 22, Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also serte specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana ·	Village ·	Plot No.	. Area in acres
1	2	3	4	5	6 ^
Etawah	Bidhvna	Bidhuna	Nawada Dado	53.	0-22
				49/4	0-29
				44/1	0-05
				44/2	0-02
				44/3	0-02
				41/1	0–10
				41/2	008
				$-\frac{41/2}{81/1}$	0-05
				39	0-34
				39 83	0-14
				426/2	0–13
				4 62/3	0-07
				186	0-17
				47	0-04
				42	0-06
				54	0-05
				187	0-07
				188	0-05
				423	0-02
				511/2	0-07
				511/3	005
				85/1	0–05
				504/2	0–17
				23	2–31
				INO	O-14016/389/84-G

[No. O-14016/389/84-G.P.

का. आ. 2015 — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह श्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच.बी.जे.तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा विछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाब्रक अप्रनुसूची में वर्णित भूमि में. उपयोग का अधिकार अजित करना ग्रावश्यक है।

काः ग्रब पेट्रालियम और खिनिज पाइपलाईन (भूमि मे उपयोग प्रिविकार का श्रजेंन) ग्रिधि,नियम, 1962 (1962 का 50) का धारा उ का उपवारा (1) द्वारा प्रदेत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का ग्रिधिकार ग्रजित करने का ग्रपना ग्राशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्तों कि उद्भत भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीवे पाइप लाइन विछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि. विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-३26019 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा भ्राक्षेप करने बाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फेंद्र।

धन्पूरक बाद धन् सूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजैन्ड

वसपद	तहसील	परगमा	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफक्ष	
3	2	3	. 4	5	6 .	
ब्रहाबा	विश्वना	विधून।	प्रसीपुर	342	0-10	
4 -1 11			ū	344	0-06	
				346	0-10	
				352	0~08	
						•
				4	0-34	

शि. ओ-14016/398/84-जी.पी.]

S.O. 2015.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H.B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the

Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 UP

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person of by legal practitioner.

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Alipur	342	0–10
			•	344	0-06
				345	0-10
				352	0–08
				4	0-34

[No. 14016/398/84-G.P.]

का द्या. 2016 ~--यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह घाषण्यक है कि उत्तर प्रदेश में एक जी जे तक पेट्रोलियम के परिवहत के लिए पाइपलाइन मारतीय गैंस प्राधिकरण सि. द्वारा विछाई जैमी चाहिए।

और यत प्रतीत होना है कि ऐसी लाइनो को बिछाने का प्रयोजन के जिए एतहुपाबद प्रमुख्यों में वर्णित सूमि में उपयोग का प्रधिकार प्रजित करना प्रावश्यक है

मत मब पेट्रोलियम और कानिक पाइपलाईन (भूमि मे उपयोग भविकारका मर्जन) मिश्रिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रकत धक्तियों को प्रयोग करते हुए केखीय सरकार ने उस मे उपयोग का मिश्रिकार फ्राजित करने का भपना भागय एसव्दाण भोषित किया हैंई

बन्नतें कि उक्त भूमि में हिनबढ़ कोई व्यक्ति उस भूमि के तीजे पाइप लाइस बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राप्तिकारी, भारतीय गैस प्राप्तिकरण जि. विकासकीय विश्विम, 22, स्टेनन रोड, लखनऊ-226019 यू पी. को इस प्रश्निसुचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेया।

बौर ऐसा घाक्रोप करने वाला हर व्यक्ति निर्निष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह काहता है कि उसकी सुमवाई व्यक्तियत रूप में हो या किसी विधि व्यक्तायों के नार्फत।

धन्पूरक बाद धन्सूची

एच. बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेस्ट

जनपद	तहसील	परगना	प्राम	षाटा नं.	क्षेत्रफल	
1 ,	2	3	4	5	6	
इंटावा	विघूना	विधूना	वहादुरपुर तहार			
				52	0-09	
				54	0-05	
				58	0-10	
				71	0-10	
				92	0-06	
				97	0-02	
				98	0 0 2	
					- بهرستان بورستان به ساوه کا ساوه که بود به بود به روستان استان استان استان استان استان استان استان استان استان	
				7	0-44	

[स. मो-14016/399/84-जी.पी.]

S.O. 2016.—Whereas it appears to the Central Governthat it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H B to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land)

Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLEMENTRY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Bahadur Pur Sahar	52	0-09
				54	005
				58	0-10
				71	010
				92	0-06
				97	002
				98	0-02
				7	0-44

[No. O-14016/399/84-G.P.]

का. हा. 2017 ---यतः केन्द्रीय धरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह भावश्यक है कि उत्तर प्रवेश में एव थी.जे. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा विछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद प्रतृसूत्री में वर्णित भूमि में उपयोग का प्रशिक र मॉजित करना सावश्यक है।

म्रातः सब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (मूमि में उपयोग प्रक्षिकार का मर्जन) मिर्धिनियम, 1962 (1962 का 50) की घारा 3 की उपवारा (1) द्वारा श्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय संस्कार ने उसमें उपयोग का मिर्फिन मर्जित करने का भवना भागय एतबुद्धारा मोवित किया है।

क्शतों कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के भीचे पाइप लाइन विछाने के लिए छाओप 'सम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण खि. विद्यासदीय विस्तित, 22, स्टेमन रीज, मंचनक-226019 यू.पी. को इस प्रधिसूचना की तारीच से 21 विष के मीतर कर सकेता। भीर ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत. यह भी कथन करना कि क्या पह चाहता है कि उनकी कुनवाई व्यक्तिगत रूप साक्षा पाकिसा विधि व्यवसायों के मार्फत।

सनुपूरक बाव प्रनुयूची एच बी .जे. गैस पाइएकार प्राजनट

जनपद	सहसील	परगना	ग्राम	गारु ५.	त्र हिन्	
1	2	3	4	5	6	
इटावा	बिधूना	बिधूमा	चादा	1 3	0 - 11	
				15	0-11	
				14	- O~v }	
				G	€ C=0	
				5	7~0 ₹	
					بالداميميرجر فالمحص يراعدها جمعي مدسونيتات	
				5	0 -3 1	
				سي ني نيسان هنده معاليي ويوانيس	عرموم فرويون مراجع	

[4. st-14016/393/84-31.41.]

S.O. 2017.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H. B. to J. in Uttar Pladesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whoreas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquition of Right of User in the Land)

Act, 1962 (50 or 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. II. B. J. Pipeline Project, vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such as objection small also state specifically whether he we has to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLEMENTRY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Arca in a	acius
1	2	3	4	5 ,	6	7
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Chando.	13	0-04	·· -
				13	0-11	
				14	0-03	
				8	0-09	
				5	0-04	
				5	0-31	•

INo. O-14016/393/84-3.P.]

का.चा. 2018. -- यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रनीत होता है कि लोकहित में यह धावण्यक है कि उत्तर प्रदश्न में एच वी ज तक पैद्रोलियम के परिवहन के लिम पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि ब्रारा बिछाई कानी वाहिए।

भीर यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने का प्रयोजन के लिये एनद्गा अड श्रनुल्की में वर्णित भूमि ने उपयोग का धाधकार अजित करना भावस्थक है।

श्वत' श्रव पैट्रोलियम और खर्निज पाइपलाईन (भृमि में उपयोग श्रांधकार का आपन) श्रांभिनियम, 1962 (1962 का 50) का बादा 3 को उपबाद (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का श्राधकार श्रांजित करने का अपना खाशाय एनद्द्वारा घोषित किया है।

बमार्ते कि उसके मूमि में हितबढ़ कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन विकान के लिये खादीप सक्षम प्रशिवकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण जि., विकासदीप बिल्बिंग, 22, स्टेंगन रोड, लखनऊ-226019 यू.पी. को क्रा पश्चिम्यना की गारीख के 21 दिन के शीवर कर सकेगा।

और ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि नेया यह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप, से हो या 14ना विधि स्पवसायी के मार्फत ।

भनुपूरक बाव भनुसूची

एस जी जे गैस पाइप लाईन प्रोत्रैक्ट

—— ज नपद	- तहसी ा	 पश्गना	ग्राम	गढि। स	भं त फल	·
	2		4	, 5	6	
		विष्ध		622	0-15	
สเพา	1ुब्य-त	(a) 2 (1)		720	0-36	
				722	007	
				590	0-10	
				614	0-18	
				591	0-14	
				587	0-12	
				800	0-03	
				799	0-01	
				798	0-02	
				725	0+22	
				726	0-03	
				721	0-05	
				681	€ O ~ O	
				14	1 61	

[म. ओ-14016/390/84-ओ.पी.]

SO .013 - V. creas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from If B to J in Utter Pradesh State Pipeline should be loid by the Gas Authority of India Ltd.

And wherea it appears that for the purpose of laying such pureline, it is necessary to acquire the right of user to the land described in the schedule annexed hereto

Now therefore, in exercise of the nowers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Fetroleum and Mineral Physhines (Acquition of Right of User in the land)

Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Lid H B J Pipiline Project, Vilas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 DP.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SUPFLEMENTRY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. Gas Pipe Line Project 3

Districe	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1		3	4	5	6
Efawah —	Bidhana	Bidhuna'	Usraha	622	0-15
Litawan	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			720	0-36
				722	7 - 07
				590)-10
				614)-18
				591)-14 '
				587	J - 12
				800	0-03
				7 99	0-01
				798	0-02
				725	0-22
				72 6	0-03
				721	0-05
				881	003
				14	1-51

का.भा.सं. — 2019 यत: केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह धायम्यक है कि अत्तर प्रदेश में एव,बी,जे. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पार्षपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा विधाई जानी चाहिये।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी साईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिये एसद्याबद्ध प्रनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का प्रशिकार प्रजित करना प्रावस्थक है।

यत यन पैट्रोसियम और व्यक्तिक पाईपलाईन (भूमि में उपयोग प्रधिकार का वर्जन) प्रधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त कक्तियों का प्रमोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें प्रयोग का प्रधिकार प्रजित करने का प्रपना प्राक्तय एतदुद्वारा घोषित किया है।

बलतें कि उक्त भूमि में हितकब कोई व्यक्ति उस मूभि के नीचे पाईपलाईन विछाने के लिये घाडोप सक्तम प्राधिकारी, भाइतीय गैस प्राधिकरण क्षि. विकासदीप विलिया, 22, स्टेशन रोड. अवनऊ-226019 यू.पी. को इस अधिसूसूना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

ं और ऐसा बाक्षेत्र करने वाला हर व्यक्ति विनिधिष्टतः यह भी कथन करेना कि नया व ह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत कप से हो या विश्वी विश्वि व्यवसायी के मार्थत ।

धनुषुरक बाव इनुसूची एच, बी.जै. गैस पाईप साईन प्रोजैन्ट

वानपंद	तहसील	परगना	' ग्रास	गारा सं.	क्रमफल	विवरण
1	2	3	4	5	в	7
द्यावा	बिद्दना	विधूना	घरमगवापुर	428	0-32	
•	÷			438	0-03	
				461	0-05	
				1150	0-03	
				1151	80-0	
				1198	0-22	
				1199	0-30	
				1199	0-10	
				1260/6	0-09	
				434	0-15	
				447	0-12	
				1148	0-03	
				1208	0-03	
]
				13	1-55	-

[स॰ ओ-14016/01/85-जी.पी.]

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquition of Right of User in the Land)

Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22 Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLIMENTARY CASE (SCHDULE)

I.B.J. Gas Pipe Line Project

District	. Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	1
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Dharmangad			
			-Pur	428	0-32	
				438	003	
				461	005	
				1150	0-03	
				1151	0-08	
				1198	0-22	

S.O. 2019.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the trensport of Petroleum from H. B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

2	3	4	5	6
			1199	0-30
			1199	0-10
			1260/6	009
			434	0-15
			447	0-12
			1148	0-03
			1208	0-03
			13	1–55

[No. O-14016/01/85-G.P.]

ंका.भा.सं. 2020---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह भावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एव.बी.जे. तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन भारतीय नैस प्राधिकरण लि. हारा विछाई जानी भाहिये।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिये एतद्पाबड प्रनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रजित करना प्रावश्यक है।

भतः सब पढ़ोलियम और खनिज-पाईपलाईन (मूमि में उपयोग संधिकार का सर्जन) सधिनियम, 1962 तु (1962 का 50) की धारा उकी छपधारा (1) द्वारा प्रवक्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें प्रयोग का संधिकार स्वित करने का सपना सासय एतव्हारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि मैं द्वितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. विकासदीप, बिल्बिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019, यू.पी. को इस मिक्षसूचना की तारीख से 21 दिन भीतर कर सकेंग़।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिधिष्टता: यह भी कथन करेगा कि नया वह चाहता कि असकी सुमवाई व्यक्तिगत कप से ही या किसी विधि व्यवसासायी के मार्फतः

सनुपूरक बाद सनुसूची एक बी.जे.गैस पाईपलाईन प्रोजैस्ट

जनप द	तहसील	प रगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवर्ण
1	2	3	4	5	в	7
हरावा इटावा	विद्युश	विस्ना	म बोख मील	710	0-07	
	-	•		719	0~0 L	
				776	0-35	
				774/9	0-05	
				774/7	0-01	
				774/8	0-02	
				767/5	0-31	
				768	0-08	
				764	0-03.	
				765	0-02	
				715	0~ 04	
				755	0~03	
				12	1-02	

S.O. 2020.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petrolaum from H. B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas A theriv of India 1.d.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land)

Act, 1962 (50 of 1962), the Court for the Trice decrees 5 min in to adquire the ingline we are

Provided that any person interested in the said land ray, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in region or by legal practitions:

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	'ļot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Marokh meet	710)_07
				719	0-01
				776	0-35
				774/9	0-05
				774/7	0-01
				774/8	0-02
				767/5	0-31
				7 68	008
				764	0-03
				765	0-02
				715	0-04
				755	0-03
				12	1-02

[No. O-14016/396/84-G.P.]

का. आ. 2021--अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच.बी.जे. तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

भीर यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनो को बिछाने का प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध ग्रनमची में वर्णित मिम में उपयोग का ग्रिधिकार ग्राजित करना आवश्यक है।

ग्रत: ग्रब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूम म उपयाग आधकार का भजन) ग्राधानयम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसे में उपयोग का ग्रिधकार ग्राजित करने का अपना आशेय एतद्द्रारा घोणित किया है।

बमतें कि उक्त भूमि में हितबढ़ कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेमन रोड, लखनऊ-226019, यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

भीर ऐसा श्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत ।

एच.बी.जे. गैस पाईप लाईन प्रोजैक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ँ ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	,3	4	5	6	7 .
इटावा ³	बिधु ना	विधुना	हरवंश पृर	452	0-22	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1997
	•	•		437	0-17	
				70	0-04	
				50	0-13	
				43	0-07	

						The state of the s
1	2	3	4	Ĩ	Ú	7
					,	
				35	0-10	
				24	0-27	
				439	0- 05	
				94	0~ 08	
				9	1-13	
				· · -		

[सं. ओ-14016/394/84-ओ.पी]

S.O. 2021.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H. B to J in Uttar Pradesh Sta e Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Itd

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule appeared hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land)

Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H B. I. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U P

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SUPPLEMENTRY CASE (SCHEDULF)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No	Area in acres
1	2	3	. 4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Harbanshpur	452	0-22
			437	0-17	
				70	0-04
				50	0–13
				43	007
				35	0–10
				24	0–27
				439	0-05
				94	. 0-08
				9	1 13

[No O-14016/394/84-G.P.]

का का स 2022—यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मंथह भागम्यक है कि उत्तर प्रदेण सं एच वी में तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को विष्णाने का प्रयोजन के लिये एतदपाश्रद्ध ग्रनुसची में वर्णित भूमि में उपयोग का ग्राधिकार अजित करना भावश्यक है।

प्रत **भव पैट्रो**लियम और खानिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग प्रिधिकार का अर्जन) श्रीक्षतियम, 1962 (1962 को 50) की धारा ४ की उपधारा (1) द्वारा प्रदान भक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का श्रीधकार ग्रीजित करने का श्रयना भ्रीशय एतबुद्वारा शोधित किया है।

बंशर्त कि उक्त भूमि म हितबद कोई व्यक्ति उस भूमि के तीचे पाईपलाईन बिछान के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण वि विकासकीप विलिया, 22 स्टेणन शेड, लखनक-226019, यू पी को इस ग्रिथिमुचना की तारीम्ब से 21 दिन ने भीतर कर सकेगा।

ार ऐसा आक्षेप करने केला तर स्पेक्त विनिधिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह बाहता है कि उसकी सनवाई ध्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि ध्यवसायों ने मार्फन ।

धनुपूरक वाद धनुसूची एच.धी.जे. गैस पाईप लाईन प्रोजैक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा में.	क्षेत्रफल	वि ब रण _,
1	2	3	4	5	6	7
इटावा े_	औरैया	औरैया	मेहुद	72	0-08	
			251	0-60		
			252	0-75		
			219	0-01		
			227	0-01		
			225	0-05		
			205	0-04		
				172	0-05	
				122	0-27	
				119	0-14	
				165	0-20	
				176	0-18	
				228	0-06	
				73	0-06	
				74	0-16	
				15	2-66	4

[सं. ओ-14016/327/84-ओ.पी |

S.O. 2022.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H R. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed here or

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the I and)

Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22. Station Road, Lucknow-226019 U.F.

And every person making such an objection shall also i state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE)

H.P.J. GAS PIPE LINE PROJECT

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	. 6,
Etawah	Auraiya	Auraiya	Sehud		0-08
				251	060
				252	0-75
				219	0-01
				227	001
				225	0-05
				205	004
				172	005
				122	0–27
				119	0-14
				165	0-20
				1 7 6	018
				228	0-06
				73	006
				74	0-16
				15	2–66

का.मा. 2023.—पतः केस्त्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह मावस्यक है कि उत्तर प्रदेश में एव.बी.जे. तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा विछाई जानी चाहिये।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनो को बिछाने का प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वॉणत सूमि में उपयोग का भश्रिकार प्रजित करना भावश्यक है।

ंग्रतः ग्रबं पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग श्रिकार का श्रर्जन) श्रीधनियम, 1962 (1962 के, 50') की धारा 3 की उपधार (1) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का ग्रिधकार ग्रिजित करने का अपना श्रामय एतद्हारा घोषित किया है

अमर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के भीचे पाईय लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. विकासदीप, बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019 यू.पी. को इस प्रधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा भाक्षेष करने ब्राला हर व्यक्ति विविधिंष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या बहु वाहलाँ है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यक्सायी के मार्फत।

श्चनुपूरक बाद अनुसूची एच.बी.जे. गैस पाईपलाईन प्रोजैस्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	भैवफ ल	विवरण
. 1	2	· 3	4	5 5	6	7
€टावा .	 औरैया	 औरैया	दौलतपुर	728	0-02	
			-	727	0-02	
				703	0-18	
				702	0-23	
				701	0-38	
				700	0-58	
				695	0-05	
				651	0-05	
				1056	0-06	
				1057	0-12	
				1035	0-05	
				1074	0-01	
				210	9-0-9	
				217	0-10	
				215	0-16	
				735	0-06	
				729	0-14	
				718	0-18	
				667	0→10	
				624	0-04	
				623	0~16	
				621	0-07	
				1012	0-10	
				1027	0-18	
				1028	0-16	
				1038	0-11	
				1055	0-04	
				1031	0-04	
				1037	0-06	
				1069	0 0 5	
				1073	0-09	
				1111	0-07	
				32	3- 75	

S.O. 2023.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum tem H. B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be said by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquissition of Right of User in the Land)

Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of india Ltd H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 UP

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULŁ)

H.B.J. GAS PIPE LINE PROJECT

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
l	2	3	4	5	6
Ftawah	Auraiya	Auraiya	Daulatpur	728	0 -02
Ltawan			_ 	727	0-02
				703	0 –18
				702	0-23
				701	0-38
				700	0-58
				695	0-05
				651	0- 0 5
				1056	0-06
				1057	0-12
				1035	0-05
				1074	001
				210	009
				217	0-10
				215	0–16
				7 35	006
				729	0–14
				718	0–18
				667	0–10
				624	004
				623	0-16
				621	0-07
				1012	010
				1 02 7	0-18
				1028	0–16
				1038	0-11
				1055	004
				1031	0-04
				1037	0-06
				1069	0-05
				1073	0-09
				1111	0-07
				32	3-75

का का 2024---मत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि कोकहिए में यह ग्रायम्पक है कि उत्तर प्रवेश में हंत्रीरा-दरेंनी-जगदीशपुर तक पेंट्रो-लियम के परिवहन के लिए पाइप नाइन मोरदीय गैस प्राधिकरण नि हारा विकाई जाती वाहिए।

भीर यह भ्रमीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछान का प्रयोजन के लिए एतदुपाइट भ्रमुमूची म वर्णित भौम म उपयाग का प्रधिकार भीतन करना भावत्यक है।

यत अस पैद्रोलियम और खिनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के मधिकार का मर्जन) अधिनियम 1962 (1962का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त गक्तियो, का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में उस मे उपयोग का अधिकार ग्रंजित करने का प्रपना ग्राधवण्यतद्वारः घोषित किया है।

बबार्ने कि उक्त भूमि में हितबब कोई स्थित उन मृति व भीजे पाइप लाइन किछाने के लिए प्राक्षेप महाम प्राधिकारी आर्शिय गैस प्राधिकरण स्थि एवं वी जे परियोजना लखनऊ 22602 1 मूं पी का इस अधिसूचन। वी तारीख ने 21 दिन ये भीतर वण्य सकेंगा।

भीर ऐसा भ्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिद्धित यह भी कथन करना कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनवाई क्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि क्यक्तार्था की मार्फत।

भनुपूरक संशोधित प्रस्ताव एक, बी जे गैस पाइप साइन प्रोजेक्ट

ভিলা	नहसील	परगना	ज्ञाम 	गाटा सं -	भेज्रफल 	विशृरण
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(5
तनपुर देशाल	- भक्षर पूर	चन यर पूर	अक्तेष्ठपु र रोगना ई	848	2 0 5	
•	-	_	-	852	0-1-0	
				9.78	0→18→0	
				889	2-1-0	
				881	0-15-0	
				887	0-3-10	
				964	0-4-0	
				965	0-5-15	
				886	0-1-5	
				899	U- I- U	
				888	0-2-0	
				890	0-1-0	
				891	0-2-0	
				992	0-1-0	
				893	0-2-5	
				8 98	0-1-0	
				899	0-1-0	
				900	0-2-0	
				905	0 0 1	
				906	0-1-15	
				907	0-1-15	
				911	1-3-0	
				908	0→ 5- _h 0	
				913	0-1-10	
				914	0-0-10	
				915	1-13-0	
				9] 4	0-16-05	
				918	0-0-5	
				922	0 0 10	
				923	0-0-10	
				912	0-0-2	
				933	0 0-3	
				927	1-12-5	
				928	0 6 0	
				929	0-6-10	
				822	0-3-10	
				818	0−8− 0	
				962	0 y u	
				861	0-9-0	

(1) -	(2)	(3)	(4)		(6) (6)	()
कारमुर रैहात	म कदरपु र	सक्त ा पुर	फतेहपुर रोशनाई	817	1+6-0	
-	ŭ	*	-	816	0-2-10	
				813	2-1-0	
				814	0-2-0	
				684	0-1-0	
				729	0-3-0	
				690	0-3-10	
				689	0-6-10	
				688	0-9-10	
				687	0-12-0	
				686	10 سے 10	
				685	0-0-3	
				695	0-0-2	
				692	0-1-0	
				694	1-4-10	
				682	0-0-15	
				681	0-0-15	
				557	0-0-15	
				558	1-5-0	
				552	03-0	
				556	0-2-10	
				559	1-10-0	
				560	0-17-10	
				561	0-0-5	
				551	0-1-0	
				550	0 1 9 0	
				485	0-9-10	
				56 <i>7</i>	0-0-10	
				566	0-0-10	
				578	1→14→10	
				577	0-0-5	
				5 75	0-G-0	
				576	1-3-0	
				571	1-14-0	
				572	1-2-0	
				416	0-5-0	
				418	0-0-5	
				417	0-5-0	
				419	0-4-0	
				404	1-4-0	
				48	1-1-5	
				47	0-14-10	
				49 46	0-1-0	
				50	0-1-0 0-8-0	
				44	2-0-15	
				4.5	0-8-0	
				3 3 3	0-2-10	
				334	0-4-02	
				335 342	0-2-10 0-13-0	
				343	0- 13- 0 0- 0- 10	
				344	70-10-0	
				341	0 2 1 0	
				340	0-0-15	
				345	0-1-0	

S.O. 2024.—Whereas it appears to the Contral Government that it is necessary in the public interest that for the turns port of Petroleum from Hajira Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land describe 1 in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land)

Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, One Authority of India I td H. B J Pipeline Project. Lucknow-226021 U P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal gractitioner.

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. GAS PIPE LINE PROJECT

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Bigha
1 .	2	3	4	- 5	6
Kanpur Dehat	Akbarpur	Akbarpur	Fatchpur	5 848	2-0-5
•	•	•	Roshnai	852	0-1-0
				878	0–18–0
				380	2–1-0
				381	0-15-0
				887	0~3–10
				964	0-4-0
				965	0-5-15
				886	0-1-5
				889	0-1-0
				888	0-2-0
				890	0-1-0
				891	0-2-0
				892	7-1-0
				893)-2-5
				8 9 8)-1-0
				899)10
				900)-2-0
				905)-0-1
				9 0 6)-1-15
				907	J-1-15
				911	130
				908	J - 5-0
				913	J-O-10
				914	0- 0 -10
				915	1-13-0
				919	0-16-05
				918	0 –0 ⊷5
				922	0-0-10
				923	0-0-10
				912	0- -0 2
				933	0-0-3
				927	1-12-5
				928	0-6-0
				929	0-6-10
				, 822	0-3-10
				818	0-8-0
				862	0-9-0
				861	0-9-0
				817	1-6-0
				816	0-2-10
				815	2-1-0

522 TH	E OAZLIIE U	OF INDIA AUGUST 8.	1701/3KAVANA II	, 1309	[PART II—SEC. 3(i1)
1	-3	3	-4	5	6
Kanpur Dehat	Akbar Pur	Akbar Pur	Fatehpur	814	0-2-0
			Roshnai	684	0-1-0
				729	0-3-0
				690	0-3-10
				689	0-6-10
				688	0-9-10
				687	0-12-0
				686	0-2-10
				685	0-0-3
				695	0-0-2
				692	0-1-0
				694	1-4-10
				682	0-0-15
				681	0-0-15
				557	0-0-15
				558	1-5-0
				552	0-3-0
				556	0-2-10
				559	1-10-0
				560	0-17-10
				561	0-0-5
				551	0–1–0
				550	0-19-0
				485	0-9-10
				567	0-0-10
				566	0-0-10
				578	1-14-10
				577	0-0-5
				575	0-6-0
				576	1-3-0
				571	1-14-0
				572	1-2-0
				416	0-5-0
				418	0-0-5
				417	0-5-0
				417	0-4-0
					1-4-0
				404	
				48	1-1-5
				47 40	0-14-10
				49 46	0-1-0
				46 50	0-1-0
				50	0-8-0
				44 45	2-0-15 0-8-0
				333	0-2-10
				334	0-4-0
				335	0-2-10
				342	0-13-0
				343	0-0-10
				344	0-10-0
				341	0-2-10
				340	0-0-15
				345	0-1-0
				346	0-0-5
				[Nia	O 14016/320/84 C D

[No O. 14016/320/84-G P.]

का आ. 2025----यतः केन्द्रीय भरकार की यह प्रतीव होता है कि लाकहित में यह धावण्यक है कि उत्तर प्रवेश में हजीरा-दरैकी-अगदीशपुर तक पैट्रॉ-नयम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लोइनो की बिछाने के प्रयोगन के लिए एततुषाबद अनुसूची में बिधत भूमि में उपयोग का प्रधिकारे प्रतित करना प्रावण्यक है।

भतः श्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के झिंधकार का भर्जन) भीध नयम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय रारकार ने उस में उपयोग का झिंखकार झिंजल करने का भपना झाश्रय एक्ख्द्रारा गैपित किया है।

बंधतें कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई अ्यक्ति उस भूमि के तीचे पाइप लाइत बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम आधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकारण लि. च की.जे. पिरियोजना लखनऊ 2260000 यू. पी. को इस ऋधिसूचना की तारीख से 21दिन के भीतर कर सकेगा।

और पैसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्षिगत रूप से ही या किसी त्रिष्ठ करेगा कि वयाव वह चाहला है कि उसकी सुनवाई व्यक्षिगत रूप से हो या किसी विक्रि व्यवसायी की मार्फत ।

श्चनुपूरक (संशोधित) प्रम्साव एच० बी० जे० गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तह् सील	परगना	ग्राम	गोष संख्या	 श्रेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
 भुरदेहास	— ——— — भक्षरर्पुर	- झकबरपुर	- विमायकपुर 	1549	0-0-10	
•	-	_	_	1548	0-1-0	
				1762	0-2-0	
				1758	0-7-00	
				1517	0-1-0	
				1,516	0-16-0	
				1515	0-7-0	
				1514	0-13-0	
				1512	0-12-5	
				1513	0-2-10	
				1510	0-12-0	
				1509	0-12-0	
				1503	0-0-15	
				1508	0-0-1	
			1765	0-0-2		
			1506	1-1-0		
				1504	0-2-0	
				1507	1-17-0	
				2109	0-2-10	
				2108	1-13-5	
				2111	0-1-0	
				2114	2-5-0	
				2107	07-0	
				2115	0-2-10	
				2116	0-16-4	
				2119	0-17-11	
				2118	0-10-15	
				2120	0-9-10	
				2121	0-3-15	
				2140	0-11-15	
				2123	0-16-5	
				2 1. 2 4	0-17-5,	
				2095	0-4-5	
				2125	0-1-10	
				2094	0-18-15	
				2089	0-12-0	
				2090	0-12-5	
				2085 .	0-17-10	

1	2	3	4	5	6	7
गानपुर देहात	ग्रकेशरपुर	ग्रक्षरपुर	विमायकपुर	2086	0-13-10	·
• .	Ť	-	ĺ	2081	0-2-0	
				2090	0-17-3	
				2078	0-4-5	
				2079	0-14-0	
				2266	0-13-10	
				2269	0-8-12	
				2770	0-2-15	
				1615	0-0-10	
				1552	1-8-0	
				1553	07-6-0	
				1554	0-8-0	
				1555	0-5-0	
				1610	0-2-0	
				1609	0-1-10	
				1607	0-17-0	
				1606	0-4-10	
				1602	0-1-10	
				1603	0-6-10	
				1551	0-3-0	
				1604	1-3-0	
				1573	0-6-10	
				1574	0-9-0	
				1590	0-1-0	
				1578	0-13-10	
				1579	0-4-10	
				1580	0-2-10	
				1581	1-1-0	
				1582	0 - 5-0	
				1269	1-8-0	
				1186	1-7-0	
				1228	0-1-10	
				1187	1-10-10	
				1188	0-1-0	
				1225	0-12-0	
				1224	0-18-0	
				1215	0-11-0	
				1222	0-19-0	
				1223	0-19-0 0-17-0	
				1221	0-3-0	
				1220	0-5-0	
				1219	0-6-10	
				1217	0-18-0	

[# O-140.16/349/84-जी -पी.]

S.O. 2025.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H. B. to I in Utar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd

2624

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby

declares its intention to acquire the right of user therein;

0 - 2 - 0

0 - 1 - 0

1601

1572

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd H. B. J. Pipeline Project, I ucknow-226001 UP . Station Road, Lucknow-226019 UT.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE) H.B.J. GAS PIPE LINE PROJECT

Kanpur Dehat	2	3,	4			
Kanpur Dehat			4	5	6	7
	Akbar Pur	Akbar Pur	Visayak Pur	1549	00-10	
				1 54 8	0-1-0	
				1762	0-2-0	
				1758	0-7-0	
				1517	0-1-0	
				1516	0-16-0	
				1515	0-7-0	
				1514	0–13–0	
				1512	0-12-5	
				1513	0-2-10	
				1510	0-12-0	
				1 509	0-12-0	
				1503	0-0-15	
				1508	0-0-1	
				1765	0-0-2	
				1506	1-1-0	
				1504	0-2-10	
				1507	1-17-0	
				2109	0-2-10	
				2108	1-13-5	
				2111	0-1-0	
				2114	25-0	
				· 2107	0-7-0	
				2115	0-2-10	
				2216	0-16-4	
				2119	0-17-11	
				2118	0-10-15	
				2120	0-9-10	
				2121	0-3-15	
				2140	0-11-15	
				2123	0-16-5	
				2124	0-17-5	
				2095	0-4-5	
				2125	0-1-10	
				2094	0-18-15	
				2089	0-12-0	
				2090	0-12-5	
				2085	0-17-10	
				2086	0-13-10	
				2081	0-2-0	
				2080	0-17-3	
				2078	0-17/5	
				2078	0-14-0	
				2266	0-14-0	
				2269	0-8-12	
				2270	0-2-15	
				1615	0-2-13	
				1552	1-8-0	
				1553	0-6-0	

1	2	3	4	5	6 7
anpur Dehat	Akbar Pur	Akbar Pur	Visayak Pur	1554	0-8-0
-			-	1555	0-5-0
				1610	0-2-0
				1609	0-1-10
				1607	0170
				1606	0-4-10
				1602	0-1-10
				1603	0-6-10
				1551	0-3-0
				1604	1-3-0
				1573	0-6-10
				1574	0-9-0
				15 9 0	0-1-0
				1578	0-13-10
				1579	0-4-10
				1580	0-2-10
				1581	1-1-0
				1582	0-5-0
				1269	1-8-0
				1186	1-7-0
				1228	0-1-10
				1187	1-10-10
				1188	0-1-0
				1225	0120
				1224	0-18-0
				1215	0-11-0
				1222	0-19-0
				1223	0-17-0
				1221	0-3-0
				1220	J5-0
				1219	0610
				1217	0-18-0
				1601	0-2-0
				1572	0 -1-0

[No. O. 14016/349/84-G:P.]

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की घारा 6 की उपचारा (1) के प्रधीन सरकार की रिपोर्ट दे वी है।

भीर भागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने ज़क्त रिपोर्ट पर विचार करने के पक्ष्यात् इस श्राधसूचना से संलग्न प्रनुसूची में विनिधिन्ट भूमियो में उपयोग का श्राधकार श्राजित करने का विनिध्चय किया है।

प्रश्न प्रतः उक्त भिष्ठिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतव्द्वारा घोषित करती है कि इस मधिसुचना में सैलग्न धनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों दें उपयोग का प्रधिकार पाइप लाइम बिछाने के प्रयोजन के लिए एन द्वारा मजिस किया जाता है।

श्रीर श्रागे उन घारा की उपघारा (4) द्वारा प्रदत गक्तिया व प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बनाय भारतीय गैंस प्रधिकरण लिमिटेट में सभी बाघाओं से मुक्त रूप में, भीवणा के प्रशासन की इस तारीख को निहित होगा।

भ्रनुसूची एख०की०जे० गैस पाइप लाइन प्रोज़ेन्ट

ग्राम छावनी	तेहसील गुना	জিপা গুৰা	राज्य : मध्यप्रदेश
मनु ० क ०		 खसरानं०	उपयोग् प्रधिकार धर्जन का क्षेत्र (हैं०से
1		Ĵ	3
1,		985	0, 5θ.
2.		986	0.297
3		1.000	0.63
4		1002	0.775
5.		1003	0.13

						
	2	4	1	2	3	r
	982	0 181	4	1002	0 778	- -
	990	0 653	5	1003	0 130	
	981	0 562	6	982	0.184	
	926	0 231	7.	980	0.653	
	777	0.054	8.	981	0 562	
	778	0.032				
	779	0 022	9,	926	0 281	
	780	0 556	10.	777	0 054	
	781	0.065	11.	778	0.032	
	889	0.038	12.	779	d. 02 2	
	891	0.011	3.	780	0 556	
	888/1/3	0.205	:4.	781	0 065	
	888/2	0.356	15,	889	0 038	
	888/1/2	0.605				
	993	0.086	16	791	0 011	
	888/3/1	0.140	17	388/1/3	0 205	
	896	0.367	18.	388/2	0 356	
	899/1 क	0.588	19.	88/1/2	0.605	
	979	0.108	20.	193	0.086	
·	893	0.022	21.	888/3/1	0.140	
क्टूल योग	•	7.339	22.	896	0.367	
	सि॰ O. 14016/599/87	ी० पी०)]	23.	899/1K	0.588	
ut						
			24.	979	0.108	
io in the Ministry	s by notification of the Gov of Petroleum & N.G. S.O.	ernment of	25	893 	0.022	
	tion (1) of section 3 of the			TOTAL	7.339	

[No. O-14016/599/87/G.P.]

i.O. 2026.—Whereas by notification of the Government of ia in the Ministry of Petroleum & N.G. S.O. 227E date 3-87 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in id) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government decid its intention to acquire the right of user in the lands cified in the schedule appended to that notification for pose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section of Section 6 of the said Act, submitted report to the vernment.

And further where the Central Government has, after isidering the said report, decided to acquire the right of r in the lands specified in the schedule appended to this iffication.

Now therefore, in exercise of the power conferred by subtion (1) of the section 6 of the said Act, the Central vernment hereby declares that the right of user in the d lands specified in the schedule appended to this notition hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by subtion (4) of that section, the Central Government directs it the right of user in the said lands shall instead of vestin Central Government on this date of the publication of a declaration in the Gas Authority of India I td. free from encumbrances.

H.B.J. GAS PIPELINE PROJECT

'illage: Chhavni Distt, : Guna Tehsil: Guna M.P. SCHEDULE 3.No Survey No. Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare 3 985 0 562 1. 2. 986 0 297 3, 1000 0 637

कार भार 2027 - पत पेट्रोसियम भीर खितिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का श्रर्जन) भिधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा उ की उपधारा (1) के सभीन भारत सरकार के पेट्रोसियम भीर प्राकृतिक गैम मलालय की श्रिधमूचना कार आर मंर 224 ई तारीख़ 21-3-1987 हारा केन्द्रीय सरकार ने उस धिधमूचना से सलस्त प्रमुख्ती में विनिर्दिग्ट भूभियों के उपयोग के भिधकार को पाइप ताहरी को विछान के लिए श्रांजित करने को अपना भ्रामय घोषित कर दिशा था।

भीर यन सक्षम प्राधिकारी ने उक्त श्रीयनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के भ्रधीन सरहार की रिपीट दे की है।

भी श्रामे, यन केम्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोट एर विचार करने के पश्चात् इस अधिमूचना से सल्पन भनुसूर्च से विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार श्रीजन करने का जिनिक्चण किया है।

श्रव श्रव. उक्त श्रधिनियम की धारा ७ की उपधारा (।) द्वारा प्रदस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रं य सरकार एनद् द्वारा घाषित करती ह कि इस यधिसूचना में सत्रात श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूभियों में उभयाग का श्रधिकार पाइन आइन विछान के प्रयाजन के लिए एन्द्द्वारा र्ह्याजन किया जाता है!

श्रीर प्रापं उस धारा की उपधारा (1) हास प्रकृत सक्तियों की प्रथान करत हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय नीम प्राधिकरण लिभिटड में सभी बाबाधा से मुक्त त्या में, चीएणा के प्रकाशन की इस नार्राख का निहित होगा।

па	æf þ	÷	गैस	TOTAL T	स्त्राह्म	प्रोजेक्ट
ii oq	41	л,	4144	4184	01184	आजिन्द

ग्राभ : मुहालपुर	तहसील : गृना	जिला : गुना प्रनुसूची	राज्य : मध्यप्रवेश
मनुक		खसरा नं	उपयोगँ श्रक्षिकार मर्जन का क्षेत्र (हें)
1		2	3
1-		1 2/1	
		•	0.03
2-		12/3	0.695
3-	J	t 0/2	0,162
कु ल योग	 		0,799

S.O. 2027.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 228E date 21-3-87 under sub-section (f) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd, free from all encumbrances.

H.B.J. GAS PIPE LINE PROJECT

_ Villa	ge : Muhalpur	Tehsil	: Gun'ı	Dist	t.: Guna	M.P.
		SCH	DULE			
S. No.	Survey No.	·			Acquired Hectare	for
1	2		3		- ,	
1.	12/1		0.03	2		
2,	12/3	,	0.60)5		
3.	10/2		0.16	2		
<i>,-</i>	TOTAL	· · · ·	0.79	9		
	-		No. C	-14016	5/600/87—C	3.P.J

का. आ. 2028: -- यत. पेट्रोलियम भीर खनिज पाइप ताइन (भूमि में उपयोग के भीधकार का ग्रर्जन) ग्राधिनिथम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के भाधीन पारत सरकार के पेट्रोलियम भीर प्राकृतिक गैम खुनालय की ग्राधिस्चना का आ सं 229 है तारीख 21-3-1987 हारा केन्द्रीय सरकार ने उस मिध्रसूचना से <mark>संलग्न बनुसूची में विनिदिष्ट भू</mark>मियों के उपयोग के प्रधिकार की पाइप लाइनों को विछाने के लिए प्रजिल करने का प्रपना शागय घोषिश कर दियाथा।

और यनः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त मधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के मधीन सरकार की रिपॉट वे दी है।

भौर त्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पक्ष्मात् इस श्रधिसूचना से संलग्न भनुसूची में विनिर्दिष्ट मूमियों में उपयोग का ग्रधिकार श्रीवन कर का विनिश्चय किया है।

शुब मत. उनत भिधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त गक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदहारा घोषित क्रती है कि इस अधिसूचना में सलग्न धनुमूची में विनिदिष्ट उनत भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिकाने के प्रयोगन के लिए एतदहारा अजित किया जाता है।

भीर आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय मरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाणन की इस सारीख को निहित होगा।

एच बी जे गैस पाइन लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : सिगवासा तहसील : गुना विला : गुना राज्य : मध्यप्रदेश

भनुक	स्रामरा नं ू	उपयोग प्रधिकार अर्जन का क्षेत्र (है० में)		
1	2	3		
1.	3 63	0,043		
2,	36-	4 0.065		
3.	365/	1 0.994		
4.	359	0.756		
5.	358	0.410		
6.	357	0.356		
7.	35€	0.216		
۶.	355	0.637		
ģ	381/	2 0.302		
10-	381/	4 0.248		
11	384	0.405		
12	392	0.659		
13	421/	1 0 016		
1-1-	421/	3 0.016		
ł 5-	404/	1 0.400		
16.	404/	2 . 0.130		
17.	403/2	-3 0,567		
18.	232	0.270		
19.	383	0.011		
20.	352	0.022		
21.	398/1	0.248		
22.	398/2	0.292		
कुस योग		7.063		

{सं. ग्रां. 14016/601/87-जी पी } राकेश कुमार, उप सचिव

要0/--

सक्षभ प्राधिकारी

गैंस अर्थारिटी झाफ इण्डिया लि.

गुसा

S.O. 2028.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 229F date 21-3-87 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of Jaying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

H.B.J. GAS PIPE LINE PROJECT

Village	: Singwasa	Tehsil; Guna Distt.: Guna M.P.			
SCHEDULE					
S. No.	Survey No.	- Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare			
1	2	3			
1,	363/	0.043			
2.	364	0,06₹			
3,	365 '1	0.994			
4.	359	0.756			
5.	358	0.410			
6.	357	0.356			
7.	356/2	0.216			
8.	355	0.637			
9.	381/2	0.302			
10.	381/4	0 248			
11.	384	0,405			
12.	392	0,659			
13.	421/1	0.016			
14.	421/3	0.016			
15.	404/1	0. 400			
16.	404/2	0.130			
17.	403/2-3	0.567			
18	232	0.270			
19	383	0.011			
20.	352	0.022			
21	398/1	0.248			
22	398/2	0.292			
	TOTAL	7.063			

COMPETENT AUTHORITY
Gas Authority of India Ltd., Guna.

\$d./ [No. O-14016/601/87-G.P.] RARKESHh KACKER. Dv Secy.

सिवेष संजालव

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1987

का.श्रा 2029—हज सिमिति नियमायली, 1963 के खंड 14 के श्रनुसार भारत सरकार को प्रदत्त शिक्तियों के तहत केन्द्रीय भरकार के श्रिधिकारी श्री सईद मोहम्मद कमालुद्दीन सुभानी की, जो बम्बई में हज सिमिति के कार्य-कारी अधिकारी थे. प्रतिनियुक्ति 22 मई, 1987 के अपराहन्त से समाप्त की जाती है, जब उन्होंने कार्यकारी अधिकारी के पद का कार्यभार छोडा था।

[मं. एम (हज)-118/1/5/85] जे.श्रार. बुग, श्रवर मचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Haj Cell)

New Delhi, the 22nd July, 1987

S.O. 2029.—In exercise of the powers vested in the Government of India in terms of Section 14 of the Haj Committee Rules, 1963, the deputation of Shri Syed Md. Knmaluddin Subhani, an officer of the Central Government, as Executive Officer, Haj Committee, Bombay is hereby terminated with effect from the afternoon of 22nd May, 1987 when he relinquished charge of the post of Executive Officer.

No. M(Haj)/118-1/5/85] J. R. DUGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1987

का० आ० 2030—राजित्यक और कौंसलीय अधिकारी (शपथ और फींस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41 वां) की धारा 2 के खण्ड (कं) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा भारतका राजदूतावास, रियाद में सहायक श्री के के कक्कड़ को 16 मई, 1987 से कींस्ली, एजेंग्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[et- 4330/2/87]

New Delhi, the 23rd July, 1987

S.O. 2030.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers' (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri K. K. Kakkar, Assistant in the Embassy of India, Riyadh to perform the duties of Consular Agent with effect from 16th May, 1987.

[T 4330/2/87]

कों .श्रा. 2031—राजयनिक और कौंसलीय ग्रधिकारी (शपथ और फीस) श्रिधिनयस, 1948 (1948 का नावां) की धारां 2 के खण्ड (क) के श्रन्सरण में केन्द्रीय सरकार एतद्दारों भारत को राजदताबास, मोजांस्विक में सहायक श्री सुभाव चन्द्र चांबलों को 8 जून, 1987 से कौंसुली एजण्ड का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करनी है।

[टी 4330/2/87

S.O. 2031—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers' (Oath and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shir Subhash Chander Chawla, Assistant in the Embassy of India, Mozambique to perform the duties of Consular Agent with effect from 8th lune, 1987.

[T 4330/2/87]

का . आ . 2032.— राजनियक और कौसलीय अधिकारी (णपथ और फीम) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एनद्-द्वारा भारत का राजदूतावास, मस्कत में सहायक श्रीओ पी महता को 18 मई, 1987 से कौसुली ऐजन्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

[दी -4330/2/87]

S.O. 2032.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers' (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereb, authorise Shri O. P. Mehta, Assistant in the Embassy of India, Muscat, to perform the duties of Consular Agent with effect from 18th May, 1987.

[T-4330/2/87]

्का . अर्ग . 2033.—- गंजनियक और कौसलीय अधिकारी (शपथ और फीस अधिनियम, 1948 (1948 का 41वा) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एनत्ज्ञारा भारत का सहायक हाई कमीशन, कैन्डी में सहायक सर्वश्री और सलवाम और एल. कृष्णामूर्ति दोनों को 18 मई, 1987 से कौसुली ऐजण्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[ਈ-4330/2/87]

S.O. 2033.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers' (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise S/Shri R. Selvam and L. Krishnamurthy both assistants in the Assistant High Commission of India, Kandy to perform the duties of Consular Agents with effect from 18th May, 1987.

[T-4330/2/87]

का . यों . 2034.— राजनियक और कौसलीय प्रधिकारी (शपथ और फीस) प्रधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के खण्ड (क) के प्रमुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा भारत का राजदतावास, ब्रीजीलिया में सहायक श्री श्रीर पी. कौशिक को 9 जून, 1987 में कौसूली ऐजण्ट का कार्य क्रिने के लिए प्राधिकृत करती है।

[**टी** 4330/2/87]

S.O. 2034,—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers' (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri R. P. Kaushik, Assistant in the Embassy of India, Brasilia to perform the duties of Consular Agent with effect from 9th June, 1987.

[T-4330/2/87]

क्यं म्रां. 2035.—राजनियक और कौसकीय मधिकारी (शपय और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के खण्ड (क) अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतुतदुहारा भारत का राजदूतावाग, दोहा में महायक श्री वी. के.मोग। को 25 जून, 1987 स की मुली ऐजण्ड का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

(라-4330/2/87)

ज . एस पण्डे उप-सन्तिव (कोम्ली)

S O. 2035.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers' (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri V. K. Monga, Assistant in the Embassy of India, Doha to perform the duties of Consular Agent with effect from 25th June, 1987.

[T-4330/2/87]

J. S. PANDF, Dy. Secy. (Consular)

विस्सी विकास माधिकरण

नई दिल्ली, 8 ग्रगस्त, 1987

मार्वजनिक सूचना

का. या 2036: --विनाक 6-1-87 को भारत के त्राजपत्न, १ खंड-3 उपखण्ड (ii) श्रमाधारण में प्रकाणित समसंख्याक सार्वजनिक को प्रधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा विल्ली मुख्य योजना/जोनल योजना में विन्निलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसे सार्वजिनिक स्थान के लिए एसट्द्रारा प्रकाशित किया जाता है। यवि किसी व्यक्ति को प्रस्ताविस संशोधन वे सर्वध में कोई प्रापत्ति हो या उसके सर्वध में कोई सुक्षाव देना हो तो वह धंपनी मापत्ति यो सुक्षाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से नीस दिन की मवधि के अंदर लिखित रूप में सचिव, विल्ली विकास-प्रधिकरण, विकास सदन, बी ब्रनाक्ष, धाई. एन. ए, नई दिल्ली को भेज दें। ग्रापत्ति करने या सुक्षाव देने वाला व्यक्ति सपना नाम और पना भी दें।

समोधन---

"लगभग 0 44 हेक्ट. (1.1-एकड़) क्षेत्र, जो जोन एफ-3 में महरीली रोड के साथ लगता है जीर जो मनुमोदिन जोनल योजना/विकास योजना में भ्रांशिक रूप से (0 08 हेक्ट०) हरित के लिए जीर भागिक रूप से (0.36 हेक्ट०) 'सरकारी और मर्ज सरकारी सुविधाओं' (स्कृल) के लिए निर्देश्ट है और जो उत्तर में हरित क्षेत्र, पूर्व में मंक्षिणिक उपयोग, दक्षिण में 9 मीटर चोडी सडक तथा पश्चिम में 60 मीटर मर्गाधिकार के महरौली रोड से धिरा हुआ है, के भूमि उपयोग को 'क्यावमायिक' (स्पानीस खरीदवारी उपयोग) में सबलने का प्रस्ताब है।'

2. प्रस्ताबित संशोधन को दर्शाने बाला प्यान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के प्रन्दर सभी कार्यशील दिवसो को उपनिदेशक, मुख्य योजना धनुभाग, छटी मंजिल, विकास सीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टैट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध होगा।

> [स. एफ. 3(123)/83-एम. पी.] जनक जुनेजा, सविव दिल्ली विकास प्राधिकरण

DFLHI DEVELOPMENT AUTHORITY New Delhi, the 8th August, 1987

PUBLIC NOTICE

S.O. 2036.—In supersession of public notice of even no. published in the Gazette of India, Part-II section-3 sub-section (ii) Fatra-Ordinary on 6-1-87, the following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan Zonal Plan for Delhi, is hereby published for

public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A., New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :-

"The land use of an area, measuing about 0.44 ha.

(1.1 acre) abutting Mehrauli Road in zone F-3, earmarked in the approved Zonal Plan Development Plan partly (0.08) for green area and partly (0.36ha.) for 'public and semi-public facilities' (School) and bounded by green area in the Noth, educational use in the Fast, 9 mtrs, wide road in the South and 60 mtrs. R|W road Mehrauli Road in the West is proposed to be changed to 'Commercial' (Local Shopping Use)."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan Section, Vikas Minar, 6th floor, I.P. Estate, New Delhi, on all working day, within the period referred to above.

[No. F. 3(123)|83-MP]

JANAK JUNFJA, Secy.

Delhi Development Authority

रेत मंबालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 22 जुल[ा]ई, 1987

का आ. 2037.—भारतीय रेन श्रधिनियम. 1890 (1890 का अधिनियम IX) की धारा 82 वी द्यारा प्रदस्त मिक्तियों का प्रयोग करते हुए, कैन्द्र सरकार 3-4-1986 को बडोदरा मंडल के देवदी और जंख्वाव स्टमनों के बीच 246 उप माल एवं पेमोंजर गांड़ी के रंजन और बोगियों के पटरी में उत्तर जाने से उत्पन्न सभी दाशों पर कारताई करने के निए एनइद्वारा श्री ए.के. शाह, सेवा निवस्त जिला जज, न(न)र पुरा को नदर्श हावा प्रायुक्त के लप में नियुक्त करती है।

[मं. 87/ई(ओर)/!ए/1/3)] सत्तीश मोहन वैश. मचित्र, रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 22nd July, 1987

S.O. 2037.—In exercise of the powers conferred by Section 82B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890) the Central Government hereby appoints Shri A. K. Shah, retired District Judge, Nanpusa, Surat as ad-hoc Claims Commissioner to deal with all the claims arising out of derailment of engine and bogies of 246-UP Goods-cum-passenger train between Devdi and Zankavay stations of Vadodara division on 3rd April, 1986. His Headquarters will be at Surat.

[No. 87/E(O)II/1/3] S. M. VAISH, Secy., Railway Board संचार मंद्रालय

(दूरभंबार विभाग)

नई दिल्लो, 20 जलाई, 1987

का. श्रा. 2038. — स्थारी श्रादेश संख्या 627, दिनाक 8 मार्च, 1960 द्वारा लाग् किये गये भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरमंजार थियाग ने मृलाना, बहिटा, छछरौली, साहा, इंडेमरा, मठेहरी, लाताडू, दायुपुर, खाखन, नाहरपुर, बिलासपुर तथा मृसिम्बल मुगलमानान टैलीफोन केन्द्र, हरियाणा, सिकल, मे दिनाक 1-8-1987 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निण्वय किया है।

[संख्या 5-13/87-पी,एच.बी.]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 20th July, 1987

S.O. 2038.—In pursuance of pata (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 1-8-1987 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Mullana, Bihta, Chhschbrauli, Saha, Handesra, Matheri, Lairu, Dadupur, Kharwan, Naharpur, Bilaspur and Mussimbal Musalmanan Telephone Exchanges under Haryana Telecom. Circle.

No. 5-13 87-PHB1

नई दिल्ती, 23 ज्लाई, 1987

का. या. 2039.— प्यापी आदेश संख्या 627, दिनाक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने कृष्मम्बूर टैलीफोन केन्द्र, तमिल नाहु संवित्त, में दिनांक 1-8-1997 मे प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निण्चल किया है।

[संख्या 5-1/87-पी एच बी] पी. श्रार. कररडा, सहायक महानिदेशक (पी.एच.बी)

New Delhi, the 23rd July, 1987

S.O. 2039.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of T. lecommunications, hereby specifies 1-8-1987 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kurumandur Telephone Exchange, Tamil Nadu Telecom. Circle.

[No 5-1187-PHB]

P. R. KARRA, Asst Director General (PHB)

स्रम जेल्लाम

न डिले ७) चनामें, 13-7

का. था. 2040.—- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के प्रमुक्तरण में, ते द्वीर्थ सरकार, ग्राकाण कीनारी कायलरी, मैसर्म भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध निप्रोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, श्रमुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक श्रधिकरण संख्या -1, धनवाद, के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 17 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF I ABOUR

New Delhi, the 22nd July, 1987

S.O. 2040.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government industrial tribunal No. 1. Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Akash Kinaree Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th July, 1987.

BEFORF THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1. DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(4) of the

Industrial Disputes Act, 1947 Reference No. 34 of 1983

FARTIES:

Employers in relation to the management of Akash Kingree Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited.

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers-Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary Bihar Colliery Kumgar Union.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 10th July, 1987

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour has, by Order No. L-20012(482)/82-D.III (A) dated, the 5th May, 1983, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:—

- "Wheter the action of the management of Akash Kinaree Colliery of Messrs Bharat Coking Coal I to., Dhambad in regularising 102 Contractor's workmen and not regularising Shii Sheo Shanker Singh, Munshi of the same contractor, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"
- 2. The case of the management, shorn of unnecessary details is as follows:

The management of Akash Kinaree Colliery which comprises of non-coking coal mines was taken over by the Central Government with effect from 31-1-1973 and ultimately the said colliery was nationalised with effect from 1-5-1973. The er while management of the colliery engaged several contact of holding are larger Single to perform various types to be and in larger Single to perform various types and in larger to concern i used to execute pibe and each by engagery, workmen of their own. The new inauagement established immediately after take over of the colliery abolished the contract system and decided to execute all works by engaging its own workmen. While doing the management took into consideration several factors and decided the requirement of various types and categories of workmen for executing the contractual tobs departmentally

The management recruited workmen on its roll from amongst the contract workers already working in the colliery The contractors used to employ temporary and casual work men to execute different types of contract works; none of them were on permanent roll and no one was enployed continuously and the contract works were mostly temporary or casual. The new management selected the workmen o the contractors according to the need of the managemen and recruited them under its direct employment, and these workman were regularised and put on permanent rolls Several workmen of various contractors approached the new management for employment; but it was not possible fo the new management to recruit all the workmen of all the contractors. The management recruited and regularised some of the contractors' workers depending upon the need. I is absured to suggest that because the management recruited and regularised about 100 contract workmen, it should rec mit and regularies all the workmen working under the cont The management has every right to recruit the number of workmen required and it cannot be compelled to recruit and regularise all workmen without any need. The concerned workmen was a Munshi of the contractor. He was attached to the contractor and was doing his job where ver the contractor used to depute him. He was not confirmed to any particular type of contract work in any particular His relationship with the contractor was differen from other ordinary unskilled or skilled workers. It is alleged that the workmen concerned has raised the disput ofter the lapse of period of 9 years with some ulterio motive.

3. The case of the concerned workman is as follows:

Sri I aliee Singh was the lease holder of Quarry No. 6 of North Teturia Section of Akashkinatee Colliery He had engaged 103 workmen for running the mine and raining coal. The concerned workmen had been working as permanent Mun hi at Quarry No. 6 He as well as the other workmen had been working under the direct control and supervision or the colliery management and necessary component/implement was being supplied by the management. But the management used to disburse the wages of the concerned workman though intermediaties of Laljee Singh which was nothing but legal camoufledge to deprive the vorkmen of their legitimate claim. All the 103 workmen become emplayees of Akashkinaree colliery on and from appointed date, i.e. 1-5-1973 after the Nationalisation Act. The con-The concerned workman had rendered continuous service and put in more than 190/240 days attendance in each calendar year and in the preceding twelve months prior to his stoppage from work. The management abruptly stopped him from rendering service with effect from 14-5-1973 without any chargesheet and without assigning any reason. He protested immediately against the illegal and arbitrary action of the management, but he was advised to wait as the matter was under active consideration of the higher each lon of the management but nothing come out and ultimately the union raised the industrial dispute. During the conciliation proceeding the management assured the union for amicable settlement and on the assurance of the management the union withdraw the dispute. The management moved note-sheet under intimation to the concerned workman; the note-sheet was forwarded and recommended by the Personnel Manager and General Manager of the Area. But in suite of the aforesaid fact the management did not allow him to resume his duty and the union again raised the dispute before the Assit. Labour Commissioner (C), Dhanba I. It is all-ged that due to a lamont attitude of the management the conciliation proreeding ended in failure and the present reference was made It is further alleged that the action of the management in not recularising the concerned workman was illeval, arbitrary, univertified and against the principle of natural justice. Under the circumstances the workman has prived that the management be directed to regularise him in service with effect from 14-5-1973 by reinstating him with full back wages,

4. In his rejoinder to the written statement of the management the congerned workman has defined and disputed each and every fact as stated in the written statement of the management. The concerned workman has asserted that he was attached to the contractor and that he was not at the back and call of the contractor. He has also asserted that his relationship with the alleged contractor was not also different from ordinary unskilled and skilled workmen.

- 5. In his rejoinder to the written statement of the workman concerned the management has further stated that it is measured to suggest that Quarry No. 6 was given on lease to Laige Singh and that it is also measured to suggest that 103 workmen were engaged by Sir Singh for running the mine and raising coal. Sir Laigee Singh was one of the contractors of the colliery and he was paying wages to his own workmen. Since the concerned workman was the Munshi of the contractor himself and since there was no need for employment of the Munshi the management did not recruit him. It has been denied that the concerned workman put in 190/240 days of attendance in each calendar year and in the preceding twelve months before natioalisation.
- 6. The management has examined only one witness in this reference, but laid no documentary evidence. On the other hand, the workman concerned examined himself and introduced in evidence a mass of documents which have been marked Exts. W-1 to W-7.
- 7. Admittedly, North Tentuliya and North Akashkinari were two separate collieras and the management of both the collieries was take over by the Coal Mines (Tuking Over of Management) Act, 1973 and vested in the Central Government on and from the appointed day, i.e., 31-1-73. It transpires from the evidence of MW-1, Sprendra Singh, that five small collieries were amalgamated and constituted a composite colliery styled Akashkinari colliery after the management of the collieries were taken over by the Central Government with effect from 31-1-1973. There is no evidence on record to dis-place or dis-prove this fact. It is also admitted position that Akashkinari colliery was nationalised under the provisions of Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 which came into force on the 1st day of May, 1973.
- 8. The management has contended that one Satdeb Singh was the lease-holder of North Tentuliya and North Akashkinari colheries which new form part and parcel of Akash-kinari colhery. On the other hand, the workman has contended that Laljee Singh was the lease-holde, of North Tentully a colliery which included Quarry No. 6. None of the parties have produced before me documents in support of their respective contentions. Hence I consider that the claim of both the parties arrayed are unsustainable in so far as the least holder's superstant of the unit of colliers. the lease-holder's interest of the said colliery is concerned. On the contrary it appears from the schedule of the Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973 and Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 that Khimji Dessa and Co., Katrasgath and Debram Ramji, Katrasgath were respectively the owners of North Akashkinari Colliery and North Tentunya Colliery, WW-1 Sheo Shankar Singh the Colliery and concerned workman has stated that Debram Ramji was the owner of North Ientuliya colliery and Lalice Singh was the lease-holder of Quarry No. 6 of the said colliery for the specific purpose of vaising the coal. But this statement of his is not supported by documents or other cogent evidence. It has been asserted by the management that Laljee Singh was the contractor engaged and he used to engage workmen as and when work was available. In the present reference the concerned workmen has been described as Munshi of the same contractor whose workmen numbering 102 were regularised by the management of M/s. B.C.C. Ltd. It transpires from evidence that 103 workmen including the concerned workman were employed by Laljee Singh in the quarry and that all of them excepting the concerned work-man were employed or departmentalised. This position also buttressed by Office Note of the management dated 14-8-1981 I'xt, W-1. Thus, the inescapable conclusion is reached that this concerned workman was a Munshi of the contractor Laliee Singh and that Laliee Singh had a work force of 103 workmen including the concerned workman of whom all except the concerned workman have been regularised or departmentalised. It is asserted by the workmen that these work force of Laliee Singh was engaged in the mining operation and that all of them worked under the direct control

and supervision or the colliery management. The management has beened that Laijer Singh was a lease-holder but na, not defined in specific terms that the work force of Laljee single was not employed in mining operation. All that the management has stated is that all of their were employed on casual basis and that they were employed and when work was available. But MW-1 Surendra Singh has himself stated that the contractors workingn were employed on contractual basis and not on casual basis. On the other hand, the evidence of WW-1 Sheo Shankar Singh firmly establishes the fact that the entire work force of Laljee Singh comprised or 103 workmen including himself were employed in the quarry and that excepting himself all other workmen were employed as stone curter, earth cutter, coal curter etc. and that the workmen used to work in groups and it was his duty to keep their attendance, out-put of every group with regard to faising of coal, carth and stone, to supply working implements to the workmen and various other jobs. Nothing has been elicited from him in crossexamination to dis-prove the fact. Thus I come to the conclusion that the entire work force of Laljes Singh, a contracfor, was corployed in Quarry No. 6 for nuning operation in me aforesaid coal mine.

- 9. It has been contended by Sii B. Joshi that there is no cope for the Tribunal to hold in view of the terms of refesence that the concerned workmen and the work force of I alice Singh were the employees of the collicity in question. On the other hand, Sri D. Mukherjee, authorised representative of the concerned workmen has laboriously submitted that the entire work force of Laljee Singh including the concerted workmen were the employees of the collery in question. In support of his contention Sri D. Mukherjee has cited before me the case reported in 1963 (II) LLI 447 (Easti Sugai Mills Ltd. Vs. Ram Ujagac and others). In that case it has been held that the words used in the definition of "workmen" in Sec. 2(z) of the Industrial Disputes Act are the aselves sufficiently wide to bring in persons doing work in an industry whether the employment was by the management of by the contractor of the management. Bemanagement of by the contractor of the management. sides this the other conclusion reached in the above decision do not apply to the facts and circumstances of the present case. Sri D. Mukherjee has also cited the decision reported in 1978 Lab. I C. 1964—AIR 1978 SC 1410 (Hussambhai, Petitioner Vr. The Alath Factory Tezhilsh Union and others, Respondent). In that decision it has been held by Hon'ble Supreme Court that :
 - "Where a worker or group of workers labouts to produce goods or services and these goods or services are for the business of another, that other is, in fact the employer. He has economic control over the workers' subsistence, skill and continued employment. If he, for any reason checkes off, the worker is, it tually, laid off. The presence of intermediate contractors with whom alone the workers have immediate or direct relationship or contract is of no consequence whom, on litring the veil or looking at the conspectus of factors governing employment, it is found, though dropped in different perfect paper arrangement, that the real employer is the management, not the immediate contractor."

In the present case the work force of Lalice Singh, a contractor, was engaged for mining operation in the coal mine in question. The evidence of MW-1, the concerned workman lends firm support to this position. That being so, it must be held that the entire work force of Lalice Singh were in fact the work force of the erstwhile management.

- 10. Even if this position remains in a fluid stage the case of the management does not get any succeur. Chapter V of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 has made provisions relating to employees of coal mines and Section 14 of the Act runs as follows:
 - "14. Employment of certain employees to continue.
 - (1) Every person who is a workman within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 and has been immediately before the about 12d day in the employment of a coal mine shall become and from appointed day, an employee of the Central Government or, as the case may be of the Government company in which the right, title and interest of such

mine have vested under this Act, and shall hold office or service in the coal mine with the same rights to pension, gratuity and other matters as would have been admissible to him if the tights in relation to such coal mine had not been transferred to, and vested in, the Central Government or the Government company, as the case may be, and continue to 'do so unless and until his employment in such coal mine is duly terminated or until his remuneration, terms and conditions of employment are duly altered by the Central Government or the Government conpany...."

This provision envisages for employment of every person in the employment of a coal mine. The word "employ" mans 'to give work to' and the word 'employment' means act of employing; that which engages or employs' (Chambers Twentith Century Dictionary—Impression 1962). The evidence on record establishes the fact that the entire work force of Laljee Singh was in the employment of the coal mine in question immediately before the appointed day i.e. 1-5-1973. The Coal Mines Nationalisation Laws (Amendment) Act, 1986 has not amended the provisions of Section 14 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, but a new Section i.e. Section 14 has been substituted by this Amendment Act for Section 14 of the earlier Act. Thus it is evident that in view of the provisions of Section 14(1) of the Coal Mines (Nationalisation) Act, the entire work force of Laljee Singh is entitled to get employment under the new management.

- 11. Admittedly 102 out of 103 of the work force have been departmentalized or regularised. The management has taken the plea that there was requirement for their srevices. They have taken the plea also that since the services of the Munshi was not required by the new management his case was not considered.
- 12. It appears from the evidence of the concerned workman that since 1968 till 13-5-1973 he worked regularly and at a stretch in the quarry of North Tentuliya colliery and that before dispensing with his services he was not afforded any opportunity to ascertain why his services were dispensed with nor was any reason assigned for dispensation with his service. There is no dispute that he worked in the quarry till 13-5-1973 i.e. even after Coal Mines (Nationalisation) Act came into force. But his services were not required by the management on the plea that there was no requirement for his service. The position taken by the management is merely ipsedixit and not supported by any cogent evidence. No evidence is carneded on record on the side of the management to evince what was the requirement of the management at the relevant time and what services were available to the management in the category of Munshi. That being so, the plea of management that there was no requirement for the service of the Munshi is not supported by any cogent evidence. Hence the plea of the management in this respect must ounder on the ground.
- 13. The workman concerned has stated that the service he was rendering for the colliery corresponds to the duties of the scale of pay of Clerk Grade III under the new management. This position has not been disputed by the management.
- 14 Convidering all these facts and circumstances I come to the conclusion that the concerned workman is entitled to be employed under M/s. Bharat Cokine Coal Ltd. as Clerk Grad- III and the scale available therefore with effect from 14 5.1973 with full back wages. Hence an award is passed holding that the action of the management of Akaslıkinari colliere of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. in not regularising the concerned workman in tervice is not justified. The concerned workman, Shoo Shankar Singh, he reinstated in service as Clerk Grade III with the scale of nay attached thereto with effect from 14-5-1973 with full back wages. The reference is answered accordingly. The parties are to bear their own cost.

S. K MITRA, Presiding Officer [No. L-20012/482/82-D.III(A)]

का. आ. 2041—शौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बामुदेव कोलयरी, मैसमं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण संख्यां -1, धनबाद के पचाट को प्रकाशिन करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुआंथा।

S.O. 2041.—In pursuance of section 17 of the Industria Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the tentral Governmen hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Basdeopur Collicry of M/s Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th July, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reterence under section 10(1)(d) o the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 23 of 1984

PARTIES:

Employers in relation to the management of Besdcopu Colliery of M/s. B.C.C.Ltd.

AND

Their Workmen

PRESENT:

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers—Shri R. S. Murthy, Advocate and Shri B. M. Lall, Dy. Chief Personnel Manager, Bhagaband Area of M/s. B.C.C.L.

For the Workmen.—Shri Chandra Mouli Sharma, Organising Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE: Bibar.

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, dated the 6th July, 1987

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012(307)/83-D.III(A) dated, the 11th April, 1984 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows:—

- "Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh that S/Shri Ramagya Yadav, Biseswar Mahato, Ramdhani Ram, Bindeshwar Bhuiya and Sidheswar Bhuiya should be treated by the management of Basdeopur Colliery of Bharat Coking Coal Limited as regular workmen with payment of wages in category-I is justified? If so, to what relief are the said workmen entitled and from what date?"
- 2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the 'tribly as required under section 15 of the Industrial Dispuses. Act 1947.

S. K. MITRA, Presiding Officer [No. L-20012/307/83 D.HI(A)]

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL FRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of Reference No. 23 of 1984

PARTIES:

Employers in relation to the Management of Bansdeopur colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd; P.O. Kusunda, Dist. Dhanbad.

AND

Their Workman

Joint Compromine Petition of the Employers and Work-noon,

The above mentioned employer and workman beg to submit jointly as follows:—

- (1) That the employers and workmen have jointly nego tiated the matter directly as covered by the aforesaid reference with diview to coming to a mutually acceptable and amicable settlement.
- (2) That as a result of such direct negotiations, the parties have arrived at a settlement on the following terms:—
 - (a) That S/Sri Ramagya Yaday, Ramdhan Ram Bisheswar Mahato, Sidheswar Fhutiya and Bineshwar Bhuiya, the workmen concerned who have put in 240 and more days of attendance would be offered employment by the Management as Miners/Loaders without any backwage.
 - (b) That the Union concerned, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh will certify the Photograph of these workers in regard to their genumeness and that workers concerned will also file affidivity to the same effect. The said certificate and affidavit will also testify that the nervous concerned are the real workers concerned in the aforesaid reference.
 - (c) That on fulfilment of the provisions referred to in classes (a) & (b) above, the dispute referred to this Honble Tribunal would stand and the resolved and that this Honble Tribunal will be requested to pass an award accordingly.
- (3) That the provisions of clauses (a) and (b) above having been fulfilled the five workers covered by the aforesaid reference have already been provided employment by the Management as Minet/Londers in Balthari Colliery of Bharat Coking coal Ltd, and they have started working in that capacity.

In view of the above, the employers and the vorkmen most respectfully pray that the Hon'ble Tribunal may be please dispose of the reference in terms of the joint compromise petition.

(Chandra Mouli Sharma) Organising Secretary Rashtriya Colliery Mazdoor For and Behalf of Workmen

(Brij Mohan Lall)

Dy. Chief Personnel Manager Bhagaband Area (Now P.B. Area) For and on Behalf of Employer.

भा भा 2042—शैद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947
(1917 का 14) की धारा 17 के श्रनुसरण में, केन्द्रीय
सरकार, भागावन्ध क्षेत्र, मैसर्म भारत कोर्किंग कोल लिमिटेड,
के प्रवन्यतंत्र के सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के
वीच, श्रनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय
सरकार औद्योगिक श्रिधिकरण संख्या-1, धनबाद के पंचाट
को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14 जुलाई,

S.C. 2042.—In pursuance of section 17 of the Industrial Deputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial tribinal No. 1 Dhanbad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhagaband Area of M/s. Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th July, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 74 of 1983

PARTIES :

Imployers in relation to the management of Bhagaband Area of Mossis Bharat Coking Coal Limited.

AND

Their Workmen

PRESENT:

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPLARANCES:

For the Employers .- Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen.-None.

SIATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 1st July, 1987

AWARD

like present reference arises out of Order No. L-20012-(155)/83-D.HI(A), dated, the 10th October, 1983 passed by the Central Government in respect of an industrial tilepute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows:—

Whe her the action of the management of Bhagaband Atea of Messis Bhatat Coking Coal Limited, Dhanbad in not promoting Shri R. A. Rai Grade-I Clerk to Special Grade while promoting his juniors is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

- 2 The dispute has been settled out of Court. A memorandum of cettlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.
- 3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

S. K. MITRA, Presiding Officer.

[No. L-20012/153/83-D.III(A)]
P. V. SREEDHARAN, Desk Officer

MEMORANDUM OF SETTLEMENT UNDER RULE 58 OF THE CENTRAL INDUSTRIAL DISPUTE RULES OF THE I.D. ACT

PRESENT:

Management representatives :

- 1. Shri T. N. Yadav, RCMS.
- 2. Shri P. Mahrai, Dy. P. M.

Union/Workmen representatives

- 1. Shri T. N. Yadav, RCMS.
- 2. Shri R. A. Rai, Area Office.

SHORT RECITAL OF THE CASE

RCMS raised an industrial dispute over non-grant of Clerital Grade Special to Shri R. A. Rai who is said to be superseded by S/Shri T. C. Prasad and S. S. Thakur. This dispute culminated in Reference No. 74/83 which is pending before the Industrial Tribunal No. 1. During the pendency of the reference, the case was discussed between the parties and after lengthy discussions it is agreed as under:

TERMS OF SETTLEMENT

- (1) Shri R. A. Rai is promoted with effect from 1-3-1980 i.e. the date Shri T. C. Prasad was promoted in Clerical Grade Special. He will get notional seniority from 1-3-1980 and monetary benefit will accrue to him from the date of reference i.e. from 10-10-1983.
- (2) There is no subsisting dispute and the dispute stands settled finally.
- (3) Copy of the settlement will be filed before the Industrial Tribunal No. 1 with the prayer from both the parties for acceptance of the settlement in full and final settlement of the above Reference before the Honble Tribunal.

Signature of the parties:

(B. M. Lall)

(T. N. Yadav)

Personnel Manager Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh Bhagaband Area,

(P. Mahraj)

(R. A. Rai)

Dy. Personnel Manager Bhagaband Area. Bhagaband Aica Office

Witness:

Sd/- Illegible.

Co: Presiding Officer, Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad.

Co.: ALC (C), Dhanbad,

Co.: Central Labour Commissioner (C) New Delhi.

Co : General Manager (Personnel), BCCL, Koyla Bhawan.

Co : General Manager, Bhababand Area.

Co: Shri R. A. Rai, Bhagaband Area Office.

Co : Finance Manager/Dy. Munager (Admn.) Bhaga-band Area.

Part of the Award

Sd-| Illegible

अध्यासी अधिकारी, केन्द्रीय सरकार आँखौगिक, न्यायाधिकरण संख्या-1, धनवाद नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1987 महिस्त

का.श्रा. 2043:—-भारत सरकार श्रम मंतालप ग्रेसिसूचना संख्या 815 दिनांक 6 मार्च, 1987 भारत के राजपत भाग 2, खण्ड 3(ii) में दिनांक 21 मार्च 1987 की प्रकाणित कम संख्या नं. 2 में "नार्दन" को "नार्थ" पटा जाये।

[संख्या एस-35019(3)/87-एम . एस . -H]

New Delhi, the 23rd July, 1987

CORRIGENDUM

S.O. 2043.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 815 dated the 6th March, 1987, published in the Gazette of India, Part II, Section 3. Sub-section (ii), dated 21st March, 1987, in serial No. 2 for "Northern" read "North".

[No. \$-35019(3)/87-\$S.II]

नर्ष दिल्ली, 24 जुलाई, 1987

का. आ. 2044 — पैसर्स मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया लि.), 467, विश्वाकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर— 302013 (आर. जे./2519) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपावन्ध ग्राधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त ग्राधिनियम कहा गया है) की धारा 17की उपधारा (2क) के ग्राधीन छुट विए जाने के लिए भागे दन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्यापन के कर्मवारी किसी पृथक प्रभिवाय या प्रीमियम, का सन्वाय किए बिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा रकीम की मामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है ये ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से प्रधिक प्रमुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चान् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन प्रमुजेय है;

पतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदन्त प्रितियों का प्रयोग करने ह्या और भारत सरकार के ध्यम मंद्रालय की प्रधिमूचना संख्या का. था. 4577 तारीख 22-11-1983 के ध्रनुसरण में और इससे उपाबद्ध ध्रनुमूची में विनिर्दिष्ट प्रतीं के प्रधीन रहने हुए उक्त स्थापन को, 17-12-1986 में तीन वर्ष की प्रविध के लिए जिसमें 16-12-1989 भी निर्मितित है, उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छूट देनी है।

ग्रन्सूर्चा

 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रावेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त राजस्थान की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदास करेगा जो केन्द्रीस सरकार सभय-समय पर निविध्य करें।

- 2 नियोगक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की मनाचि के 15 बिन के भोतर मन्द्राग करेगा जो केन्द्रीय सरकार, ज्यन मधिनियम नी धारा 17की उपधारा (3क) के खरह (क) के मधीन समय-समय पर निविष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्त-र्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियग का सन्वाय, लेखाओं कां अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्वाय श्रादि भी है, होने बाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- अ नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा प्रनुमोदित पामूहिक बीमा रकीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें मंशोधन किया आए, तब उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य कातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदणित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य लिधि का या उक्त श्रिक्षित्तियम के श्रिक्षीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य लिधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के स्था में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत ग्रावश्यक प्रीमियम भारतीय बीजन नीमा नियम को सन्दन करेगा।
- 6. यदि साप्तहिक बीमा स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाते हैं तो, नियोजिक उक्त स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों की उपजब्ध फायदों में समृचित्र क्या से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मनारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदें उन फायदों से श्रधिक श्रामू हो, जो उन्तर स्कीम के श्रधीन श्रनज़ेय है।
- 7 साम्हिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्म रारी की मृत्यु पर इस रकीम के अधीन सन्देय रकम उस रका। से कम है जो कर्मचारी को उस दणा में सन्देय हो ति जब वह उक्त रकीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी है विधिक बारिस/नामनिर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. माम् तिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजरधान के पूर्व अनुसोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां कियी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अपनर देगा ।

- 9. यदि किती कारगरण 'पाग के कर्नचारी, भारती जीवन नीमा निगम, की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या उस प्यीम के प्रजीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदें किये रीति से क्या हो जाते हैं, जो जह छुट रह की उस सकती है।
- 10. यदि किसी कारणत्रण, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में श्रमफल रहता है, फिर पालिसी को व्यय-गत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्धाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की देशा में, उन गृत सदस्यों के नामनिर्दे-शिनियों या विधिक नारिमीं को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के श्रन्तर्गत होते, बीमा कायदों के मन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के श्रवीत होते वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राणि के हक्दार नामनिर्देणिती/विधिक वारिसों को उस राणि का सन्याय नत्परता में ओर प्रत्येक दणा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिण्वित करेगा।

[मंख्या एस . - 35014/225/83-पी . ए . 2/एस . एस . - 2]

New Delhi, the 24th July, 1987

S.O. 2044.—Whereas Messrs Modern Food Industries (India) Limited, 467 Vishwa Karma Industrial Area. Jaiput-302013 (RJ/2519) (heremafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-action (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Finployees Deposit I inked Insurance Scheme, 1976 thereinafter referred to as the said Scheme;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 4577 dated the 22-11-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 17-12-1986 upto and inclusive of the 16-12-1989.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Raiasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under

clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month,

- 3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of recounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insuran e Scheme as approved by the Central Government and, is and when amended, alongwith a translation of the salent leatures thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas, an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him is a member of the Group Insurance Scheme and pay neces any premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Reigonal Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Reigonal Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view
- 9. Where, for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Inversaries Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this. Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fells to ask the premium etc within the due date as fixed by the I fe In nance Corporation of India and the rolley stall we no lapse, the exemption is liable to be cancelled
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for navment of asymmetric benefits to the nominees or the legal hers of decreased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, chall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members colored under the Scheme the Life Insurance Corporation of India state a prompt payment of sum assured to the nomine or the Legal beits of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

INO. S-35014/025/93 FF H & F1

का०अ:० 2045:— मैंसर्स दी करण बावाया वैद लि० बी. नं. 21, कहर-2 तामित नाउ (टी पन /4177) (जिसे इसमे इसके पाखात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मबारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबना स्थिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमे इसके पण्यात् उपन अजिनियम गरा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) में सबीन एट बिए जाने के लिए **प्रावेदन किया है** ;

र्शर नेरिशा धरशार का समाजात हो गा। है कि उस्त र तामन के समनारी जिला पृथक श्रिषदाय या प्रीमियम का संताय किए जिला ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन नीमा किए जिला ही सामृद्धिक बीमा रकीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उटा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदा से श्रीभक श्रीभक्ष है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहयद बीगा स्भीन, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उस्त स्काग कहा गया है) के अबीन श्रानुजीय है,

श्रव केन्द्रीय संकार, उक्त श्रीधिनियम की धारा 17 वी उपधारा (25) द्वारा प्रवन्त श्रीधिनियम का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रिधिमूचना सकता का श्राव अवश्रव तारीख 1-10-1983 के श्रमुंसरण में और इससे उपायद्ध अनुसूची में विनिद्धिष्ट शर्ती के श्रधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 22-10-1986 में तीन वर्ष की श्रविध के लिए जिसमें 21-10-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी जान्यों के प्रवर्तन से छट देनी है।

ग्रनभची

- । उत्त स्थापन के सम्बन्ध मे नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त शामिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जा केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2 नियोजन ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्त के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार जन्म प्राधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के स्थान (६) के अधीन समय-समय पर निरिष्ट करें।
- 3 भामहिस बीमा स्काम के प्रशासन में, निमके अन्तर्गत तिकाओं का रम्या आता, विवरणिया का प्रमृत किया जाता, वीमा गामिश्रम का सदाय, लेखाओं का ग्रन्तरण, निरीक्षण प्रमाण का संदाय ग्राहि भी है, होने बाले सभी व्ययों का यांग निरीक्षण लाग किया जाएगा।
- । निर्मानया, केन्द्राच सरकार द्वारा पथा अनुमोदित भागतिक गामरकिय के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उन्ह संगारत किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति संगा स्में गरिया का बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का समाद स्थापन के सूचनायट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- त्यांद होई ऐसा सर्वनारों, जो कर्मनारी भविष्य निधि ता भ अस पिर्धानयम के पक्षीन छूट प्राप्त किसी स्थापन भी भीराय पिर्ध का पहल हो सदस्य है, उसके स्थापन म निर्धाणि। निभा जाना ह ना नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के स्वास असका नाम तुरना दर्ज करेगा और उसकी नानन गायम्य प्रीपियम भा तीय जीवन बीमा निगम को सान वरेगा ।

- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के मधीन कर्मेचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के मधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के मधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से मधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के मधीन अनुक्षेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि ध्रायुक्त, तामिलनाड़ के पूर्व ध्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कुर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि ध्रायुक्त, भ्रपना भ्रमुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा ।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहने ग्रपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, िमयोजक भारतीय जीवन वीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में ग्रसफल रहता है, और पालिसी को ब्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रह की सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाप में किए गए किसी ध्यतिक्रम की दणा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के भ्रन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. इस स्कीम के प्रधीन [प्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाइत राणि के हकदार नामनिर्देणिती विधिक वारिमों को उस राणि का गंदाय नन्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिध्चित करेगा।
 - मिं. एस 35014/177/83-पी, एफ. 2/एस. एस-2]

S.O. 2045.—Whereas Messrs The Karur Vysya Bank Limited, P.B. No. 21, Karur-2 Tamil Nadu (TN/4177) (hereinafter referred to a, the said establishment) have appled for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employers' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

679 GI/87—13

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of I abour S.O. 3982 dated the 1-10-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-10-1986 upto and inclusive of the 21-10-1989.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. hall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas, an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6 The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more fovourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount movable under this scheme, he less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall may the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation
- 8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil North and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view
- 9 Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adorted by the said establishment, or the hencitis to the employees under this. Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as used by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees of the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No S-35014/177/83-PF.II-SS II]

का. थ्रा. 2046:—मैसर्स दी वन्याकमारी जिला को-श्रापरे-दिव स्पिनिंग मिल्स लि., श्ररलवेमोझी, तामिलनाडू-62930 (टी. एन / 5610) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मेचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त श्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के श्रिधीन छूट दिए जाने के लिए श्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उबन स्थापन के कर्मजारी किसी पृथक श्रिभदाय या प्रीमियम का गन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों की उन फायदों से श्रधिक श्रनुकूर हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्व बीमा रकींग, 1976 (जिंगे इसमें इसके पश्चात उन्त स्कीम कहा गया है) श्रधीन श्रनुक्रेय हैं।

स्रतः केन्द्रीय गरकार, उपत श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2 क) द्वारा प्रदन्न श्रिक्तयों का प्रयोग करने हुए और भारत गरकार के श्रम मंद्रालय को श्रिधिसूचना संख्या का श्रा. 2085 मारीख 18-4-1983 के अनुमरण में और इससे उपावद्ध अनुसूची में बिनिर्दिष्ट शर्तों के प्रधीन रहते हुए उबत स्थापन को, 7-5-1986 से तीन वर्ष की श्रवधि के लिए जिससे 6-5-1989 भी सम्मितित है, उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छुट देती हैं।

भ्रनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संग्ध के नियोजन प्रादेणिक भविष्य निधि भ्रायुक्त नामिल नाडु को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समर-समय पर गिरिट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्येक मान की ममाष्ट्रिक के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उप धारा (3क) के खण्ड (क) के श्रिप्टीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

- 3. मानूहिक बीमा स्कीम के प्रणामन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवर्णायों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का मन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने बाने सभी व्यं में का बहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा श्रनुमोदित सामूहिक दीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मवारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का श्रनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उसन श्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाना है तो नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरता दर्ज करेगा और उसकी वावत श्रावण्यक प्रीमिणम भारतीय जीतन वीमा निगम को सन्दत्त करेगा।
- 6 यदि सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाते हैं, तो, नियोजक उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों से समुजित रूप से यृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदें उन फायदों से ग्रधिक मनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन ग्रमुक्त है।
- 7. सातूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किमी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अर्धान सन्देह रक्तम उस रक्तम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उकत रकीम के अधीन होता तो, तियोजक कमवारी के विधिक वारित नाम निर्देशिती की प्रतिकर के का में दोनों रक्तमों के अन्तर के बराबर रक्तम का सन्दाय करेगा।
- 8 सामूहिक स्कीम के उजबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि ध्रायुक्त नात्रित नाडू के पूर्व ध्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किनी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृल प्रभार पड़ने की समावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि श्रीयुक्त प्रपता ध्रनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टि होता स्माट करने का यक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवण, रथाणन के वर्मनारी भारतीय जीवन योगा निगम की उस सामृहिक वीगा स्वीम के जिस् स्थापन पहेंने श्रपना खुका है, श्रधीन नहीं रह जाने हैं या उस स्कीम के अधीन वर्मचारियों को प्राप्त होने बाहे फाउँदे कियी रीति से कम हों जाने हैं. यो यह छूट रद्द कें सकती है।

- 10 यदि किभी कारणवर्ग, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भिर्देश तारोब के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करन में अप्रफल रहता है, आर पालिसी की व्ययभत हो जाने दिया जाता है तो छूट रहुद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिकाम की दणा में, उन भृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विविध बारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायिन्व नियाजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अर्धान आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होते पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बामाकृत राणि के हकदार नामिनिईणिती/विधिक वारिसीं को उस राणि का सन्दाय तत्परता से आंट प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/83/83-मो. एफ. 2/एस एस-2]

S. O. 2046.—Whereas Messrs The Kanyakumari District Co-operative Spinning Mills Limited, Aralvaimazhis, Tamil Nadu-62930 (TN/5610) (hereinaiter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provient Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premimum, in enjoymnt of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefit admissible under the Employees Depasit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2085 dated the 18-4-1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 7-5-1986 upto and inclusive of the 6-5-1989.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All Expenses involved in the administration of the Group I surance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4 The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

- 5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits amissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the logal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corpc ation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/83/83-PF.IJ-SS.II]

का.श्रा. 2047.— मैंसर्स इन्डस्ट्रियल डिवैलयमैन्ट कारपोरेणन श्राफ उड़ीमा लि., स्रदार पटेल हाल, भुवनेश्वर (ओ. श्रार. /294) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध श्रिधिनयम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चान् उक्त श्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के श्रिधीन छूट दिए जाने के लिए श्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थान के कर्मचारी किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए दिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जोवन बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से श्रधिक श्रमुकल है जो उन्हें

कर्म चार्रा निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीत धनुजेय है,

श्रत अन्द्रीय मरकार, उक्त ग्रीधिनयम की घारा 17 की उपधारा (2क) बारा प्रवन्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ग्रीधिमूचना संख्या का. श्रा. 3713 तारीख 15-9-1983 के ग्रनुसरण में और इसरो उपायद्ध प्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के ग्रधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 1-10-1986 से तीन वर्ष की श्रविध के लिए जिसमें 30-9-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

श्रनुमूची

- उस्त स्थापन के सम्बन्ध मे नियोजन प्रादिशिक भविष्य निधि प्रायुक्त उड़ीसा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम को धारा 17 की उप-धारा 3(क) के खण्ड (क) के प्रधीन ममय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक वीसा स्कीम के प्रशासन में, जिसके प्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवर्णायों का प्रस्तुत किया जाना, वीगा शिमियम का सन्दाय, लेखाओं का ग्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का मन्दाय भ्रादि भी है, होने वाले मभी व्ययों का बहुत नियोजक हारा किया जाएगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा प्रनुमोदित सामृहिक कीना स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी एनमें स्लोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति सथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का प्रनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदिशित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मघारी, जो कर्मघारी भविष्य निधि का या उक्त श्रिधिनियम के श्रिधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीय के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त धर्ज करेगा और उसकी बावत श्रायश्यक श्रीमियम भारतीय जीवन वीमा निगम की सन्दत्त करेगा।
- 6 यदि साम्हिक बीमा स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्द फायदे बड़ाये जाते हैं तो, नियोजक उनत स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों मे समुचित का मे वृद्धि की जाने की ध्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के जिए सामूहिक बीमा स्कीम के श्रयीन उपलब्ध फायदें उन फायदों मे श्रधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के श्रधीन श्रनुकों। है।

- 7. सामूहिक बीमा स्काम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु परं इस स्कीम के प्रधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती है जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोक्त कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती का प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के प्रन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संणोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त उड़ीसा के पूर्व श्रनुगोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संणोधन से कर्म- चारियों के हित पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ने की सभावता हो यहां, प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, श्रपना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मनारियों को श्रपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बामा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाते हें, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणबा, नियोजक भारतीय जीवन वीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में भसफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उन्त स्कीन के प्रन्तर्गत होते, वीमा फायदो के सन्दाय का उत्तरशायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कोम के ग्रधीन ग्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हक्त र तानिर्देशिनी/विधिक वारियों को उस राशि का सन्दाय नत्नरता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावें की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सक्या एस-35014/161/82-पी. एफ. 2/एस. एस.-2]

S.O. 2047.—Whereas Messrs Industrial Development Corporation of Orissa Limited, Sardar Patel Hall, Bhubaneshwar (OR|294) (hereinatter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of I ife Insurance which are more favourable to such employees that the benefit admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation contact the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3713 dated the 15-9-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-10-1986 upto and inclusive of the 30-9-1989.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Orissa and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All Expenses involved in the administration of the Group I surance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall inimediately enrol him as a membes of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits amissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Orissa and where any amendment is likely to affect adversely the interst of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving the approval, give a reasonable opportunity to the employers to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered

under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal Bers of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/161/82-PF-II-SS-H]

का. ग्रा. 2048— मैसर्स जबरायल इन्डिया लि., एम-304, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, मुलुन्द, बाम्बे-100081 (एम. एच. /5817) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रिधित्यम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त ग्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के श्रिधीन छूट दिए जाने के लिए ग्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय भरकार का समाधान हो गया है कि उक्स स्थापन के कर्मचारी कियी पृथक ग्रिवाय या प्रीमियम का सन्दाय किए विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से प्रधिक प्रमुक्त हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन अनुभेय है;

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त मिधिनियम की धारा 71 की उपधारा (2क) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की मिधिसूचना संख्या का. भा. 3505 तारीख 18-9-1982 के मनुसरण में और इससे उपायद्ध प्रनुसूची में विनिर्दिष्ट गर्तों के मधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 2-10-1985 से तीन वर्ष की मबिध के लिए जिसमें 1-10-1988 भी यम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है।

ग्रनुसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भिविष्य निधि श्रायुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भैजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निरिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की ममाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के श्रधीन समय-समय पर निविष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके ग्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का ग्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का मन्दाय ग्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा धनुमोदित सामूहिक बीमा रकीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मजारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुबाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदिश्यत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त श्रिधिनियम के श्रिधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम नुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबन ग्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों मे ममुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन धनुन्नेय हैं।
- 7. सामूहिक वीमा स्कीय में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सन्देय रकम उस रकम से कम हैं जो वर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के भ्रन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, श्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व श्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, श्रपना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को ग्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा ।
- 9. यदि किसी कारणश्रम, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिमे स्थापन पहले अपना खुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण, नियोजक भारतीय जीवन श्लीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में श्रसकल रहता है, और पालिसी को व्ययगत श्ली जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 1.1. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी क्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिवें-

शितियों या विधिक वारिसों को जो र्याद यह छूट न वी गई होती तो उक्त रकीम के भ्रन्तर्गत होने, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्य नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के श्रधीन म्राने वाले किमी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जं पन बीमा निगम, बीमाकृत राणि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसो को उस राणि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दणा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/152/82-पी.एफ.-2/एस. एस.-2]

S.O. 2048,—Whereas Messrs Gabrial India Limited S-304, Lal Babadur Shastri Marg, Mulund, Bombay-400081 (MH|5817 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of primum, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more tavourable to such employees that the benefit admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3505 dated the 18-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 2-10-1985 upto and inclusive of the 1-10-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, Direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Comporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the

benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissiner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Cyporation of India. and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefit; to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

INO S-35014/152/82-PF.H-SS III

का ग्रा. 2049. — मैंसमें फैनर (इंडिया) लि, 19/21 मनोहर दास स्ट्रीट, जी. पी. ओ. के सामने, बस्बई—400001 (एम. एच./14567) (जिमे इसमें इसके पण्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कमेंचारी भविण्य निधि और प्रकीणं उपबन्ध श्रिधिनयम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त श्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के श्रिधीन छूट दिए जाने के लिए श्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से ग्रधिक ग्रन्कूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के ग्रधीन ग्रनुजेय है;

ग्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ग्रिधिसूचना संख्या का. मा. 29 तारीख 6-12-1982 के मनुसरण में और इसमें उपायद भनुसूची में विनिर्दिष्ट गतों के मधीन रहुते हुए उक्त स्थापन को, 1-1-1986 से तीन वर्ष की मवधि के लिए जिसमें 31-12-1988 भी सम्मिलत है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट वेती है।

भ्रनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक शिवच्य निधि भ्रायुक्त महाराष्ट्रा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए क्ष्मि सुविधाएं प्रधाम करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक सास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खंड (क) के प्रजीन समय-ममय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गंत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय ग्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजन द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा भ्रानुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बानों का अनुवाद स्थापन के सूचना पटट पर प्रदिश्चित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त श्रिधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिविष्य निधि का पहले हो सदस्य है, उसके स्थापन में नियो-जित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के ग्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों मे समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों मे ग्रधिक ग्रनुक्ल हों, जो उक्त स्कीम के ग्रधीन ग्रनुक्त हैं।
- 7. सामृहिक बीसा स्कीस में किसी यात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारों की मृत्य पर इस रकीम के अधीन संदेय रकम उस रकम में कम है जो कर्मचारी को उय दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता क्षो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामनिर्देशियों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के वरावर रकम का संदाय करेगा।

- 8 सामृहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व श्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्म-चारियों के हिंत पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त, ग्रपना भ्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रमना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त ग्रवसर देगा।
- यदि कि डी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निर्गैम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भ्रपना चुका है, श्रधीन नहीं रह जाते हैं या उस स्कीम के प्रधीन कर्मजारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति मे कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द को जा मकती है।
- 10 यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में भ्रमफत रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिकम की दणा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्दे-∵ शितियों या विधिक वारियों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
 - 12. इस स्कीम के ब्रधीन ब्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राणि के हकदार नामनिर्देशिकी विधिक धारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से ऑर प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर मुनिश्चित करेगा।

[मंख्या एम-35014/348/82 - पी. एफ. 2/एस एस-2]

S.O. 2049.—Whereas Messrs Fenner (India) Limited, 19/ 21, Manohardas Street, Opp. GPO, Bombay-400081 (MH/14567), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of primum, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefit admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme); under the

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of Section 17 of the said Act and in continua-tion of the Government of India in the Ministry of I abour, S.O. 29, dated the 6-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Govern-ment hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 7-1-1986 upto and inclusive of the 31-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

ment may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, Direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns navment of insurance premia, transfer submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the said features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits amissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest employees, the Regional Provident dent Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to nay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is ollowed lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased memehers who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

- कर. ए 2009 -- कनी इक्टकार को गर्प पिर होता है क निस्नितिखित त्यापन से सप्तक वियोजक और कर्मधारियां की बहु संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मधारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन की लागू विये जाने चाहिए --
- मैसर्स दा प्रिन्टर्स इंजिनियरिंग कपनी, प्लाट न.
 27ए, सैक्टर-25, बल्लभगढ ।
- 2. मैसर्स हरमन डीजल सर्विस, हम्बो हाउस रनधीर लेन. करनाल और इसकी 224 घरबन एस्टेट 11, हिसार स्थित शाखा ।
- 3. मैसर्म रिसर्च-एन-सेल्म सेटए एम-2 इंडस्ट्रियल एरिया, सोनीपत और इसका 1-62, कनाट सर्कम, नर्ड दिल्ली स्थित मुख्य कार्यात्त्वर ।
- 4 मैंसर्म हरियाणा शीट ग्लास ग्राम सेवली पोस्ट ग्राफिस राई कस्वा सोनीपत और इमका करोल बाग, नई दिल्ली स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय तथा ग्रलग-अलग जगह स्थित 10 शाखाएं।

श्रतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त श्रिधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करनी है।

[संख्या एस - 35019(27)/87 - एस एस - 2]

- S.O. 2050.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the tollowing establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—
 - 1. M/s. The Printers Engineering Company, Plot No. 27-A, Section 25, Ballabgarh.
 - 2 M/s. Harman Diesel Service, Hambo House, Randhir Lane, Karnal including its branch at 224, Urban Estate-II, Hissar,
 - M/s. Research-N-Sales Centre, M-2, Industrial Area, Sonepat including its Head Office at 1-62, Connaught Circus, New Delhi.
 - 4 M/s. Haryana Sheet Glass Limited, Village Sevli, Post Office Rai, District Sonepat, including its Registered Office at Karol Bagh, New Delhi and ten branches at different places.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by a thesection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[\$-35019 (27)/87-SS-II]

का न्ना 2051—केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि निम्नालिखन स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की विष् रित्या इस बात पर सह्मत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निध्य सीर प्रकीर्ण उपबन्ध श्रीधनियम, 1952 (1952 679 GI, 87—14

- का 19) के उपबन्ध संबंधिल स्थापन को सागू किए जाने
- मैसर्स टिफिन रूम "स्पेशल ब्यूरी भारत सरकार" उंजस्ट्रियन अगुरेन्श जिल्डिंग द्वित्यि मंजिल चर्च गेट, वम्बई-20।
- 2 मैंसर्स श्रडक्लरटाईजिंग कन्मेशनरीं प्राईवेट लिमिटिङ, 602 मेंकर चैम्बर, 5 नारिमन प्याईट, बम्बई-21।
- 3 मैंसर्स टावर इंगोरेन्स एंड रिष्ट्रणारेन्स सर्विसिज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 7/5 मेकर चैम्बरस, 5 नारिभन प्वार्डट, बस्बर्ड-21।
- 4 मैंसर्स भ्रशयनी कुमार एउ कंगनी, 4ए, कीम चैंम्बर्स प्रथम मंजिल प्रम्बालाल दोषी मार्ग (हमाम स्ट्रीट) फोर्ट, बम्बर्ट-23।
- 5. मैंसर्म त्रिमृति द्रैवल्स एंड टूर्म प्राईबेट लिमिटेड, णाले विल्डिंग, 28 बैंक स्ट्रीट, बम्बई-23 ।
- मैं सर्स डिपार्टमैन्ट्स स्टाफ कैन्टीन कन्ट्रोल्स श्राफ डिफेन्स श्रकाउट नैवी (नाभी), कपरेज रोड, बम्बई-39।
- 7 मैंसर्स श्री ज्योतीर लिंग पाणी, परवता सेवा सहकारी संस्था सर्वादित कृणिटे ताल्ल्क पन्हाला जिला, कोल्हापुर।
- 8. मैंसर्स ग्राप जे ग्रासोसिएटस (इजीनियर्स) प्राईवेट लिमिटिड, एक्सल स्टेट, एस वी रोड, गोरे गांव (पश्चिम) बस्बई-62 और इसका बस्बई-54 स्थित रिजस्टर्ड कार्यालय तथा बस्बई-21 स्थित एक युनिट ।
- 9 मैंसर्स स्मृति इंटर प्राइजिज (फैक्ट्रो) 51, सिद्धपुर इडस्ट्रियल स्टेट मासराती लेन कुर्ला, बम्बई-70 और इसकी बम्बई-36 स्थित णाखा ।
- 10. मैंसर्स प्रलंडाड फर्मा प्लांट 235 जबाहर को-ओपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेंट कामटे और इसका बम्बई-50 स्थित प्रणासनिक कार्यालय ।
- 11 मैं मर्स श्री सीष्ठम प्राईवेट लिमिटेड, मोन्धा पोस्ट ग्राफिस, मोन्धा रोष्ठ, औरंगाबाद-1 और इसकी (1) हैदराबाद (2) जयपुर (3) ग्रारमूर (श्राध्न प्रदेश) (4) लाट्र (5) बेलरी (6) इंटीर स्थित छ शाखाएं।
- 12. मैंसर्स श्री नारायण ध्रारगनिक्स प्राइवेट लिमिटिड प्लाट न. 70 तलोजा जिला रामगढ और इसका 9 महा-राष्ट्र स्टेट को-ओपरेटिव बैंक बिल्डिंग, नागिनदास मास्टर रोड, एक्सटेन्शन फोर्ट, बम्बर्ड-23 स्थित कार्यालय ।
- 13. मैं मर्ग ग्रारट्रीए कन्मलटेन्ट कपनी लिमिटिङ दितीय मंजिल शीयाट महल, 463, डा. ग्रनीवस्त रोड, सम्बर्ध-25 ।
- 1.4 मैसर्स रीलको पेपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटिङ, वस्बई-31 ऑर डेसका 7 कुम्बरा स्ट्रीट, वेलाई १टेट, बस्बई -58 रिथन कार्यालय ।
- 15 मैंसर्स ग्राफिस ग्राफ दी ट्रस्टीज पान्सी पंचायत फड्स एंड प्रापर्टीज, 209 दादा भाई नौरोजी रोड, फोर्ट

बम्बई-1 और इसकी (1) खरेघाट कालोनी हुयग्स रोड बम्बई (2) पारूख धर्मभाला (3) डूंगरवाडी (4) पारसी पंचायत की भ्रालग-भ्रालग कालोनियों में स्थित शाखाएं।

16. मैमर्स गैमको सिस्टम्स इंडिया प्राईवेट लिमिटिड गैसको हाऊस ए-30 भ्राभीमनसरी सोसाइटी, पासान रोड, बी बी नं. 2, एन सी एल पोस्ट पूना-8।

17. मैंसर्स भोलानाथ इंजिनियरिंग वर्क्स युनिट नं. 11 केमब्रोस इंडस्ट्रियल स्टेट सोनापुर लेन श्राफ एल बी एस मार्गे, भान्डप, बम्बई-78।

श्रतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, को उग्न-ारा 4 द्वारा प्रवत्त मिन्तयों का प्रयोग करते हुए उक्त श्रिधिनियम के उपन्यन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एस॰-35018(2)/87 - एस॰ एस॰ 2]

S.O.2051.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—

- M/s. Tiffin Room Special Bureau Government of India Industrial Assurance Building, 2nd Floor, Charch Gate, Bombay-20.
- M/s. Advertising Concessionaries Private Limited, 602, Maker Chamber No. 5, Nariman Point, Bombay-21.
- M/s. Tower Insurance and Reinsurance Services (India) Private Limited. 7/5. Maker Chambers, 5, Nariman Point, Bombay-21.
- M/s. Ashwini Kumar and Company, 4-A, Karim Chambers, First Floor Ambalal Doshi Marg (Hamam Street) Fort, Bombay-23.
- M/s. Trimurti Travel and Tours Private Limited, Shale Building, 28, Bank Street, Bombay-23.
- M/s. Departmental Staff Canteon. CO (Nevy), (Nabhi) Cooperage Road, Bombay-39.
- M/s. Shree Jyotir Ling Pani Purvathaseva Shakari Sanstha Maryadit, Kushire, Taluka Panhala, District, Kolhapur.
- M/s. R. J. Associates (Engineers) Private Limited, Excel Estate. S. V. Road, Goregaon (W) Bombay-62, including its Registered Office, at Bombay-54 and Bombay-21.
- M/s. Smiritl Enterprises (Factory) 51, Sidhpura, Industrial Estate. Masrani I ane, Kurla, Bombay-70 including its branch at Bombay-36.
- M/s. Allied Pharma Plot 235, Jawahar Co-op. Industrial Estate, Kamothe Panvel, Kolaba, including its branches at Bombay-50.
- M/s. Shree Seeds Private I imited. Mondha Road. Aurangabad, including its six branches at
 Hyderabad (2) Jaipur (3) Armoor (A.P.)
 Latur (5) Bellary (6) Indore (M.P.).
- 12. M/s. Shri Narayan Organics Private Limited, Plot No. J170, M.I.D.C., Industrial Estate Taleja District Raigad-8 including its offices at 9. Maharashtra State Co-operative Bauk Building Nagindas Master Road, Extension Port, Bombay-23.
- M/s. Austrind Consultants Company Limited, Second Floor, Ceat Mahal, 463, Dr. Annie Besant Road, Bombay-25.

- M/s. Recico Paper Products Private Limited Cross Road, Wadala, Bombay-31, including its office at Bombay-38.
- M|s. Office of the Trustees of the Parsi Panchayat Funds and Properties, 209, Dadabhai Naroji Road, Fort, Bombay-1 including its branches
 - (1) Khareghat Colony Huges Road, Bombay,
 - (2) Parukh Dharamshala (3) Doongerwadi
 - (4) Different Colonies of Parsi Punchayat.
- M/s. Gaco Systems India Private Limited, Gaco House, A-30, Abhimanshree Society, Pashan Road, B. B. No. 2, NCL Post, Poona-8.
- Ms. Bholanath Engineering Works, 11, Kembros Industrial Estate, Sonapur Lane, Off L.B.S. Marg, Bhandup, Bombay-78.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35018(2)/87-SS-U]

- का. द्या. 2052—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए:—
- 1. मैसर्स महानग्र टेलीफोन निगम लिमिटिड, (भारत सरकार का एक उपक्रम संचार। मंत्रालय) कनिष्का प्लाजा, तृतीय मंजिल 19 अणोक रोड, नई दिल्ली-1 और इसका (1) पंजीकृत कार्यालय और दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय खुर्शीद लाल भवन, जनपथ नई दिल्ली-50 (2) बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय टेलीफोन भवन, कोलाबा बन्बई-5 तथा (3) दिल्ली और बम्बई स्थित दूसरे कार्यालय और स्थापन;

श्रतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनो को लागू करती है।

[गंख्या एस०-35019(31)/87 - एस. एस०2]

- S.O. 2052.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—
 - M/s. Mahanagar Telephone Nigam Limited, (A Gevernment of India Enterprises, Ministry of Communications), Kanishka Plaza 3rd Floor, 19 Ashoka Rond, New Delhi-1, including its (1) Registered Office and Delhi Circle Office at Khursheed Lal Bhawan, Janpath, New Delhi-50 (2) Bombay Circle Office at Telephone Bhawan, Colaba, Bombay-5 and (3) the attached offices establishments in Delhi and Bombay.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Centra Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

का. भा. 2053:——सैंसर्स फैंडरेशन ग्राफ इंडिया चैंग्बर्स ग्राफ कामणे एंड इंडस्ट्रीज, फैंडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई विल्ली—1 (डी.एल./3553) (जिसे इसमें इसके पण्पात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध ग्राधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त ग्राधिनियम कहा गया ह) की धारा 17 की उपधारा (2क) के ग्रधीन छूट दिए जाने के लिए ग्रावेदन किया है:

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किमी पृथक श्रिभवाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उटा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इमके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं।

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रिधिसूचना संख्या का. श्रा. 4585 तारीख 28-11-1983 के श्रनुसरण में और इससे उपावद्ध श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के श्रधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 17-12-1986 से तीन वर्ष की श्रविव के लिए जिसमें 16-12-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

श्रन्सूची

- 1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्वीम में प्रशासन में, जिसके श्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा श्रीमियम का मंदाय, लेखाओं का श्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय ग्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, रथाान के स्थना-पट्ट रिंग प्रविधित करेगा।

- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामृहिक सीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवष्यक श्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से श्रधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के श्रधीन श्रनुज्ञेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के श्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के श्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामनिर्देणिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के श्रन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, देहली के पूर्व प्रतुमोदन के विना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म- वारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि, श्रायुक्त श्रथना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाने फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में घ्रसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत पदस्यों के नामनिर्दे-णितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती ता उसन स्कीम के श्रन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उनुरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वग्ले किसी मदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन वीमा निगम, बीमाकृत राशि के

हमधार नामनिर्देशिती/विधिक बारिसों को उस राशि का मंदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावै की प्रप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/285/83-पी एफ 2/एस एस-2]

S.O. 2053.—Whereas Messis Lederation of India, Charabers of Commerce and Industry, Federation House, Tansen Marg, New Delhi-110001 (DL/3553) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4585 dated the 28th November, 1983 and sub-incit to the conditions agreeifed in the Schedule agreed beauty ject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 17th December, 1986 upto and inclusive of the 16th December 1989 ber, 1989.

SCHEDULE

- 1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be horne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient fea-tures thereof, in the language of the majority of the em-
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India poration of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to attect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/285/83-PF, II-SS, 11]

का.ब्रा. 2504 —मैसर्म, नेशनल इन्स्ट्रू मैण्टम लि.,1/1 🖁 राजा एम.सी. मलिक रीड, कलकत्ता–32 (डब्ल्यू वी./ 1752) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध श्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त प्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के ग्रंभीन छूट दिए जाने के लिए शाबेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए जिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन भीमा स्कीम को सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से प्रधिक ग्रन्कूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमे इसके परचात उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन अन्ज्ञेय हैं ,

भ्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रक्षिनियम की धारा **1**7. की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए ओर भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ग्रक्षिसचना संख्या का.ग्रा. 318 तारीख 6-1-1984 के ग्रनसरण मे और इससे उपाबद्ध श्रन्मुची में विनिर्दिष्ट शर्नों के श्रधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 28-1-1987 से तीन वर्ष की ग्रवधि के लिए जिसमें 27-1-1990 भी सम्मिलित है. उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है ।

ग्र**न्**स्ची

- 1 उनत स्थापन के मंबन्त में नियोजक प्रादेशिक अविष्य निधि भ्रायुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेंगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार ममय-ममय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खंड (क) के श्रिधीन ममय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके श्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय लेखाओं का श्रन्तरण. निरीक्षण, प्रभारों का संदाय ग्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा स्रनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का श्रनुबाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त दर्ज करेगा और उमकी बाबत ग्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की संदस्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाते है तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित स्प सं वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के श्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उवत स्कीम के श्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के श्रन्तर के बराबर का संदाय करेगा।
- 8 सामूहिक क्काम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भित्रय निधि शानुकत पश्चिम शंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी

- संशोधन ने कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि, भार्युवन, अपना श्रनूमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टि-कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, की उस गामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवर्ण, नियोजक भारतीय जीवन त्रीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में श्रसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती हैं।
- 11. निरोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देगितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के प्रधीन भ्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संवाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण वाये की प्राप्ति के एक माम के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/302/83-पी. एफ. 2/एम एस-2]

S.O. 2054.—Whereas Messrs National Instruments Limited, 1/1, Raja S. C. Mullick Road, Calcutta-32 (WB/1752) (heremafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 318 dated the 6th January, 1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 28th January, 1987 upto and inclusive of the 27th January, 1990.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall automat such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such tacilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Calcutta and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the I ife Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member cuttled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/302/83-PF II-SS-II]

का .श्रा. 2055.— मैसर्ग यूनिवर्सल इण्डस्ट्रीज, 23, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गोविन्दपुरा भोपाल (एम.पी /2073), (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ते कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपलब्ध प्रधिनियम, 1952 (1959 का 17) (जिसे इसमें इसके पण्चात उक्त श्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपलब्ध परिवास के बिधिस हुए दिने जाने के लिए प्रविद्य किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्राभिदाय या प्रीमियम का लंदाय किये बिनाही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक वीपा स्कीम के ग्राधीन जीवन बीमा के रा में फायदे उठा रहे हैं और ऐस कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से श्रिधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहयद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे अममें इसके पण्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के ग्राथीन उन्हें अनुजेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उनधारा 2क द्वारा प्रदत्त पक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्ती के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है।

श्रन् सूची

- 1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाये प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्विष्ट करें!
- 2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क के खंड (क) के ग्रधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सागूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके भ्रन्तर्गत वेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का मंदाय, लेखाओं का भ्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय ग्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक हारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें राशोधन किया जाये, तब उस मंगोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पहुषर प्रविशत करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम नुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावत श्रावन्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उन्नत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन एसद्दा ने अधिक अनुकूल ती जो उन्हें स्वरीम के अधीन अनुक्षेय है।

- 7. सामूहिक नीमा एकीप में कियी मान के होते हुए घी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस रकीम में अधीन अदेय रकम उस रक्स से कम हैं जा कर्मचारी की उस दशा में सदेय होगी जब यह उक्त रकीम के मधीन होता तो, नियोजक कर्यचारी है विविध वारिस/नाम निर्वेधिनी की प्रतिकर के क्य में दोनो रकमा के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपवन्धों में कोई भी सणोधन प्रावेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त मध्य प्रदेण के पूर्व अनुमौदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन ने कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की सभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त श्रपना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-यवत श्रथगर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले ग्रपना चुका है ग्रधीन नहीं रह जाना है या इस स्कीम के ग्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाल फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवंश नियोजक उस नियम नारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने मे श्रसफल रहता है और पालिमी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक तारा श्रीमियम के सदाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशि- तियों या विधिक वारियों को जो यदि वह छूट न वो गई होती तो, उक्त स्कीय के श्रन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के प्रश्नीन ग्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके तकदार नामनिर्देशितियों/विधिक बारसो को बीमाकृत रक्तम का सदाय तत्परना से आर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रक्तम प्राप्त होने के एक मास के भीनर निश्चित करेगा।

[मस्या एम-35104(66)87-एसएस-2]

S.O. 2055.—Whereas Messrs Universal Industries, 23. Industrial Estate, Govindpura, Bhopal, (MP/2073) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act. 1052 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of the Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the mid Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the pro-isions of the said Scheme for a period of three years

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month
- 3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 5 here as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features the eof in the language of the majority of the employees
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view
- 9 Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and due the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but grant of this exemption, shall be that of the employer
- 12 Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure mempt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one mouth from the receipt of them complete in all coxet

का.शा. 2056. — पैसर्स आर्डन फैबीकेट्रज, 37-ए, इस्डप्-ट्रीयल एरिया गोबिक्दपुरा, भोषाल (एम पी /२०३०) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमे इसके पण्चात् उक्त ग्रधिनियम कहा गया है) की धारा 12 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिये जाने के लिए श्राबेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्स स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रीभवाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के ख्य मे फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायवों से प्रधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें श्रनुक्षेय हैं.

भत केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के श्रिधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की ग्रबधि के लिए उक्त स्काम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में हुट देती हैं।

ग्रनुसुची

- 1 उक्त रथापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भिविष्य निधि, श्रीयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा नथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाये प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3 क खण्ड-क के श्रधीन समय-समय पर निर्दिट करें।
- 3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके श्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवर्णायों का श्रम्मुत किया जाना बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों भादि भी है, होने वाले बाले सभी यय का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएग ।
- 4 नियोजन, केन्द्रीय मरकार द्वारा श्रनुमोदिन सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें मंशोधन किया जाये, तब उस मशोधन को प्रति तथा कर्म-चारिया की बहुगख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का श्रनुबाद स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी मिविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन नो भिबाय निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन मे नियोजिन विया जाता है तो नियोजन सामूहिक बीमा र्नीम के सबस्य के रूप में उसका नाम मुरुन्त दर्ज करेगा और उसनी

भावतः प्रावश्यकः श्रीपियम भारतीय जीवल बीमा निश्न को नंतरः कर्शनाः

- 6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाते हैं तो, नियोजक मामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि किये जाने की ब्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्वीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रश्नीन सदेय रक्षम उस रक्षम से कम ई को कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो. नियोज इक्मचारी के विधिक/वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनो रक्षमों के अन्तर के बरावर रक्षम का संदाय उरेगा।
- 8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोधन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि भायुक्त प्रभान प्रनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण ग्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मकारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिमे स्थापन पहले श्रपना चुका है भ्रधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह रह की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख़ के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करन मे असफल रहता है और पालिमी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11 नियोजकं द्वारा प्रीमियम के गवाय में किये गये किसी व्यतिष्मम की दणा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्दे-शितियों या विधिक बारिमों को जो यदि यह छूट न दी गर्ड होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के सदाय का उन्तरदायिन्व नियोजक पर होगा।
- 12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोगित देश स्कीम के स्थित श्रामें वाति शिरी जदस्य की जन् होने प उक्ति हकदार नाम निर्देशि शिं/बिधिक वारिसा के 4 माहा रकेम के स्थाय तत्परता से और प्रत्येक देशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाहत रकेम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिष्यित करेगा।

[भ. एस-35014(67)87-एस एस 2]

5.O. 2056.—Whereas Mossrs. Modera Fabricators, 37-A, Industrial Area, Govindpura, Bhopal-462023, (MP/2050) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscollaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specied in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Funds Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the etablishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features the eof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is "Iready a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. No, withstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regonal Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer mapayment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensurance prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(67)/87-SS.II]

का. ग्रा. 2057:—मैंसर्ग दि एम. पी. स्टैट माइ-निंग कारपोरेशन लि., प्लाट नं. 229, जोन-1, महा-राणा प्रताप नगर, भोपाल (एम. पी./1445) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मजारी भविष्य निधि और प्रकीणं उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 का (1952 17) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त ग्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के ग्रिधीन छूट दिये जाने के लिए भावेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्रभिदाय या प्रीनियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की , सामूहिक बीना स्कीम के ग्रजीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे . उन फाउदों से ग्रविक ग्रनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध जीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चान उक्त स्कीम कहा गया है) के ग्रधीन उन्हें ग्रनुक्षेय है;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करो हुए और इसमे उपाबद्ध श्रनुमूची में विनिर्दिष्ट शर्तो के श्रश्नीत रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्षे की श्रप्रधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

ग्रन्युची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त मध्य प्रदेश को एसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोधण के लिए ऐसी सुविधायें प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, सन्नय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3क के खण्ड-क के ग्रिधीन समय-समय पर निर्दिश्ट करें!

- 3 सामृहिक धीना स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का भ्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय भ्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा धनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संगोधन किया जाय, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की वहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुसाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मनारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रतीन छट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उपैके स्थापन भें नियोजिन किया जाता है तो, नियोजन सामृहिक बीमा स्कोम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन वीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ायें जाते है तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सत्मिहक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध पायदे उन फायदों से शक्षिक धन्कूल हो जो उक्त स्कीम के प्रधीन ध्रनज्ञेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में कियी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम ने प्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस देशा में संदेप होती जब वह उदन स्कीम के प्रधीन होता तो, नियांजक कर्मचारी के विधिक बारिम/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के प्रत्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मणोधन प्रादेशिक भविष्य निधि स्नायुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मवारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की सम्नावना हो, वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना श्रनुसोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भ्रयसर देगा।
- वि किसी कारणवंश स्थापन के कर्मवारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामुहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, सो यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियंत तारीख भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे,

- प्रीमिनक का संबाय करने में असकल रहता है और पालिसी की व्यवगत हो जाने दिया जाना है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संबाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उल मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियों या विधिक वारिसों को जो ,यदि यह छूट न दी गई होती तो, उबत स्कीम के अन्तर्गत होते। श्रीमा फायदों के संदाप का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के पार्धीन धाने वाले किसी सदस्य की सृत्य होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विश्वित वारिनो को जीपाकृत रक्तम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस. 35014/(68)/87 - 8 एस. -2]

S.O. 2057.—Whereas Messrs. The M. P. State Mining Corporation Limited, Plot No. 229, Zone 1, Maharana Pratap Nagar, Bhopal (M.P./1445) (herematter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident I unds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month,
- 3, All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance piemia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in

his establishment, the employer shall immediately entol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Iusura ce Corporation of India.

_ _ +2+ --

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Greup Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(68)/87-SS.II]

का. श्रा. 2058:— मैसर्स पिको इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्री-कलज लि., लूमिनेयर सेन्टर, पी-65, तारा टोला रोड, कलकत्ता-700088 (डब्ल्यू. बी./15706) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क्) के प्रधीन छूट दिये जाने के सिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी वृषक धिभदाय या प्रीमियम का संदाय किये विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू-हिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे क्मंचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से भिश्वक भनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम बहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजेश हैं,

ान : केन्द्रीय सरकार, उन्त प्रधिष्यिम की भारा 17 की उपधारा 2 क हारा प्रदत्त एक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध प्रमुश्ची ने त्रिनिर्दिष्ट गर्ता के श्रयीन रहते हुए उन्त स्थानन को तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उपन ग्रवीन स्कीम के सभी उपबन्धा के प्रवर्गन से छूट देती है।

धनुसूर्वा

- 1. उन्न स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भनिष्य निधि श्रायुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-पर्मय पर निदिश्य करें।
- 2 नियोजक, ऐसे निरोक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3 क के खब्ड क के प्रधीन यमय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके ब्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का भ्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारो संदाय भ्रादि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक वीमा स्कोम के नियमों की एक प्रति जब कभी उनने संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मवारियो की बहुमंग्रमा की भाषा ने उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के मूचना भट्ट पर अदिशित करेगा ।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त श्रिधिनियम के ग्रिधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजित सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत ग्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के ग्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के भ्रयीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाते की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उम फायदों से श्रधिक ग्रनुकूल हीं जो उक्त स्कीम के श्रधीन ग्रनुक्य हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी वात के होते हुए भी यवि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के ध्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब दह उक्त स्कीम के श्रधीन होता तो,

नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रति-कर के रूप में दोनों रकमों के प्रन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोध्यन प्रादेशिक भिवष्य निधि श्रायुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व धनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भिवष्य निधि प्रायुक्त अपना प्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीया निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले श्रपना चुका है ग्रधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियस तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में मसफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीभियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशि- तियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, ,उक्त स्कीम के भन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के भ्राधीन भ्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक-दार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस.-35014 (69)87-/एस. एस-2)]

S.O. 2058.—Whereas Messrs Peico Electronics and Electricals Limited, Luminaire Centre, P-65, Tara Tolla Road, Calcutta-700088 (WB/15706) (hereinafter referred to as the establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said estblishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premlum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legel heirs of deceased members who would have been covered under the said but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

का. ग्रा. 2059 :—मैसर्मे—एम. पी. उर्जा, विकास निगर ंग्ल, "बी" स्लोक, जी. टी. बी. कम्पलैक्स, भोपाल-462003, (एम. पी./5186) (जिसे इसमें इसके पल्चान् उक्त स्थानन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पल्चान् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के प्रधीन छूट दिये जाने के लिए धाबेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उपत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्रिभदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के भ्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं आर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से ग्रधिक श्रनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के ग्रधीन उन्हें श्रनुक्रेय हैं,

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त भिधिनयम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इतमे उपावढ अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षतों के प्रधीन रहते हुए, उन्त स्थापन की तीन वर्ष की भवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

श्रनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि धायुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीगियम का संदाय, लेखाओं का श्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय ग्रादि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा धनुमोदित सामहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें मंशोधन किया जाये, तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुबाद स्यापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उनत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसकें स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तूरन्त दर्ज करेगा और उसकी

बावत प्रावण्यक श्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

- 6. यदि उनत स्कीम के ग्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फारदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के भवीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाते की व्यवस्था करेगा जिसरों कि वर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से श्रधिक अनुकूल हो जो उनत स्कीम के ग्रधीन अनुक्षेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किमी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के श्रधीन संदेय रक्तम उस रक्तम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संतेय होती जब वह उक्त स्कीम के श्रधीन होता तो, नियोजक कर्मनारी के विधिक बारिम/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धा में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि भायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व भनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कमचारियों के हित पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, यहां प्रारेशिक भविष्य निधि भायुक्त भपना भनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किनी कारणवण स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले श्रपना चुका है श्रधीन नही रह जाता है या इस स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, श्रीमियम का संवाय करने में श्रसफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी
 ातिकम की देशा उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों था
 विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो,
 उक्त स्कीम के प्रन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का
 उत्तरदायित्य नियोजक पर होगा।
- 12. उपत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के भ्रधीन भ्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेणितियों/विधिक वारिसों की वीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर मृत्यिकत करेगा।

[संख्या एस.-35014(70)87-एस. एस.-2]

S.O. 2059.—Whereas Messrs M. P. Urja Vikas Nigam Limited, "B" Block G.T.B. Complex, Bhopal (MP/5186) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Source as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable approval, give a reasonable approval, their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not temain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is hable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominces or the legel hears of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S. 35014/70/87-SS.II]

का. म्रा. 2060 ----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मधारियों की बहुमंख्या इस बात पर महमन हो गई है कि कर्मधारी निविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध म्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने धाहिए:---

- मैसर्स रासी एण्ड कम्पनी, 61 मदुराई रोड, तिरूचिरापन्ली-8
- मैं मर्स मुपर गेपर्स, डी-57 एण्ड 58 डबलपमेंटस, इन्डस्ट्रियल स्टेट युबाहुदी तिरूविरापल्ली-15
- 3 मैसर्ग प्रभात विविग फैक्ट्री पोस्ट बाक्स 73, राधवेन्द्रा चैरिपर स्ट्रीट कोमरापालायाम-183, सेलम कस्वा
- 4. नैसर्स श्री विद्या मन्दिर हायर सैक्डरी स्कूल ग्रानन्द श्रमरामम मिथानूर रोड, सेलम-4
- 5. मैसर्स मुथ्यु कुमार इन्जिनियरिंग वर्क्स रामलिगपुरम पोस्ट श्राफिस करीपदी (वाया मेलम-6)
- 6. मैंसर्स ग्रार राजन इण्डियन ग्रायल कारपोरेशन डीलर 108, वैकटेसापुरम पेक्सनवालूर त्रिची कस्बा
- मैसर्स विची इंजीनियरिंग वर्क्स डी-118, डबलपड प्लाट स्टेट ध्वा कुडो, विची-15
- मैंसर्स श्री लंधमी विलासम प्रेस, मद्रास ट्रंक रोड,
 8ए न्यू कालोनी संतूर
- 9. मैसर्स श्री लक्ष्मी बार्टिङग वर्ष्स, 8वीं न्यू कालोनी संतूर-203
- मैसर्न मैपको सचलैक इंजीनियरिंग कालेज, शिवाकाशी-124

- 11 मैसर्स की मुख्यानुनार काटन प्रेमिस फैस्ट्री, 65,- - वालीपालायाम रोट, विचुर-601
 - 12 मैं सर्व एच. एम. हाजी मूमा, 1/69 गोदाम स्ट्रीट, मद्रास-1
 - 13. मैंगर्स पी एएड ब्राई सर्विस माफ इन्डिया नं. 48, राजाजी सलाए तृतीय मणिल, महास-1
 - 14. मैसर्म दी तिमलनाडु बैकवई क्लास इकोनोमिक डबलनमेन्ट कारपोरे शर्न लि., नं. 807 (पांघवीं मंजिल) श्रन्नायलाए, मद्रास-2
 - ग्रेसर्ग दी तमिलनाडु बैकवर्ड क्लास इकोनिमक उवलपमेन्ट कारपोरेकन थि., नं. 807 (पांचवीं मंजिल) ग्रभासलागं, मद्रास-2
 - नैससं फुल्लर के० सी०पी० लि., 183 माऊन्ट रोड, मद्रास-6
 - 17 मैं समें इलैंक्ट इन्लिनियमें नं. 2, मुधायल रेड्डी न्ट्रीट, एलेन्ट्रर, मद्रास-16
 - 18. मैसर्स मद्रास टाक लेकर बोर्ड वृभेन बैलफेयर एमोन्सिन्गन, एम. डी. एल. बी. हार्ट्सिंग कालोनी, टांडीप्रपर्पेट, महास-81
 - 19 मैंसर्स झयप्पा भिन्यूरिटो ब्यूरो (प्राइवेट) लि., 12, बालाजी एतेन्यू तिरूमलाए रोड, प्रथम स्ट्रीट, टी तथर, मद्रास-17
 - 20. मैमर्स लक्ष्मी इलैक्ट्रीकल एन्टरप्राइजिज, 1 बैंक स्ट्रीट, लक्ष्मीपुरम चरोमयट्ट, मद्रास-44
 - 21. मैसर्स जैनी घ्रपारेल्य, ः4, प्रकाशन, एलाए, मद्राग-108
 - 22. मैसर्स पाला जी सर्विसेस सेन्टर, 176 रेलवे कालोनी, मुदराई-10
 - 23. मैंनर्स कन्सोलीडेटिड पब्लिशिंग (प्राइवेट) लि., 308 नेहरू नगर, मद्राम-96 और इसका नं. 7, 5, क्राम स्ट्रीट सी म्राईटी कालोनी, मयलापुर, मद्राम-4 स्थित प्रशामनिक कार्यालयू.
 - 24. मैसर्स कनारा एडबरटाइजिंग सर्विस, 15 जूल चर्च रोड मद्रास-४ और इसकी (1), 19/2 भन्धेरी रोड बंगलौर-27 (2) हिलफोर्ट रोर, हैदराबाद-४ (3) गोपाल-प्रभ् रोड, कोचिन-35 स्थित शाखाएं
 - 25 मैंसर्म स्वीजवरो इन्स्ट्रुमेन्ट (प्राइवेट) लि., 169 सिडको इन्डस्ट्रीयल स्टेट मद्राम-98 और इसकी नं. 14 थानीचाकाचलम रोइ,टी नगर, मद्रास-17 स्थित शाखा

श्रतः केन्द्रीय गरफार उकत धारा नियम की धारा 1, की उन्धारा 4 द्वारा प्रदत्त अक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रश्नितियन के उत्पत्तक उक्त स्थानों को लागू करती हैं।

[संख्या एस.-35019(28)/87-एम. एस.-2)]

- S.U. 2060.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellandous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—
 - M/s. Rasi and Company, 61, Madurai Road, Tiruchirapalli-8.
 - 2. M/s. Super Shapers, D-57 and 58 Developments Industrial Estate, Thuvakudi, Tiruchirapalli-15.
 - M/s. Prabath Weaving Factory, Post Box 73, Ragavendra Chariar Street, Komarapalayam-183, Salem District.
 - M/s. Sri Vidya Mandir Higher Secondary School, Anadd Asramam, Meyyanur Road, Salem-4.
 - M/s. Muthukumar Engineering Works, Ramalingapuram Post Office Karipetty (Via), Salem-6.
 - M/s. R. Rajan, Indian Oil Corporation Dealer, 108, Vemkatesapuram, Perambalur, Trichy.
 - 7. M/s. Trichy Engineering Works, D-118 Developed Plot Estate, Thuvakudi, Trichy-15.
 - M/s. Sree Lakshmi Vilasam Press, Madras, Trunk Road, 8A New Colony, Sattur.
 - M/s. Sree Lakshmi Binding Works, 8-B, New Colony, Sattur-203.
 - 10. M/s. Mepco Schlenk Engineer College, Sivakasi-124.
 - M/s. Sri Krishna Kumar Cotton Pressing Factory, 65, Valipalayam Road, Triuppur-601.
 - M/s. H. M. Hajee Moosa, 1/69, Godown Street, Madras-1.
 - M/s. P and I Services of India, No. 48, Rajaji Salai 3rd Floor, Madras-1.
 - M/s. The Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation Limited, No. 807. (V Floor) Anna Salai, Madras-2.
 - M/s. The Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation Limited, No. 807, (V Floor) Anna Salai, Madras-2.
 - M/s. Fuller K. C. P. Limited, 183, Mount Road, Madras-6.
 - M/s. Eltech Engineers No. 2, Muthial Reddy Street Alandur, Madras-16.
 - M/s. Madras Dock Labour Board Women's Welfare Association, M.D.L.B. Housing Colony Tondiarpet, Madras-81.
 - M/s. Ayyappa Security Bureau (Private) Limited, 12, Balaji Avenue, Thirumalai Road, 1st Street, T. Nagar, Madras-17.
 - M/s. Lakshmi Electrical Enterprises, 1, Tank Street, Lakashmipuram Chrompet, Madras-44.
 - 21. M/s. Jeni Apparels, 44, Prakasm Salai Madras-108.
 - M/s. Balaji Service Centre, 176, Railway Colony, Madurai-10.
 - 23. M/s. Consolidated Publishing (Private) Limited, 388, Nehru Nagar, Madras-96, including its Administrative Office at No. 7, 5th Cross Street, C.I.T. Colony, Mylapore, Madras-4.
 - 24. M/s, Kanara Advertising Service, 15, Iuz Church Road, Madras-4 including its branches at (1) 19/2 Andree Road. Bangaloic-27, (2) Hill Fort Road, Hyderabad (3) Gopala Prabhu Road, Cochin-35.
 - M/s. Swizbro Instruments (Private) Limited, 169, SIDCO, Industrial Estate, Madras-98, including its branch at No. 14, Thanickachalam Road, T. Nagar, Madras-17.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above-mentioned establishments.

[No. S-35019(28)/87-SS.II]

- का. श्रा. 2061.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीस होता है कि निम्नलिखित स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुमंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ध्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए
 - मैसर्स जनरल यूटीलिटी टैकनीकल सर्विस,
 1.10.216, प्रशोक नगर, हैदराबाद-1
 - मैसर्स बैनसन इन्डस्ट्रीयल मिन्यूरिटी कन्मलटैन्टस, 107 पार्क लेन, सिकन्द्राबाद-3
 - मैसर्म पब्लिक स्कूल मुख्यालायनी, पालम, विभाष्ट्रापट्टनम-17

धत. थेन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त ध्रधिनियम के उपधन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[मंख्या एम.-35019(30)/87-एम. एस.-2]

- S.O. 2061—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—
 - M/s. General Utility Technical Services, 1.10.216, Ashok Nagar, Hyderabad.
 - M/s. Banson Industrial Security Consultants, 107 Park Lane, Secunderabad-3.
 - M/s. Public School Muvvalavani Palam, Visakha-Patnam-17.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above-mentioned establishments.

[S. 35019(30)/87-SS.II]

का. प्रा. 2062 — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बंधित स्थापन को नागू किये जाने चाहिए:—

- मैमर्म लवली रबर इन्डस्ट्रीज, 163/170 गलोब कालोनी, इन्डस्ट्रीयल एरिया जालन्धर
- 2- मैसर्स पंजाब लेवर बैलफेयर बोर्ड, 731, फेस-3 वी आई मोहाली
- मैमर्म पंजाब होरटीकस्चर कारपोरेशन लिमिटेड, एस. सी. ओ. नं. 309-310 सैक्टर 35-यी, चण्डीगढ
- मैसर्स ऐवट कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 7 प्रीन पार्क, जालस्थर ग्रहर और इसकी ग्राप गाजीपुर जालस्थर रियन गाखा

5. मैसर्स स्वीडवेज टायर सर्विस, जी टी रोड, जालन्धर और इसकी मालरकोटला रोड, लक्षा स्थित शाखा

भातः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त भक्तियों का प्रयोग करने हुए उक्त प्रविनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करनी है।

[संख्या एस.-35019(29)/87-एस. एम.-2]

- S.O. 2062.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—
 - M/s. Lovely Rubber Industries, 163/170 Globe Colony, Industrial Area, Jallandhar.
 - M/s. Punjab Labour Welfare Board, 731, Phase 3BI, Mohali.
 - M/s. Punjab Horticulture Corporation Limited, SCO No. 309-310 Sector 35-B, Chandigarh.
 - M/s. Avet Chemicals (Private) Limited, 7, Green Park, Jalandhar City, including its branch at Village Gazipur, Jalandhar.
 - M/s. Speedways Type Service, G. T. Road, Jalandhar, including its branch at Malerkotla Road, Khanna.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above-mentioned establishments.

[S. 35019(29)/87-SS.II]

मुद्धि-पत्र

का. मा. 2063:— भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 3 जनवरी, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की मधिसूचन्ना संख्या का. मा. 39 दिनांक 16 दिसम्बर, 1986 की दूसरी पक्ति में ("एस. एच./3449" के स्थान पर (एस. एच./4349)" पढे।

[भक्षा एम. 35014(276)/86-एम. एस.-2]

CORRIGENDUM

S.O. 2063.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 39, dated 16th December, 1986 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd January, 1987, in line 3 for "(MH/3449)" read "MH/4349".

[No. S-35014(276)/86-SS.II]

का.भा. 2064:— कर्मचारी राज्य जीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की भारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदन्त मिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-8-1987 को जिस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त प्रधिनियम के भ्रष्ट्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिपाय जो पहले ही प्रवृत्त को जा चूकी है) और भ्रष्ट्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की

जा चुकी है) के उपबन्ध श्रान्धा प्रदेश राज्य के निम्न-लिखित क्षेत्र में प्रवृत्त हों, अर्थात:---

"जिला ग्रानन्तपर में ग्रेगनन्तपुर राजस्व मण्डल के श्रानन्तपुर टाउन की नगर सीमाओं और राजस्व ग्राम पापमपेट, कल्कालापप्पल्ली, ए-नारायणपुरम सोमा नाडोडी, और ग्रानन्तपुर ग्रामीण के श्रम्तर्गत ग्राने वाले क्षेत्र"।

[संख्या एस-38013/23/87-एस . एस-1]

S.O. 2064.—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st August, 1987 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely:—

"The areas within the Municipal limits of Anantapur Town and also the revenue villages of papampet, Kakkalapalli, A-Narayanapur, m., Somanododdi and Anantapur rural in Anantapur revenue mandal in Anantapur District."

[No. S-38013/23/87 SS-I]

का. था. 2065:—कर्म चारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्द्वारा 1-8-1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त प्रधिनियम के श्रध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्न की जा चुकी है) और प्रध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत की जा चुकी है) के उपबन्ध श्रान्ध्र प्रदेश राज्य के निम्न-लिखित क्षेत्र मे प्रवृत्त हों, श्रथांत्:—

"रंगा रेस्डी जिले में मडचल राजस्य मण्डल के राजस्य ग्राम मेडचल गृत्डुलापोचम्पाल्ली और कन्दला कोई के श्रन्तर्गत श्राने वाले क्षेत्र"।

[संख्या एस-38013/26/87-एस-एस-1]

S.O. 2065.—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st August, 1987 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely:—

"The area within the revenue Villages of Medchal Gundlapochampalli and Kandiakoi under Medchal revenue mandal in Ranga Reddy District."

[No. S-38013/26/87-SS.I]

का. श्री. 5966: — कर्मचारी राज्य बीमा श्रिधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदल्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-8-1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको जक्त धिवित्यम के श्रध्याय 4 (धारा 44 और 45 के यिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और श्रध्याय 5 और 6 धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध श्रान्ध्र प्रदेश राज्य के निम्न लिखित क्षेत्र में प्रवत्त होंगे, श्रर्थात: —

"जिला मदूक में पारनचरू राजस्य मण्डल के राजस्य ग्राम मथान्ती के भ्रन्तर्गत ग्राने वाले क्षेत्र"।
[संख्या एस-38013/24/87-एस.एस.-1]

S.O. 2066.—In exercise of the powers conferred by sursection (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st August, 1987 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 76, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely:—

"The area within the revenue village of Muthangi under Patancheru revenue mandal in Medak District."

[No. S-38013/24/87-SS. I]

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1987

का.श्रा. 2067:—मैंसर्स ट्रायनकोर टिटानियम प्राडेक्टस लि., कोचवली, विवेन्द्रम-695021 (के.ग्रार./167) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उत्तर स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रिधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त ग्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छट दिय जाने के निए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रभिदाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के श्रशीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कमचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से श्रश्चिक श्रनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चास् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रशीन उन्हें श्रनुज्ञेय हैं,

ग्रत केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाबज् श्रनमूची में विनिदिष्ट शर्सों के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

भनुसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त केरला को ऐसी विवरणियां भेजेंगा और ऐसे लेखा रखेंगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के ग्रिधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके भन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, वीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का भन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय भ्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का श्रमुखाद स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त श्रिधिनियम के ग्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करगा और उसकी बाबन श्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदन्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के भ्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृजित रूप में वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से श्रधिक श्रनकूल हों तो उक्त स्कीम के प्रधीन भ्रमुत्रेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी आत के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संदेय रकम उम रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों स्कीमों के अन्तर के खराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी
 संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त केरला के पूर्व
 प्रमुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी
 संशोधन से कर्मचारियों के हिस पर प्रतिकृष प्रभाव पड़ने की
 संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त अपना
 प्रमुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट
 करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।

- 9. यदि किसी कारणवश स्थापम के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमों निगम को उस सामूहिक बीमों स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वालें पायर्वे किसी रीतिसे कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियंत तारीय के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियंत करें प्रीमियम का संदाय करने में ग्रसफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्धे-शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संक्षाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के ग्रधीन ग्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितयों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन वीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(93)/87-एस . एस . --2]

New Delhi, the 27th July, 1987

S.O. 2067.—Whereas Messrs. Travancore Titanium Products Limited, Kochuveli, Trivandrum-695021 (KR/167) (herein after referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Ac 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act)

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employee than the benefits admissible under the Employees' Deposi Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said es ablishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts,

submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer,

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient feature thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corpbration of India as already adopted by the said establishment, or the benefits of the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one mouth from the receipt of claim complete in all respect,

[No. S-35014/93/87-SS-II]

का. थ्रा. 2068 — मैसर्स मैकमेट इंडिया प्रा. लि. 27—बी, कामक स्ट्रीट, कलकत्ता—700016 (डब्लू. बी. /24973) और इसकी इसी कोड नं. के अंतर्गत म्राने वाली शाखाएं (जिसे इसमें इसके पण्यात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध म्रधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पण्यात् उक्त म्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के म्रधीन छूट दिए जाने के लिए मावेदन किया है।

ओर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थान के कर्मचारी, किसी पृथक ग्राभदाय या प्रीमियम का मंदा किए जिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू-हिक बीमा स्कीम के भ्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से श्रधिक ग्रनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें ग्रनुजेय है,

अतः केन्द्रोय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबन अनुसूची में विनिविष्ट शतौं के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छट देती हैं।

अन्सूची

- 1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक मित्रिय निधि आपुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुत्रिधारों प्रदान करेगा जो सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खाउ-क के अबीन समय-जमय पर निर्दिष्ट करें।
- 3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का मंदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरोक्षण प्रभारों मंदाय आदि भी हैं, होने वाले मभी क्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायगा।
- 4 नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुनंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बानों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदिशत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मवारी भविष्य निधि का य उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का गहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बायत आवश्यक श्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ायें जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित एए से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के निए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 33-

लब्ध फायदों से अधिक अनुकुल हो जो स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

- 7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त रकीम के अधीन होता तो, ियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय
- सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त पश्चिम बगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी सशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ने की संभावना ही, वहां प्राविशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में भ्रसफल रहता है और पालिसी को व्यप-गत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियों या विधिक वारिसो को जो यदि यह छूट न दी गई दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते। बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के मधीन माने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियो/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से वीमाक्कृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिधिचत करेगा।

[संख्या एस - 35014 (92)/87 + एसएस-2]

S.O. 2068.—Whereas Messrs Macmet India Private Limited, 27-B, Camac Street, Calcutta-700016 (WB/24973) and its branches covered under the same code No. (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group insurance Scheme of the

Life insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benents admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinalter referred to as the said Scheme);

> Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund commissioner West bengal and auntain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 1/ of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheine as approved by the Cential Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient feature thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Limployees' Provident Fund or the Provident Fund of an e tablishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is ligely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said esta-blishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to the cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer is payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceases members who would have been covered under the sais Scheme but for grant of this exemption, shall be that o the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee, legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/92/87-SS-II]

का०आ० 2069.—मैंसमं भोपाल दुग्ध मंघ सहकारी मर्याटीज हवीवनंज भोपाल (एम.पी./3305) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आयेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किया पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन वीमा के रूप में फायदे उठा ,रहे हैं और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सह-बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इमके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुझेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2-क द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रड्ने हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के निए उक्त स्कीम उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी क्ष्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें मंगोद्यन किया आये, तब उस मंगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातो का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निश्चि का या उक्त अधिनियम के अधीद छूट प्राप्त किसी स्थापन को मंबिष्य निधि का पहले ही सदस्य है. उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामृहिक वीमा रकीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त दर्ज करणा और उसकी बाबन आवण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदस करेगा।
- 6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे वहाये जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उगत स्कीम के अधीन अनुभेय है।
- 7. मामूहिक बीमा म्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कभ है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त ईस्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त श्रपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों की श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियुक्त श्रयसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणविश्व स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि कियी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में श्रसफल ग्हता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिकाम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दी दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा वायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के प्रधीन ग्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को वीमाग्रत रकम का

संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बोमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगान

[संख्या एस - 35014(91)/87 - एस एस-2]

S.O. 2009.—Whereas Messis Bhopal Dugdh Sangh Sahakan Manjadit Hobibganj, Bhopal (MP/3305) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lite Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2.1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such focilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient feature thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of he Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance. Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the aid Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Com-

missioner shall before giving his approval, give a teasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/91/87-SS-II]

का. ग्रा. 2070.— मैंसर्स रासी सिमेन्ट लि., पो. बो. नं. 1805, 1-10-125, ग्रशोक नगर हैदराबाद (ग्र. प्र.) (ए. पी./12877) और (ए. पी./13143) (जिमे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त ग्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के ग्रधीन छूट दिए जाने के लिए ग्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्रिभदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक वीमा स्कीम के ग्रश्नीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहें हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से ग्रधिक ग्रनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 जिसे (इसमें इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के ग्रधीन उन्हें ग्रनज्ञेय हैं,

ग्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधिन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त हैदराबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके प्रन्तर्गंत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का श्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय श्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय संरकार द्वारा श्रनुमोदित सामूहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाय, नव उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातो का अनवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त ग्रिधिनयम के ग्रिधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत ग्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायद उन फायदों से प्रधिक श्रनकूल हो जो उक्त स्कीम के प्रधीन श्रन्तुक्तेय है।
- 7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के ब्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्तमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त, हैदराबाद के पूर्व श्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृष प्रभाव पड़ने की संभाधना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त श्रपना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियुक्त श्रवसर देगा ।
- 9. यदि किसी कारणवण स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भ्रपना चुका है, श्रधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते .हैं, तो यह रद् की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उम नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम

- का संदाय करो ें ग्रात हल रहना है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता हैतो, छूट रद्द की जा सकरी है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यितिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उनत स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन स्नाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियो/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दणा में भारतीय जीवन वीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर मृनिश्चित करेंगा।

[संख्या एस.-35014(90)/87-एस. एस.-2]

S.O. 2070.—Whereas Messrs Rassi Cement Limited, P.B. No. 1805, 1-10-125, Ashok Nagar, Hyderabad (A.P.) (AP/12877 and AP/13143) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission, of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient feature thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall imediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessory premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more tavourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhia Pradesh and Where any amendment is ligely to affect adversely the Interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/90/87-SS-II]

का. ग्रा. 2071—मैंसर्स प्रैस्टींज फिड्ज मिन्ज, 30, ज्योरा कम्पाऊड, इन्दौर (एम. पी./3821) (जिसे इसमें इसके पश्चान् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रिधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चान् उक्त ग्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के श्रधीन छूट विये जाने के लिए मावेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मधारी, किसी पृथक ग्रिभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के ग्रिधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहें हैं और ऐसे कर्मधारियों के लिए ये फायदे उन फायदों के ग्रिधिक श्रनुकूल हैं जो कर्मधारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चान् उक्त स्कीम कहा गया है) के ग्रिधीन उन्हें श्रनुजेय हैं;

ग्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्न शिंतियों का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाबद्ध श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के ग्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की भवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट वेती है।

ग्रन्स्ची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भृतिष्य निधि श्रायुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधायें प्रदान करेगा जो केस्थीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक' मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय मेरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खंड-क के ग्रिथीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रबा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, वीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, तिरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययो का वहन नियोजक हारा दिया जाएगा।
- 4 नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें पणोधन किया जाये, तब उस संणोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुतसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बानों का श्रन्वाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी अविषय निधि का या उना अधिनियम के अप्रीत छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्न दर्ज करेगा और उसकी वावन ग्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायरे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप मे बृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से श्रधिक श्रनुकूल हो जो उक्त स्कीम के श्रमुक्य हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम रो कम है जो कर्मचारी को उस दक्षा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक/बारिस/नाम निर्देणिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई प्रादेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहा प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त भ्रपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भ्रवसर देगा।

- 9. यदि किसी कारणवंत स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा नियम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिले स्थापन पहले भपना चुका है, ग्रेशीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के भधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदें किसी रीति ने कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवंश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में श्रगफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जासकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यतिकम की दशा में उन मृत नदस्यों के नाम, निर्देशितियों या बिधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गतं होते । बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायन्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार-नाम निर्वेशितियों/विधिक वारिसों को वीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर स्निच्चित करेगा।

[संख्या एम. 35014(89)/87-ए,म एस० -2]

5.0, 2071.—Whereas Messrs, Prestige Feed Mills, 30, Jaora Compound, Indore (MP/3821) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance other as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient teature thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessory premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts able approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered and re the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure moment payment of the sum assured to the nominee/leual bers of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of clalm complete in all respect

[No S-35014/89/87 SS-III

का.शा.2072—मैसर्स जिला सहकारी केन्द्रीय बँक मर्याद्दीत शिवपरी (म प्र) (एम/पी./1090) (जिसे उसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध श्रधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त श्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के श्रधीन छूट दिये जाने के लिए श्रावेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्रिभदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक वीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे

679 GI/87--17

उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से ध्रधिक धनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीना स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उपत स्कीम कहा गया है) के ध्रधीन उन्हें धनुशेय हैं,

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की भारा 17 की उपभारा 2क बारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायद्व धनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंग्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

प्रनुसूची

- ा. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाये प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- '2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खंण्ड-क के श्रिधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके भ्रतगैत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का भ्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारो संदाय भ्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4 नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रनुमोवित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म- चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का श्रनुवादं स्थापना के मूचना पट्ट पर प्रविशत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐुमा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत ध्रायम्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के ग्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिश बीमा स्कीम के ग्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से ब्रिक्ष किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन उपलब्ध फायदे उन ग्रधिक श्रमुक्ष हो जो उक्त स्कीम के ग्रधीन श्रमुक्षेय है।
- 7. साम्हिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा

- में संदेय होती जब यह उक्त स्कीम के ग्राधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में धोनों रकमों के सन्तर के अराबर रक्तम का संदाय करेगा।
- 8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी संगोधन प्रादेशिक भीविष्य निधि श्रायुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व धनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संगोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिक्षूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशि भविष्य निधि ग्रायुक्त श्रपना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्कीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवरा स्थापन के कर्में बारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले प्रपना चुका है, प्रधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारण्रवा नियोजक उस नियंत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियंत करे, प्रीमियम का संदाय करने में ग्रसफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जामे दिया जाता है तो, छू रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय मे कियेगये किसी व्यंतिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्वे- शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उनत स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उमके हकदार नाम-निर्देणितियों/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का संबाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माम के भीतर सुनिष्ठित करेगा।

[संख्या एस-35014(88)/87-एस.एस-2]

S.O. 2072.—Whereas Messrs Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Shivpuri (MP) (MP/1090) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule appeared hereto.

the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Sentime for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall should such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Covernment may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) or sup-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses, involved in the administration of the Group insurance scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient feature thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible ender the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provindent Fund Commissioner, Madbya Pradesh and where any amendment is ligely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reason able opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said estalishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to Japse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme, but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the decensed member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/88/87-SS-II]

का. आ. 2073: — मैसर्स-टी ट्रडिंग कारणेरेशन आफ इण्डिया लि., 7, वह स्ट्रीट, कलकत्ता (डब्ल्लू.बी./14964) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ते कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त ग्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के ग्रधीन छूट दिये जाने के लिए ग्रावेदन किया है।

और कन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम क संदाय किय बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिये वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

श्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा(2-क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबद्ध श्रनुसूची में विनिद्धिट शर्तों के श्रिधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

श्रनुसूची

- 1: उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के श्रिधीन समय-समय पर निर्देश्ट करें
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके भन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का प्रस्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय भावि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा भ्रतुभादित सामृाहक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का भ्रतुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदेशित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त ग्रिधिनियम के ग्रिधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त दर्ज करेगा और उसकी

बाबत भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदल करेगर

- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जान है तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में बिद्ध किये जाने की व्यवस्थ करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में प्रधिक अनुक्ल हों जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनुक्षेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्काम म किसा बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृध्य पर इस स्कीम के श्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के श्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के छप में दोनो रकमो के श्रन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पहने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दिटकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन, के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापन पहले प्रपना चुका है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवस, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करे. भीमियम का संवाय करने मे श्रसफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किये गए किसी व्यक्तिकम की वशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के श्रन्तर्गत, होता। बीमा फायदों के संवाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उन्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के प्रधीन श्रामे वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक-दार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय नन्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एफ माम के भीनर मृतिश्चित करेगा।

भिष्या एस-35014/87/87-एस . एस- $oldsymbol{II}$

S.O. 2073.—Whereas Tea Trading Corporation of Incla Limited, 7, Wood Street, Calcutta-700016 (WB/14964) thereinafter referred to as the said establishment) have applied tor exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favorable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinatter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The, employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses, involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient leatures thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable oportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled

- 10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lanse, the exemption is liable to be cancelled
- 11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium, the responsibilty for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer
- 12 Upon the death of the members—covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect

[No \$ 35014/87/87-\$\$ 11]

का मा 2074 — मैसर्स रिव इन्जीनियरिंग वर्क्स प्लाट न 3, इण्डस्ट्रीयल ऐस्टेट, गोविन्दपुरा भोपाल (एम पी /5271) (जिसे इसमे इसके पश्चात उंक्त स्थापन कहा गया है) न कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रक्षित्रियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त श्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के मधीन छूट दिय जाने के लिए ग्रावेंदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किय बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुकाय है।

स्रत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) झारा प्रवल शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावक अनुसूची में विनिधिष्ट सर्ती के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट∮देती है।

श्रनुसूची

- 1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भिविष्य निधि भ्रायुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाय प्रवास करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्विष्ट करें।
- 2 नियोजक ऐसे रिरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगी जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के श्रधीन मन्य गम्य पर निद्विष्ट करें।
- असमृहित बीमा स्तीन के प्रणासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियी का प्रस्तुत किया जाना,

- भीमा प्रीमियम का संधाम, लेखाओ का झन्तरण, निरीक्षण प्रभारो का सदाय भादि भी है, होने माले सभी अपयो का वहन नियोजक द्वारा किया आएगा।
- 4 नियोजन, केन्द्रीय मरकार द्वारा धनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाय, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म- चारियों की बहुसख्या की भाषा म उसकी मख्य बातों का धनुवाद स्थापन के सूचनापटट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कमचारी जो कमंचारी मिवष्य निधि का या उक्त श्रंधिनियम के श्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उमकी बाह्यन प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मदत्त करेगा।
- 6 यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिव प्रनुकूल हो जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनुकूष है।
- 7 सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के भ्रधीन सदय रकम उस रकम सं कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के श्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनो रकमो, के भ्रन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा।
- 8 सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी सशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व श्रृतुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन सं कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की सभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त श्रपना श्रृतुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोशा स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9 यदि निसी कारणवश स्थापन के कर्मधारी भारतीयं जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले श्रपना चुका है मधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छुट रह की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवण नियांजन उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, श्रीसिश्म ना संशाय करने में असपल रहुता है और पोलिसी भो व्यक्ष्मत हो जाने विया जाता है तो, छूट रह की जा मकती है।

- 1-1. नियोजक द्वारा प्रीसियम के संवाय, में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सवस्यों के नाम क्रिवें-िशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के प्रन्तर्गत होते; बीमा फायदों के संदाय का उक्तरदायित्व नियोजक पर होता।
- 12. उस्त स्थापन के सम्बन्ध मे नियोजक इस स्कीम के ग्राप्तीन माने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितयों/विधिक वारिसों की बीम कृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होन के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(86)/87-एस.एस-II]

S.O. 2074.—Whereas Messrs Ravi Engineering Works, Plot No. 3, Industrial Estate, Govindpura, Bhopai (MP/5271) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lite Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charge etc., shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immeiately exact him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme, are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Copporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium, the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been cevered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme-the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all-respect.

[No. S-35014/86/87-SS.II]

का. आ. 2075.—मैंसर्स क्वालिटी इन्जिनियरिंग एण्ड इन्सूलेशन प्रोडक्ट, 71-ए, इण्डिस्ट्र्यल एस्टेट, गोविन्द-पुरा, भोपाल (एम. पी. /2056), (जिसे इसमें उसके पश्चास् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध मधिनियम, 1952 (1952की 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्र्भिवाय या श्रीमिधम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों के श्रधिक भनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इनके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के सधीन उन्हें श्रनुतोय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उनत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हमसे उपाबद्ध अनुसूची में निर्मिष्टि शर्तों के अधीत रहते हुए, उक्त स्थापन को सीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन में छूट देशी है

श्रनुसूची

- गुजनत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेंगा और ऐसे लेखा रखेंगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेंगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रिधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के प्रधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके श्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का श्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय श्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा.
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें मंशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का ग्रम्भाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्यों के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा। और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को मंदन्त करेगा।
- 6 यदि उक्त स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा, स्कीम के श्रधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदो में समुचित्तः रूप से वृद्धि किए जाने की ब्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों मे श्रधिक श्रनुकूल हो जो उक्त स्कीम के श्रधीन अनजेय हैं।
- 7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस देशा में सदेय होती जब वह उकत स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देशिसी को प्रतिकर के अप में दोनो रकमों ने अन्तर के बराबर रकम ना संदाय करेगा।

- ह सासूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी सशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी सशोधन से कर्मवारियों के हित पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त अपना ग्रनुमोदन देने मे पूर्व कर्मवारियों को ग्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त ग्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस समामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना खुका है अधीन नही रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवण, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का मंदाय करने में ग्रसफल रहता है और पालिसी को स्यपगत हो जाने दिया जोता है तो, 'छूट रह की जा मकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिकाम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियों का विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के श्रन्तगैत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के श्रधीन श्रानं वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/बिधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मांस के भीतर मृनिश्चित करेगा।

[संख्या एस 35014/(85)/87-एस. एस-2]

S.O. 2075.—Where is Messrs Quality Engineering & Insulation Product, 71-A Industrial Estate, Govindpura, Bhopal-462023(MP/2056) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Instrance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immeiately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Machya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view
- 9. Where, for any feason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of Judia as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members—covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect

का. मा. 2076.—मैसर्स-दि जोधपुर सेन्दूल को. औ. तैंक लि., मिल का हमा, मन्दोर रोक, जोधपुर-342006१ (मार. जे/840), (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप-वैध प्रधिनियम, 1952 का 17 (जिसे उनमें इसके पण्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धार्म 17 की उपभारा 2 (क) में अधीन छट दिए जाने के लिए आग्रेंदन दिया है।

और केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक धिन्नदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन जीवन बीमा के रूप का फायदे उठा रहे है और ऐमे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से ग्रधिक धनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिमे इसमे इंसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के ग्रधीन उन्हे ग्रनभेय हैं.

धत. केट्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावध प्रनृसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्थाप के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

ग्रनुसूची

- ा उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्राप्तेशिक भिविष्य निधि ध्रायुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केद्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारों 17 की उपधारा 3 क के खण्ड क के प्रधीन समूच समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विधरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखीओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का मंदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4 नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रनुमोदित सामूहिव वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें सामोधन किया जाए, तब उस मंगोधन की प्रति तथा कमं चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मृख्य बातो क स्रमत्राद स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रतिगत करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भिविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिविष्य निधि का पहले ही सदस्य है. उसके दंशापन रे. नियोजित किया जाता है तो, नियोजित साम्हिक बीमा स्काम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दुर्ज करेगा और

उपको बाबत स्रावस्थक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदल करेगा ।

- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की ध्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से ग्रिधिक ग्रनुकुल हो जो उक्त स्कीम के ग्रधीन श्रनुकेय हैं।
- 7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दणा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक धारिस/नाम निर्देणिती को को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के श्रन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक भविष्य निश्चि भ्रायुक्त राजस्थान के पूर्व ग्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संणोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त भ्रपना ग्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रपना दृष्ट्रिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन वीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीमः के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किमी कारणवंश नियोजक उस नियत तारीखं के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में श्रसफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी ध्यतिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के मन्तर्गत होते । बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन ग्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशीतियों/विधिक वारिसों को बीमाक्कत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माम के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(84)/87-एस. एस.-2]

S.O. 2076.—Whereas, Messrs The Jodhpur Central Co-operative Bank Limited, Manji Ka Hatha, Mandor Road, Jodhpur-342006 (RJ/840) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) or section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month,
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rule, of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Fmployees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immeiately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Inturance Scheme appropriately, if the besefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal helr/nominee of the employee as compensation
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Raiasthanned where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be Hable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(84)/87 SS.II]

का. ह्या. 2077.-; मैसर्स पहवा इण्डस्ट्रीज, ए-17 से 20 इण्डस्ट्रीयल ग्स्टेट, जोघपुर (भार.जे./1895), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रीधनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त भ्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के मधीन छूट दिए जाने के लिए घावेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक भ्रभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से प्रधिक अनुकृत हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें ग्रन्शेय हैं ;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध श्रनुसुची मे विनिर्दिष्ट शर्तों के श्रधीन रहते हुए, . उक्त स्थापन को तीन वर्ष की ग्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी जपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

प्रन्यूची

- 1. उन्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि भ्रायक्त राजस्थान को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ' ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विधाये प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के मधीन समय समय पर निविष्ट करें।

- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओ का भन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा धनुमोदित सामुहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रवर्ति करेगा ।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कमचारी भविष्य निधि का या उक्त ग्रधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उन्त स्कीम के म्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाए जाते हैं, तो. नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से श्रधिक र्धन्कुल हो जो उक्त स्कीम के श्रधीन प्रनुज्ञेय है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होने हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के ग्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के ग्रन्तर के बरावर रक्षम का संदाय करेगा ।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ने की रांभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त स्रपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 🚉 ग्रपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भ्रपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायद किसी रीति से कम हो आते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवंश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में भ्रमफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाना है तो, छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा शीमियम के संवाय में किये गये किमी व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। श्रीमा फायदों के सदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन भाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसकें हक-दार नाम निर्देशिनियों/विधिक वारिमों को बीमाकृत रकम का मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर मृनिक्ष्वित करेगा ।

[मंख्या एस-35014(83)/87-एस . एम-2)]

S.O. 2077.—Whereas Messts, Pahwa Industries, A-17 to 20 findustrial Estate, Jodhpur (RJ|1895) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (bereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed heretog the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- '5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- t. The employer shall arrange to suhance the benefits available to the employees under the Group Insurance

- Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benents available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee open covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a teasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomineely legal heirs of the deceased member entitled for it and inlany case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014|83|87-SS. II]

का. भा. 2078.— मैंसर्स न्यू इरा इण्टरप्राइज, 23-बी, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गोविन्दपुरी मोपाल-462023 (एम. पी./3649) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध भिवित्यम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त श्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के भिधीन छूट दिये जाने के लिए धावेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का सगाधान हो गया है कि उवत स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक प्रभिदाय पा प्रीमियम का संवाय किये विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उटा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से ग्रधिक ग्रनुकृल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के ग्रधीन उन्हें ग्रनुक्षेय हैं,

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमे उपायद्व प्रनुसुषी में धिनिविष्ट शर्तों के प्रधीन रहते हुए, उनत स्था। न को तीन वर्ष की प्रविध के लिए उवन स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

ग्रनुसूची

- 1 उक्त स्थापन के मम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भिवट्य निधि ग्रायुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाये प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट वरे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के श्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3 सामृहिक वीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके प्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाओं का प्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सदाय ग्रादि भो है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4 नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बांमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म- जारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य वालों का अनुवाद स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐ ना कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के श्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावज श्रावण्यक श्रीभियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदस करेगा।
- 6 यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि किये जाने की व्यास्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारों की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन मंदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस देशा में संवेय होती जब वह उकत स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्वेशिसी को प्रतिकर के हल में दोनों रकमों के प्रन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपनन्धों में कोई मी सशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व

- श्रनुमोदन के बिना महीं किया जाएगा और जहाँ किमी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की, संभावना हो, वहा प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त ग्रपना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उप मामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं, तो यह रह की जा मकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने मे अमफ्ल रहता है और पालिमी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किये गये कियी क्यतिकम की दक्षा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के ग्रन्तर्गत होते । बीमा फायवों के संदाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के ब्राधीन ग्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक-दार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(82)/87-एस.एस-2)]

S.O. 2078.—Whereas Messrs, New Fra Enterprise, 23-B, Industrial Estate, Govindpura, Bhopal Pin. Code 462023 (MP|3649) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to a the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges at the Central Government may, from time to time, direct

under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

- 3. All expenses involved in the icaninistration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, subtinission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the ensployer.
- 4 The employer shall disptay on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund of the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shift immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Copporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Netwithstanding enviling contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount poyable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal hen homence of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be notice without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is fixely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain govered under the Group Insurance Scheme of the Life insurance Corporation of India a already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be hable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is hable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any nade by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life formance. Corporation of India shall casure prompt payment of the sum assured to the nomineel legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/82/87-5S-IJ]

का. आ. 2079.—मैंसर्ग—जांधपुर बाइर्स, 16-बी, 111, हैर्ना इन्डिन्ट्रियल एरिया, जोधपुर (आर जे./2944) (जिसे इसमें इसके परचात् उपत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भित्रप निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध श्राधिनियम, 1832 (1852 का 17) (निसे इन्हें इसके परचात उक्त

अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छुट दिये जाने के लिए ब्रावेदन किया है।

अीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हा गया है कि उक्त रथापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्वीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फापदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों के श्रीधक अनुकूत हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिंग उनमें इसके पण्चान उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अन्तेय हैं,

श्रत केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त मिन्नयों का प्रयोग करते हुए और इसेंग उपायद्व श्रम्भूती से विनिर्दिष्ट मती के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रविध के लिए उक्त स्वीम के सभी उपबन्धों के श्रवर्तन से छूट देती है।

अनमूची

- उक्न रथापन के सम्बन्धे में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त राजस्थान को ऐसी विवर्णियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदेशन करेगा को केन्द्रीय संकार, समय गमय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय रारकार, उक्त श्राप्रिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय रास्य पर निर्दिग्ट करें।
- 3 साभूहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके भ्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का भ्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय श्रादि भी है, होने वाने सभी व्ययो का बहुन नियं। ज हारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमांदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति अंश्रिजब कभी उनमें संणोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य आतों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जी कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है हो, नियोजन नामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाग नुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबन ग्रावण्यक' प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदन्त करेगा !
- ७. यदि अवत रकीम क अवीन कर्मचारियों को उपलब्ध पायदे गढामे जाते हैं तो, नियमक समृहिक सीमा स्क्रीम के प्रशीन कर्मवारियों को अवलब्ध कायदों में समृष्ठित क्रव

से बुद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्म-चारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदां में श्रधिक श्रनुकूल हो जो उक्त स्कीम के म्रधीन ग्रनुज्ञेय हैं।

- सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम मे कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेश होती जब वह उक्त स्कीम के श्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के ग्रन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा ।
- सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त राजस्थान के पूर्व **ग्र**नुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त श्रपना भन्मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भ्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस मामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है प्रधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के मधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किमो कारणवण नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे. प्रीमियम का संदाय करने में ग्रसफल रहता है और पालिसी को न्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छुट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के श्रधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियो/विधिक वारिसो की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रक्षम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

संख्या एस-35014

S.O. 2079.—Whereas Messrs, Jodhpur Wirey, 16-B-III, Heavy Industrial Area, Jodhpur (RJ|2944) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provinces Act, 1952 (1901 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hercinafter referred to as the said Scheme);

now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Governthent may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurances Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund et an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately entol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the tenelits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this S eme !e less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation,
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to nifect adversely the insurance of the provident Fund. the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain then point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date es fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

The state of the s

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under, the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomineel legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect

[No. S-35914/ 81)/87-SS JT]

का. ग्रा. 2080---मैसर्स-तिमिल नाडु को-ओपरेटिव स्टेट लैंड डिवलपमेंट बैंक लि. मद्रास-600004 और इसकी इसी कोड नं. के प्रन्दर ग्राने वाली सभी गाखाएं (टी-एन-/4152) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छट दिये जाने के लिए ग्रावेदन किया है।

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उकत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृंधक ग्रभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा. स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चाम उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें श्रनजेय है.

भ्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रवस्त मिन्तियों का प्रयोग करने हुए और इससे उपावद श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट मतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

ग्रन्सुची

- 1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्स मद्रास को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधार्थे प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रश्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा--17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के ग्रिधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके श्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना. विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना. बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाओं का श्रन्तरण. निरीक्षण प्रभारों संदाय श्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमे

- संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियो की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सुखना पट्ट पर प्रवक्तित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त श्रिधिनयम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजित सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत श्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6 यदि उनत स्कीम के अधीन समंचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से यृद्धि किये जाते की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनकृल हो जी उक्त स्कीम के अधीन अनुजेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संदेग रकभ उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दणा में संदेग होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के श्रन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन प्रादेशिक भिवष्य निधि प्रायुक्त मद्रास के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो. वहां प्रादेशिक भिवष्य निधि प्रायुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9 यदि किनी कारणवश स्थाप्त के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सान्हिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को प्रान्त होने वाले फायदे किसी रीति से कमहो जाते है, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश्य नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जावन बामा निगम नियस करे, प्रीमियम का मंदाय करते में असफन रहता है और पालिमी को व्ययगत, हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की देशा में उन मृत सदस्वों के नाम निर्देशितियों या त्रिधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्काम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उना स्थापन के सन्यन्य में लियोजन द्वा स्ती । है अधीन प्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी हकदार माम निर्देशितियो/पाधिक वारियो को बीमाङ्गा स्कप का संदाय सत्परना से और प्रत्येक दणा मे भारतीय जीवन **बीमा निगम से बीमा**कृत रक्षम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[मंख्या एस-35014(80)/87-एस . एस . -2]

S.O. 2080.—Whereas Messrs lamid Nadu Co-operative State Land Development Bank Limited, Madras-600004 (TN/4152) and its branches covered under the same code No. (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges, as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of tetuens, payment of insurance, premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said A.t, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to e Tife Insurance Corporation of India.
- 6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are ennanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissisble under the said Scheme.

- 7. Nativith conding as, thing coul field in the Group, Invorance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employed bem covered under the said Schenie, the employer shall nev the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu and where any amendment is likely to illest adversely the interest of the employees, the Regional Provident I und Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alleady adopted by the sail establishment, or the fencility to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10 Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the duc date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to rapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomineel. legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

• [No. S-35014(80)]87-SS-II]

का० ग्रा० 2081:---मैनर्स राजा एग्रो सर्विस सेन्टर, गार्डन एरिया, सिमीगा 577201 (के० एन०/7/872) (जिसे इसके पश्चान् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिमे इसमें इसके पग्नान् उक्त श्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अभीन छट दिये जाने के लिए आविदम किया है।

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उतन स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अधिदाय या प्रीमित्रण का संदाय किने विना ही. भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीधा रक्तीम के ध्रशीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा के १ और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से भैक्षिक भ्रमुखन है जो धर्मवारी निजेग सहबद्ध बीमा भकीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्यात् उत्तर स्वीम जहा गया है) के प्रधीन उन्हे सनजेय हैं,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम भी घारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त णिनतयों का प्रयोग करते हुए और स्थमे उपाबक्र अनुमूर्च। में विनिद्धिष्ट मतों के अधीन रहते हुए, जनत स्थापन को नीन वर्ष की अवधी के ीलए उपल सर्त,म के सभी उपबंधों के प्रवर्तन ने छुट देती ^है।

श्रनसूत्री

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भिक्षिप निधि भाग्यत कर्नाटका को ऐसी जिवरणियां भेजेंग। भीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविबाये प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय, गमय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजय, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 विन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियस की धारा-- 17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के श्रधीन समय-समय पर निदिष्ट करें।

- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके घ्रस्तांत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का घ्रस्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय घादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सर्केंगर द्वारा ध्रनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति धौर जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का ध्रनुवाद स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मवारी जो कर्मवारी भविष्य निधि का या उक्त क्षिधित्यम के प्रधीन छ्ट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में निधीजत किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त दर्ज करेगा भीर उसकी बाबत धावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के भयीन कर्मचारियों को उपबन्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीज कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप ने वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुकेष की पायदे उस फायदों से भिक्ष भनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन भनुकोग हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रतीन संदेय रकम उस रक्षम से कम है जो कर्मचारी को उन दक्षा में सदेय होती कब वह उक्त स्कीम के भ्रतीत होता तो, कर्मचारी के विशिक्त वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के कर्म दोने रक्षमों के भ्रत्य के वरावर रकम का सदाय करेगा।
- 8. सामृहिक वीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक मिल्य निधि भागुक्त कर्नाटका के पूर्व मनुमोदन के जिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन ने कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पहने की संभावना हो, वहा प्रावेशिक भविष्य निधि मागुक्त भपना भनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुक्तिस्वन प्रथमर देगा।
- 9 यदि किली कारणवश स्थापन के कर्मनारी मारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्थाम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अबीन कर्मनारियों को प्राप्त होने बाले कायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणविष्य नियोजक उस नियत सारीख के भीतर जो भारसीय जीवन बीमा निगम नियत करे, श्रीमिथम का संवाय करने में भसकल रहता है भीर पालिसी को व्ययगत हो जाने विद्या जाना है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक हारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशिनियों या विश्विक नारियों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उन्हें स्कीम के प्रस्तांत होते। बीमा कायदों के संदाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. जनत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के मधीन प्राने काले किसी सवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से भीर प्रत्येक दणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम होने के एक मास के भीतर श्रानिश्चित करेगा।

[संख्या एस॰ 35014/79/87-एस॰एस-2]

S.O. 2081.—Whereas Messra Raja Agro Service Centre, Garden Area, Simoka-577201 (KN|7872) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A)) of Section 17 of 679 GI/87—19

the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Governement hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance, Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas on employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of 18 m to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately. If the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amenoment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Groun Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as

already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No S. 35014]79[87-SS. II]

का॰ आ॰ 2082 — मैंससं वि साऊष इष्णियन एक्सपोर्ट के प्रा॰ लि॰ मैंसूर बैंक बिल्डिंग, 231, एन॰एस॰सी॰ बोस रोड, मद्रास (टी॰एन॰/2313) (जिसे इसमें इसके पम्बात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मधारी भविष्य निष्ठि भौरप्रकीणें उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त ध्रिजियम कहा गया है) की धारा 17 की उप धारा (2क) के ध्रधीन छूट दिये जाने के लिए धावेदन किया है।

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्में जारी, किसी पृथक श्रीभवाय या प्रीमियम का संवाय किये प्रिणा ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की मामृहिक बीमा स्कीम के ध्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायवे उठा रहे हैं श्रीर ऐसे कर्मश्राप्यों के लिए ये फायवें उन फायवों से श्रीधक श्रमुकूल हैं जो कर्मश्राप्यों के सिए ये फायवें उन फायवों से श्रीधक श्रमुकूल हैं जो कर्मश्राप्य निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके प्रथमान् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रीमा उन्हें श्रमुक्षेय हैं,

मतः केन्द्रीय सरकार, उनतः मधिनियम की धारा 17 की उपचारा 2क द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए भीर इससे उपायक धनुसूची में विनिर्विध्य सर्तों के ग्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की भवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती। है।

भन्युची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि भायुक्त गुगास को ऐसी विवरणियां भेजेगा भीर ऐसे नेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विधायें प्रवास कारेगा को केव्सीन सम्बन्ध नाम-समय पर निविष्ट करें।
- 2. नियोजक ऐसे भिरीक्षण प्रधारों का प्रत्येक ास की समाप्ति के 15 विंम के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रश्विनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के झंधीन समय-समय पर निर्मिष्ट करें।
- 3. साम्हिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके श्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुन किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का धन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय मादि भी है, होने वाले सभी क्यों का बहुन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय संरकार द्वारा धनुमोवित सामृहिक कीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति धीर जब कभी उनमें संकोधन किया जाये, तब उस संबोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उन्हों मुख्य बाबों का धनुवाद स्थापन के सूखना पट्ट पर प्रविणित करेगा।

- 5 यदि कोई ऐसा कर्नवारी को कर्नवारी भिष्ट्य निर्धि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्वान्त को अविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोज्ञित किया जाता है तो, नियोजन मामूहिक घीमा स्थीम के सवस्य के क्य में उसका नाम सुरस्त वर्ज करेगा और उसकी बावत भावश्यक प्रीमियम भारती । नियम को संबक्त करेगा।
- 6. यथि उक्त स्कीम के मधीन कर्मवारियों को उपनक्त फायदे बहाये जाने हैं तो, नियोगक सामृश्चिक बीमा स्कीम के मत्रीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायदों में समृज्यिन क्या से वृद्धि जिन्ने काने की व्यवस्था करेगा निमसे कि कर्मवारियों के लिए सामृत्विक बीमा स्कीन के व्यवीत उपनक्ष्य फायदे उन फायदों से स्वीक धनुकूल हो जो उक्त स्कीम के मधीन मनुनेष हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यि किसी कर्मचारी की मृह्यु पर इस स्कीम के प्रधीन रांदेन रकम उस रक्तम से कम हैं जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब तर उक्त स्कीम के प्रतीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्तों के ध्रत्यर के वरावर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहित भीमा स्कीन के उपबन्धों में कोई नी संगोधन प्रायेणिक मित्रिय निधि मायुक्त मदास के पूर्व अनुमोदन के जिना नहीं किया आएना भीर जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हि। पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की सभावना हो, वहां प्रादेशिक शिवश्य निधि मायुक्त प्राना मनुमोदन देने मे पूर्व कर्मवारियों को अन्य प्रदिकाण स्वष्ट करने हा गुनित-यक्त ध्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी मारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृद्धिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अबीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छुट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवंश र्मियोक्षक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा शिम नियत करें, प्रीमियन का संदाय करने भें भ्रमफल रहता है और पानिसी को व्ययगत हो आने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक बारा प्रीमियम के संवाद में किये गये किसी व्यतिक्रम की वशा में उन मृत सवस्यों के नाम निर्धेशितियों या विधिक वारिसों को जो दिव यह छूट न दी गई होती तो, उनत स्कीम के अन्तर्गत होते।
 वीमा कायदों के संवाय का उत्तवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12 उनत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के भ्रधीन भान काल किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हु त्यार नाम निर्वेशितियाँ/विधिक थारिसों को बीथाकृत रकम का संवाय तत्परता से भीर प्रत्येक बता में भारतीय जीवन बीमा निजम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिविचत करेगा।

[सन्तर एस॰ 35014(78)87 एस॰ एम॰-2]

S.O. 2082.—Whereas Messrs The South Indian Export Company Private Limited, Mysore Bank Building, 231, N.S. C. Bose Road, Madras-60001 (TN|2313) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A)) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miccellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Incurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that

he benefits admissible under the Employees' Deposit Linked insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by ub-section (2A) of section 7 of the said Act and subject to he conditions specified in the Schedule annexed hereto, he Central Government hereby exempts the said establishment rom the operation of all the provisions of the said Schene or a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall ubmit such returns to the Regional Provident Fund Comnissioner Tamul Nadu and maintain such accounts and rovide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the lentral Government may, from time to time, direct under lause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the troup Insurance Scheme, including maintenance of accourts, ibmission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne y the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the stablishment, a copy of the rules of the Group Insurance theme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient atures thereof, in the language of the majority of the uployees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the mployees' Provident Fund or the Provident Fund of an tablishment exempted under the said Act, is employed in a establishment, the employer shall immediately enrol him a member of the Group Insurance Scheme and pay necestry premium in respect of him to the Life Insurance Corpration of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits adable to the employees under the Group Insurance heme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the nefits available under the Group Insurance Scheme are pre favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insunce Scheme, if on the death of an employee the amount yable uder this Scheme be less than the amount that puld be payable had employee been covered under the id Scheme, the employer shall pay the difference to the gal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance heme, shall be made without the prior approval of the gional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu d where any amendment is likely to affect adversely the terest of the employees, the Regional Provident Fund mmissioner shall before giving his approval, give a reaso-ble approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said esslishment do not remain covered under the Group Insunce Scheme of the Life Insurance Corporation of India as eady adopted by the said establishment, or the benefits the employees under this Scheme are reduced in any inner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer falls to pay the mium etc. within the due date, as fixed by the Life nurance Corporation of India, and the policy is allowed lapse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for pyment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/78/87-SS, II]

का०आ 2033 — पैनर्न पूनाइटिङ इनिबट्ट कान्य 17-की, इंडस्ट्रीयल एरिया, गोबिन्दपुरा भोगल (एम०पी०/4892) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निश्चि और प्रतीर्ण उपनम्ब अधिनियम, 1952 हा 17 (जिसे इसमें इसके पश्चान् उक्त अधीन अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपपारा (2क) के अधीन छूट विये जाने के लिए आवेषन किया है।

श्रीर फेन्द्रीय सरकार का समाधात हो गया है कि उनन स्यापन के कर्मभारी किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीन के अवीन जीवन, बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मभारी के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुसूत हैं जो कर्मभारी निजेन सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 जिने इपमें इनके पश्चान् उनन स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुनिय हैं,

अत केन्द्रीय सरकार, उन्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रवत्त सक्तिमों का प्रयोग करने हुए और इससे उराबद्ध अनुसूची में विनिविध्ट सनौं के अप्रीन रहते हुए, उन्त स्थानन को तान वर्ष का अवधि के लिए उन्त स्कीम के सभी उनस्मां के प्रवर्तन से छुट देती है।

अनुसूची

- 1 जन्दस्यापन के सम्बंध में निर्मातक प्रावेशिक भविष्य निश्चित्रायुक्त मध्य प्रदेश की ऐसा वितरिंगिर्म भेगेता और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुलिधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्राय मरहार संसय समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रमारी काप्रत्येक माम की समाप्ति के 15 विन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय मरतार, उक्क अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खड-क के अधीन समय समय पर निविच्य करें।
- 3. सामृहिक बीमा रकीम के प्रवासन में, किनके पर्नान लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रम्युत किया जाना, बीमा प्रीमिथम का सवाय, लेखाओं का प्रनरण, निरोक्षण प्रभारों संग्रप आदि भी है, होते वाले सभी व्ययों का यहन नियोग द्वारा विद्या जार्गा।
- 4. नियोशम, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुनीवित सामूहिक बीमा स्क्रीम के नियमों की एक प्रति मौर जब कभी उन्नें संगोधन किया जाये, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मकारियों की संदुर्मध्याकी भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुगद स्वाप्त के सूत्रना पट्ट पर प्रवित्त करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्नवारी जो कर्नारी संविष्य निधि का या उथन अधिनित्रम के अधीन छूट प्राप्त कियो स्वापन को संविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो मियोजन गामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के क्या में उसका नाम तुरस्त क्यों ब्रहेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदरत करेगा।

6. यदि उनत स्कीन के अश्रीत कर्मवारियों को उत्तर्ध्य फायरे ये जाते हैं तो, निश्रोजक सामूहित दोमा स्कीम के अश्रीत कर्नवारियों को उपलब्ध फायबों में समुचित का से बृद्धि किये जाते की क्यवंस्था फरेगा जिससे कि कर्नवारियों के निर्माहित दोना स्कीप के श्रात उपलब्ध फायदे उन कायदों से अधित अनुकूत हो जो उना स्कीन के अधीन अनुन्नीय हैं।

7. मान्दित बोना कतान में दिता बात रहा। हुए गा र ेगा कार्मवारी की मूल्यू पर इन स्तोन के जनगा किंग उन रहत ने कर है जो कर्मवारों को उन दवा ने पन हाएं। गा पूर्वा का का कि जना हो।
अना होगा ना गियात होगा के गोल बलील में विदेशियों
की प्रतिकर के देव में दोनां रहतां के अनर के बरानर रहत का संदान
करेगा।

8. सामृहिक बीमा रुकीम के उनवंत्रों में कोई भी संगोधन प्रादेशिक भिविष्य निश्चि आनुकत मध्य प्रश्ना के पूर्व अनुनादन के शिश नहीं किय आए गा स्वीर जहां किमी संगोधन से कर्नवारियों के दिन पर प्रतिकृत भाव पत्रों को समावना हा, नहा प्राहेशिक भिवेश्य कि बाहुत अन्तर अनुनादन दें है पूर कर्नियों का आना वृध्यिकान स्वय्य करा है

9 यदि किस कारगार निर्मा के कारास नारास नोत बोन निगम को उस सामूहिक बोगा स्कोन के , िने स्वान नहते असीत मुका है अजीत नहा रह जाना है याद स्कान के असार करेबिटियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं, तो यह रह की जा सकती है।

10. यदि कियो कारणयग तिमात उप निमन नारोज के भोतर जो भास्तीय जीवन बीमा निगन नियत करे, प्रोमियम का संग्रीय करने में असकन रहता है भीर पानियी का स्थानत हो जाते दिया जाता है तो, छुट रह की जा सकती है।

11 नियान के हारा प्रशिष्ठ के नाम निर्देश में किया करिया कि द्वार में उन एक महत्त्वां के नाम निर्देश किया प्रशिष्ठ करियां के नाम निर्देश की प्रशिष्ठ करियां को जो प्रशिष्ठ करियां के प्रशिष्ठ की प्

12 उनन स्थापन के संप्रंथ में निरोधक इस स्कीम के अधीत आने बाने किसी सबस्य की मृत्यु होते पर उनके हरूबारका नाम निद्यातियों/ बिश्रिक बारिसों को बीमारून राशि रक्तम का नंदाप्र तत्वरता से छोर प्रत्येक बगा मे बारतीय जायन बोमा नियन से बीमारून रक्तम प्राप्त कृति के इक्त मास के भातर सुनिश्चित करेगा।

[नं. ए -35014/17/87-एस. एस-2]

S.O. 2083.—Whereas Messrs. United Electricals, 17-D. Industrial Area, Govind Pura, Bhopal (MP|4892)) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 7 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas on employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.

. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the sald establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the I ife Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for pyment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomine-legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

का. घा. 2081:—मैंसर्घ टेस्ला ट्रांसफार्मरज प्रा. लि., 30-बी, इप्य-स्ट्रीयल एरिया, गोलिन्दपुरा, भोणल (एम. पी./2057) (जिसे इसमें इसके परवात् उक्त स्थापन वहां गया है) ने कर्मनारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध धरिन्दियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके परवात् उक्त प्राधिनियम क्या गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीम खुट दिये जाने के लिए धाउँवन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मेषारी, किसी पृथक प्रक्षिदाय या प्रीमियम का संदाय किये जिना ही, भारतीय कीयन बीमा निगम की सामृत्रिक बीमा कि के कु ध्र्य न जीवन बीमा के रूप में कायवे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से प्रधिक भनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इनमें एसके पश्चात् उक्त रकीम कहा गया है) के ध्रवी : उन्हें अनुशेय हैं,

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त धाधिनिध्य की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इगसे उपस्य धनुसूची में विनिविष्ट शर्तों के धधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की धविब के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

धन्यू **यो**

- 1. उमा स्थापन के सन्बन्ध में नियोजक प्राविधिक प्रविष्य निधि धायुक्त मध्य प्रदेश की ऐसी विषयणियों मेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी गुविधाये प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समयसमय पर निविष्ट करें।
- 2. नियोगक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रक्षितियम की धारा 17 की उपयारा (3 क) के खण्ड क के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूर्डिक जीमा रकीम के प्रणासन में, जिसके धन्तगत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रम्तुन किया जाना, वीमा प्रीमिषम का संवाय, जिलाओं का धन्तरण, निरीक्षण प्रभारो संवाय धावि भी है, होने बाले सभी व्ययों का बहन नियोजक हारा विया जाएगा।
- 4. नियोगन, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रनुमोदिन मामूहिक बीमा स्क्रीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संगोधन किया जाये, सब उस संगोधन की प्रति क्या कर्मेचारियों की धरुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुवाद स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रदिशास करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामृहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त यर्ज करेगा और उसकी खावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबक्त करेगा।
- 6. यदि उनत स्कीम के मधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवें बढ़ायें जाते हैं तो, नियोंगक सामूहिक बीमा स्कीम क भधीन कर्मजारियों को उपलब्ध फायदों में समुधित रूप से वृद्धि कियें जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के भधीन उपलब्ध फायदें उन फायवों से मधिक धनुकूल हो जो उनत स्कीम के भधीन धनुजेय है।
- 7. सामूहिक बीमा स्तीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मवारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संवैय रकम उस रकम से कम है जो कर्मवारी को उस दक्षा में संवैय होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीम होता तो, नियोगक कर्मवारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितो की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के घन्तर के सराबर रकम का संदाय करेगा।

- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भितिष्य निश्चि भायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व भनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिशृख प्रभाव पड़ने की संभावना हो, बहां प्रादेशिक भविष्य निश्चि घायुक्त अपना भनुमोदन प्रेने से पूर्व/कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।
- 9. यदि किसी कारणवंश स्थापन के कर्मचारी शास्तीय जीवन बीमा निगम को उम सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले धपना चुका है सबीन नहीं रह जाना है या इस स्कीम के बंधीन कर्मचारियों को प्राप्त हीने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवर्षा नियोजक उस नियत लारी के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में भ्रमकल रहना है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमिथम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्वेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूटन दी गई होती तो, उनन स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायथों के संशय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होंगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के भ्रधीन भारे वाले किसी सदस्य की मृत्यु हाने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियों/विधिक वारिसों को बीमाइत रकम का संवाय तत्परता से बीर प्रत्येक बना में भारतीय जीवन किएम से बीमाइत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

S.O. 2084.—Whereas Messrs. Tesla Transformers Private Limited, 30-B, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (MP|2057) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (heremafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer

of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient feauties thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the bene available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- . No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomineellegal beins of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S. 35014]76[87-SS. II]

का. मा. 2085:— मैससं-पिकी इलेक्ट्रोनिक्स एवड इलेक्ट्रोकल्ल लि., 7 जलटीस चरवरा मदाबरोड, क्लक्ता-20 (इड्लू. बी./5179) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निश्चि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की घारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का संमाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मकारी, फिली पूथक प्रक्रियाय सा प्रीमियम का संबाय किये जिना ही, सारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्क्रीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मवारियों के लिए ये फायदे जन फायदों से प्रधिक प्रमुक्त हैं जो कर्मवारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें प्रमुक्षय हैं,

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त सिधित्यम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त वाक्तियों का प्रयीग करते हुए और इससे उपाबद्ध भनु-सूची में विभिविष्ट शर्तों के भ्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की सीन वर्ष की भ्रविष्ठ के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट वैती है।

बनुसूची

- 1. उबत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रविधिक भविष्य निधि प्रायुक्त कलकसा को ऐसी विजरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (उक्त) के खण्ड के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामृहिन बीमा स्कीम के प्रयासन में, जिसके ग्रन्तर्गत से बाओं का रखा जाना, निवरणियों, का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का ग्रन्तरण, निरीक्षण प्रधारों संवाय भावि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा विया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोधित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का ग्रनुवाद स्थापन के सूचनुर अर पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मवारी जो कर्मवारी भविष्य निधि का या उक्त प्रिष्ठितयम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की, भविष्य निधि का पहले ही संवस्य है, उसके स्थापन में नियोजिन किया जाता है तो, नियोजन सामू-हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त दर्ज करेगा और उसको बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा।
- 6. मिंद उक्त स्त्रीम के प्राचीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्त्रीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे में गमुजित कप से बृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध कायदे उन फायदों से श्रीवक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनुत्रेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यिष किसी कर्मवारी की मृत्यु पर इस स्कीम के भवीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मवारी की उस वशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के भवीन होता ती, नियोजज कर्मवारी के विश्विक वारिस/नाम निवंशिती को मितकर के क्य में दीनों रक्तमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीटके उपवंक्यों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक श्विविध्य निधि मायुक्त कलकत्ता के पूर्व मनुमीयन के जिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पढ़न की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि श्रीयुक्त मपना मनुमीयन देने से पूर्व कर्मचारियों की ग्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त मवसर देगा।
- यदि किसी कारणवश्च स्थापन के मर्मेनारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहित बीमा स्त्रीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका

है सधीन मही रह जाता है या इस स्कीम के सधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले पायवे किसी रीति से नम हो जाते हैं, हो यह रहू की जा सकती सकती है।

- 10. यदि किसी कारणवंश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करें, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यवकान हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह. की जा सकती है।
- 11. मियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की बन्ना में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के भन्तर्गत होते बीमा फायदों के संवाय का उत्तर वायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के स्सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन बाले बाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्वेशितियों/ विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम का संबाय तरफरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन जीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014 (75)/87-एस. एस-2]

S.O. 2085.—Whereas Messrs Peico Electronics and Electriculs, Limited, 7, Justice Chandra Modhab Road, Calcutta-700020 (W.B./5179) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establismenht are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group narrance Scheme as approved by the Contral Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in

- his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give R reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S. 35014(75)/87-SS.II]

का. था. 2086:—मैसमें मुपर स्पॅनिंग मिरुज लि., ए-पूर्ति हिन्तुपुर, आन्छ प्रदेश (ए. पी./2678) (िहे इपमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कमेंनारी मित्रिय निधि और प्रकीर्ण उत्तवन्य मधिनियम, 1952 (19द्2 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उनक अधिनिय कहा गया है) की सारा 17 की उपसारा (2क) के भधीत सूट दिये जाने कहा गया है। की सारा है।

बीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन्त स्यापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीगियम का संदाय किये विना ही, भाग्तीय जीवन दीमा निगम की सामृहिक वीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए के फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत है जो कर्मचारी निजेन सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुकृत हैं।

धतः केन्द्रीय सरकार, उकत प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 क द्वारा प्रवत्त गरितयों का प्रयोग करते हुए और इसदे उनावद्ध धनु-सूची में किनिविष्ट शर्तों के प्रधीन रहते हुए, उकत स्थापन को तीन वर्ष की प्रविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

धनुपुषी

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भरिष्य निधि धायुक्त, ज्ञान्ध्र अवेश को ऐसी विवरणियां गेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधार्थे प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केस्त्रीय मरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3 क के खण्ड क के ध्रधीन गमय-समय पर निर्धिण्ड करें।
- 3. सागृहिक जीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का का रखा जाना, जिवरणियों का प्रस्तुस किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का प्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय खावि भी है, होने वाले सभी ब्ययों का बहुत नियोजक हारा किया जाएगा ।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय . सरकार द्वारा धनुमोवित सामूहिक भीमा स्क्रीम के नियतों भी एक प्रति धौर जब कभी उनमें संशोधन किया आसी, सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की धनुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्टू पर प्रविधित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी मिवज्य निधि का या उपन अधिनियम के अधील छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य तिथि का पहले ही सदस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिंक बीभा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत ज्ञावस्थक प्रीमियम भारतीय जीवन बीभा निगम को संदक्त करेगा।
- 6. यदि उक्त रकीम के अधीन कर्मभारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तां, नियोजक सामूहिक कीमा स्कीम के अधीन कर्मभारियों की उपलब्ध फायदों में मिमुदिन रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मभारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदें उन फायदों से अधिक अमूकुल हो जी उक्त स्कीम के अधीन अनुनेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेव होती अब वह उत्तत स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक अर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितो की प्रक्षित है हप में दोनों रकमों के प्रश्तित है बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक भविष्य निधि धायुक्त, धान्ध्र प्रवेश के पूर्व धनुमोवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत्व प्रभाव पड़ने की संभावना हो, धहां प्रावेशिक भनिष्य निधि भायुक्त अपना धनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिक्क्किण स्पष्ट करने का युक्तयुक्त अपसर वेगा ।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के पर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भपना चुका है स्थीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के स्थीन कमेचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं, तो यह रह् की जा सकता है।
- 10. यदि किसी कारणयण नियोजक उस नियत्तारी के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में प्रमक्त रहना है और पालिसी को व्यप्यम हो जाने विया जाना है तो, कृट रह की जा सकती है
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाध में किये तथे किसी व्यतिकम की दशा में उन मृत मदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिष्ठ वारिसों को

- जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के ध्रम्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोचक इस स्कीम के म्राधीन भ्राने वाले किसी सबस्य की मृत्यु होने गर उनके हकदार नाम निर्वेशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदात्र तलरना से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्रान्त हाने के एक मास के भीतर सुनिश्वित करेगा ।

" [सं. एस-35014 (74) 87-एस. एस-2]

S.O. 2086.—Whereas Messrs Super Spinning Mills Limited, A-Unit Kirikera-Hindupur, Andhra Prade (AP/2678) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exempt on under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and subject to the co-ditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government may, from time to time, direct under from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Funds Commissioner, Andhra Pradeels and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the lnguage of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that

would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to asplain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as affeady adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Tour-opportunity to the employees to explain their point of view.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[Not S. 35014(74)/87-SS.II]

का प्रा 2087: मैसर्स गोमधी स्पीनर्ज बंगारूपलम 517416, बित्तूर जिला, प्रान्ध्र प्रदेश (ए. पी /13177) (जिसे इसमें इसके प्रश्वात् उक्त स्थापन करा गया है) ने कर्मवारी मिवाय निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसें इसके प्रश्वात उक्त ध्रक्षिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क्षं) के प्रधीन छूट दिये जाने के लिए ध्रावेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या पीमियम का संवाय किये विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की साम्हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और गैमे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनूकुल हैं जो कर्मचारी निजीप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमे इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभेय है,

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रीधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 क द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करने हुए और इसमे उपाबद्ध श्रन्-सूची में विमिर्विष्ट शर्तों के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीम वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देनी है।

ग्रन<u>्</u>यूची ं

- 1 उक्त स्थापन के सम्बद्ध में नियोजक प्रादेशिक शिवष्य निधि खायुक्त ग्रान्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाध्नि के 15 दिल के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उन्त ध्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3 क के खण्ड क के ध्रिधीन समय-समय पर निरिष्ट करें।

- 3 तामृहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके सत्तर्गत नेवाधों का रखा जाना, जिवरणियों का प्रस्तुन किया जाना, बीमा झीमियन का संदाय, लेखाओं का भ्रन्तरण, निरोजण प्रभारों का संदाय छादि भी है, होने थाने सभी व्ययों का बहुन नियोजक हारा दिया जारूगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा ध्रतुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब बामी उनमें संगोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति नक्षा कर्मवारियों की बहुनव्या की भाषा में उसकी मुख्य बानों का ध्रतवाद स्थापन के पृथना पहुंपर प्रदर्शित होता ।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मनारी जो कर्मजारी सविष्य निधि का या उन्त भिधिनयम के भ्रधीन खूट प्राप्त किसी स्थापन को भिविष्य निधि का पहते ही सदस्य है, उसके स्थापन से निर्मातित किया जाता है तो, निर्माण क सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के का में उपका नाम तुरस्त दर्ज करेगा और उपका बावत भ्रावण्यक प्रीसियम भारतीय जीवन बीमा निश्म की संबत्त करेगा।
- 6. यदि उन्त स्कीम के ध्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बहाये जाते हैं तो, ब्रिशोजक सामूहिक बीमा स्कीम के ध्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचिन रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदें उन फायदों से ध्रधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के मधीन अनुक्रेम हैं।
- 7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के श्रधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संत्रेय होती अब वह उक्त स्कीम के ध्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिण/नाम निर्देणिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमीं के अन्तर के बरावर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिंक बीमा स्कीम के उपबन्धों म कोई भी संगोधन प्रादेशिक भविष्य निशि श्रामुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व भ्रनुमोदन के बिना नहीं किया अएगा और जहा किसी संबोधन में कर्मचारियों के छित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की मंभावना हो, वहा प्रादेशिक भविष्य निधि श्रामुक्त श्रपंता श्रमुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों का श्रमना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा ।
- 9. यदि किसी कारणवंश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिमे स्थापन पहले भ्रयता चुका है अधीन नहीं रह जाना है या इस स्कीम के श्रवीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे कि री रीनि से कम हो जाने हैं, तो यह रह की जा सकती
- 10. यदि किमी कारणवश नियोजक उस निया नारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियंत करें, प्रीमियुम का संदाय करने में अमफल रहता है और पालिमी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी क्यतिक्रम की दला में उन मृत सदस्थों के नाम निर्देशितिया या जिल्लिक त्रारिनों को जो यदियह छूट न वी गई होती तो, उक्त स्कीम के श्रन्तर्गन होते । बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । '
- 12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीय के ध्रश्नीत ध्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उगके हकदार नाम निर्देशितियों/ विश्विक वारिसों को बीमाक्कृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रस्थेक दशा में भूगितीय जीवन बीमा निगम से बीमाक्कृत रकम प्राप्त होने के एक माल के भीतर मुनिण्चित करेगा ।

[म. एस-35014 (73) 87-एस. एस-2]

S.O. 2087.—Whereas Messrs Gomethy Spinner Bangarup alyam-517416, Chittoor Distt, Andhra Pracesh (AP/13177) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 thereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of, all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Régional Provident Fund Commissioner. Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and nay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Groun Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme he less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurface Scheme shall be made without the pilot approval of the Regional Provident Fund Commissioner Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable approval give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view

- 2. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the I ife Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of daftult, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S. 35014(73)/87-SS.II]

का. आ. 2088 -----नैसर्स समैदा इन्डस्ट्रीज, 6/1, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गोविन्दपुरा, भोपाल (म प्र) (एस. पी./1624) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपकृष्य भित्रित्तगम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के भर्धीन छूट दिये जाने के लिए ग्रावेदन किया है।

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारों किसी पृषक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीका स्कीम के अधीन जीवन के रूप में फायवें उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महुबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इममें इसके पण्चान् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुनेय हैं.

श्रम केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्राधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क हारा प्रदक्त पक्तियों का प्रयोग करने हुए ग्रीर इससे उपबाद भन्सूची में बिनिर्दिष्ट गर्नों के ग्राधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की ग्राथि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपग्रन्थों के प्रवर्तन छूट देती है।

धन्सूची

- 1. उक्त स्थापन कें सम्यन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि धायुक्त, मध्य प्रवेश की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा नथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधार्थे प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पन्न निर्दिष्ट करें।
- 2 तियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक सास की समास्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धार। 17 की उपधार। 3 क के खण्ड क के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में जिसके मन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रम्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाओं का घन्नरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय घावि भी है, होने वाले सभी व्ययों का यहन नियोचक कारा दिया जाएगा।
- 4 नियोगक, केन्द्रीय सरस्रार द्वारा चनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमो की एक प्रति भीर जब कथी उनमे संशोधक कियाँ जाये, तब उस राशोधक की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसक्या की भाषा में उसकी मुख्य निष्कों की चनुवाद स्थापन से सुचता पड़ पर प्रदेशित करेगा ।

- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी श्रविष्य निधि का या उक्त श्रिधितयम के श्रधीन छूट प्राप्त किर्मा न्यापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियाजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के यवस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा श्रीर उसकी बाबत आयाय्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का सदल करेगा।
- 6. मदि उन्द स्कीम के ग्रंथीन कर्मनारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ायें जाते हैं तो. नियोजक सामृष्टिक बीआ स्काम के ग्रंथीन कर्मबारियों की उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से बृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मबारियों के लिए सामृद्धिक बीमा स्कीम के ग्रंथीन उपलब्ध फायदे उस फायों से ग्रंथिक श्रंपुकृत हो जो उक्त स्कीम के ग्रंथीन ग्रंपु- जेय हैं:
- 7 सामूहिक बीमा स्वीत भ किसी वान के हीते हुए भी ,यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर एसे स्कीम के प्रवीत सदेय रक्षम उस रक्षम से कन है, जो कर्मचारी की उस दण, में संधेय होतों जब वह उनत स्कीम ने प्रधीत होता तो, सियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों की प्रतिकट के रूप में दीनों के प्रत्यार के बरावर रक्षम का संदाय करेगा।
- 5. सामृहित कीमा स्कीम के उपबन्धों में काई की संशोधन प्रादेशिक सिविष्य निधि धायुक्त मध्य प्रवंश के पूर्व ध्रमुमोदन के विना नहीं किया जाएगा भीर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रान-कूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहा प्रादेशिक भविष्य निधि ध्रायुक्त ध्रवना सनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकांण स्पष्ट करन का युक्तियुक्त ध्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन वीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारिया की प्राप्त . होने वाले कायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, सो यह रह की जा सकती हैं।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोगक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन कीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में प्रसक्त सकती है भीर पालिमा को व्ययगत हो जाने दिया जाना है तो, छूट रह की जा रखता है।
- 11. नियोजक हारा प्रीप्तियम के संदाय में किय गये किसी व्यक्तिप्रम की दशा में उन सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसो की जो यदि यह छूट न दी गई होती हो, उनत मैंकाम के प्रन्तर्गत होते जाना फायदी के मदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 1.2. उक्त स्थापन के गम्बन्ध में नियोजन इस स्कीम के प्रधीन प्रान वाले किसी गवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियो/विधिक वारिसों को बीमाफ़त रकम का संदाय तत्परता में घीएं प्रत्येक दला में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाफ़त रकम प्राप्त होने के एक भाम के भीतर मुनिश्चित करेगा

[संख्या एस-35014 (72)/ 87-एस, एस -2]

S.O. 2088.—Whereas Messrs Narmada Industries, 6/1. Industrial Estate, Govindpura, Bhopal (M.P.) (MP/1624) thereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lile Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said. Act and subject to the conditions specified in the Schedule amexed hereto, the central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in telation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Commun Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the estations meeting a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Limployces' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employee in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corpolation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available, to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer tails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any rade by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nomineer or the legal heirs of deceased members who would have been coveted under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life insurance Corporation of India shall ensure

prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S. 35014(72)/87-SS.11]

का आ 2089 --- मैसर्च डेबी एसमीर इन्डिया लि , 6 ए , भिडणटन स्ट्रीट कलकत्ता 700001 (इन्यू. बी./11265) भीर इसकी प्राखाए जो कौड नं. के मधीन कवरड हैं (जिसे इसमें इसके प्रकात् उपन स्थापन कहा गया है) ने कमेंचारी भविष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबन्ध शिक्षित्यम, 1952(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त श्रीधिनयम कहा गया है) को भारा 17 की उपधारा (2क) के भीषीन खूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

श्रीर केर्द्राय मरकारका समाधान हो गया है कि उन्नल स्थापन के कर्मजारी, किसी पृथक ग्राभिवाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवम बीमा के रूप में फायब उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से ग्राधिक ग्रनुकुल हैं जो कर्मचारी निश्चेष यहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे असमें इसके प्रचान उन्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें श्रनुक्षेय हैं,

श्रत : केन्द्रोय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 का उपधारा 2-क द्वारा प्रदम गक्तियों का प्रयोग करते हुए भौर इससे उपावद श्रनु-सूची मे विनिर्दिष्ट गर्तों के श्रद्यान रहते हुए उक्त स्थापन को र्तान वर्ष की श्रविध के लिए जुक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

भनुसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक ध्विष्य निधि प्रायुक्त कनकक्ता को ऐसी विवरणियां भेजेंगा और ऐसे लेखा रखेंगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधायें प्रवान करेंगा जो केन्द्रीय सरकार, सभय-समय पर निविष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाध्ति के 15 विन के भीतर संदाय करेंगा जो केन्द्रीय सरकार, उपत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड क अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके धन्मर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुन किया जाना, बीमा प्रीमियम का संप्रार्थ, लेखाओं का धन्तरण, निरीक्षण प्रभागें संदाय ध्रादि भी है. होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियांजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रनुमादित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति श्रीर जब कभी उनमें सशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उमकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदेशित करेगा ।
- 5. यदि कोई ऐसा वर्मचारी जो कर्मचारी भिन्नष्य निधि काया उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भिविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके रथापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामू- हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदन करेगा।

- 7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्नबारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान सदय रकन उस रकम से कम हे जो कर्मबारी की उस दशा में सदय होती जब वह उपन स्कीम के प्रधान होती तो, नियाजक कर्मबारी के विधिक बारिस/नाम निर्देशित की प्रतिकर के स्पा में दोनों रकमी के घल्लार के बराबर रकन का संवाय करें।
- 8. सामृहिक, बाम स्कोन के उपबन्धा में कोई भी छंका त प्रादीक्षक भविष्य निधि प्रायुक्त कलकत्ता के पूर्व अनुमोदन के जिना नहीं किया जाएता और जहां किसी संशोधन से कर्मजारियों के हित पर अजिकूल अभीव पढ़ने की संभावना हो, यहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त माना मनुमादन देने में पूर्व कर्मजारियों को अपना दृष्टिकाण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त मवमर देगा।
- 9. यदि किही कारणयम स्थापन के कर्मभारी भारताय जीवन बीमा निगम का उस सामूहक बीमा स्काम के, जिसे स्थापन पहले भाषना चुका हे मधीन निही रह जाता है या इस स्कीम के मधान कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले क्रायद किती राति स कम हो जात ह, तो यह रह का जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण नियाजक उस नियत तारीख के भीतर ज भारताय जावन बाना नियन नियत कर, प्रतिभयम का संवाय करन में असफल रहेता है आर पालिसा का व्ययमन हा जाने दिया जाता है ता, छूट रह का जा सकर्ता है।
- 11. नियानक द्वारा प्रानियम क सदाय म किये गथ किया व्यक्तिम का दशा म उन मृत सदस्या क नाम निदायतिया या विधिक वारिसा का जा याद यह छूट न वा गई हाता तो, उन्त स्काम क मन्तगंत हाते तो बामा फायदा क सदाय का उत्तरवायित्व नियानक पर हाया ।
- 12. उनते स्थापन क सम्बन्ध म नियानक इस स्काम क अधान मान वाले किसा नदस्य का मृत्यु होन पर उसक हकदार नाम निदाणितया, व्याधिक बारिसा का बामाक्कन रकन का सदाय तत्वरता स भार प्रस्यक दणा म भारतत्य जावन बामा निर्णेम स बामाक्कत रकम प्राप्त होने क एक मास क भातर मुनिश्चित करेगा।

. सि. एस. --35014 (71) 87-एस. एस. 2) . क. भट्टाराइ, सबर संत्वव

S.O. 2089.—Whereas Messis Davy Ashmore India Limited, 6-A, Middleton Street, Calculta-700001 (WB/11203) and its branches covered uncer the same code No. (hereinatter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Migoflaneous Provisions Act, 1952 (19-of 1952) (hereinalter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment or benefits under the Group insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinalter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of suc section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Nouce Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Schome as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Imployees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the croup Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees that the benefits admissible under the said Scheme.
- 7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nonunce of the employee as compensation
- 8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance

- of the Life Insuronce Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be hable to be cancelled.
- 10 Whose, for any reason, the employes fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer
- 12 Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the ronnnee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No S 35014(71)/87 SS II] A K BHATTARAI, Under Secy

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1987

का भ्रा 2090 — सिनेमा कर्मकार जीर सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) श्रिधिनियम, 1981 (1981 का 50) की धारा 2 के खड (घ) के अनुसरण मे, केन्द्रीय मरकार नीचे दी गई मारणी के कालम (1) में उल्लिखित जम्मू जीर कश्मीर मरकार के अधिकारी को उक्त मारणी के कालम (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि म विनिद्दिट क्षेत्र के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए प्राधिकृत करनी है —

श्रिधिकारी का पदनाम श्लेव श्ल

मारणी

New Delhi, the 24th July, 1987

S.O 2090—In pursuance of clause (d) of section 2 of the Cine-Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act, 1981 (50 of 1981), the Central Government hereby authorises the officer of the Government of Jammu and Kashmir mentioned in column (1) of the Table below, to perform the functions of the competent authority under the said Act for the area specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table:—

T	Δ	R	ì	н

	Désignation of the Officer	-	Area	
1	Labour Commissioner		Whole of Janumu	

2

का . ग्रा . 2091 :—सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर
कर्मकार (नियोजन का विनियमन), 1981 (1981
50) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए,
केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में
उल्लिखित जम्मू और कक्मीर सरकार के श्रिधिकारियों को
उक्त सारणी के कालेम (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में नि-
दिष्ट क्षेत्र के लिए उक्त भ्रधिनियम के प्रयोजनार्थ मंशोबन
म्राधिकारी नियुक्त करती है .—

सारणी

 ग्रधि	 कारी क	_ · _ ग पदनाम	—	 श्रोव	
—–	-	-	- ' —		
		1		2	
- *	-				
Ţ	सहायक	अभायक्त,	श्रीनगर	जिला श्रीनः	ार

जिला भ्रनंतनाग

सहायक श्रमायुक्त, बारामुल्ला

जिला बारामुह्ला

4. सहायक श्रमायुक्त, क्पवाङ्ग

जिला कृपवाडाः -जिला जम्मू

सहायक श्रमाय्क्त, जम्मू

सहायक श्रमायुक्त, अधमपुर ।

जिला ऊधमपुर जिला कथुग्रा

7. सहायक श्रमायुक्त, कथुन्ना 8 सहायक श्रमायुक्त पुछ

जिला पुछ

9. सहायक श्रमायुक्त, राजौरी

जिला राजौरी

10. सहायक श्रमायुक्त, डोडा

जिला डोडा

1

11. सहायक श्रमायुक्त, लेह

जिला लेह

12. सहायक श्रमायुक्त, कारगिल

जिला, कारगिल

सं. [एस~61011/5/87—डी-1 (ए) (ii)]

नन्द लाल, ग्रवर सचिव

S.O. 2091 In exercise of the powers conferred by section 4 of the Cine-Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act, 1981 (50 of 1981), the Central Government hereby appoints the Officers of the Government of Jammu and Kashmir mentioned in Column (1) of the Table below to be Conciliation Officers for the purposes of the said Act, for the area specified in the corresponding entry in Column (2) of the said Table:—

TABLE

	Designation of the Officer	Area
1.	Assistant Labour Commissioner, Srinagar.	Srinagar District
2.	Assistant Labour Commissioner, Anantnag.	Anantneg District.
3.	Assistant Labour Commissioner, Baramulla.	Baramulla District.
4.	Assistant Labour Commissioner, Kupwara,	Kupwara District.
5.	Assistant Labour Commissioner, Jammu.	Jammu District.
6.	Assistant Labour Commissioner, Udhampur.	Udhampur District.
7.	Assistant Labour Commissioner, Kathua.	Kathua District.
8.	Assistant Labour Commissioner, Poonch.	Poonch District.
9.	Assistant Labour Commissioner, Rajouri.	Rajouri District.
10.	Assistant Labour Commissioner, Doda.	Doda District.
11.	Assistant Labour Commissioner, Leh.	Leh District.
12.	Assistant Labour Commissioner, Kargil.	Kargil District.

[No. S-61011/5/87-D.I(A)(n)] NAND LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1987

का , ग्रा , 209 2:--केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवास प्रधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 27 द्वारा प्रवस मिन्तयों का प्रयोग करते हुए, भ्रवर मचिव, उत्प्रवास प्रभाग, नई दिल्ली को. ग्रधिनियम के ग्रधीन किसी भ्रपराध की बाबत किसी व्यक्ति के ग्रिभियोजन के लिए पूर्व मैंजूरी प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[मं. जैष्ड-11025/30/87--उत्प्रवास-II] ए० बी० एस० शर्मा, अबर सचिव New Delhi, the 24th July, 1987

5.0: 2092,-In exercise of the powers conferred by section 27 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Under Secretary, Emigration Division, New Delhi to grant previous sanction for prosecution of any person in respect of any offence under the Act.

> [No. Z-11025(30)/87-Emig.II] A. V. S. SARMA, Under Secy.

नई बिल्ली, 27 जुलाई, 1987

फा॰ आ॰ 2093:-- उत्प्रवास भिन्नियम, 1983 (1983 का 31) ी धारा 5 द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय संदेकार ा उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय, मद्राय में महायक श्री भ्रार० मृन्दरलाल हो दिनांक 17-6-1987 को उत्प्रवास संस्की, मद्रास के सभी कार्य र्हरने के लिये प्राधिकुए कियां है।

[संख्या ए० 22012/1/86 उत्प्रवास **II**)] ए०वी०एस० शर्मा, भवर सचिव

New Delhi, the 27th July, 1987

S.O. 2093.—In exercise of the power conferred by Section of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Jovernment authorised Shri R. Sundar Lal, Assistant in the office of Protector of Emigrants, Madras, to perform all func-ion of Protector of Emigrants, Madras on 17-6-1987.

[No. A-22012]1]86 Engration-II] A. V. S. SARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1987

का . या . 2094 .-- औद्योगिक विवाद मधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के श्रनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय लोक निर्माण बिभाग हिन्डन गाजियाबाद के प्रवधतंत्र मे सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच, ग्रनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, नई दिल्ली के पवाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय भरकार को 10 जुलाई, 1987 को प्राप्त हश्राथा।

New Delhi, the 24th July, 1987

S.O. 2094.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Aunexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of C.P.W.D. Hindon Ghaziabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th July, 1987.

BFFORE SHRI G. S. MALMA. FRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 26/86

In the matter of dispute between:

Shri Barkat Ram, Assistant Operator (E&M), 11988-Motia Khan, Gali Pippal Wali, Delhi. प्रस्वा में 👝

Versus

The Executive Engineer, Central Electrical Sub-Division I,
Hindon Ghaziabad, C.P. W.D. TIEFF PURTY IN

APPEARANCES:

Shri B. Ku Aggarwalimfor the workman 11 1905 ()? Shri Narinder Chaudhary for the Wandscheft of agact to raise here on a dword war gold to be the following the benefit to a control of the con

TheoCentral Government in the Ministro of Andur wide intermediation No. 1142012/40/85-DII(B) uthtel 8th Jahuary 1980 Hastreferred the inflowing industrial disputcion this Tribunal for adjudication: [80] And diff add as income Tribunal for adjudication:

"Whether the action of Executive Engineer Electrical for Hindon Central Electrical Sub-Division-I, CPWD, in refusing Shri Burkat Ram, Assistant Operator, to resume duty from 1st February, 1980 is legal and justified. If not to what relief the concerned workmen is entitled to?"

Some of the undisputed facts are that the workman Shri Barkat Ram joined service with the Management as Assistant Operator on 24th February, 1967; that he was made semi-permanent w.e.f. 1st September, 1969 and was working under the Court of the Charlest and charge at the Electron Division standard. the Control and charge of the Electrical Division Hindon Sub-Division-I CPWD Ghaziabad; that the workman did not perform duty from 1st June, 1969 to 31st Jan. 1980; that the worklan reported for duty on 1st February, 1980 and submitted a medical certificate but was not allowed to join duty; that a charge sheet was served on the workman on 30th August, 1982 to which the workman submitted his reply dated 10th September, 1982; that a domestic enquiry was ordered against the workman and the first hearing was held. on 29th December, 1983 and that the workman was allowed to join his duties w.e.f. 13th Match, 1986.

3. Since the workman has admittedly been allowed to join duty w.e.f. 13th March, 1986 the dispute now boils down to the payment of back wages and the continuity of service from 1st February, 1980 to 12th March, 1986. At the outset, it may be observed that the very fact that the Management has allowed the workman to join duty w.c.t. 13th March, 1986 amounts to admission that the earlier action of the Management in not allowing the workman to join duty w.e.f. 1st February, 1980 was clearly wrong Rule 19(1) of the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972 supulates that an application for leave on medical certificate made by nongazetted government servant shall be accompanied by a nightcal certificate, in form IV given by an authorised medical attendant or a registered medical practitioner. Sub-Rule 3 of rule 19 further provides that the authority competent to grant leave may at its discretion seeme a second medical opinion by requesting a government medical officer not bellow the rank of Civil Surgeon or Staff Surgeon to have the applicant medically examined on the earliest possible date. Now it is admitted that the workman had filed a medical certificate from a registered medical practitioner at the time of submitting joining report on 1st February, 1980. Thus the only curse open to the competent authority was either to account medical certificate produced by the workman are to secure medical certificate produced by the workman or to secure second medical opinion by requesting a Government Medical Officer to have the applicant medically examined on the earlier possible date. MW1 Shri K. K. Verma, X.En. CPWD. Hindon Central Electrical Division Ghazabad has stated in cross-examination that the workman was asked to produce medical certificate from Government Doctor the moment he had produced medical certificate from Private Practitioner, No written order was given and that the workman was not asked to appear betote any particular Government Dactor, by a specific order. This was clearly contrary to Sun-Ripe 3 of Rule 19 ibid because it was for the competent authority to secure a second medical opinion by requesting a Governto secure a second medical opinion by fequesting a Government Medical Officer to examine the applicant and the applicant could not have been asked to produce certificate from the Government Medical Officer. The Government of India have given detailed instructions under Rule 11 in Part 1 of the C.C.S. (CCA) Rules as 10 how the unauthorised observed that the employee is to be treated. It has been suggested that the employee found to be an inflanting seed absence should be asked to reddin duffit within a specific period, However, no such letter was issued by the Manuschert in the case of the workman. It has further been suggested that if an employee reports for duty during discipling y proceeding over them. reports for duty during disciplinary proceeding over them he should be allowed to join duty. In the present case the workman had reported for duty on his nyn even hefore, the workman had reported for duty on his nyn even hefore, the initiation of any disciplinary proceedings and he should have been allowed to join duty and then? must be considered necessary However, had management was missing in the workman to join duty weef. 1st February. 1980. It has been held in 1964-42) S.L.R. 163 Kerala that putting an employee off duty without any enging and non-1980. It has been held in 1984 (2) S.L.R. 101 Kerala mai putting an employee off duty without any enquiry and non-payment of salary for an unduly long period is mala fide and unauthor sed, at all the first officially at all the first officially at office was writing at the way without any office was a supplied to the way without any end of the way with any end o August, 1982 when a chargesheet was served. Even then the enquity was unduly prolonged and the first hearing was held only on 29th December, 1983. The request of the Management that it may be allowed to continue with the enquiry on the charge sheet dated 30th August, 1982, must be declined because the Management failed to follow the rules and seek second medical opinion which was possible only on 1st February, 1980 when the workman had reported for duty and it is too late in the day now to seek a second medical opinion. Under the encumstances, it is held that the action of the Management in refusing the workman to resume duty from 1st February, 1980 was not justified The workman, is, therefore, entitled to full back wages with continuity of service for the period upto 12th March, 1986 and the reference stands disposed of accordingly.

Further, it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

> G. S. KALRA, Presiding Officer [No. I -42012/40/85-D II(B)] HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 24 जल^गई, 1987

का . मा . 2095 . -- औद्योगिक विवाद मिशिनयम 1947 (1947 को 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मोहन कोलियरी और धेस्टर्न कोल फील्डम लि. जिला छिन्दवाडा (म.प्र.) के प्रबंधतंत्र पोल्ट झनारदेव. मे सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, धनवंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय मरकार औद्योगिक ग्रधिकरण, जबसपुर के पंचांट को प्रकाशित करती है. जो केन्द्रीय सरकार को 13-7-87 को प्राप्त हम्राया।

New Delhi, the 24th July, 1987

S.O. 2095.—In pursuanc of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mohan Colliery of W.C. Ltd., P.O. Junnardeo, District Chhindwara (M.P.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th July, 1987.

BEFORE SHRI V. S. YADAV. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

Case No. CGIT/LC(R)(31)/86

PARTIES:

Employers in relation to the management of Mohan Colliery of Western Coalfields Limited, P.O. Junnardeo. District Chhindwara and their workman Shil I. U. Chisty, Leave Clerk, Datla East Colliery P.O. Junnardeo, District Chhindwara (M.P.).

APPFARANCES:

For Workman-Shri S. K. Rao, Advocate.

For Management-Shri P. S. Nai, Advocate.

JNDUSTRY · Coal Mines. DISTRICT : Chhindwara (M.P.)

AWARD

Dated, the 2nd July, 1987

The Central Government in exercise of its powers under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication, vide Notification No. L-22012(46)/85-D. V, dated the 10th February, 1986:

"Whether the action of the management of Mohan Colliery of Western Coalfields Limited, P.O. Junnai deo, District Chhindwana (M.P.), in dismissing Shri I. U. Chisty, Leave Clerk from 3rd July, 1981 is justified? If not to what relief the workman is entitled?'

This case was registered on 24th February, 1986. Thereafter parties filed their respective pleadings. Workman raised certain preliminary points. After hearing both the parties I passed a detailed order on 8th April, 1987 and held that the domestic enquiry was not fair and just. The case was then fixed for filing documents on next. But the natties have filed settlement before me which is duly signed by parties and verified on behalf of the management by Shri P. S. Nair Advocate.

- I have gone through the settlement and I find that the settlement is mutual just and fair and in the interest of the workman.
- . I, therefore, pass award in terms of the settlement which are as follows:-
 - It was agreed that Shri I. U. Chisti will be taken back in employment as Clerk Gr. II and he will be posted in any of the units of Kanhan Area.
 - It was agreed that the period of idleness from 3rd July, 1981 to the date of employment will be treated as dies-non i.e. 'No work, No pay' basis However, the said period will be counted for the limited purposes of continuity for gratuity payment.
 - It is further agreed that he will be allowed notional fixation with incremental benefits but no arrear for the above veriod will, be paid While fixing him notionally, the last basic pay drawn by him will from the basis for subsequent increments and benefits are the particular of th fits accruing on account of fixation in NCWA-III.
 - It was agreed that action will not be taken against Shri Chisti on the basis of any other charge-sheets pending against him as on date
 - In view of the above, he has agreed to give up all other claim/benefits and accept the above terms as full and final settlement and shall not claim any other benefit in respect of the matter in dispute.
 - It was agreed that this settlement shall not be treated as precedent in any other case.
 - The parties agreed to file compromise settlement before the Presiding Officer, C.G.I.T., Jababuar and request for an Award in terms of the settlement.

V. S. YADAV, Presiding Officer

[No L-22012/46/85-D. V]

का. श्रा. 209 6. -- औद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केम्द्रीय सरकार, रावनवारा ग्रुप आफ माईनस, श्राफ वेस्टर्म कोल फीरुडम लि., पोस्ट परामिया, जिला छिन्दवाङ्ग (म.प्र.) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच. ग्रनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक ग्रधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाणित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-7-87 को प्राप्त हम्रा था ।

S.O. 2096,—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government bereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rawanwara Group of Mines of of W.C.L.P.O. Purasia, District Chhindwara (M.P.) and their workmen, which was receved by the Central Government on the 13th July, 1987.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT JABALPUR

Case No. CGITLC(R) (89) 86

PARTIES:

Employers in relation to the management of Pench East Incline of Rawanwara Khas Colliery of W.C.L. Pench Area, P.O. Parasia, District-Chhindwara and their workmen Shri Ramalal, Attendance Clerk represented through the General Secretary, BKKMS (BMS), P.O. Chandametta, District Chhindwara (M.P.).

APPEARANCES:

For Workmen-None.

For Management-Shri Rajendra Mohan, Advocate.

INDUSTRY: Coaf Mine, DISTRICT: Chhindwara (M.P.).

AWARD

Dated the 2nd July, 1987

The Central Government in exercise of its powers under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication, vide Notification I.-22012[21|86-D.V. dated the 24th October, 1986.

"Whether the action of the management of Pench Fast Incline of Rawanwara Khan Colliery of WCL Pench Area, P.O. Parasia, District—Chlindwara in dismissing Shri Ratanlal, Attendance Clerk from service with effect from 25-3-84 is justified? If not, what relief the concerned workman is entitled to ?'

This case was registered on 8th December, 1986, Thereafter parties contested the dispupte by filing their respective statement of claim. The case was fixed for filing documents and issues but the parties have filed settlement duly signed by them and verified on behalf of the management by Shri P. S. Nair, Advocate,

I have gone through the settlement and I find that the settlement is mutual, lawful and in the interest of the workmen.

I therefore, pass award in terms of the settlement which are as under

- It is agreed by the management to reinstate Shri Ratanlal x-clerk at Shivpuri No. 2 Mine in Pench Area, He shall report for duty to Manager Shivpuri No. 2 Mine within one month from the date of the settlement.
- 2. The period of absence from the date of dismissal to the date of joining will be treated as dies-non.
- 3. Shri Ratanlal will not be entitled to wages for any other payment whatsoever for the period of idleness from the date of dismissal to the date of reinstatement.
- 4. On reinstatement Shri Ratanial will be kept on probation for a period of one year during which period his performance and conduct will be closely watched. An assurance of good performance and conduct will be furnished by the workman in writing before joining the duties. If performance and or conduct during the probation period is not found satisfactory, his services will be liable to be terminated. However, if his performance and conduct during the probation period are found satisfactory the management may consider to grant him continuity of service for the limit purpose of payment of gratuity.
- 5. The Union/workman agreed to drop all other claims benefits in respect of the matter under dispute.

- 6. This settlement settles the dispupte fully and finally and it shall not be treated as precedent if any other
- 7. The parties agree to file the compromise settlement before the Presiding Officer, CGIT Jabalpur and request for an Award n terms of the settlement.

V. S. YADAV, Presiding Officer [No. L-22012]21[86-DV]

का आ . 2097--- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सब-एरिया न Π , घुगुस कोलियरी, **मैसर्स नैस्टर्न** कोलफील्ड्स लि., डाकघर घुगस, जिला-चन्द्रापुर (महाराष्ट्र) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, श्रनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक श्रधिकरण, जबलपुर के पंचांट की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-7-87 को प्राप्त हुम्रा था ।

S.O. 2097.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the industrial disputte between the employers in relation to the management of Sub-Area No. II, Ghugus Collieries, M|s. W.C. 14d P.O. Ghugus, District Chandrapur (M.S.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th July, 1987.

BEFORE SHRI V.S. YADAV, PRESITING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABATPUR

Case No. CGIT/LC(R) (70)/190/

PARTIES:

Employers in relation to the management of M/s. Western Coalfields Limited in Sub Area No. U. Ghugus Colliery, P.O. Ghugus, District-Chandrapur (M.S.) and their workman Shri Premdas Sadashiv Kamble Clo Murlidhar Durve, Behind Janta Junior College, P.O. Ghugus, Tahsil & District-Chandrapur.

APPEARANCES:

For Workman-Shii Premdas Sada-hiv Kamble,

For Management-Shri Rajendra Menon, Advocate.

INDUSTRY: Coal Mines DISTRICT; Chandrapur (M.S.)

AWARD

Dated the 1st July, 1987

The Central Government in exercise of its powers under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication, vide Notification No. L-21012|13|86-D.III(B), dated 26th May, 1987.

"Whether the action taken by the management of Mis. Western Coalfields Limited in Sub Area No. II. Ghugus Colliery, P.O. Ghugus, District Chandrapur (MS) is justified in terminating the services of the workman Shri Premdas Sadashiv Kamble with effect from 20-6-1985 ? If not, what relief the workman concerned is entitled to ?"

This case was registered on 8th June, 1987. Thereafter parties were to file statement of claim. Parties have filed settlement before me which is duly verified and accented on behalf of the management by Shri R. K. Singh and on behalf of the workman himself.

I have gone through the settlement and I find that the settlement is mutual, lawful and in the interest of the work-

I therefore, pass award in terms of the settlement and answer the reference as follows:—

- Shri P. S. Kamble will be reinstated on the same post held by him at the time of termination.
- The period of absence from the date of termfhation to the date of joining will be treatd as dies-non i.e. "No Work no Pay".
- The workman will not be entitled to wages or any other payment whatsoever for the period of idleness from the date of his termination to the date of his reinstatement|joining his duties.
- 4. On reinstatement Shri P. S. Kamble will be kept on probation for a period of one year during which his attendance performance and conduct will be closely watched. An assurance of good performance, conduct and punctuality will be furnished by the workman before joining the duties. If performance conduct during the probation period is not found satisfactory, his services will be liable to be terminated. However, if his performance and conduct during the probation period are found satisfactory the management may consider to grant him a continuity of service for the limited purpose of payment of gratuity.
- The posting of Shri P. S. Kamble shall be decided by the management.
- The workman will be allowed to join duty within the period of one month of signing the Memorandum of settlement.
- 7. Both the party agreed to sattle the dispute on the above terms and conditions; and the Memorandum of settlement will be submitted to the Ministry for closing the case once for all.

V. S. YADAV, Presiding Officer [No. L-21012|13|86-D.IH(B)]

का आ. 2098—-औद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के ग्रनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बेस्टर्न कीलफील्ड्स लिमिटड के प्रबंधतंत्र से सम्बध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, श्रनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक ध्रधिकरण, जबलपुर के पंचांट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-7-87 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2098.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th July, 1987.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT|LC(R)(97)|1985

PARTIES:

Employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, Dhanpuri Open Cast Mines, P.O. Amlai Colliery, District Shashdol (M.P.) and their workmen represented through the Rashtriya Koyla Khadan Mazdoor Sabha, Sohagpur Area, P.O. Dhanpuri, District Shahdol (M.P.).

APPEARANCES:

For Workmen -Shri S. K. Rão, Advocate.

For Management-Shri P. S. Nair, Advocate.

INDUSTRY: Coal Mining DISTRICT: Shahdol (M.P.)

AWARD

Dated, 3rd July, 1987

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour by Notification No. L-22012(16)|85-D.V. dated 31-10-85 1st Nov. 85 for adjudication of the following dispute:

- "Whether the dismissal of S|Shri Satrughan Pandey, Kanta Singh, S. K. Kayoom and Ambika Prasad Chowbey, Elect. Helper, Mining Sirdar, Fitter and Dumper operator respectively of Dhanpuri Open cast Mines from services with effect from 24-9-84 by the General Manager, Sohagpur Area of Western Coalfields Limited P.O. Dhanpuri District Shadol is justified? If not, to what relief the concerned workmen are entitled for?"
- 2. Non-controversial facts of the case are that on behalf of the management it was alleged that on 5-1-1984 at about 11.30 A.M. Shri S. K. Kayoom along with S|Shri Satrughan Pandey, Kanta Singh and Ambika Prasad Chowbey and more than about 30 workers gheraod the Sub-Area Manager and abused him. They also threatened to kill him. On the basis of the said allegation chargesheets dated 6-1-1984 were issued to them in the following words:
 - "It has been reported to the undersigned as under :—
 That on 5-I-84 at about 11.30 A.M. you along with S|Shri S. K. Kayoom, Fitter, Kanta Singh, Mining Sirdar and Shatrughan Pandey, Elec. Helper instigated a mob of about 30 workers while on duty hours and gheraod Shri Birbal Kapoor, Sub-Area Manager upto 1.30 P.M. You also abused him in a most filthy language which is reproduced below:—

"MADARCHOD-BETT CHOD" VAGAIRAH VAGAIRAH.

- You also threatened to kill him if he does not sign the papers produced by Shri Kayoom, Inspite of the resistance, you forced him to sign by catching hold of his hand and as such you have obstructed him to discharge his official duties which constitutes a major misconduct under the standing orders applicable to you which reads as under:
- 17(i)(e)—Drunkness, fighting or riotous, disorderly or indecent behaviour while on duty at the place of work.
- 17(i) (p)—Leaving work without permission or sufficient reasons.
- 17(1)(c)—Any breach of the Mines Act, 1952, or any other Act or any rules, regulations or bye-laws thereunder or of any standing orders.
- 17(i)(r)—Threatening, abusing or assaulting any superior or co-worker."

The wor men replied to the show cause notice but it was not found satisfactory by the management. Therefore it decided to hold departmental enquiry and appointed Shri D. H. Goswami as an Enquiry Officer. Notice of enquiry was served on the workmen and they attended the enquiry with their co-worker. The enquiry against the four of the workmen was held jointly. After the necessary enquiry Enquiry Officer submitted his report finding the charges proved. Management passed orders dismissing the workmen from their services on the basis of the enquiry report, hence these proceedings. The management has supported the enquiry and findings of the Enquiry Officer and mishment awarded.

They also prayed that in case enquiry is vitiated the management be permitted to prove the misconduct on merits before this Tribunal.

- 3. The workmen have challenged the enquiry findings and the punishment awarded to them on various grounds which will be taken up while deciding the issues.
- 4. I framed the following issues and treated Issue Nos. 1 to 3 as pieliminary issues. My findings with reasons on preliminary issues are as under:—

ISSUES

- 1 Whether the enquiry is proper and legal ?
- 2. Whether the management is entitled to lead evidence before this Tribunal ?
- 3. Whiher the punishment awarded is proper and legal ?
- 4. Whether the termination of the workman is justified on facts of the case?
- 5. Relief and costs ?

FINDINGS WITH REASONS:

- 5. Issue Nos. 1, 2 and 3.—Parties submitted their written arguments. In their written arguments workmen have only pressed certain grounds to show that the enquiry is vitiated. Firstly it has been contended as a preliminary objection that the Western Coalfields Limited i.e. the management has no specific Standing Orders certified under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (hereinafter referred to as the Act of 1946) Therefore the enquiry is vitiated on this ground alone.
- 6. Next it has been contended that before the Nationalisation of the Burhar and Amlai Collieries of Rewa Coalfields Ltd. they were governed by their Standing Orders of the Company. After Nationalisation new Company has been formed. Therefore the action taken by the management on the basis of non-existing Company's standing order is illegal. It has been further contended that the management has not sought any permission or submitted any Draft Standing Orders, therefore the Model Standing Orders will not be applicable to the present case. Therefore the charge-sheet issued and domestic enquiry held and findings and punishment given on the basis of Model Standing Orders are illegal and the enquiry is vitiated.
- 7 On the other hand, on behalf of the management it has been contended that admittedly the present workmen were appointed prior to the Nationalisation and at that time they were governed by the Standing Orders of Rewa Colliery but after Nationalisation Rewa Coalfields were taken over by the management of Western Coalfields Limited and there being no certified Standing Orders of W.C. Ltd. management has taken action on the basis of Model Standing Orders and it is not necessary to take any permission to make the Model Standing Orders applicable as is apparent from Section 13A of the Act of 1946. I am of the opinion that the Act of 1946 nowhere lavs down that any prior approval or permission is required for adopting of Model Standing Orders. It is true that as per Section 3 of the Act of 1946 within six months from the date of the Act becomes applicable to an industrial establishment the employer is required to get the Standing Orders certified. But atmittedly the W.C. I td. did not get any such Standing Orders certified Therefore in the absence of such certification provision of Section 12-A of the Act of 1946 which is reproduced below will apply
 - "12-A Temporary application of model standing orders" -
 - (1) Notwithstanding anything contained in Section 3 to 12 for the period commencing on the date on which this Act becomes applicable to an industrial establishment and ending with the date on which the Standing orders as finally pertified under this Act come into operation under Section 7 in that establishment the are cribed model standing orders shall be deemed to be adopted in that establishment, and the growing of Section 9, sub-section (2) of section 13 and Section 13-A shall apply to such standing orders as the apply to the standing orders as the apply to the standing orders as containing orders as the apply to the standing orders as certified.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to an industrial establishment in respect of which the appropriate Government is the Government of the State of Gujarat or the Government of the State of Maharashtra."

The above provision clearly says that notwithstanding anything contained in Sec. 3 to 12 the model standing orders shall be deemed to be adopted in the establishment in the intervening period. It speaks of no prior approval or permission as contended by the Learned Counsel for the workmen.

- 8 Leaned Counsel for the workmen has also relied on the case of Western India Match Company Ltd Vs. Their workmen (reported in AIR 1973-Not page 531, but page 2650). I have gone through the authority and I find that nowhere it supports the contention of the workmen that the model standing orders will not apply unless prior permission of approval is sought for the Standing Orders. In fact, Hon'ble Judge of our own High Court of Madhya Pradesh in the case of Sakhrullah Khan Nasrullah Khan Vs. State Industrial Court, Indore and others (MPLJ 1978 p. 455) have held that model Standing Orders under Sec. 12-A are applicable till the Standing Orders are got certified.
- 9 I carned Counsel for the workmen had further contended that the charge nowhere mentions which particular Standing Orders were contravened by the workmen. Therefore the charge is in any case bad for vagueness. I find that in the charge the sections of the model Standing Orders are mentioned. Therefore the omission to mention the word 'model Standing Orders' is not fatal.
- 10 The second ground on which the domestic enquiry has been challenged is that the workmen were not furnished with the copy of the complaint either to the management or to the policemen or even the rame of the witness who had made complaint was not made known. Therefore the projudice has been caused to the workmen and the enquiry I have gone through the record and I find that vitiated the Agent, Dhanpuri Open Cast Mine who issued the chargeheet has clearly mentioned that it has been reported to the undersigned. He has nowhere said that he was given a complaint in writing by any particular person. So the question of furnishing a copy of the non-existing document does not give In any one programment beautiful to the contract of the contra not arise. In any case, management has not relied on any such written complaint in support of his case. Therefore also it was not required to furnish a copy of name of the complainant. It is true that in serious cases of law and order situation it is the State through the police who takes action but not in all cases. In the instant case, department dealt it departmentally and not through the police. Therefore the question of furnishing a non-existing police report does not
- 11. Lastly it has been contended that the workmen were not informed whether they are satisfied with the appointment of the Enquiry Officer because the Enquiry Officer was a Deputy Personnel Manager and a good friend of Shri Birbal Kapeor, Sub-Area Manager. Besides thesir official capacity there is nothing on record to prove that they were very good friends. Any way, learned Counsel for the workmen was not able to point out to me that they raised any such objection during the course of enquiry. There is no such provision that the management should satisfy the workmen about the appointment of the Enquiry Officer without even any objection in that regard.
- 12 No other points though pleaded has been pressed before me perhaps because there is no substantial basis for the same on record. The appreciation of evidence also cannot said to be perverse.
- 13 From the above discussions, I find there is neither any illegibility nor impropriety in conducting the domestic enquiry or in the finding given by the Enquiry Officer. As for punishment, I find that the conduct alleged and proved against the subordinate staff about the treatment meted out to the superior officer in public the punishment awarded does not appear to be harsh or in any way excessive. Since the findings and the punishment is proper it is not necessary to give the management an opportunity to prove misconduct

before this Tribunal. I decide the preliminary issues No. 1. 2 and 3 accordingly and answer the reference as under :-

That the dismissal of S/Shri Satrughan Pandey, Kanta Singh, S. K. Kayoom and Ambika Prasad Chowbey, Elect. Helper, Mining Sirdar, Fitter and Dumper Operator respectively of Dhanpuri Open Cast Mine from services with effect from 24-9-84 by the General Manager, Sohagpur Area of Western Coal-fields Limited P.O. Dhanpuri, Disti. Shahdol is justified. Workmen concerned are not entitled to any relief. No order as to costs.

> V. S. YADAV, Presiding Officer [No, L-22012/16/85-D.V] V. K. SHARMA, Desk Officer

Dated: 3-7-1987

नई दिल्ली, 28 जूलाई 1987

का० आ० 2089:--ग्रीग्रोणिक विवाद ग्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) के धारा 17 के धनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, लक्ष्मी कर्माणयल बैंक लिमिटेड के प्रबन्धनंत्र से पंबद्ध नियोजकों भौर उनके कर्मकारों के भीज, प्रनुबन्ध में निर्दिष्ट भीगोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार श्रीचीगिक मधिकरण, नई दिल्ली में पंचाट को प्रकाशित करती है, जा केन्द्रीय सरकार को 10~7~1987 को प्राप्त **ह**न्ना था।

New Delhi, the 28th July, 1987

S.O. 2099.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Lakshmi Commercial Bank now amalgamated with Canara Bank and their workingn, which was received by the Central Government on the 10th July, 1987.

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT

Industrial Tribunal, New Delhi I. D. No. 61/80

In the matter of dispute between: Ashok Kumar Gupta s/o Shri Ram Gupta, r/o 4/48, Rodu Mohalla, Taran Taran, District Amritsar.

Versus

The Chief Personnel Manager, Lakshmi Commercial Bank, H-Block, Connaught Circus.

New Delhi.

APPEARANCES:

Shri Tara Chand Gupta-for the workman.

Shri N. C. Sikri for the Management

AWARD

The Central Government in the Ministry of I abour vide its notification No. L-12012/101/79-D. II. A, dated 1st July, 1980 has referred the following industrial dispute to this Fribunal for adjudication :

"Whether the action of the Mmanagement of Lakshmi Commercial Bank Ltd., H. Block, Connaught Circus, New Delhi (subsequently amalgamated with the Canara Bank) in terminating the services of Shri Ashok Kumar Gupta, Clerk-cum-Cashier-cum-Godown Keeper At Bundala Branch of the Bank with effect from 20-5-1978 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

2. Some of the undisputed facts are that the workman Shri Ashok Kumar Gupta made an application dated 29-12-77 to the Management of the bank formerly known as Lakshmi Commercial Bank I id. and later on amalgamated with the

Canala Bank vide notification dated 23-8-1985 (hereinafter reteriod to as the bank) for appointment as clerk/Cushiel, wheroupon he was appointed Clerk-cum-Cashier-cum-Godown that pending the issue of formal letter of appointment the workman joined the branch of the bank at village Bunala workman joined the branch of the bank at village Bunala Tehni and District Amritsar on 10-1-1978; that a formal order of appointment was issued on 13-3-78 informing the workman that on the basis of his application dated 29-12-1977 he had been selected and taken into service of the bank as Clerk-cum-Cashier-cum-Godown Keeper w.e.f. the date of joining on the basis of six months probation during which period his services could be terminated at any time by giving him proper notice; that the services of the workman were terminated w.e.f. 20-5-1978. A.N. w.e.f. 20-5-1978. A.N.

3. The case of the workman is that his services were terminated on the basis of a telegram the text of which read "work and conduct of Shri A. K. Gupta Clerk-cum-Cashier on probation not found satisfactory relieve him by paying full dues for full settlement of his claim forthwith." The workman has contended that the action of the Management the reminate his services during the probation on the Theorem terminate his services during the probation on the alleged misconduct was illegal unjustified and amounted to unfair labour practice. It is further stated that assuming but not admitting that his work was not found satisfactory the Management was within its rights to extend his probation period per para 495 of the Shastri Award. The workman has also alleged violation of sections 25-F, G and H of the I. D. Act. The workman further stated that in the written comments submitted by the Management before the Assistant Labour Commissioner, his services had been terminated on account of the following allegations based on surmises, and assumptions:

That he had misrepresented the fact that he was local candidate from Bundala and that he was coming late to office and was leaving bank before normal working hours of the bank and the bank branch Manager accordingly made several complaints to the Head Office about his work and for not performing complaints to the the duties satisfactorily.

In the event his services were terminated on the alleged misconduct he should have been provided proper opportunity to explain his conduct and there should have been proper enquiry.

2. The case of the Management is that the liability of the Canara Bank is limited to the provisions of the scheme of amalgamation clause 10 of part III whereof provides that employees of the erstwhile Lakshmi Commercial Bank who were in the employment of the bank on the date of take over should be deemed to be in the employment of the transferee bank, if they exercise their option to the effect that the very fact that Mr. Ashok Kumar Gupta was not in the employment of the Lakshmi Commercial Bank and his contract of employment stood terminated as far back as 20-5-1978, the Canara Bank cannot be held liable in terms of the aforesaid scheme of amalgamation which has statuto a decision of an institution which has staticated or force and over rides the general law including the I. D. Act. On merits the termination of the services of the workman during the period of probation was justified on the ground that the work and conduct of the workman had not been found satisfactory; that the termination of the services during the world of stability does not see that the services. been found satisfactory; that the termination of the services during the period of probation does not amount to disciplinary proceedings and it is a case of discharge simplicitor; that the workman had made mis-representation in the application dated 29-12-1977 that he belonged to a very respectable family of Bundala whereas subsequently it was found that the workman was not a resident of Bundala and found the first belonged to Taron Taron. That he was quite the in fact belonged to Taran Taran. That he was quite unpunctual in reaching the bank from Taran Taran with the result that the work of the bank suffered and there were complaints from the customers and inspite of warning the worl man did not show any improvement. It was further stated that the workman was appointed mainly for the reaching that the workman was appointed mainly for the reaching that the workman was appointed mainly for the reaching that the workman was appointed mainly for the reaching that the workman was appointed mainly for the reaching that the workman was appointed mainly for the reaching that the workman was appointed that the workman was appointed to the transfer of the tra stated that the workman was appointed mainly for the reason that he was local resident of Bundala and will help in mobilising deposits and his claim that he belonged to Bundala was according to his one admission found to be incorrect and this resulted in loss of confidence.

5 I have given my anxious con deration to the entire focts and circumstances of this care and to the arguments unhanced and authorities relied upon by the ld. representatives of both the parties and I am of the opinion that it action of the Management in terminating the services of the workman is quite justified. It is not disputed that the workman was appointed on probation of six months w.e.f. 10-1-1978 when he joined the services of the bank and his services were terminated during the probation per od w.e.f. 20-5-78. It is apparent that he had not completed centinuous service of one year as defined in section 25-B and, therefore, the workman did not acquire the statutory protection of section 25-G and H in the case of this workman does not arise because the termination was within the probationary period and in this respect he is governed by the bank Award and the Binartite Settlements. The order dated 20-5-1978 of termination passed by the bank reads as under:

"I akshmi Commercial Bank Limited, Bandala."

Ref. No.

Dated 20-5-78

Tô

Shri Ashok Kumar Gupta Clerk|Cashier B|O Bundala.

Dear Sir,

As per telegraphic instructions received from H|O New Delhi vou are hereby relieved from the services of the Benk w.e.f. 20-5-78 A.N. as per Order No. 16|78 of date is also handed over to you amounting to Rs. 389.88 (Runees Three hundred eighty nine and paise 88 only) being the full and final settlement of your dues.

Yours faithfully, Sdl-

Manager

The telegraphic instructions mentioned in the above order are also reproduced below:

"The Lakshmi Commercial Bank I lmited,

(Regd. Office: 'H' Block Connaught Circus,

New Delhi).

Ref. No. Estt, 3424 78

Dated 16th May, 1978.

TELEGRAM

MANAGER

LAKSHMI COMMERCIAL BANK
BUNDALA

DISTRICT AMRITSAR

WORK AND CONDUCT OF ASHOK GUPTA CLERK CUM CASHIER ON PROBATION NOT FOUND SATISFACTORY (STOP) RELIFIVE HIM BY PAYING FULL DUES IN FULL SATISFACTION OF HIS CLAIM FORTHWITH

LAKSHMI COMMERCIAL BANK."

It is apparent that the above order of termination amounts to discharge simplicitor and does not pass any stigma on the workman and hence no charge sheet or enquiry was necessary. Although it was not necessary for the Management to explain the reasons for discharge during pobation period vet it has been clearly demonstrated that he workman had made a mis-tepresentation regarding his place of domicife. In his application dated 29-2-77 he had stated that he belonged to very respectable family of Bundala District Amriesar. The Management has placed on record a letter dated 31-12-77 addressed by the Assistant General Manager to the Personnel Manager of the Bank contents of which are reproduced below:

"The Personnel Manager,

Head Office, Connaught Circus,

New Delhi-110001.

Dear Sir.

Reg : Wr Ashok Kumar Gupta-Local appointed for Bundala Branch.

We enclose an application of the above named duly recommended by the Franch Manager for appointment as Clerk-cum-Cashier in place of Mr. Ajit Singh, who has been promoted.

Since Mr. Ajit Singh was a local appointee, we thought fit to select the above named as he is also a local man.

This refers to the discuss on the undersigned had with you, I Indly get the appointment approved from the Chairman for issuin; the regular appointment letter. In the meantime, we have advised the Branch Manager to allow the above named to join duties.

Thanking you.

Yous faithfully, Sd]-

ASSTI. GENERAL MANAGER."

It is apparent from the above letter that the fact that the workman was local man was the major consideration for his appointment. However, the workman himself in the identity from dated 18-3-78 submitted by him gave his home address as house No. 4|48, Rodu Mohalla Taran Taran and he gave his present residential address as Clo Dr. Amar Singh Veid V. P. & O. Bundla, This was a clear admission that the workman did not belong to Bundala and consequently the statement made to this effect in his application dated 29-12-77 was a mis-representation. This was a reasonable ground for loss of con dence and no further enquiry was called for on the part of the bank. It is an accepted fact that during the probation period an employee is on test and he has to satisfy his employer regarding his work and conduct during this period and the Management is not required to give reasons for the termination of service during the probaton period. Para 522 of the Shastri Award clearly provides that the services of the probationer may be terminated by one month's notice or on payment of a month, pay and allowances in lien of notice. No doubt part 495 of the Shastry Award provides for the extension of the probation period by further 3 months after the initial period of six months but it is not mandatory for the Management to extend the probationery period for the further period of 3 months after the initial peiod of six months. It is admitted by the Management that they did not serve the requisite one month notice on the workman nor did they make any payment of one months now and allowances in lieu of notice. In fact the Management has offerred to make payment of the one month's pay and allowances in liou of period of notice. The lapse of the Management in this repard is contractual in nature not mandatory and the only relief the workman is entitled to is nav and allowance for one month in lieu of non-rervice of the notice. The amount of nav and allewance for one month has not been indicated either by the Management or by he workman However, taking into consideration the long time which has elaused and the cost of the proceedings the workman had to hear the Management is directed to nay to the workman a lumn sum commensation of Rs 2000's for is lanse in not serving notice or naving one months may and allowance in lieu of the natice. This reference stands disposed of accordingly.

Further it is ordered but the requires number of corrier of this award may be forwarded to the Central Government for necessary action of their end.

G. S. KALRA, Presiding Officer

23rd June. 1987

[No L 12012[101]79-D.H(A)]

का० आ० 2100 :-- श्रौद्योगिक विवाद ध्रीगितयम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, यृतियन बैंक आफ इण्डिया के प्रवन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों धीर उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट् भौगोगिक विवाद में श्रीयोगिक ध्रुमिकरण ध्रह्मदाबाद के पंचाट की प्रकार करती है जी नेण्डीन सरकार की 13-7-87 की प्राप्त हुआ था।

S.O. 2100.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government bereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad as hown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th July, 1987.

BEFORE SHRI C. G ROTHOD, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT AHMEDABAD

Reference (ITC) 11 of 1986

ADJUDICATION

BETWEEN

Management of Union Bank of India, Dudheshwar Branch, Ahmedabad.

AND

The workmen employed under it.

In the matter of terminating the services of Smt. R. R. Solanki with effect from 1-12-84 is justified? If not, to what relief is Smt. Solanki entitled to?

STATE : Gujarat

INDUSTRY . Banking Ahmedabad.

AWARD

The Desk Officer, Ministry of Labour, Government of India in exercise of the powers conferred u/s. 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the dispute which exists between the management of the Union Bank of India, Dudheshwar Branch, Ahmedabad and their workmen namely Smt. R. R. Solanki in regard to the termination of her services with effect from 1-12-84. The said dispute was first referred to the Industrial Tribunal No. 2, Bombay but by subsequent order dated 4-11-86, Government of India has transferred the same to the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Ahmedabad with the direction that the said Court shall proceed with the proceedings from the stage at which It is transferred and dispose of the same according to law. The statement of claim in this case was filed before the Industrial Tribunal, No. 2, Bombay vide Ex. 2 and by Ex. 6 the same was permitted to be treated as statement of claim filed in the present reference.

2. In the statement of claim at Ex. 2, it is contended by the concerned workman that she was working as a Lavatory Cleaner in the Union Bank of India at Dudheswar Branch and that she was working as a Parttime but the work was of permanent nature; that she was working with the Bank for he last ten years and that she was being paid Rs. 15 per month; that the payment was made by obtaining signature on the voucher; that during this period, the wages of the other employees were revised in the upward division whereas the second party was not given any increment or the rise in the wages. As the prices were rising, the work-man submitted an application on 26-11-84 to the Manager to revise the wages. It is further her case that the second party also reliably learnt that the first party-Bank was contemplating to recruit the Safai Kamdar with higher wages, Therefore, she also submitted an application for the revision of the wager in upward directions and that she further requested that she be employed as Safai Kamdar. It is further her case that on 1-12-1984 when she reported for work, the first party i.e. the Bank informed her that her services were no longer required by the Bank; that the Bank abruptly terminated her services without assigning any reasons. It is further contended that Dudheswar Branch of the Union Bank of India is still functioning and the Branch has not been closed down so far. It is also submitted that the workman was doing the work of cleaning the lavatories: that the work of cleaning lavatories can not he said to be of a temporary noture; that it was of a permanent nature

and, therefore, it can be said that she was working on temporary basis. It is also contended that the concerned worknian has put in service of 10 years and during the tenure of the service she was not served with any notice; that her performance was worthy of emulation. It is also contended that merely because the concerned workman gave an application for revising the wages, she became the eye-sore of the Management that the only disqualification on the misconduct of the concerned workman was that she has raised a demand for higher wages. It is further contended that the action of the Bank in terminating the services of the second party is arbitrary and deserves to be struck down; that the Bank has not issued any show cause notice, no written order has been served upon the second party for terminating her services and the Bank has not advanced any reasons for terminating her services and this action of the Bank in terminating her services is in gross violation of the principles of natural justice. It is also contended that the Bank has not paid the notice pay, unpaid wages and the detrenchment compensation and, therefore, that action of the Bank is in violation of the provisions contained in the Industrial Disputes Act. 1947. It is contended that the workman gave an application to the first party Bank for revising the wages in 1984 and that application for revision of the wages has incurred displeasure to the first party. In the circumstances, it is contended that the Bank should be directed to re-instate the workman concerned as Lavatory Cleaner or as Safar Kamdar w.e.f. 1-12-1984 and should also be paid full back wages till the date of re-instatement.

- 3. The Union Bank of India has filed its written statement Ex. 4 and it is contended, inter alia, that the reference is not tenable in law and it has no basis in law; in fact the reference is legally incompetent, that there was no relationship of employer-employee between the parties and, therefore, the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 are not attracted; that the second party is not a workman and, therefore, she has no locus standi to raise the present issue; that it is denied that since the workman concerned gave an application for revision of wages she has incurred the displeasure of the Bank. It is contended that the said allegation is totally false and misleading. It is denied that the concerned workman was working as a Pari-timer and that the payment of Rs. 15 per month to her was a starvation wage. It is contended that there is no contract of service at any point of time. The Bank happened to enter into an arrangement with the workman in the year 1972 under which in consideration of the payment of Rs. 10 p.m. which was subsequently raised to Rs. 15 pm the concerned workman performed the job of cleaning utinals and lavatory of Dudheshwar Road Branch of the Bank. It is contended that the work of cleaning urinals and latrine is not incidentally connected with the main work of Bank activity and that looking to the nature of job performed by second party. it was only an arrangement to perform the job work of cleaning urinals and latrines; that she could do that job at any time convenient to her; there was no obligation on her to wok for a fixed period: that there was no actual supervision of the work; that there was no control of the Bank on the manner of the job being performed by the second party and it was not obligatory on the parts of the second party to do the job personally; that the Bank authority had no right to take disciplinary action against the concerned workman; that the work hardly took fifteen minutes per day. The arrangement entered into between the bank and the workman was that of a contractor to do a particular iob and that of master and servant relationship. It is contended that per Justice K. T. Desai's award the persons who were employed by the Bank to do job work are excluded from the operations of the Award. In view of what has been stated above, the second party is not entitled to any of the relief whatsoever as prayed for and she is not entitled to reinstatement with back wages.
- 4. Mr. Yogesh Vyas appeared for the Bank and Mr. D. S. Vasavda for the concerned workman and after the evidence was recorded in the case. I have heard their arguments fully.

- 5. The poin's which require to be considered are-
 - Whether the action of the management of Union Bank of India, Dudeshwar Branch, Ahmedahad in terminating the services of Smt. R. R. Solanki w.e.f. 1-12-84 is justified?
 - 2. If not,, to what relief she is entitled to?
- 6. My answer to the aforesaid points are as under:---
 - 1 No.
 - 2 As per order below.

REASONS

- 7. In the present reference the concerned workman has been examined at Ex. 7 and on behalf of the Bank, Mr. Natwarlal Chin sulat Patel, Planning and Development Officer, who was Manager in the Dudheshwar Branch of the Union Bunk of India in the year 1972-73 is examined at Ex. 15 and Sh. Ganpathhai Ramjibhai Chauhan who was working as Part-time Sweeper of the Union Bank is examined at Ex. 18. In the evidence of Smt. R. R. Solanki, vide L... 7, she has stated that she was working as Sweeper in the Dudheshwar Branch of Union Bank of India. Admittedly even according to the written statement filed and as per the evidence of Shi N. C. Patel, Ex. 15, it appears that she was appointed as Sweeper in the year 1972-73; that her work was that of cleaning lavatories. Admittedly the concerned workman was required to clean four urinals and one lavatory at the Dudheshwar Branch of the Bank. This is the say of the concerned workman, Smt. R. R. Solanki vide Ex. 7. She has also stated that she was employed by the Branch Manager and she w.s instructed to come between 9.30—10.00 A.M. for an hour and complete the work. Admittedly she was not given any written order as regards her appointment, but she was orally instructed what work should be done by her. According to her she was instructed to do this work personally and not with the help of anyone cise. Smit R. R. Solatki, Ex. 7, further states in her without the for the right of the states of her the states of the states. evidence—that for eleaning lavatories she was he'ry supplie? piece cloth, acid etc. She has further stated in her evidence that for doing this work of cleaning, she required to work for one nour. She denied the allegation in the cross examination that she required only Rs. 15 for doing this work. She has also stated that she has to do this work personally and she could not get this work done by anyone else. She had also denied the allegation that it is not true to say that the Manager was not supervising her work. She has also denied the allegation that the Manager had no right to reprimand her for unsatisfactory work.
- 8. If we were refer to the evidence of Mr. Natwarlal C. Patel, he has stated that this is a job work and does not require more than 10 minutes. He has also stated that they were not supervising this work. He has stated that the workman concerned used to work before 11.00 AM and used to clean favatories and the urinals; that there were two lavatories and three urinals. He has stated that for cleaning the labatories and urinals, pheneoils and Acid was required to be used. He has stated that he has not seen Ranjanabblen Ramanlal, but he has admitted that the work-of cleaning lavatories and urinals was of permanent nature. At present the person who is employed at Dudheshwar Branch for cleaning the office is also cleaning Lavatories and Toilet.
- 9. The next witness, Shri Ganpathai R. Chauhan, vide Ex. 18, has stated in his evidence that he was doing the work of cleaning labatories and toilet at Dudheshwar Branch. He has stated that this work would not take more than 10 minutes, but in the cross examination, he had to admit that for cleaning the labatories water is required to be used. It is required to be cleaned by brew; that for cleaning the toilet, it requires only one minute. I am not prepared to accept that the toilet can be cleaned within a minute. Eventhough, the allegation to the workmen concerned by the

management was that it would take not more than half an hour for that work, the concerned workman has stated that it will take having regard to the nature of the work such as the use of phenoil, acid, water, etc. that the concerned workman used to work at the Bank for little more than half an hour but less than 45 minutes.

- 10. Now admittedly her services were terminated on 1-12-84, but her services were terminated orally. It is her say that she gave an application for raising her wages by application Ex. 9. In the said application she has also stated that it takes about one hour for doing the said work and that her wages be increased but instead of increasing the wages it appears that her services were terminated orally after she gave an application at Ex. 8. The Management, of course, denied this fact, but they have not come out with any specific ground as to why her services were terminated all of a sudden. Now it appears from what has been stated as above that the work of cleaning the lavatories, uringle or toilet was done by the concerned workman. She was doing this work since about ten years. Initially, she was paid Rs. 10 per month and, thereafter, the wages were increared to Rs 15 per month. Now, it is contended by the Management that her work had not been supervised, but since she was engaged for cleaning prinals and lavatories and when material for cleaning were being supplied by the Bank, it is clear that her work was being supervised by the bank authorities. It would not be correct or proper to brush aside the case of the concerned workman on the ground that her work was not being supervised on the ground that she was required to do the work before 11.00 A.M., and therefore, her work could not have been approvised by anyone. As stated, earlier, she was being supplied material such as acid, a piece of cloth etc. and she was required to clean the lavatories and urinals with the help of the said material and water and it being so, it cannot be said that her work was not supervised by the Management. The Management had really a control and supervision of the work done by her.
- 11. Various decisions are cited by Mr. Yogesh Vyas for the Bank and if we were to refer the same, we find that none of authorities really help the Bank or the Management. In the decision namely Achuta Achar Annappa Achar v. Management of M/s. Sharada Jewellery, Mangalore, 1968 Lab. IC 716, it appears that the firm used to entrust the gold to the goldsmiths for making jewels. The wages were mutually agreed upon depending upon the work to be done. The goldsmiths used to work in the premises of the management to suit the convenience of the customers, although, sometimes, the goldsmiths used to take the gold to their own houses and that there were no fixed hours of work and that the goldsmiths were free to work at any time without being subject to the control or supervision by the management. In view of this evidence, the Labour Court held that he was not under the order or control of, the proprietor of the concern. This decision does not in any way help the management in as much as the principles on this point are well settled. In this case, two Supreme Court decisions were referred to.

One of the decision referred to is D. C. Dewan Mohideen Sahib and Sons v. Secretary, United Beedi Workers' Union, Salem. AIR 1966, SC, page 370. In the said decision their Lordships of the Supreme Court observed the correct approach therefore, was to consider whether, having regard to the nature of the work, there was due control and supervision by the employer. It was further held that the question whether the relation between the parties was one as between an employer and employee or matter and servant was a pure question of fact, depending upon the circumstances of each case.

Similarly another decision namely Dharangadhara Chemicals Works Ltd. v. State of Saurashtra, AIR 1957, S.C. page 264 is referred to In the aforesaid decision. In Dharangadhara Chemicals Works Ltd., it is observed in para 14 as under:—

"The principle which emerges from these authorities is that the prima facie test for the determination of the relationship between master and servant is the existence of the right in the master to supervise and control the work done by the servant not only in the matter of directing what work the servant is to do but also the manner in which he shall do his work, or to borrow the words of Lord Uthwatt at page 23 in Mersey Docks and Harbour Board v. Coggins & Griffith (Liverpoor) Ltd., 1947-1 AC 1, at p. 23(E), The proper test is whether or not the hirer had authority to control the manner of execution of the action in question."

"The nature or Extent of control which is requisite to establish the relationship of employer and employee must necessarily vary from business to business and is by its very nature incapable of precise definition."

In view of the two Supreme Court's decisions as above, it is clear that the relationship between master and servant is the existence of the right in the master to supervise and control the work done by the servant and further in what number it shall be done. In the instant case, though the case is of a simple nature, the evidence on record clearly leads me to held that the management has the right to supervise and control the work. The witness for the Bank, Shri Ganaptbhai R. Chauhan has admitted that if he did not carry out his work at Dudheshwar Branch properly, he would be reprimanded. Thus, it is clear that the work that was being done by the present workman was such that as and when necessary, the management had a right to give instructions. The management could tell the concerned workman to clean the lavatories more properly and thoroughly and that it could be said that there was a control in respect of the work done by the concerned workman. There is no dispute of the fact that the Branch Manager had employed the concerned workman that she was employed to do this work and as stated above, the management had the power to supervise and control her work.

- 12. The next decision cited is Management of Radia Foundation Engineering Ltd. v. State of Bihar, 1970 Lab. IC, page 1119. In the said decision also it is stated that the question whether the relationship between the parties is one as between master and servant is a pure question of fact, the important test for determination being the existence of the right in the master to supervise and control the work done by the servant. In the said decision, it is also stated that mere fact that the workmen are paid on daily rates or temporary basis, will not make any independent contractors.
- 13. The next decision cited by the learned Advocate, Shri Yogeshbhai Vyas, for the management is namely M/s. Pivate Lal Adishwar Lal v. Commissioner of Income-tax, Delni AIR 1960, SC 997. In the said decision, though, the question involved was under the Income-tax Act the same principle as referred to me in Dharangadhara Chemicals Works Ltd. v. State of Saurashtra, AIR 1957, SC, page 264 are referred and they need not be repeated here. Similarly, a decision was cited on behalf of the mangement namely shankar Balaji v. State of Maharashtra, AIR 1962, SC, p. 517, namely was a case of Bidi roller and the question was conviction u/s. 92 of the Factories Act. In that case there was no agreement or contract between the appellant and Pandurang As stated in the decision it appears that Mr Pandurang whenever he went to work, the appellant used to supply Tobacco and for rolling Bidi Pandurang was paid at a certain extent on the quantity of bidis turned out. The management in that case exercise no control or supervision on Pandurang but such is not the case here. Here the workers has to attend the work regularly and she was not free to report to work whenever she liked.
- 14. Mr. D. S. Vasavda for the workman has referred to a decision namely Shining Tailors v. Industrial Tribunal II U.P., 1983, II I.I.J., page 413. In that case since the payment was made on piece-rate basis, the Tribunal held that there is no relationship between master and servant and the workmen were independent contractors. The Supreme Court has observed that the test employed in the past was one of determining the degree of control that the employer

wielded over the workmen. However, in the situation in Silver Jubilee Tailoring House v. Chief Inspector of Shops and Establishments, (1973-II LLJ 495, Mathew), speaking for the Court observed that the control idea was more suited to the agricultural society prior to Industrial Revolution and during the last two decades the emphasis in the field has shifted from, and no longer rects exclusively or strongly upon, the question of control. It was further observed that a search for a formula in the nature of a single test will not serve any useful purpose, and all factors that have been referred to in the cases on topics, should be considered to tell a contract of service. Approaching the neitter from this angle, the Court observed that the employer's right to reject the end product if it does not conform to the instructions of the employer speaks for the element of control and supervision. So also, the right of removal of the workman or not to give the work has the element of control and supervision. If these aspects are considered decisive, they are amply satisfied to the facts of this case. So in the instant case also it is clear that the concerned workman was doing the work under the control and supervision of the Branch Manager. trol or supervision need not mean that the authorities ought to remain present there. It is possible that he may remain present, but in any case that is not in any way material. The question is whether he had a right to take the work and give suitable instructions to the concerned workman. As stated earlier, they were supplying the necessary material for cleaning the lavatories and utinals and, therefore, it is clear that they had a control over the work done by her. It, therefore, follows that the concerned workman was not merely a job worker. No such point, it appears, was canvassed during the course of the arguments, therefore it is clear that the concerned workman was doing the work as an employee of the Bank.

15. It is then urged that the work she was required to do was of a short period of about half an hour and, therefore, she could not be said to be a worker. If we have to refer to the definition of the word "workman" as defined u/s. 2(s) of the I.D. Act, it is clear that workman means any person (including an apprentice) employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward, Moreover in the decision namely Mukunda v. Managing Director, KSRTC, 1986,ILLJ, p. 470, it is held that Badlis are workmen who fall within the definition of workmen in S. 2(s) of the Industrial Disputes Act 1947 and they are entitled to the benefits in Chapter V-A of the said Act. Even a casual worker is held to be a workman (See the case of Tapan Kumar Jang v. Calcutta Telephones, 1981, II LLJ, p. 382). Therefore, there is no doubt that the conferned employee is a workman as defined under the Industrial Disputes Act.

16. Now as decided in the case of Santosh Gupta v. State Bank of India, 1980, II LLJ, p. 72 by the Supreme Court, we find that in the instant case there was a termination of services and this is not denied and, therefore, as held by the Supreme Court when such a termination is without following the procedure u/s. 25F, it would be bad. In the said decision, it is observed that in our view if due weight is given to the words "the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever" and if the words "for any reason whatsoever" are understood to mean what they plainly say, it is difficult to escape the conclusion that the expression "retrenchment" must include every termination of the service of a workman by an act, of the employer. The underlying assumption, of course, is that the undertaking is running as an undertaking and the employer continues as an employer but where either on account of transfer of the undertaking or on account of the closure of the undertaking the basic assumption disappears, there can be no question of "retrenchment" within the meaning of the definition contained in S. 2(00).

17. The other decision namely Malkhan Singh v. Union of India, 1981, II LLI, p. 174 in which the Delhi High Court held that "Retrenchment" at defined in S. 2(00) would include termination of services of a temporary railway servant. Similarly, in the decision namely Ramachandra Vithuji Kothare v. Industrial Court, Nagpur, 1986, I LIJ.

p. 363, it is held that termination of service for any reason whatsoever, except by way of punishment in retrenchment within the meaning of the said word in the LD. Act. It is also stated that any reason referred to in the definition would include the reason of loss of confidence. It is further stated that the provisions of S. 25F are the provisions of statute which superimpose or super-add certain obligations upon the employer in respect of his conduct of employment, statutory or otherwise with the workmen to whom I. D. Act applied. The effect of provisions of S. 25F would be that irrespective of the contract of employment, the mandatory provisions of S. 25F will have to be complied with.

18. In view of what has been stated as above, it is clear that in the instant case, the termination of services of the concerned employee by the Management without giving one month's notice and or pay in lieu of such notice is in clear contravention u.fs. 25F of the I.D. Act. Again she has not been paid retrenchment compensation and it is also in clear violation of 25F of the Act. It, therefore, appears to me that the Management was not right in terminating the services of the concerned workman, The work which she was carrying on was of a permanent nature and though it is possible that the work she was carrying on required about 30 to 40 minutes is not itself a sufficient criterial to reject the contention of the workman that she was an employee of the Bank. The work of the concerned workman was being supervised by the Bank authorities. had a right to instruct her but not terminate. Naturally she is a workman of the Bank after her services were terminated orally and another workman namely Shri Ganpatbhai R. Chauhan, Ex. 18, was appointed in her place and he was being paid Rs. 340 for two hours work. He was also required to do the said work and besides that, according to him, he was also required to do the work of cleaning of office and it would not take more time. Therefore, it is office and it would not take more time, clear that the services of Smt. R. R. Solanki were wrongly terminated without following the procedure as laid down u/s. 25F of the I.D. Act. The termination is, therefore, ab initio void. She has to be re-instated and paid wages. Her wages shall be fixed on the oasis of duty hours. Before parting with the case I may state that eventbough a contention was raised in the written statement filed by Bank that in view of the award passed by Justice, Shri K. T. Desai in reference No. 1 of 1980, the persons employed by the Bank to do the job work are excluded from the opera-tion of the award. The award was not produced nor any The award was not produced nor any specific provisions therein were brought to my notice and, therefore, it appears that there is no substance in the contention, Moreover, as stated above, I have already held that this is not a case of job work. Lastly, I may state that eventhough this reference was received by the Tribunal in December, 1986, in view of the strike of the Advocates, no substantial progress could be made till 5th of March, 1987. It is in these circumstances that there has been a delay in the disposal of the present reference. I, threfore, pass the following order,

ORDER

- 19. The concerned workman, Smt. R. R. Solanki be reinstated in Union Bank of India of Dudheshwar Branch effective from 1-12-1984 and the be paid back wages on the basis that she had to carry out this work for 40/45 minutes.
- 20. The Management shall reinstate her within one month of the publication of this award and make the payment of artears within two months of the publication of this award.
 - 21 No order as to costs.

Sd/(Illegible),
Secretary.
Ahmedabad, 22nd June, 1987

C. G. RATHOD, Presiding Officer[No. L-12012/255/85-D.H(A)]N. K. VERMA, Desk Officer